सुभाषित *बिना निराश हुए ही हारको सह लेना पृथ्वीपर साहसकी सबसे बड़ी परीक्षा है।* ❑ हितोपदेश

मतदान कर्मियोंकी शहादत

लोकतंत्रके महाउत्सवमें ७५ मतदान कर्मियोंकी शहादतने चुनाव आयोगकी कार्यशैलीपर सवालिया निशान लगा दिया है। तेज धूप और लूके थपेड़े मतदान ड्यूटीमें लगे कर्मचारियोंके लिए आफत बन गये। छह चरणके चुनावमें गर्मीसे कहरसे मौतोंकी संख्यामें लगातार वृद्धि हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेशमें ३० मतदान कर्मियोंकी मौत स्तब्धकारी है। गर्मीसे जहां लोगोंकी मौत हो रही है वहीं बड़ी संख्यामें मतदान कर्मी उल्टी, दस्त, रक्तचाप जैसी बीमारियोंसे ग्रसित होकर जीवन-मृत्युके बीच संघर्ष कर रहे हैं। शुक्रवारको दर्ज की गयी मौतोंमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेशमें १७, बिहारमें १४, ओडिशामें पांच और झारखण्डमें चार मतदान कर्मीकी मौत हुई है। आज हम तकनीकमें बहुत आगे हैं और सटीक पूर्वानुमान भी सम्भव है ऐसेमें स्थितिका आकलन करनेमें कैसे चूक हुई इसपर गम्भीरतासे मंथन करनेकी जरूरत है। मतदान कर्मियोंके लिए जो भी व्यवस्था चुनाव आयोगने की, वह नाकाफी रही और उसका खामियाजा मतदान कर्मियोंको उठाना पड़ा है। भीषण गर्मीके चलते मतदान प्रतिशतमें गिरावटके बावजूद मतदान केन्द्रोंपर धूप और गर्मीसे बचनेके लिए कोई आवश्यक उपाय नहीं किये गये। हम एक देश, एक चुनावकी दिशामें आगे बढ़ रहे हैं, वैसेमें लोकसभाके सात चरणमें चुनाव करानेमें भी चुनाव आयोगकी कार्यशैलीपर प्रश्न उठना चिन्ता और विचारका विषय है। मतदान कर्मियोंकी रक्षा और सुरक्षा चुनाव आयोगकी जिम्मेदारी है। इसपर चुनाव आयोगको गम्भीरतासे विचार करना होगा। आयोगको चुनावके लिए ऐसे मौसमपर विचार करना चाहिए, जो सबके अनुकूल हो। फरवरी और मार्चमें यदि चुनाव कराये जाते हैं तो इस तरह मतदान कर्मियोंकी शहादत नहीं होगी और मतदानके प्रतिशतमें भी रेकार्ड वृद्धि सम्भव है। सरकारको भी ऐसे प्रयास करने चाहिए जिसमें जोखिम कम हो और परिणाम ज्यादा हो। चुनाव आयोगको चुनाव कार्यक्रम बनाते समय सभीके साथ समन्वय बनानेकी जरूरत है, क्योंकि लोगोंकी शहादतपर मुआवजाका मलहम लगा दिया जाता है, जबकि एक परिवार बिगड़ जाता है। ऐसेमें सरकारको मतदान ड्यूटीमें तैनात कर्मियोंकी मृत्युपर मुआवजा तो देना ही चाहिए साथ ही परिवारके एक सदस्यको सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए।

दहेज कानूनका दुरुपयोग

दहेज विरोधी कानूनका दुरुपयोग अत्यन्त चिन्तनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। वैवाहिक विवादोंमें कई महिलाएं दहेज विरोधी कानूनको हथियार बनाकर पति उनके परिवार और रिश्तेदारोंके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराती हैं और उन्हें समाजमें बदनाम करतीहैं जो देश, समाज और कानूनके समक्ष बड़ी चुनौती है। इस सम्बन्धमें केरल उच्च न्यायालयका यह कहना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि अदालतें वैवाहिक विवादोंके मामलोंको सावधानीसे देखें, क्योंकि कई महिलाएं क्रूरताका आरोप लगाकर अपने पतिके करीबी रिश्तेदारोंको परेशानीमें डालनेके लिए आईपीसीकी धारा ४९८ (ए) दुरुपयोग करती हैं। कानूनकी इस धाराके तहत पीड़ित महिला दहेज प्रताड़ना या क्रूरता करनेका आरोप लगाकर पति या ससुरालोंके खिलाफ मामला दर्ज करा सकती है। न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीनकी इस टिप्पणीसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वैवाहिक विवादोंमें कुछ महिलाएं पतिके माता-पिता, भाइयों-बहनों और अन्य रिश्तेदारोंके विरुद्ध अस्पष्ट आरोपोंके आधारपर आपराधिक मामला दर्ज करा देती हैं। आजके दौरमें ऐसे मामले धीरे-धीरे प्रचलनका रूप लेते जा रहे हैं, जो उचित नहीं है। इसे रोकनेके लिए ठोस और सार्थक कदम उठानेकी जरूरत है। ऐसे मामले सिर्फ केरलमें ही नहीं अपितु पूरे देशमें हो रहा है। न्याय और कानून मंत्रालयको इसपर विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि आईपीसीकी धारा ४९८-ए की समीक्षा की जाय और इसमें व्यापक संशोधन होना चाहिए जिससे निर्दोष लोगोंको फंसानेपर रोक लगे। मामला विद्वेषपूर्ण साबित होनेपर आरोप लगानेवाली महिलापर भी काररवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासनका भी यह उत्तरदायित्व है कि वह ऐसे मामलोंकी पूरी निष्पक्षतासे जांच करनेके बाद ही आरोप-पत्र दाखिल करे तभी इस कानूनके दुरुपयोगको रोका जा सकता है।

लोक संवाद

असत्य राजनीति

महोदय,- इतिहास भी कमालके गोते लगाता है! भला सोचिये २०२४ में वह १९२७ की कहानी दोहरा रहा है। तब यानी १९२७ में एक थीं कैथरीन मेयो और एक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन थे यह तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन कैथरीन मेयो कौन थीं यह जाननेकी जरूरत अधिकांश पाठकोंको पड़ेगी। वे एक अमेरिक, श्रेष्ठताके भावसे भरी, नकचढ़ी पत्रकार सरीखी कुछ थीं, जिन्हें कुछ लोग तब उसी तरह इतिहासकार भी कहते थे। १९२० के दशकमें मिस मेयो भारत आयी थीं, गांधीजीसे भी मिली थीं, दूसरी हस्तियोंसे भी मिली थीं, रवींद्रनाथ ठाकुरसे भी मिली थीं। गांधीजीके निर्देशमें चल रहे भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलनसे असहमत, असंतुष्ट, नाराज मेयो मैडमने एक किताब लिखी : मदर इंडिया! नाय नाय आप ऐसा मत मान बैठियेगा कि महबूब खानकी प्रसिद्ध फिल्म मदर इंडिया मेयो मैमकी इस किताबसे प्रेरित थी। यह किताब भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलनके मूल्यों, उसकी दिशा, उसकी उपलब्धियों आदिकी धज्जियां उड़ाती हुई यह साबित करती है कि भारतीय समाज कुरीतियों, अन्याय, अत्याचार तथा शोषणकी गंदी व्यवस्थापर टिका एक ऐसा गर्हित समाज है जिसे गुलाम बनाकर अंग्रेजोंने कुछ सभ्य, कुछ मानवीय बनाया है। बहुत कहनेपर गांधीजीने न केवल मदर इंडिया पढ़ी, बल्कि चौतरफा आग्रहके कारण बहुत व्यस्ततामेंसे समय निकालकर उसपर एक टिप्पणी भी लिखी जो १५ सितंबर १९२७ को यंग इंडियामें प्रकाशित हुई। नाली सफाई जमादारकी रिपोर्ट! गरज यह कि जिसका धंधा ही गंदगीको उकेर-उकेर कर देखना है, वह गंदगीके अलावा देखेगा भी तो क्या और वर्णन भी करेगा तो गंदगीका ही करेगा। महात्मा गांधीकी शैलीमें यह खासी कड़ी टिप्पणी थी। गांधीजीने लिखा कि यह बड़ी चालाकीसे लिखी गयी सशक्त किताब है, जो किसी हदतक सत्यका बखान, असत्यके प्रचारके लिए करती है। अब न कैथरीन मेयो हैं, न गांधीजी, लेकिन गंदगी फैलानेका धंधा जोरोंपर है। गन्दगीको सहेजने तथा बड़ी चालाकीसे सत्यका बखान इस तरह करना कि असत्यका प्रचार हो वाली संस्कृति जीवित भी है, जारी भी। प्रधान मंत्रीने इस कलामें महारत हासिल कर ली है। वे अब इस कलाके उस्ताद बन गये हैं। हम देखें तो प्रधान मंत्रीका कुल इतिहास २०१४ से शुरू होता है और कुर्सीतक पहुंचकर चुक जाता है। वे सत्ताकी जिन दो कुर्सियोंपर बैठे हैं- मुख्य मंत्री एवं प्रधान मंत्री। यदि वे कुर्सियां हटा दी जायं तो उनके पास कुछ भी बचता नहीं है। चुनावके सन्निपातमें इधर जब-जब मुंह खोल रहे हैं, इतिहासका मुंह खुलाका खुला रह जाता है। वैसे भी प्रधान मंत्री झूठ एवं सचमें फर्क करने जैसी नैतिकतामें पड़ते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसका चुनाव घोषणा-पत्र उन्हें मुस्लिम लीगके घोषणा-पत्र जैसा लगता है। कोई प्रमाण। कोई साम्यता। नहीं, यह सब बताना प्रधान मंत्रीका काम थोड़े ही है! उन्हें पता है कि उनकी बातको गोदी मीडिया देशभरमें पहुंचा देगा। आज राजनीतिमें अधिकतर नेता असत्य बोलते हैं। **-कुमार प्रशांत, वाया ईमेल।**

धर्मके नामपर आरक्षण

महोदय,-हालमें कलकत्ता हाईकोर्टने धर्मके नामपर आरक्षणको गैर-संवैधानिक बताते हुए इसे लागू न करनेका आदेश देते हुए ममता सरकारको झटका दिया। जो मजहबके नामपर आरक्षणकी मांग कर रहे हैं, उनसे एक सवाल है कि मान लो धर्म विशेषका कोई व्यक्ति समृद्ध है, लेकिन उसका बच्चा पढ़ने-लिखनेमें कमजोर है या फिर पढ़ाई करनेमें लापरवाही बरतता है, लेकिन किसी कोर्स या नौकरीमें उसे आरक्षणके कारण प्रवेश मिल जाता है और वहीं दूसरी तरफ किसी दूसरे मजहबके गरीब व्यक्तिका बच्चा पढ़ाईमें दिन-रात मेहनत करता है, लेकिन उसे धर्म विशेषके आरक्षणके कारण कहीं कोर्स या नौकरीमें प्रवेश नहीं मिलता है, क्योंकि हर जगह सीटोंकी संख्या सीमित होती है, क्या यह दूसरे धर्मके मेहनती युवाओंके साथ बेइंसाफी नहीं होगी। **-राजेश कुमार चौहान, वाया ईमेल।**

इस बार क्यों कम हुआ मतदान

इस बारके लोकसभा चुनावमें मतदानका कम प्रतिशत लोकतंत्रके लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। २०२४ के लोकसभा चुनावकी शुरुआतसे ही कम मतदान प्रतिशत चिंतनीय है। लोगोंका अपने मताधिकारका इस्तेमाल करनेमें इस प्रकारसे कम दिलचस्पी लेना यकीनन मजबूत लोकतंत्रके लिए अच्छा संकेत नहीं है।

❑ डा.वरिंदर भाटिया

भारतमें गरीब और अल्पसंख्यक वर्गको वोट एक अस्त्र जैसा लगता है जिसके इस्तेमालसे वे अपनी अहमियत जता सकते हैं तो ये लोग कोशिश करते हैं कि वोट अवश्य दें। शहरोंके गरीबोंमें एक बड़ी संख्या प्रवासी लोगोंकी होती है जिनके नाम मतदाता सूचीमें नहीं होते हैं, जबकि गांवोंमें कई बार मतदान केन्द्र बहुत दूर होते हैं जिसकी वजहसे भी कई लोग मतदान करने नहीं जाते हैं। फिर भी कुल मतदान प्रतिशतमें इस वर्गके लोगोंका प्रतिशत ३० से कम नहीं होता है। इनके द्वारा अल्पसंख्यकोंकी समर्थक पार्टी या जाति आधारित पार्टी या पैसा बांटनेवाली पार्टीको वोट देनेकी संभावना ज्यादा होती है। बाकी बीस प्रतिशत मतदान निम्न मध्यम वर्ग और कुछ मध्यम वर्ग द्वारा किया जाता है। उच्च वर्ग अकसर मतदानसे विरक्त रहता है। इस प्रकार सामान्य समयमें जब हम ५० प्रतिशत मतदान देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि लोग सरकारसे न तो ज्यादा खुश होते हैं, न ज्यादा असंतुष्ट होते हैं। लेकिन जब सरकार निरंकुश, भ्रष्ट, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करती या निष्क्रिय प्रतीत होती है तो मध्यम वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग अपनी पूरी ताकतके साथ सरकार बदलनेके लिए बाहर निकलता है और मतदान प्रतिशतमें १५ से २० प्रतिशतकी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार यह देखा गया है कि जब भी मतदान ६० प्रतिशतसे काफी ऊपर हो जाता है तो विपक्षकी पार्टी जीत जाती है।

जीवंत लोकतंत्रके लिए जरूरी है कि मतदाता पूरी सक्रियता और तन्मयतासे चुनाव प्रक्रियाका हिस्सा बने, लेकिन इस बारके चुनावमें पहले चरणसे ही देखनेमें आया कि मतदानके रोज अनेक मतदाता अपने परिवारके साथ घूमने-फिरने निकल पड़े। कुछ कहते सुने गये कि उनके परिवारके मत न भी पड़े तो क्या फर्क पड़ेगा। जीतनेवाली पार्टी तो जीत ही जायगी। बाहरी उम्मीदवारकी मौजूदगी भी कम मतदानके उभरते हुए कारणोंमें एक है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी होनेके कारण भी मतदाता वोट करने घरसे नहीं निकल रहे। चुनाव आयोगने पहले चरणके कम वोट प्रतिशत रहनेपर अपनी कोशिशें और तेज कर दी थी ताकि ज्यादासे ज्यादा मतदाता वोट करने घरोंसे निकलें, लेकिन मतदाताकी उदासीनता टूटी नहीं। दिल्ली जैसे राजधानी शहर, जहांके निवासी बनिस्बत पढ़े-लिखे और जागरूक माने जाते हैं, में भी मत प्रतिशत पिछली दफासे भी कम रह जाना वाकई चिन्ताकी बात है। दरअसल एक तो चुनावमें कोई लहर नहीं बन सकी है और चुनाव पूरी तरह स्थानीय मुद्दोंपर आ सिमटा है, परन्तु कम मतदानको किसी भी तर्कसे वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है। कम मतदान चिन्ताकी बात है। भारतके घटते मतदाता टर्नआउटके लिए पांच स्पष्ट कारण हैं। सामान्य तौरपर पहला, बहुतसे समृद्ध और शहरी निवासियोंका मानना है कि सरकारपर निर्भर न होनेके कारण उनके जीवनपर मतदानका बहुत कम बोझ है। दूसरा, प्रवासनके कारण बड़ी संख्यामें लोग अपने शहरोंसे बाहर निकल गये हैं। तीसरा, युवा और मध्यम वर्गके मतदाताओंको अकसर ऐसे राजनीतिज्ञोंसे संबंधित करना मुश्किल हो जाता है जो आपराधिक, सामंती प्रभु या नीतिगत विशेषज्ञताके अभाव वाले सेलिब्रिटी हैं। चौथा, कुछ लोग मतदान नहीं करते, बल्कि वास्तविकतामें वे मुद्दों या उम्मीदवारोंसे अनभिज्ञ हैं। पांचवां, मतदानको प्रोत्साहित करनेके लिए सेलिब्रिटी और आधुनिक टेक्नोलॉजीका उपयोग करनेमें पूरी सफलता नहीं मिली है। आज तमाम राजनीतिक दल, उम्मीदवार और खुद चुनाव आयोग भी इस बातको लेकर चिंतित नजर आ रहा है कि आखिर लोग वोट देने घरोंसे क्यों नहीं निकले। कम वोटिंगके पीछे गर्मी बड़ा कारण भले ही न हो, लेकिन एक कारण जरूर हो सकता है। कई वर्षोंके बाद अप्रैल महीनेमें इतनी तेज गर्मी पड़ी है। इससे कुछ फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कमसे कम मैं तो गर्मीकी वजहसे वोटिंग कम होनेको बड़ा कारण नहीं मानता। यदि ऐसा होता तो फिर सुबह और शाम वोटिंग प्रतिशत अधिक होता, जो अभीतक ट्रेंडमें दिखाई नहीं दिया। वोटर लिस्टमें वोटर और वोट देनेवालोंमें अन्तरके कई कारण हो सकते हैं। जैसे, वोटर उस समय उस स्थानपरसे कहीं कार्यके लिए बाहर चला गया। वह कार्य निजी, व्यावसायिक या नौकरीका हो सकता है। करोड़ों सरकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटीमें लगाये जाते हैं। हालांकि उनको पोस्टल बैलेटकी सुविधा दी जाती है, लेकिन उसमें फार्मलिटी अधिक है। इसलिए बहुतसे फॉर्म नहीं भरते। कई लोग नौकरी दूसरे शहरोंमें करते हैं, लेकिन वोट अपनी पुश्तैनी जगह ही बनवाया हुआ होता है। वोटके लिए ही अपने शहर या ग्राम खुदके खर्चसे जाकर वोटके लिए ही लोग जा नहीं पाते। कुछ लोगोंने दो जगह भी वोट बनाया होता है, एक पुश्तैनी जगह, दूसरा नौकरीका शहर। वह एक ही जगह तो वोट डाल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स दूसरी जगह पढ़ाई कर रहे होते हैं और होस्टलमें या किरायेपर रहते हैं। वे भी वोट डालने नहीं आ पाते। वृद्ध लोग या अकेली गृहिणी भी वोट देनेमें संकोच करती है। कुछ लोग बीमार हो सकते हैं। कुछ लोगोंकी शादी होनेपर दूसरी जगह जानेसे या वोटरका निधन होनेसे भी वोट नहीं पड़ पाता। कुछ लोग स्विंग वोटर होते हैं, वे नार्मल परिस्थितियोंमें वोट देनेकी जहमत नहीं उठाते। ये लोग जब वर्तमान सरकारको हटाना होता है, तब दूसरे पक्षके फेवरमें वोट करते हैं। बाकी जो जिस पार्टीके वोटर हैं, वे तो अपनी-अपनी लॉयल पार्टीको वोट करते ही हैं। ये स्विंग वोटर ही मतदान का प्रतिशत बढ़ाते हैं। परन्तु यदि शत-प्रतिशत मतदान नहीं हो रहा है तो डेमोक्रेसीके लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हमें मतदानको मूलभूत आवश्यकताके रूपमें समझकर मतदान करना चाहिए, साथ ही औरोंको भी प्रेरित करना चाहिए। मतदान एक मौलिक अधिकार और एक नागरिक कर्तव्य है। इसे अनिवार्य बनानेसे अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रक्रियामें भाग लेनेके लिए प्रोत्साहित होंगे और यह सुनिश्चित होगा कि सरकार लोगोंकी इच्छाकी प्रतिनिधि है। मतदान डेमोक्रेसीकी आत्मा है। गलत मतदान-मतदान नहीं करना, तटस्थ मतदान, लालच, सम्प्रदाय, जाति, पंथ, भाषा या क्षेत्रवादसे प्रेरित होकर मतदान करना किसी भी डेमोक्रेसीके लिए सही नहीं है।

यदि शत-प्रतिशत मतदान नहीं हो रहा है तो डेमोक्रेसीके लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। मतदान एक मौलिक अधिकार और नागरिक कर्तव्य है। इसे अनिवार्य बनानेसे अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रक्रियामें भाग लेनेके लिए प्रोत्साहित होंगे और यह सुनिश्चित होगा कि सरकार लोगोंकी इच्छाकी प्रतिनिधि है। मतदान डेमोक्रेसीकी आत्मा है। गलत मतदान न करना, तटस्थ मतदान, लालच, सम्प्रदाय, जाति, पंथ, भाषा या क्षेत्रवादसे प्रेरित होकर मतदान करना किसी भी डेमोक्रेसीके लिए सही नहीं है।

प्रेरक है प्राचीन भारतका इतिहास

भारत प्राचीन राष्ट्र है। लेकिन कई यूरोपीय और देशके वाम विचारके विद्वान भारतको राष्ट्र नहीं मानते। इस विशाल देशमें अनेक बोलियां, रीति-रिवाज एवं भाषाएं हैं। वामपंथी इतिहासकार रामशरण शर्माने भारतीय संस्कृतिको विलक्षण बताया है।

❑ हृदयनारायण दीक्षित

वामपंथी इतिहासकार रामशरण शर्माने प्रारंभिक भारतका परिचयमें भारतीय संस्कृतिको विलक्षण बताया है। यह सुंदर किताब है। उन्होंने लिखा है, भारत अनेकानेक मानव प्रजातियोंका संगम रहा है। प्राक् आर्य, हिन्द आर्य, यूनानी, शक, हूण और तुर्क आदि प्रजातियोंने भारतको अपना घर बनाया है। प्रत्येक प्रजातिने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तु कला और साहित्यके विकासमें यथाशक्ति अपना अपना योग दिया है। सभी समुदाय और उनके सांस्कृतिक वैशिष्ट्य इस तरह मिल गये हैं कि उनमेंसे किसीको हम उनके मूल रूपमें पहचान भी नहीं सकते। यूनानी, शक, हूण आदि इस तरह मिल गये कि उन्हें पहचानना कठिन है। शर्माने इस घुलनशीलताका श्रेय मूल भारतीय आर्य संस्कृतिको नहीं दिया। इस्लाम भारतीय समाजमें घुल नहीं पाया। ब्रिटिशोंने भारतीय संस्कृति, इतिहास परम्परा और दर्शनको परलोकवादी बताया। दुर्भाग्यसे उनके निष्कर्ष यहां आधुनिक कहे जाते हैं। यह चुनौती बड़ी है। देशमें बाहरसे आयी प्रजातियोंके योगदानकी प्रशंसा उचित है। कला और साहित्यके विकासमें भी उनके योगदानका उल्लेख सही है। लेकिन शर्मा जीने यहांके मूल निवासी अभिजनोंके रचनात्मक कार्योंकी ओर ध्यान नहीं दिया है। भारतमें वैदिक कालमें ही शिल्प, वास्तु और साहित्यका विकास हो चुका था। भारतके लोग राष्ट्रीय एकताके लिए सक्रिय रहे हैं। इसका मूल कारण उनके चित्तमें सक्रिय सांस्कृतिक राष्ट्रभाव था। रामशरण शर्माने भी लिखा है, भारतके लोगोंने इस विशाल उपमहाद्वीपको एक अखण्ड देश समझा। सारे देशको भरत नामक एक प्राचीन वंशके नामपर भारतवर्ष नाम दिया गया। ऋग्वेदके अनेक ऋषि भरतजन हैं। ऋग्वेदमें इनकी चर्चा है। शर्माने लिखा है, हिमालयसे समुद्रतक फैली यह भूमिको सार्वभौम राजाके द्वारा शासित क्षेत्रके रूपमें कल्पित है। हिमालयसे कन्याकुमारीतक। पूर्वमें ब्रह्मपुत्रकी घाटीसे पश्चिममें सिन्धु पारतक अपना राज्य फैलानेवाले राजाओंका व्यापक यशोगान किया है।

राष्ट्र यहांके निवासियोंके लिए आराध्य रहा है। सो इस अखण्ड देशका राजा यशस्वी होना चाहिए। ऐसे राजा प्राचीन कालमें चक्रवर्ती कहलाते थे। देशके बड़े भू-भागकी राजनीतिक एकताका स्वप्न काल्पनिक नहीं था। ईसापूर्व तीसरी सदीमें अशोकने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचलको छोड़कर सारे देशमें फैलाया। इसके पहले चन्द्रगुप्त मौर्यका शासन भी उल्लेखनीय है। चौथी सदीमें समुद्रगुप्तकी विजय यात्रा गंगाकी घाटीसे तमिल देशके छोरतक पहुंची थी। शर्माने याद दिलाया है कि राजनीतिक एकताके अभावमें भी सारे देशमें राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा था। इसका कारण संस्कृति है। सांस्कृतिक एकता महत्वपूर्ण होती है। यहां सांस्कृतिक एकता मजबूत करनेके प्रयास जारी रहे हैं। ईसापूर्व तीसरी सदीमें प्राकृत भाषा काफी बड़े हिस्सेमें प्रयुक्त होती थी। अशोकके शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपिमें लिखे गये। शर्मा जीने संस्कृत भाषाके सम्बंधमें सही बात लिखी है, बादमें संस्कृतने प्रतिष्ठित स्थान पाया। संस्कृत देशके अधिकांश हिस्सोंमें राजभाषाके रूपमें स्वीकृत थी। प्राचीन भारतका इतिहास प्रेरक है। भारतीय विद्वानोंने हस्तलिखित महाकाव्यों और पुराणों आदिमें अपने प्राचीन इतिहासको लगातार व्यवस्थित करनेका काम जारी रखा। लेकिन यूरोपीय विद्वानोंकी शिकायत है कि प्राचीन भारतके इतिहासमें इतिहास लेखनकी यूरोपीय शैली नहीं मिलती।

ब्रिटेनने भारतका शासन हथिया लिया। शासन चलानेके लिए उन्हें भारतीय इतिहासकी जानकारी की आवश्यकता प्रतीत हुई। १७६५ में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कम्पनीके शासनमें आ गये। अंग्रेज शासकोंके सामने काफी कठिनाइयां आयी। हिन्दुओंके उत्तराधिकारकी न्याय व्यवस्थाके संचालनमें कठिनाई आयी। भारतकी विधि व्यवस्थापर अलग-अलग प्राचीन ग्रंथोंमें सामग्री थी। रामशरण शर्माने बताया है कि १७७६ में सबसे अधिक प्रामाणिक मानी जानेवाली मनु:स्मृतिका अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉजके नामसे किया गया। १७८४ में कोलकातामें ईस्ट इंडिया कम्पनीके सिविल सर्वेंट विलियम जोंस (१७४६-१७९४) ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थाकी स्थापना की। दिलचस्प बात यह है कि जोंसने १७८९ में कालिदासके अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटकका अंग्रेजीमें अनुवाद किया। एक विद्वान विलकिंसने भगवद्गीताका अंग्रेजी अनुवाद किया। एशियाटिक सोसाइटी काफी चर्चामें थी। मुम्बईमें भी एशियाटिक सोसाइटीकी स्थापना हुई और लंदनमें भी। विलियम जोंसने लिखा है कि मूलत: यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओंसे बहुत मिलती हैं। यह बड़ा तथ्य था। उन्होंने संस्कृतकी प्रशंसा की। जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि यूरोपीय देशोंमें भारतीय दर्शनके प्रति विद्वानोंमें आकर्षण बढ़ा। जर्मनीके विद्वान मैक्समूलर (१८२३-१९०२) ने वैदिक साहित्यका अनुवाद किया। अंग्रेज १८५७ के विद्रोहसे परेशान थे। उन्हें अनुमान हो गया कि भारत जैसे विशाल देशपर राज करना आसान नहीं है। भारतीय परम्पराओं और सामाजिक व्यवस्थाका अध्ययन जरूरी था। ईसाई मिशनरी धर्मांतरणके लिए सक्रिय थे। वे भी हिन्दू धर्मकी खामियां बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे थे। ईसाई धर्मांतरणका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यकी मजबूती था। लेकिन भारतीय दर्शनके प्रति पूरे यूरोपमें रुचि बढ़ रही थी। मैक्समूलरके सम्पादनमें प्राचीन भारतीय ग्रंथोंका बड़ी मात्रामें अनुवाद हुआ। यह अनुवाद सैकरेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट सीरीजमें लगभग ५० खण्डोंमें संकलित है। पाश्चात्य विद्वानोंने जानबूझकर निष्कर्ष निकाला कि प्राचीन भारतके लोगोंको इतिहासका विशेषतया काल और तिथि क्रमका बोध नहीं था कि भारतके लोग स्वेच्छाकारी शासनके आदी रहे हैं। वे आध्यात्मिक या पारलौकिक समस्याओंमें ही डूबे रहे। पाश्चात्य विद्वानोंने कहा कि भारतवासियोंको राष्ट्रीय भावनाका अहसास नहीं था। ऐसे सारे निष्कर्षोंके आधारपर विंसेंट स्मिथकी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया चर्चाका विषय रहती है। उनका दावा है यह प्राचीन भारतका पहला सुव्यवस्थित इतिहास है। भारतके विरुद्ध सारे आरोप मिथ्या थे। कालिदासने रघुवंशमें रामके समय के इतिहास-बोधकी चर्चा की है। भवभूति, कालिदास और राजशेखरने रामायणको इतिहास बताया है। बौद्ध जातकोंमें अयोध्याके इक्ष्वाकुवंशीय मांधाता, दशरथ और रामका उल्लेख है। बौद्ध पंथ अंधविश्वासी नहीं है। राम भारतकी श्रुति एवं स्मृति में हैं। कुछेक राजनेता, वामदल और विद्वान रामको इतिहास नहीं मानते। दरअसल भारतने यूरोपीय तर्जपर इतिहास संकलन नहीं किया। अलबरूनीका भी आरोप था, हिन्दू चीजोंके ऐतिहासिक क्रमपर अधिक ध्यान नहीं देते, वे अपने सम्राटोंके काल क्रमानुसार उत्तराधिकारके वर्णनमें लापरवाह हैं। भारतने राजाओंकी विवरणी नहीं बनायी। भारतीय इतिहासकारोंका मुंह भविष्यकी ओर था। उन्होंने इतिहाससे अनुकरणीय पात्र छाटें, उन्हें काव्य और गीत बनाया। लोकस्मृतिने बुद्धिमें सुरक्षित जगह दी और लोकमनने हृदयमें। राजा और राज्य बहुत हुए, लेकिन रामराज्यने गांधीको भी मोहित किया। आधुनिकता अंग्रेजी सभ्यताकी नकल नहीं हो सकती।

सत्यको स्वीकार करें

❑ ओशो

जब कभी तुम आतंकित महसूस करो, बस विश्रांत हो जाओ। इस सत्यको स्वीकार लो कि भय यहां है, लेकिन उसके बारेमें कुछ भी मत करो। उसकी उपेक्षा करो, उसे किसी प्रकारका ध्यान मत दो। भय जड़ें जमानेके लिए शरीरमें एक तरहकी तनाव दशा बना देता है। यदि शरीर विश्रांत है, भय निश्चित ही समाप्त हो जायगा। विश्रांत व्यक्ति भयभीत नहीं हो सकता है। तुम एक विश्रांत व्यक्तिको भयभीत नहीं कर सकते। यदि भय आता भी है, वह लहरकी तरह आता है। वह जड़ें नहीं जमायगा। भय लहरोंकी तरह आता है और जाता है और तुम उससे अछूते बनते रहते हो, यह सुंदर है। जब वह तुम्हारे भीतर जड़ें जमा लेता है और तुम्हारे भीतर विकसित होने लगता है, तब यह रोग बन जाता है। तब वह तुम्हारे अंतसकी बनावटको अपाहिज कर देता है तो जब कभी तुम आतंकित महसूस करो, एक चीज देखनेकी होती है कि शरीर तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। जमीनपर लेट जाओ और विश्रांत होओ, विश्रांत होना भयकी विनाशक औषधि है और वह आयगा और चला जायगा। तुम बस देखते हो। दिन गर्म है, तुम क्या कर सकते हो। शरीरसे पसीना छूट रहा है। तुम्हें इससे गुजरना है। एक बार तुम्हें इसकी कला आ जाती है। यदि तुम विश्रांत होते हो, भय तुम्हें पकड़ नहीं सकता कि यह आता है और जाता है और तुम्हें बिना भयभीत किये छोड़ देता है, तब तुम्हारे पास कुंजी आ जाती है और यह आयगी। यह आयगी, क्योंकि जितने हम बदलते हैं, उतना ही अधिक भय आयगा। हर बदलाव भय पैदा करता है, क्योंकि हर बदलाव तुम्हें अपरिचितमें डाल देता है। यदि कुछ भी नहीं बदलता है और हर चीज स्थिर रहती है, तुम्हारेको कभी भी भय नहीं पकड़ेगा। इसका अर्थ होता है, यदि हर चीज मृत हो, तुम डरोगे नहीं। उदाहरणके लिए तुम नीचे बैठे हो और वहां नीचे चट्टान है तो कोई समस्या नहीं है, तुम चट्टानकी तरफ देखोगे और हर चीज ठीक है। अचानक चट्टान चलने लगे तो तुम भयभीत हो जाते हो। गति भय पैदा करती है और यदि हर चीज अडोल है, वहां कोई भय नहीं है। इसी कारण लोग भयपूर्ण स्थितियोंमें जानेसे डरते हैं। लोग लगभग अपनी कब्रोंमें जीते हैं। जिसे तुम सुविधाजनक और आरामदायक जीवन कहते हो वह और कुछ नहीं बस सूक्ष्म कब्र है। इसलिए जब तुम बदलना शुरू करते हो, जब तुम अपने भीतरकी यात्रा शुरू करते हो, जब तुम अपने अंतसके जगतके अंतरिक्ष यात्री बनते हो और हर चीज इतनी तेज बदल रही है कि हर क्षण भयके साथ कांप रहा है। बदलाव तुम्हें जीवन शक्ति देगा। अधिक जीवंतता, जोश, ऊर्जा देगा। तब तुम कुंडकी तरह नहीं होओगे, सब तरफसे बंद, कोई हलचल नहीं। तुम नदीकी तरह बन जाओगे अज्ञातकी तरफ प्रवाहित, समुद्रकी तरफ जहां नदी विशाल हो जाती है।

समाप्तिकी ओर है इंतजारकी घड़ियां

❑ आर.के.सिन्हा

अधिकतर जानकारोंका यह दावा है कि देशमें फिरसे नरेन्द्र मोदीके नेतृत्वमें ही एनडीए गठबंधनकी सरकार बनने जा रही है। प्रख्यात पॉलिटिकल कमेंटेटर और डेटा साइंटिस्ट सुरजीत भल्ला कह रहे हैं कि भारतके लोगों बीते दस सालोंके दौरान जो तरक्की देशमें देखी है इतनी तरक्की सत्तर सालमें नहीं देखी। भाजपाको इस चुनावमें कुल ४२ से ४५ प्रतिशततक वोट मिल सकते हैं। ज्यादा भी मिल जायें तो कोई आश्चर्य नहीं। जाहिर है यदि भाजपा और उसके मित्र दलोंको इतने फीसदी वोट मिले तो सरकार तो उनकी ही बनेगी। अब बात कर ले अपनेको महान राजनीतिक चिंतक बतानेवाले योगेन्द्र यादव की। वे राहुल गांधीकी एक पदयात्रामें भी शामिल हुए थे। डा. लोहियाके विचारोंको माननेवाले योगेन्द्र यादवके मुताबिक इन चुनावोंमें भाजपाको २४०-२६० और एनडीएके साथी दलोंको ३५-४५ सीटें मिल सकती हैं। मतलब भाजपा-एनडीएको २७५ से ३०५ के बीच सीटें मिलने जा रही हैं। देशमें सरकार बनानेके लिए २७२ सीटें चाहिए और जारी लोकसभा चुनावमें भाजपा-एनडीएकी ३०३-३२३ सीटें हैं। यह तो राहुल समर्थक योगेन्द्र जीकी भविष्यवाणी है। हालांकि मेरा मत है कि एनडीए गठबंधनको योगेन्द्र यादवके दावेसे कहीं अधिक सीटें मिल रही हैं। मैं भी १९६७ से लेकर अबतकके सभी चुनावोंको करीबसे देखता रहा हूं और अपने अनुभवके आधारपर यह कह रहा हूं कि इसबार भाजपा और सहयोगी दलोंका प्रदर्शन अबतकके सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला होगा। मैंने लोकसभा चुनावकी कैंपेनके दौरान सारे देशभरकी खाक छानी है। आम जनतासे बातें की और उनका मन टटोला। उसके बाद मैं या मानता हूं कि एनडीएको हर हालातमें ३५० से अधिक ही सीटें मिलेंगी। इस बीच मुंबईके जाने-माने ज्योतिषी, स्तंभकार और लेखक पंडित जेपी त्रिखा पिछले कमसे कम दो लोकसभा चुनावोंकी सटीक भविष्यवाणी कर चुके हैं। उन्होंने २०१४ और २०१९ में एनडीएकी सफलताकी भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने ज्योतिष विद्याके आधारपर २०२४ के लोकसभा चुनावोंके परिणामोंपर भी गहन शोधके बाद अपनी भविष्यवाणी कर दी है। पंडित त्रिखा कहते हैं, मेरा ज्योतिष अध्ययन स्पष्ट रूपसे कहता है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीके नेतृत्वमें भाजपा २०२४ के लोकसभा चुनावमें सबसे अधिक सीटें जीतनेवाली पार्टी बनने जा रही जा रही है। इस मामलेपर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। इसलिए भारतकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदीको ४ जूनके बाद सरकार बनानेके लिए आमंत्रित करेंगी। पंडित त्रिखाके अनुसार नरेंद्र मोदीकी चंद्र राशि वृश्चिक है। उनका जन्म १७ सितंबर, १९५० को हुआ था। वे मंगल ग्रहसे शासित हैं। वृश्चिक राशिवाले बहुत बुद्धिमान और चतुर होते हैं और उनमें नेतृत्व करनेके गुण होते हैं। वे जन्मजात नेता होते हैं। मोदीने इसे बार-बार साबित किया है। दिलचस्प बात यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी वृश्चिक राशिके हैं। वृश्चिक राशिवाले जुनूनी, दृढ़संकल्पसे भरे और संकटमें भी जुझारू रूपसे मैदानमें डटे रहते हैं। वृश्चिक राशिवाले संकटोंको संभालने और चुनौतियोंको पार करनेमें अच्छे होते हैं। इस बीच चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेसको लेकर दावा कर रहे हैं कि २०२४ के लोकसभा चुनावमें कांग्रेस पार्टी तीन अंकोंके आंकड़ेतक नहीं पहुंचेगी। इसके साथ ही वे इस बातपर भी जोर दे रहे हैं कि भाजपा इस बार २०१९ के आम चुनावोंमें प्राप्त अपनी सीटें दोहराने जा रही है या उससे भी आगे निकल सकती है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें भाजपाकी तरफसे कितनी सीटें जीतनेकी उम्मीद है तो प्रशांत किशोरने कहा कि मेरे पास जो भी अवलोकन और अनुभव है, उसके आधार मुझे नहीं लगता कि भाजपाकी संख्या २०१९ में जहां थी वहांसे कम हो जायगी। वे दावा कर रहे हैं कि २०१९ में भाजपाके पास जो संख्या थी, कमोबेश वही संख्या मुझे दोहराती हुई दिख रही है या शायद यह और भी बेहतर हो जायगी। हालांकि उनके दावोंपर बहुत बवाल भी मचा हुआ है। उनकी रायसे इत्तेफाक न रखनेवाले उनपर तमाम तरहके आरोप भी लगा रहे हैं। परन्तु सुरजीत भल्ला या योगेन्द्र यादवके दावोंपर कोई कुछ नहीं कर रहा। यानी कमोबेश देशको पता चल चुका है कि देशमें अगली सरकार किसकी बनेगी। इस बीचए दिल्लीके मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवालने हालमें राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था, जब उन्होंने दावा किया था कि मोदी ७५ वर्षकी आयुतक पहुंचनेपर प्रधान मंत्री पद छोड़ देंगे। मतलब उन्होंने पूरी तरह यह मान लिया था कि उनका गठबंधन हार रहा है। स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाहने साफ कर दिया है कि मोदी २०२९ के बाद भी प्रधान मंत्री बने रहेंगे। पंडित त्रिखा भी कुछ इसी तरहका दावा करते हैं कि मोदी २०२९ तक प्रधान मंत्री पदपर बने रहेंगे। चुनाव आयोगको सरकार और सियासी दलोंसे मिलकर यह तय करना चाहिए कि आगामी लोकसभा चुनाव मार्चके महीनेतक सम्पन्न हो जायं। बिना किसी ठोस कारणके मतदान न करनेवालोंपर उचित दंड या पांच वर्षोंतक सरकारी सुविधाओंसे वंचित करनेपर भी विचार किया जा सकता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अब रिजल्ट का इन्तजार

आठ राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग के साथ ही 18वीं लोकसभा के लिए चल रही 7 चरणों वाली लंबी मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। इस दौरान चुनाव आयोग को कई तरह की चुनौतियों से दो-चार होना पड़ा। इन अनुभवों से मिले सबक पर गौर करना इसलिए जरूरी है कि आगे के चुनावों की क्वॉलिटी बेहतर की जा सके। ये चुनाव ऐसे समय कराए गए, जब देश का ज्यादातर हिस्सा भीषण गर्मियों की चपेट में रहता है। इस तथ्य को जितनी अहमियत मिलनी चाहिए थी, उतनी न देते हुए आयोग ने छह सप्ताह की अप्रत्याशित रूप से लंबी मतदान प्रक्रिया निर्धारित कर दी। इसके पीछे मकसद निश्चित रूप से मतदान प्रक्रिया को यथासंभव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाए रखना था, लेकिन इस वजह से नेताओं, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में चुनावों को लेकर दिलचस्पी बनाए रखना मुश्किल होता गया। कम मतदान प्रतिशत के पीछे एक वजह यह भी मानी जा रही है। मतदान को इतना लम्बा खींचना किसी भी तरह से उचित नहीं था। वोटरों को वोट देने के लिए बूथ तक जाना होता है और अनुभव बताता है कि यह हमेशा आसान नहीं होता, इसलिए इसका ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जहां तक हो सके, वोटरों के घर से बूथ की दूरी ज्यादा न हो। लेकिन अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में इसका ख्याल नहीं रखा गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि मतदान प्रतिशत कम रहा।

भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में अगर चुनाव विश्वसनीय माने जाते रहे हैं तो इसका श्रेय चुनाव आयोग को ही जाता है। सहज और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है इस प्रक्रिया पर मतदाताओं का विश्वास। इस विश्वास को मजबूती मिलती है आंकड़े समय पर जारी होते रहने से। ध्यान रखना चाहिए कि सूचनाओं का अभाव संदेह को जन्म देता है। मतदाता सूची को अपडेट करना भी एक बड़ी चुनौती रही। आयोग की पूरी कोशिश के बाद भी मतदाता सूची में बहुत गड़बड़ी दिखी।

देखा जाए तो चुनाव आयोग के लिए सबसे मुश्किल होता है विभिन्न पार्टियों के नेताओं से चुनावी आचार संहिता का पालन कराना। अक्सर पार्टियों का नेतृत्व आयोग के नोटिसों को पर्याप्त महत्व नहीं देता। इन नोटिसों और दिशानिर्देशों को अदालतों में चुनौती भी दी जाती है। जो बात चुनाव आयोग के पक्ष में जाती है वह है यह परसेप्शन कि आयोग अपने सख्त रुख पर अडिग रहा और पक्ष-विपक्ष की चिंता किए बगैर आचार संहिता के उल्लंघनों पर त्वरित प्रतिक्रियाएं देता रहा। आयोग को भविष्य में भी इस परसेप्शन का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसके निष्पक्ष रहने जितना ही जरूरी है उसका निष्पक्ष दिखना।

चुनाव, जाति और लोकतंत्र

प्रेमकुमार मणि

1970 के दशक में जब मेरी पीढ़ी युवा थी, तब हमलोग इक्कीसवीं सदी के समाज की कल्पना करते थे. सोचते थे अगली सदी आने तक जातिवाद की संकीर्णताओं से हमारा समाज मुक्त हो चुकेगा. मैंने उसी दौर (1973) में एक छोटी-सी किताब लिखी थी- ₹ मनुस्मृति :एक प्रतिक्रिया₹. लखनऊ के बहुजन कल्याण प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया था. मनु की सामाजिक संहिता की मैंने आलोचना की थी. हालाकि तब मुझे यह एहसास नहीं था कि जातिप्रथा मनु से बहुत पहले की चीज है. मनु ने जातियों को वर्ण के चौखटे में बाँधा था और व्यक्ति से पेशा चुनने की आजादी छीन लेने की व्यवस्था दी थी. प्रतिलोम विवाहों को हतोत्साहित किया था. चांडालों को तमाम नागरिक अधिकारों से वंचित करने का प्रावधान था. इस समाज व्यवस्था को मैंने अलोकतांत्रिक और अमानवीय बताया था. तब से आज पचास साल हो गए. जाने कितने परिवर्तन हुए. उपभोग के जाने कितने सरंजाम विकसित हुए. हम मशीनी युग से इलेक्ट्रोनिक युग में आ गये और अब उस से भी आगे जाने वाले हैं. लेकिन अफसोस, हम जाति का जुआ अपने कांधे से उतार नहीं पाए. यह कमजोर होने के बजाय बढ़ता गया.

आखिर क्या है इस जाति में कि इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है. दुनिया के सभी समाजों में किसी न किसी रूप में श्रेणी विभाजन रहा है. भारतीय संस्कृति में यह कुछ गहरे रूप में है. पेशा छोड़ने और नया पेशा चुनने की आजादी यहाँ नहीं है. एक ही पेशे में बंधे रहने की विवशता से एक ऊब और थकान होने की संभावना होती है,जिससे उत्पादन प्रभावित होता है. इसकी खूबियां भी हैं और खराबियां भी. खराबियां अधिक हैं. इसका एक चरित्र है कि धीरे-धीरे यह संरचना स्पायरोगायरल फॉर्म में आ जाता है. स्पायरोगायरा एक वानस्पतिक सेवार है, जिसकी हर कोशिका स्वतन्त्र अस्तित्व रखती है और फिर उनका एक समुच्चय भी होता है. भारतीय समाज स्पायरोगायरा के चरित्र का ही है. अलग-अलग भी है और फिर एक होने का संघर्ष भी है. प्रायः इस के एक होने के चरित्र पर ध्यान कम दिया गया है. इस के एक होने के चरित्र पर जोर दिया गया तो इस के बेहतर परिणाम आ सकते हैं। लेकिन अभी तो हम चुनाव और राजनीति से इसके सम्बंध को देखना चाहेंगे. लोकतंत्र से जाति की संगत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस के कारण मानवीय मुद्दे ओझल हो जाते हैं और चुनाव राजनीतिक प्रक्रिया की जगह एक संग्राम बन जाता है. कुल मिलाकर इस से राजनीति का अवमूल्यन होता है।

आखिर क्या है इस जाति में कि इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है. दुनिया के सभी समाजों में किसी न किसी रूप में श्रेणी विभाजन रहा है. भारतीय संस्कृति में यह कुछ गहरे रूप में है. पेशा छोड़ने और नया पेशा चुनने की आजादी यहाँ नहीं है. एक ही पेशे में बंधे रहने की विवशता से एक ऊब और थकान होने की संभावना होती है,जिससे उत्पादन प्रभावित होता है. इसकी खूबियां भी हैं और खराबियां भी. खराबियां अधिक हैं. इसका एक चरित्र है कि धीरे-धीरे यह संरचना स्पायरोगायरल फॉर्म में आ जाता है. स्पायरोगायरा एक वानस्पतिक सेवार है, जिसकी हर कोशिका स्वतन्त्र अस्तित्व रखती है और फिर उनका एक समुच्चय भी होता है. भारतीय समाज स्पायरोगायरा के चरित्र का ही है. अलग-अलग भी है और फिर एक होने का संघर्ष भी है. प्रायः इस के एक होने के चरित्र पर ध्यान कम दिया गया है. इस के एक होने के चरित्र पर जोर दिया गया तो इस के बेहतर परिणाम आ सकते हैं.

लेकिन अभी तो हम चुनाव और राजनीति से इसके सम्बंध को देखना चाहेंगे. लोकतंत्र से जाति की संगत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस के कारण मानवीय मुद्दे ओझल हो जाते हैं और चुनाव राजनीतिक प्रक्रिया की जगह एक संग्राम बन जाता है. कुल मिलाकर इस से राजनीति का अवमूल्यन होता है.

इस चुनाव में भी जाति की चर्चा किसी भी एक मुद्दे से अधिक गहरी है. जब भी चुनाव चर्चा होती है, लोग जाति समीकरणों की बात करने लग जाते हैं. अमुक लोक सभा क्षेत्र में अमुक- अमुक जाति के इतने-इतने वोट हैं. अभी हाल में बिहार में जाति गणना हुई है. बावजूद इस के वोट की संख्या इस तरह बतायी जाती है कि उन तमाम वोटों को एक साथ गिन दिया जाय तो उस जाति की संख्या उनकी वास्तविक संख्या से कई गुना अधिक हो जाए.

समाज में जाति है तो उसका प्रभाव पड़ेगा. लेकिन इतना नहीं जितना बताया जाता है. यदि ऐसा होता तो नरेन्द्र मोदी इतने बड़े वोट-आखेटक न होते. उनकी जाति गुजरात के एक हिस्से में है, जो संख्या में नगण्य है. जाने कितने लोगों ने कितनी बार दावा किया कि उनकी जाति पिछड़े वर्ग में नहीं है या गलत रूप से है. लेकिन जनता सुनती कहाँ है. इसी तरह सोनिया जब राजनीति में आईं तब लोगों ने कोहराम किया कि वह विदेशी हैं. जनता ने उन्हें चुन कर ला दिया. और उनके होशियार बेटे ने जैसे ही मंदिर- जनेऊ की शरण ली,जनता ने उनकी औकात बता दी. बिहार में नीतीश या उडीसा में नवीन जाति-गणित से नहीं, राजनीतिक समझदारी और जोड-तोड़ से सत्ता में हैं. गाँधी, नेहरू को लोगों ने जाति के हिसाब से अपना हीरो नहीं बनाया था. इन्दिरा गाँधी ने व्यक्तिगत जीवन में जाति-अवयवों की अवहेलना की. लेकिन देश ने उन्हें नायक बनाया.

बहुत पहले हिन्दी लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने उपन्यास मैला आँचल में हिंदुस्तानी समाज की इस चेतना को ठीक से समझा है. उस उपन्यास में वर्णित गाँव मेरीगंज में बारहों बरन के लोग हैं . जातिवाद भी खूब है. लेकिन जैसे ही गाँव में बाहर से आया अन्जाने कुलशील का डॉक्टर प्रशांत नई बातों की प्रस्तावना करता है पूरा गाँव उसका प्रशंसक बन जाता है. वह नायक बन जाता है.

चुनावों में जाति को बड़ा कारक सिद्ध करने वाले कुछ निहित स्वार्थ वाले लोग होते हैं. पत्रकारों में तो इस बात की होड़ होती है कि कौन कितना जातिभेद का जानकार है. इन्हीं लोगों की शह पर जातिवार दल बन रहे हैं. जनता बार-बार इन्हें नकारती है, लेकिन ये फिर खड़े हो जाते हैं. उदाहरण केलिए बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने जातिवादी दलों से अपने को अलग रखा. उसे इसका फायदा हुआ. लेकिन एक बार फिर उस ने इन्हें प्रश्रय दिया है.

सांप-सीढ़ी का यह खेल अभी कुछ समय तक चलेगा. लेकिन आखिर कब तक, यह कोई नहीं जानता. नई पीढी को यह तय करना होगा कि वह इन जातिवादी अवयवों से कैसे मुकाबला करेगी।

कश्मीर और गुलाम कश्मीर में अंतर क्यों?

बलबीर पुंज

अभी कश्मीर से दो खबरें सामने आई. लोकसभा चुनाव के दौरान श्रीनगर में ढाई दशक में पहली बार सर्वाधिक झ्र 38 प्रतिशत मतदान हुआ है। वहीं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गुलाम कश्मीर में हजारों लोग दो वक्त की रोटी के लिए बंदूक की गोलियों का सामना करने को तैयार हैं और पाकिस्तानी सरकार भी उन्हें आटे के बदले मौत देने में संकोच नहीं कर रही है। दोनों घटनाएं देखने में मामूली लग सकती हैं, परंतु यह अपने भीतर एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश को समेटे हुए हैं। खंडित भारत आज जो कुछ भी है, वह अपनी बहुलतावादी हिन्दू संस्कृति के कारण है। गुलाम कश्मीर की बदहाली और पाकिस्तान के विनाश के लिए उसकी ह्यकाफिर-कुफ्रह्न प्रेरित कट्टरवादी सोच जिम्मेदार है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीओजेके में आटे की आसमान छूती कीमत और बिजली की दरों में वृद्धि के खिलाफ आंदोलित लोगों पर पाकिस्तानी रेंजरों ने गोलियां बरसा दी। बीते नौ माह से वे दमन सहते हुए रह-रहकर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु सरकार की नजरअंदाजी के बाद 10 मई को हिंसक रूप ले लिया. हजारों लोग ह्यआजादी-आजादीह्न के नारे लगाते हुए पाकिस्तानी सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतर आए। इस दौरान मीरपुर-मुजफ्फराबाद आदि क्षेत्रों में आंदोलन को कुचलने हेतु तैनात पाकिस्तानी रेंजरों को स्थानीय लोगों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और उनके वाहनों को फूंक दिया. इस जनाक्रोश को थामने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने 23 अरब पाकिस्तानी रुपये का सब्सिडी पैकेज गुलाम कश्मीर के लिए जारी किया था। चूंकि यह मदद ह्यऊंट के मुंह में जीरेह्न के समान थी, इसलिए इसे आंदोलनकारियों ने अस्वीकार कर दिया।

स्पष्ट है कि गुलाम कश्मीर के लोगों को अब इस्लाम के नाम पर अधिक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता. वे देख रहे हैं कि समय बीतने के साथ उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है। दशकों के शोषण के बाद वहां न तो बिजली-सड़क-पानी की समुचित व्यवस्था है और न ही जिंदा रहने के लिए पर्याप्त अनाज। इसकी तुलना में जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोगों का जीवनस्तर धारा 370-35ए के संवैधानिक क्षरण के बाद निरंतर सुधर रहा है। इसके कारण उनका शासन-प्रशासन पर विश्वास भी बढ़ रहा है। 18वें आम चुनाव के चौथे चरण (13 मई) में श्रीनगर सीट पर 1996 के बाद बिना किसी अप्रिय घटना के पहली बार सर्वाधिक मतदान- इसका प्रमाण है। यह सकारात्मकता घाटी में बहते विकास की बयार की देन भी है। जम्मू-कश्मीर की जीडीपी वर्ष 2018-19 में 1.6 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 2.64 लाख रुपये करोड़ हो गई है। दिसंबर 2023 तक क्षेत्र का जीएसटी राजस्व 6018 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि से 10.6 प्रतिशत अधिक है। जम्मू-कश्मीर की नई औद्योगिक नीति (2019) के अंतर्गत, देश-विदेश से 90 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं, जिसे जमीनी स्तर में उतारने हेतु दशकों से लंबित आधारभूत सुधारों के साथ 46 नए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण और अन्य अवरोधकों को दूर किया जा रहा है। पर्यटन, जम्मू-कश्मीर जीडीपी का प्रमुख आधार है. वर्ष 2023 में यहां दो करोड़ों से अधिक पर्यटक (विदेशी सहित) आए थे, जिसके इस वर्ष और अधिक बढ़ने की संभावना है। देर रात तक लोग प्रसिद्ध शिकारा की सवारी का आनंद ले रहे हैं। घाटी में रात्रि बस सेवा बहाल की गई है, तो स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालय भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। दुकानें भी लंबे समय तक खुली रहती हैं। तीन दशक से अधिक के अंतराल के बाद नए-पुराने सिनेमाघर भी सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। इस परिवर्तन में प्रधानमंत्री के साथ इस केंद्र शासित प्रदेश के उप-राज्यपाल ने भी प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया है। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार है, जब जम्मू-कश्मीर प्रशासन का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त है। स्वाभाविक है कि इससे स्थानीय कश्मीरी संतुष्ट है।

यह सब इसलिए संभव हुआ, क्योंकि भारत वर्ष 2014 से आमूलचूल परिवर्तन का साक्षी बन रहा है. कई प्रकार के वैश्विक उथलपुथल के होते हुए भी भारत- दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, लद्दाख से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत, पिछले 10 वर्षों में लगभग 90 करोड़ लाभार्थियों को बिना किसी जाति, पंथ, मजहबी और राजनीतिक भेदभाव के 34 लाख करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से वितरित कर चुकी है। परंतु कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरी है। जब तक यहां मूल संस्कृति के ध्वजावाहक लौटते नहीं, तब तक घाटी सूनी है।

गुलाम कश्मीर की दयनीय स्थिति, पाकिस्तान की बदहाली का प्रतिबिंब मात्र है। सामान्य पाकिस्तानी बीते कई वर्षों से कमरतोड़ महंगाई और लकवाग्रस्त आर्थिकी नीतियों से जूझ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 3 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की स्वीकृति देते समय जो कड़ी शर्तें लगाई थीं, उसके कारण वहां पहले व्याप्त नकदी संकट, भारी-भरकम कर्ज और मुद्रा-स्फीति में अत्याधिक वृद्धि हो गई है। एक समय पाकिस्तान में महंगाई दर 38 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। वहां स्थिति कितनी विकराल है, यह दर्जनभर अंडों के दाम 400 रु, 600 रु/किलो चिकन, दूध 200 रु/लीटर, चावल 300 रु/किलो, टमाटर 200/किलो और प्याज 250 रु/किलो की दर से स्पष्ट है।

वर्ष 2022 से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध से वैश्विक खाद्य और ईंधन की कीमतें बढ़ने के बाद पाकिस्तानी विदेशी मुद्रा भंडार में अत्याधिक दबाव में है। इसी तरह का वित्तीय असंतुलन श्रीलंका को कंगाल कर चुका है। अब अधिक राजस्व पाने हेतु पाकिस्तानी सरकार ने अपने नागरिकों पर कर का भारी बोझ डाल दिया है। जब भीषण महंगाई के कारण लोग टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो पाकिस्तानी सरकार दूरसंचार कंपनियों के साथ मिलकर टैक्स न जमा करने वाले उपभोक्ताओं के मोबाइल बैलेंस से पैसे काटकर सरकारी खजाना भर रही है। व्यापक रूप से विदेशी सहायता पर निर्भर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में उसका निजी क्षेत्र आज भी अविकसित है। उसका शेयर बाजार वर्षों से मृत-प्राय है। आईएमएफ के अनुसार, पाकिस्तान को अगले पांच वर्षों में 123 अरब डॉलर के सकल वित्तपोषण की आवश्यकता है। पीओजेके इसलिए भी अधिक झुलस रहा है, क्योंकि फरवरी 2019 में पाकिस्तान समर्थित पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा सूखे खजूर, सेंधा नमक, सीमेंट और जिप्सम जैसे पाकिस्तानी उत्पादों पर सीमा शुल्क 200 प्रतिशत करने से पीओजेके में व्यापारियों को भारी क्षति पहुंची है।

पाकिस्तान की तुलना हम उस घर के मालिक से कर सकते है, जो अपने पड़ोसी के प्रति वैमनस्य और घृणा से लबालब भरा है। वह मूर्ख मालिक अपने घर को यह सोचकर आग के हवाले कर देता है कि इसके धुंए से उसका पड़ोसी भी परेशान होगा। प्रगति से ध्यान हटाकर स्वयं को इस्लामी आतंकवाद की पौधशाला बनाना और उसी में पनपे जिहादियों द्वारा अपने ही हजारों-लाख सह बंधुओं को मौत के घाट उतारना- इसका प्रमाण है। अब जो पाकिस्तान अपनी कु-नीतियों के कारण पहले ही दिवालिया होने की चौखट पर खड़ा है, वह कैसे अपने कब्जे वाले कश्मीर का भला कर सकता है?

स्पष्ट है कि गुलाम कश्मीर के लोगों को अब इस्लाम के नाम पर अधिक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता. वे देख रहे हैं कि समय बीतने के साथ उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है। दशकों के शोषण के बाद वहां न तो बिजली-सड़क-पानी की समुचित व्यवस्था है और न ही जिंदा रहने के लिए पर्यात्त अनाज। इसकी तुलना में जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोगों का जीवनस्तर धारा 370-35ए के संवैधानिक क्षरण के बाद निरंतर सुधर रहा है। इसके कारण उनका शासन-प्रशासन पर विश्वास भी बढ़ रहा है। 18वें आम चुनाव के चौथे चरण (13 मई) में श्रीनगर सीट पर 1996 के बाद बिना किसी अप्रिय घटना के पहली बार सर्वाधिक मतदान- इसका प्रमाण है। यह सकारात्मकता घाटी में बहते विकास की बयार की देन भी है। जम्मू-कश्मीर की जीडीपी वर्ष 2018-19 में 1.6 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 2.64 लाख रुपये करोड़ हो गई है। दिसंबर 2023 तक क्षेत्र का जीएसटी राजस्व 6018 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि से 10.6 प्रतिशत अधिक है। जम्मू-कश्मीर की नई औद्योगिक नीति (2019) के अंतर्गत, देश-विदेश से 90 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं, जिसे जमीनी स्तर में उतारने हेतु दशकों से लंबित आधारभूत सुधारों के साथ 46 नए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण और अन्य अवरोधकों को दूर किया जा रहा है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

अब नतीजों का इंतजार

रुपेश कुमार सिंह
संपादक
चौथी वाणी

भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में अगर चुनाव विश्वसनीय माने जाते रहे हैं तो इसका श्रेय चुनाव आयोग को ही जाता है। सहज और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है इस प्रक्रिया पर मतदाताओं का विश्वास। आठ राज्यों की 57 सीटों पर आज होने वाली वोटिंग के साथ ही 18वीं लोकसभा के लिए चल रही 7 चरणों वाली लंबी मतदान प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इस दौरान चुनाव आयोग को कई तरह की चुनौतियों से दो-चार होना पड़ा। इन अनुभवों से मिले सबक पर गौर करना इसलिए जरूरी है कि आगे के चुनावों की क्वॉलिटी बेहतर की जा सके।

मौसम की प्रतिकूलता : ये चुनाव ऐसे समय कराए गए, जब देश का ज्यादातर हिस्सा भीषण गर्मियों की चपेट में रहता है। इस तथ्य को जितनी अहमियत मिलनी चाहिए थी, उतनी न देते हुए आयोग ने छह सप्ताह की अप्रत्याशित रूप से लंबी मतदान प्रक्रिया निर्धारित कर दी। इसके पीछे मकसद निश्चित रूप से मतदान प्रक्रिया को यथासंभव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाए रखना था, लेकिन इस वजह से नेताओं, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में चुनावों को लेकर दिलचस्पी बनाए रखना मुश्किल होता गया। कम मतदान प्रतिशत के पीछे एक वजह यह भी मानी जा रही है।

बूथों की तादाद: चूंकि ज्यादातर वोटरों को वोट देने के लिए बूथ तक जाना होता है और अनुभव बताता है कि यह हमेशा आसान नहीं होता, इसलिए इसका ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जहां तक हो सके, वोटरों के घर से बूथ की दूरी ज्यादा न हो। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ही बात की जाए तो यहां की सातों संसदीय सीटों में बूथों की संख्या 2019 के मुकाबले कम रखी गई थी। वह भी तब, जबकि मतदाताओं की संख्या में 9 लाख का इजाफा हो चुका था। जाहिर है, ऐसे में खास तौर पर बुजुर्ग मतदाताओं के लिए वोट देने जाना थोड़ा और मुश्किल हुआ।

आंकड़ों की उपलब्धता : भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में अगर चुनाव विश्वसनीय माने जाते रहे हैं तो इसका श्रेय चुनाव आयोग को ही जाता है। सहज और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है इस प्रक्रिया पर मतदाताओं का विश्वास। इस विश्वास को मजबूती मिलती है आंकड़े समय पर जारी होते रहने से। ध्यान रखना चाहिए कि सूचनाओं का अभाव संदेह को जन्म देता है।

नेताओं पर अंकुश : देखा जाए तो चुनाव आयोग के लिए सबसे मुश्किल होता है विभिन्न पार्टियों के नेताओं से चुनावी आचार संहिता का पालन कराना। अक्सर पार्टियों का नेतृत्व आयोग के नोटिसों को पर्याप्त महत्व नहीं देता। इन नोटिसों और दिशानिर्देशों को अदालतों में चुनौती भी दी जाती है। जो बात चुनाव आयोग के पक्ष में जाती है वह है यह परसेप्शन कि आयोग अपने सख्त रुख पर अडिग रहा और पक्ष-विपक्ष की चिंता किए बगैर आचार संहिता के उल्लंघनों पर त्वरित प्रतिक्रियाएं देता रहा। आयोग को भविष्य में भी इस परसेप्शन का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसके निष्पक्ष रहने जितना ही जरूरी है उसका निष्पक्ष दिखना।

रिश्तों की दरकती बुनियाद

विजय गर्ग

परिवार को समाज की नींव का पत्थर कहा जाता है। पर अब कुछ समाजशास्त्रियों ने पारिवारिक जीवन और परिवार के महत्त्व को लेकर सवालिया निशान लगाए हैं। परिवार में जहां एक तरफ सदस्यों को प्रतिबद्धता के मूल्य सिखाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में प्रविष्ट करा कर व्यक्तिवादिता के मूल्यों से परिचित कराया जाता है, ताकि वे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र और स्वावलंबी बन सकें। परिवार में कुछ और परिवर्तन प्रौद्योगिकी विकास और अन्य विकास प्रक्रियाओं के कारण उभरने लगे हैं। उदारवादी दौर में गतिशीलता बढ़ने से अनेक बार परिवार करिअर में बाधक नजर आता है, क्योंकि संबंधों में उदारता उभरा है। संतानोत्पत्ति को स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में बाधक माना जाने लगा है। परिवार में निजता का दायरा भी बदल गया है। अब निजता में हम केवल उन्हें शामिल करते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं और जिन्हें हम परिवार में नहीं चाहते हैं उनके साथ तनावपूर्ण संबंध होते हैं। यानी पति या पत्नी के माता- -पिता और भाई बहन भी इस निजता के दायरे में शामिल नहीं होते। तेजी से उभरते भौतिकतावाद ने परंपरागत परिवार संरचना के सामने अनेक संकट उत्पन्न कर दिए हैं।

तलाक दर में वृद्धि, विवाह के पूर्व सहजीवन, एकल अभिभावक परिवार और एकल व्यक्ति गृहस्थी वे प्रवृत्तियां हैं, जो परंपरागत परिवारों के सम्मुख अनेक सवाल पैदा करती हैं। समाज वैज्ञानिकों का मत है कि यह परिवर्तन आधुनिक समाजों में व्यक्तिवाद के बढ़ते प्रभाव को बताते हैं। यह व्यक्तिवादिता परंपरागत परिवार को अस्थिर बना देती है। कुछ विचारकों का यह भी मानना है कि समाज में हो रहे परिवर्तनों ने अस्थिरता और असुरक्षा को व्यवस्था का हिस्सा बना दिया है, जिसकी अभिव्यक्ति परिवार में अस्थिरता के रूप में होती है। पूर्व के समाजों में परिवार विस्तृत नातेदारी का एक हिस्सा था, जबकि आधुनिक समाज में परिवार नातेदारों और संबद्ध समुदाय से कमोबेश कट से गए, जिसके फलस्वरूप भावनात्मक दबाव परिवार का एक आवश्यक, पर नकारात्मक अवयव बनकर उभरा है। हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में घटित कुछ घटनाओं के आधार पर इन विभिन्न पक्षों को समझा जा सकता है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक महिला ने अपनी तीन साल की बेटी की हत्या कर दी। पति-पत्नी में किसी बात पर झगड़ा हुआ था, इस बीच उनकी बच्ची रोने लगी, तो गुस्से में पत्नी ने बच्ची को एक पेड़ के नीचे ले जाकर उसका गला घोंट दिया। इसी तरह बंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ ने गोवा के एक होटल में अपने चार साल के बेटे की हत्या कर दी थी। पति से तलाक के बाद वह नहीं चाहती थी कि उसका पति बेटे से मिले। एक और घटना राजस्थान के बारां जिले की है, जिसमें बेटे ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने बुजुर्ग माता-पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के बड़ौत में एक बेटे ने संपत्ति से बेदखल किए जाने के बाद गुस्से में अपने पिता और दो सगी बहनों को मौत के घाट उतार दिया। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि भोगवादी संस्कृति के प्रसार ने लोगों को इतना व्यक्तिवादी और स्वार्थ केंद्रित बना दिया है कि अपने छोटे से लाभ के लिए जीवनसाथी, अपने बच्चों या माता-पिता की हत्या करने तक से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। किसी की हत्या करना और खासकर किसी अपने की हत्या करना मानो एक खेल सा हो गया है। और ऐसा तभी संभव है, जब रिश्तों में भावनाएं, प्यार, लगाव समाप्त हो जाएं। या यों कहें कि आजकल के संबंधों में अपनत्व और प्रेम का स्थान पैसे ने ले लिया है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आधे रिश्ते तो लोग इसीलिए निभा रहे हैं कि उनसे कभी न कभी काम पड़ सकता है। कहा जाता था कि दुनिया में भाई- ई-बहन का रिश्ता सबसे निकट का और सबसे ज्यादा प्यार भरा होता है, लेकिन अब यह रिश्ता भी संपत्ति और उपहारों की भेंट चढ़ गया है। जिस दिन बहन ने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा मांगा उसी दिन से वह सबसे बड़ी शत्रु दिखाई देने लगती है। बहन का घर आना भी खलने लगता है, जबकि शादी से पहले यही बहन उसकी सबसे प्रिय सखी और हमदर्द हुआ करती थी। यह कैसा विकास है, जहां मशीनें 'स्मार्ट' बनने लगीं हैं और इंसान अपनी 'स्मार्टनेस' खोते जा रहे हैं। अपना अधिकांश समय 'स्मार्ट गजेट्स' के साथ बिताने के कारण लोगों में अपने परिवार और मित्रों के साथ संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी रिश्ते या संबंध में संवाद होना महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचना क्रांति के इस दौर में 'स्मार्ट फोन' ने रिश्तों की गर्माहट को ही खत्म कर दिया है। पहले हर रिश्ते हर दोस्त में अलग भावनात्मक लगाव हुआ करता था और उनकी अभिव्यक्ति भी भिन्न-भिन्न होती थी, लेकिन 'स्मार्ट फोन' के जमाने में एक ही संदेश हर किसी को भेज दिया जाता है। जब तक किसी से काम न पड़े, तब तक उससे संपर्क भी करने की जरूरत अनुभव नहीं की जाती। आज लोगों के जीवन में धन-संपत्ति इतनी महत्त्वपूर्ण हो गई है कि अपने ही खून के रिश्तों का कत्ल करने से भी वे नहीं चूकते । विवाह संस्था में विश्वास की समाप्ति, परिवारों में विघटन, भौतिक वस्तुओं को अधिक से अधिक पाने की लालसा, स्वयं को श्रेष्ठ और अन्यों को हीन मानने की प्रवृत्ति ने लोगों को अवसाद और निराशा के गर्त में धकेल दिया है। इसके अलावा जबसे हर चीज का बाजारीकरण हो गया है, तबसे रिश्तों का महत्त्व और भी कमजोर हुआ है। आधुनिक विकसित तकनीक के माध्यम से बच्चे पैदा हो जाना, उनका पालन- पोषण करने के लिए अनेक सार्वजनिक संस्थानों की मौजूदगी, जिससे मां का स्थान 'स्मार्ट मशीन' लेने लगी है। घर और दफ्तर के हर काम के लिए रोबोट के इस्तेमाल ने रिश्तों को बाजार की वस्तु बना दिया है। ऐसे में जब मानव जीवन के अस्तित्व की निरंतरता ही खतरे में हो, तो रिश्तों की समाप्ति का संकट हैरानी की बात नहीं।

कविता

बचपन की साइकिल

वो बचपन की साइकिल
इक पैडल मार कर
कहां से कहां पहुंच जाया करते थे
हवाओं के संग खूब सारी
बातें किया करते थे
खुली सांस भरकर
जिंदगी जिया करते थे।

वक्त बदला उम्र बदली
नए दौर में आ गए
अपने स्टेटस को अपडेट करके
दो पहिए से चार पहियों पर आ गए।

सोचा बहुत कुछ हासिल होगा
पर प्रदूषण इतना बढ़ा कि
बस उसमें उलझ कर रह गए
आधुनिकता के प्रवाह में बह गए।

साइकिल पर लगी हुई चेन
महत्व चैन का बता रही
छूट गए वो मस्ती के पल
फिर से याद दिला रही।

हां माना साइकिल से शुरू हुई जिंदगी
और चांद पर पहुंच गई है
शायद पाया तो बहुत होगा
पर उससे अधिक खो गई है।

"साइकिल चलाओ
अपनी सेहत बनाओ।"

मधु भृतहा 'अक्षरा'
गुलाबी नगरी जयपुर

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप 34 मामलों में दोषी करार - सजा का ऐलान 11 जुलाई 2024 को होगा

अमेरिकी संविधान के अनुसार सजा के बाद भी चुनाव लड़ सकते हैं-पात्रता 35 वर्ष व अमेरिकी नागरिक होना जरूरी, मीडिया में जानकारी आई : एडवोकेट किशन भावनानी

अमेरिका के इतिहास में पहली बार पूर्व राष्ट्रपति अपराधिक मामलों में दोषी करार

लेखक
किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियां में जहां लोकतंत्र के सबसे बड़े देश भारत में 19 मई से 1 जून 2024 तक दुनियां का सबसे बड़ा चुनावी महापर्व चला, वहीं लोकतंत्र के सबसे पुराने देश अमेरिका के इतिहास में पहली बार दिनांक 31मई 2024 को किसी पूर्व राष्ट्रपति को 34 मामलों में दोषी पाया गया,तो वहीं दूसरी तरफ हांगकांग में भी वहां की संसदद्वारा बनाए गए नए कानून के तहत लोकतंत्र के समर्थक 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, परंतु भारत में मंगलवार दिनांक 4 जून 2024 को लोकतंत्रके हीरो यानें संसद कौन बनते हैं, किसकी सरकार बनती है यह निश्चित हो जाएगा। जबकि अमेरिका में आगामी 5 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं,जिसमें अनेकों उम्मीदवारों के नाम थे लेकिन अब मुख्य मुकाबले की दौड़ में दो व्यक्तियों के होने का अनुमान है परंतु 31 मई 2024 को आई खबर ने पूरे विश्व की नजरें अमेरिका की ओर घुमा दी है क्योंकि राष्ट्रपति पद के प्रबल उम्मीदवार पर न्यूयॉर्क कोर्ट ने 34 आरोपों में दोषी करार दिया गया है, जिसपर 11 जुलाई 2024 को सजा का ऐलान किया जाएगा, जो 4 वर्ष तक कैद या जुमार्ना या दोनों हो सकते हैं। परंतु सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अमेरिकी संविधान में कोई भी किसी भी आरोप का दोषी चुनाव लड़ सकता है जो जेल में ही क्यों ना हो,जीत सकता है, सरकार भी बन सकता है और जेल से सरकार भी चला सकता है, जो उसके पावर से बाहर रहकर उपराष्ट्रपति वह अन्य पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर चला सकते हैं। परंतु इससे अमेरिका में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने का अंदेशा जताया जा रहा है, जो चिंतनीय है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ने इसका विरोध ऊपरी कोर्ट में अपील करने की बात कही है, वही फैसला देने वाले जजों पर भी उंगली उठा दी है। बता दें कि राष्ट्रपति का नॉमिनेशन फॉर्म 5 जुलाई 2024 को भरा जा सकता है, जबकि सजा का ऐलान 11 जुलाई को होगा। चूंकि अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को अपराधों में दोषी साबित किया गया है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप 34 मामलों में दोषी करार, सजा का ऐलान 11 जुलाई 2024 को होगा। साथियों बात अगर हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को दिनांक 31 मई 2024 को न्यूयॉर्क की कोर्ट द्वारा दोषी करार देने की करें तो,अमेरिका के लिए 31 मई 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है लेकिन ये पन्ना अमेरिका के काले सच को बयां कर रहा है। क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को पोर्न स्टार केस में दोषी करार दिया गया है। 11 जुलाई को न्यूयॉर्क कोर्ट उन्हें इस मामले में अब सजा सुनाएगा। वे किसी मामले में दोषी पाए जाने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपती भी बन गए हैं। हालांकि अमेरिका के कई राष्ट्रपति कई आरोपों से घिरे रहे लेकिन अभी तक अमेरिका का इन राष्ट्रपतियों पर दोष सिद्ध नहीं हो पाया। लेकिन पोर्न स्टार वाले मामले में अब ऐसा हो चुका है। न्यूयॉर्क कोर्ट की ज्यूरी ने पोर्न स्टार को चुप कराने के लिए किए गए भुगतान को छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के सभी 34 मामलों में दोषी पायाहै उनको फिलहाल बिना जमानत के रिहा किया गया है। ये केस अब अमेरिका का ऐसा पहला मामला बन गया है जिसमें अपराधी कोई और नहीं बल्कि अमेरिका समेत पूरी दुनियां का सबसे ताकतवर पद पर रहा शख्स यानी अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति है।(1) उनपर बिजनेस रिकॉर्ड में हेरफेर का आरोप लगा है। गलत बिजनेस रिकॉर्ड दिखाने के मामले में 34 चार्ज लगाए गए हैं। ये सभी चार्ज 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले पोर्न स्टार को चुप रहने के लिए 1 लाख 30 हजार डॉलर करीब 1 करोड़ 70 लाख की राशि दी गई है।(2) उनपर लगाए गए 11 आरोप चेक साइन करने से जुड़े हैं। वहीं 11 मामले ट्रंप के पूर्व निजी वकील की लीगल कंपनी में जमा किए गए गलत इनवॉइस के हैं।(3)- इसके अलावा 12 मामले उनके रिकॉर्ड्स में गलत जानकारी को लेकर लगाए हैं।बता दें कि कोर्ट उनको 11 जुलाई कोफैसला सुनाएगा। जो कि अमेरिका के चुनाव के लिहाज से अहम है क्योंकि 11 जुलाई के कुछ दिन बाद ही मिल्वौकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन होना है। जिसमें उनके उनके समर्थन में ग्रांड ओल्ड पार्टी के नेता उन्हें अपना औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित करते। उनको गुप्त धन मामले से जुड़े सभी 34 मामलों में दोषी पाया गया है। इसी के साथ वे अमेरिका के इतिहास के पहले पूर्व राष्ट्रपति बने हैं, जिन्हें घोर अपराध का दोषी करार दिया गया है। उनपर 2016 में व्हाइट हाउस में आने से पहले पूर्व पोर्न स्टार के साथ अपने यौन संबंधों को छिपाने के लिए व्यापारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप है। इस मामले में 34 आरोप, 11 चालान,12 वाउचर और 11 चेक पेश किए गए। मैनहट्टन के 12 जूरी सदस्यों ने गुरुवार को कहा कि वे ट्रंप ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के लिए एडल्ट स्टारको 130 हजार अमेरिकी डॉलर का गुप्त भुगतान किया। इसे छुपाने के लिए उन्होने व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी की। जूरी ने कहा कि उनको राष्ट्रपति चुने जाने से नहीं रोका जा सकता और अब यह 5 नवंबर को मतदाताओं पर ही निर्भर करेगा। जूरी ने 22 गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला सुनाया, जिनमें एडल्ट स्टार भी शामिल थीं। साथियों बात अगर हम न्यूयॉर्क कोर्ट के फैसले पर पूर्व राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया की करें तो, सजा पर सुनवाई के लिए 11 जुलाई को सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया है। खास बात यह है कि 11 जुलाई से ठीक चार दिन पहले मिल्वौकी मेंरिपब्लिकन पार्टी की बैठक होगी, जहां ट्रंप को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना है। जिस समय यह फैसला सुनाया गया, उस समय ट्रंप शांत रहे लेकिन, कोर्ट से बाहर निकलकर उन्होंने इस फैसले को शर्मनाकबताया।जूरीके फैसलेपर कहाकियह अपमानजनक था। उन्होंने कहा कि यह एक विवादित और भ्रष्ट न्यायाधीश द्वारा किया गया मुकदमा था।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा 5 नवंबर को असली फैसला जनता की अदालत में होगा। जनता जानती है कि असली सच क्या है। हम जानते हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूं, मैं अपने देश के संविधान के लिए लड़ रहा हूं। इस समय हमारे देश में धांधली हो रही है।उन्होने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति बाइडन ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाने के लिए जान-बूझकर ऐसा किया हैउन्होने ज्यूरी में शामिल जज पर एक और गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने कहा था कि वे नहीं चाहते कि उनके खिलाफ लगाए गए फर्जी आरोपों पर एक मत से फैसला हो।पूर्व राष्ट्रपति ने जज के व्यवहार को बेकार, असंवैधानिक और अमेरिका विरोधी करार दिया। वहीं, जज ने असल में ज्यूरी के सभी सदस्यों से कहा था कि सभी 34 मामलों में फैसला एकमत से लिया जाना चाहिए। न्यूयॉर्क इलेक्शन लॉ का मसला उठने के बाद जज ने कहा था कि ज्यूरी के अन्य सदस्यों को ट्रंप द्वारा अपनाए गए गैरकानूनी तरीकों पर फैसला लेने में एक राय होने की जरूरत नहीं है। साथियों बात अगर हम इस मामले पर वर्तमान राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया की करें तो, उनकी तरफ से आई प्रतिक्रियाहालांकि ट्रंप अभी भी चुनाव लड़ने के योग्य हैं और वो चुनाव लड़ सकते हैं। बाइडेन के चुनाव अभियान ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता। उन्होने हमारे लोकतंत्र के लिए जोखतरा पैदा किया है, वो पहले कभी इतना बड़ा नहीं था।उधर बाइडन हैरिस अभियान ने जूरी के फैसले का स्वागत किया है। बिडेन-हैरिस 2024 के संचार निदेशक ने कहा कि अमेरिका में कानून से ऊपर नहीं है। आगे कहा कि ट्रम्प ने हमेशा इस बात पर भरोसा किया कि कानून तोड़ने पर उन्हें परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा लेकिन, इसके ठीक उलट हुआ है। साथियों बात अगर हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस की करें तो, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति खुद को फिर से व्हाइट हाउस में देखना चाहते हैं इसके लिए वो 5 नवंबर को होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की जी तोड़ तैयारी कर रहे हैं। प्राइमरी इलेक्शन में उन्होंने बंपर जीत हासिल की है। हालांकि अब जब उन्हें दोषी करार दिया गया और सजा भी सुनाई जानी है तो भी उनके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार का नियम भारत की तरह सख्त नहीं है। यहां पर नियमों के मुताबिक उम्मीदवार(1) संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मा व्यक्ति है (2) अमेरिका की ही नागरिकता हो (3) कम से कम 35 वर्ष का हो (4) 14 सालों से संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हो,यानी वे अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं और वो सजा काटने के दौरान भी चुनाव लड़सकते हैं और अगर जीत जाते हैं तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। हालांकि, उनके वकीलों नेट्रायल को गलत बताया है और कहा है कि वो इसके खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे। मीडिया मुताबिक उनको जेल हो सकती है। वहीं, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्हें जुमार्ना भरवाकर छोड़ा जा सकता है। न्यूयॉर्क शहर का प्रोबेशन डिपार्टमेंट ट्रम्प का इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू के दौरान दोषी पाया गया शख्स अपनी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करता है। ये दलील देता है कि उसे क्यों कम से कम सजा मिलनी चाहिए।

एग्जिट पोल के नतीजों का जनता को ही नहीं शेयर बाजार को भी रहता है इंतजार

लोकसभा चुनाव 2024 के तहत सातवां और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को समाप्त हो गया जिसमे 8 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश चंड़ीगढ़ सहित 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो गया , जिसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे।लेकिन इससे पहले अंतिम चरण की वोटिंग के बाद सभी का नजरें एग्जिट पोल पर ही रही , जो चुनावों के बाद संभावित सरकार की भविष्यवाणी करते हैं। क्योकि चुनाव और उसके नतीजे शेयर बाजार पर किस तरह का असर डालते हैं, वो हम पहले भी काफी देख चुके हैं। फिर चाहे वो साल 2019 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर पिछले साल पांच विधानसभा चुनाव के नतीजे हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एग्जिट पोल शेयर बाजार पर असर डालते हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें फेज का मतदान खत्म होने के बाद टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स पर तमाम एग्जिट पोल्स के आंकड़ें रेंगने शुरू हो गए । इन आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि 4 जून के नतीजे किस तरह के देखने को मिल सकते हैं। चुनाव परिणाम के दिन तो शेयर बाजार रिएक्ट करेगा ही, लेकिन उससे पहले 3 जून यानी सोमवार को शेयर बाजार पर इन एग्जिट पोल का कुछ असर देखने को मिलेगा? अगर साल 2004 के लोकसभा चुनाव से लेकर साल 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो और एग्जिट पोल के आंकड़ें आने के बाद शेयर बाजार पर असर साफ दिखाई देता है। यदि हम सिलसिलेवार बीते चार लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार के आंकड़ों को देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर इन अनुमानित आंकड़ों का कितना असर देखने को मिला है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव का आखिरी फेज 10 मई को हुआ था। उसके बाद करीब 5 एग्जिट पोल सामने आए थे। इनमें से 3 पोल्स ने जो संकेत दिए गए थे, वो हंग पार्लियामेंट के थे। इसका मतलब था कि किसी भी गठबंधन को फुल मैज्योरिटी नहीं मिल रही। सिर्फ दो ही ऐसे सर्वे थे जो एनडीए को फुल मैज्योरिटी दिखा रहे थे। उसके बाद जब 11 मई को शेयर बाजार ओपन हुआ तो सेंसेक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 10 मई को जब शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 5,555.84 अंकों पर बंद हुआ था। 11 मई को ये आंकड़ा 5,325।90 अंकों पर आ गया। यानी सेंसेक्स में 229.94 अंकों की गिरावट देखी गई थी। इसका मतलब है कि निवेशकों को 4.14 फीसदी का नुकसान हुआ था। साल 2009 के लोकसभा चुनाव का आखिरी फेज 13 मई को था और शाम को एग्जिट पोल आए थे। उसमें कुछ पोल यूपीए को 190 से 200 सीट मिलने का अनुमान लगा रहे थे। तो एनडीए को 180 से 195 सीटें मिलने का अनुमान लगा गया था। मतलब साफ था कि लगातार दूसरी बार एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव के परिणाम का अनुमान हंग पार्लियामेंट लगा रहे थे। लेकिन इसका असर शेयर बाजार पर वैसा नहीं देखा गया जैसा कि साल 2004 में देखने को मिला था। अगर बात सेंसेक्स की करें तो 13 मई 2009 में 12,019.65 अंकों पर बंद हुआ। जबकि उसके बाद सेंसेक्स 11,872.91 अंकों पर आ गया। इसका मतलब है कि सेंसेक्स 1.22 फीसदी यानी 146.74 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज हुआ था। जबकि निफ्टी 3,635.25 अंकों से गिरकर 3,593.45 अंकों पर आ गया था। यानी निफ्टी एग्जिट पोल के असर से 1.15 फीसदी यानी 41.8 अंक टूटा था। साल 2004 और 2009 के विपरीत इस बार एग्जिट पोल्स ने पहली बार फुल मैज्योरिटी के संकेत दिए। साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार केंद्र की राजनीति में देखे गए। 12 मई को आखिरी फेज के मतदान हुए थे। उसके बाद जो एग्जिट पोल के आंकड़ें आए उससे किसी को कोई हैरानी नहीं हुई। कोई ऐसा एग्जिट पोल नहीं था जो एनडीए को फुल मैज्योरिटी देता हुआ ना दिखाई दिया हो। सभी ने एनडीए को 272 से लेकर 340 तक सीटें दीं। वहीं यूपीए का एग्जिट पोल में आंकड़ा 150 सीटें भी देता हुआ दिखाई नहीं दिया। कुछेक ने तो यूपीए को 100 से नीचे भी उतार दिया। एग्जिट पोल के आंकड़ें एक्सपेक्टिड थे। इसलिए इन आंकड़ों को शेयर बाजार पहले ही डाइजस्ट कर चुका था। ऐसे में एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में कुछ ज्यादा हरकत देखने को नहीं मिली। 12 मई को सेंसेक्स 23,551 अंकों पर बंद हुआ। उसके बाद 13 मई को सेंसेक्स में 1.36 फीसदी यानी 320.23 अंकों की तेजी देखने को मिली। वहीं निफ्टी 7,014.25 अंकों से 7,108.75 अंकों पर आ गया। यानी निफ्टी 1.35 फीसदी यानी 94।5 अंक बढ़त के साथ दिखाई दिया।

लेखक
अशोक भाटिया
वसई पूर्व, मुंबई

ये हैं फटाफट, ठकाठक, गटागट का दौर!

सुनील कुमार महला

आज का जमाना फटाफट का जमाना है। या यूं भी कह सकते हैं कि अब ठकाठक,गटागट का जमाना है। यहां देरी करने वालों को कोई स्थान नहीं है। बेरोजगारी दूर करनी है तो फटाफट कीजिए। महंगाई दूर करनी है तो फटाफट कीजिए। काम कोई भी हो, ठकाठक ,फटाफट होना ही चाहिए। राजनीति भी इस फटाफट, ठकाठक से दूर नहीं रह गई है और राजनेता आजकल फटाफट, ठकाठक, गटागट, टकाटक जैसे शब्दों का जमकर प्रयोग कर रहे हैं और एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। खैर जो है सो है लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि इस ठकाठक, गटागट, टकाटक और फटाफट के चक्कर में कोई सफेदपोश सफाचट नहीं हो जाए। वैसे, राजनेता आजकल ऐसे शब्दों का प्रयोग करके अपने भाषण में एक अच्छी राइम-स्कीम जरूर बना रहे हैं, जो कानों को सुनने में अच्छी लग रही है। ऐसे लगता है जैसे राजनेता अपने चुनावी भविष्य के लिए फटाफट, ठकाठक, गटागट और सफाचट जैसे शब्दों से सत्ता की कुर्सी के लिए कोई जानदार शानदार कविता लिख रहे हैं। वे टकाटक झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। जनता फटाफट उनको टीवी चैनलों पर देख,सुन रही है और ठकाठक वोट भी डाल रही है। सच तो यह है कि राजनीति झमाझम झमाझम 400 के पार में उलझी हुई है। आज बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक व सामाजिक असमानता मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा तो खटाखट वर्सेज ठकाठक का है। ठकाठक-ठकाठक झूठ पर झूठ फेंको और फटाफक फटाफट वोट लूट लो। जब तक यह व्यंग्य किसी अखबार में छपेगा तब तक खटाखट चुनावी रिजल्ट भी आ जाएंगे। हारने वाले दल फिर ईवीएम पर ठकाठक,ठकाठक करेंगे। चैनल वाले फटाफट, फटाफट ईवीएम पर डिबेट दिखायेंगे। फिर जनता के दिल भी धकाधक-धकाधक करेंगे। खैर, आजकल गर्मी भी बहुत पड़ रही है। सूरज देवता भी फटाफट,ठकाठक चमक रहे हैं।पारा धकाधक धकाधक 50 के पार। 'लू' भी ठकाठक-ठकाठक चल रही है और धरती का तापमान पचास डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। हास्पीटल मरीजों से ठमाठम-ठमाठम हो रहे हैं। डाक्टरों, हास्पीटल वालों और मेडिकल वालों की जेबें झमाझम-झमाझम हो रहीं हैं। तापमान तो इतना अधिक हो गया है कि राजस्थान के रेतीले धोरों में तो अंडे तक उबाल कर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दिखाए जा रहे हैं। इससे जमाजम-जमाजम लाइक्स पर लाइक्स और शेयर पर शेयर मिल रहे हैं। वैसे शेयर बाजार के साथ सोना-चांदी भी झूम बराबर झूम गीत गा रहे हैं और हवा में ठकाठक-ठकाठक खबरें लहरा रहे हैं कि 'हम भी किसी से कम नहीं।' आप खरीद सकते हैं नहीं। अजी ! आप में इतना दम नहीं। इधर ,राजधानी पानी के लिए ठकाठक-ठकाठक लड़ाई लड़ रही है। पानी हो या वोट हर तरफ ठकाठक टकाटक की प्रतिस्पर्धा है। कुछ मिलाकर, खटाखट टकाटक की राइम स्कीम हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। सड़क से लेकर संसद तक। गली से लेकर चौबारे तक और राजनीति के हर गलियारे तक। हम सोच रहे हैं कि हम भी इस राइम स्कीम को अपनाने के साक्षी बनें। टकाटक टकाटक की राइम स्कीम सुनने पर दिल 'हूम-हूम' नहीं करता, दिल गार्डन- गार्डन हो जाता है। हम ठहरे एक छोटे-से, अदने से लेखक। हम सोच रहे हैं कि हम भी अपने नाम के आगे फटाफट-ठकाठक चिपका लें और अपने जीवन को हसीन और सुंदर बना लें। आप भी हमारे इस व्यंग्य को फटाफट ठकाठक पढ़िए और ढ़ेरों लाइक और शेयर गटागट गटागट सभी को पिला दीजिए, क्या पता आपकी फटाफट,ठकाठक से इस अदने से लेखक का भी उद्धार हो जाए और यह लेखक भी लेखन के क्षेत्र में फटाफट ठकाठक नाम कमा जाए। आपको फटाफट ठकाठक की कसम। आप हमारे इस व्यंग्य को चटाचट, चटाचट अपनी दिल और दिमाग की आंखों से पीजिए और इस व्यंग्य का मजा लीजिए।

प्रकाशक, संपादक, मुद्रक रूपेश कुमार सिंह, रैप एक्सप्रर्टस प्राइवेट लिमिटेड पटना द्वारा, कॉमी तंजीम पब्लिसर्स प्रा. लिमिटेड, अमीन मंजिल, सब्जीबाग, पटना-800004 से मुद्रित। ज्योति प्रकाश भवन, जकरियापुर एसएफसी कॉलोनी, जीरो माइल गंगा पेट्रोल पंप के नजदीक, पटना से प्रकाशित। संपर्क सूत्र ¶ 9835055017@7004145686] RNI NO&BIHHIN/2021/85413, RNI TITLE CODE : BIHHIN/11898

सम्पादकीय

अपराधियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के अभियान को मिले गति

राजस्थान पुलिस ने अपराधियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए उनकी नाजायज सम्पत्तियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इस अभियान को और अधिक गति की आवश्यकता है। दरअसल पुलिस ने तस्करी में लिप्त अपराधियों की अवैध सम्पत्ति पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाना शुरू किया है। ये कंसपेट पुलिस ने उत्तर प्रदेश से लिया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर राज्य में गत 15 मई से नशाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक दर्जनों अपराधियों की सरकारी जमीन पर की गई कब्जेखोरी को ध्वस्त किया गया है। हाल ही में मंगलवार को सांचौर जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दाता गांव निवासी मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त दो तस्कर भाइयों की संपत्ति को फ्रिज कर साइन बोर्ड लगा दिए। पुलिस ने इनके दो आलीशान मकान एवं 744 ग्राम सोने के आभूषण फ्रिज किये हैं, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये है। दाता गांव निवासी भूताराम ऊर्फ भभूता राम विश्नोई एवं उसका भाई जेता राम विश्नोई मादक पदार्थ के बड़े तस्कर हैं। भूता राम के विरुद्ध पंजाब के पटियाला जिले में थाना बस्सोबाला, सांचौर तथा थाना करड़ा में सात व जेताराम के विरुद्ध सांचौर करड़ा एवं सिरोही के मण्डार थाने में पांच अवैध मादक पदार्थ व शराब की तस्करी सहित अन्य अपराधिक एनडीपीएस एक्ट, राजस्थान आबकारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता का अलग—अलग धाराओं में दर्ज हैं। दोनों तस्कर भाइयों ने मादक पदार्थों की तस्करी की काली कमाई से अपने गांव में अलग-अलग अपने आलीशान मकान बना रखे हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सक्षम प्राधिकरण को फ्रीजिंग की कार्रवाई के आदेश के लिए लिखा गया। भारत सरकार के सक्षम प्राधिकरण से इनकी संपत्ति फ्रिज करने के आदेश पुलिस को मिले। इसी सिलसिले में इनकी सम्पति को फ्रिज करने की कार्रवाई मंगलवार को अंजाम दी गई। ऐसे ही कई मामलों में पुलिस ने बुलडोजर चलाकर सम्पत्तियों को ध्वस्त किया है। कुछ दिन पूर्व ही गंगानगर में भी ऐसे ही अपराधियों के मकान ध्वस्त किए गए। कुछ माह पूर्व जयपुर पेपर लीक के एक आरोपी के मकान के अवैध हिस्से को गोपालपुरा बाइपास ढहाया गया था। दरअसल अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि इस अभियान का दायरा बढ़ाया जाए। तभी अपराधी अपराध करने और अपनी काली कमाई से अकूत सम्पत्तियां खड़ी करने से रुकेंगे।

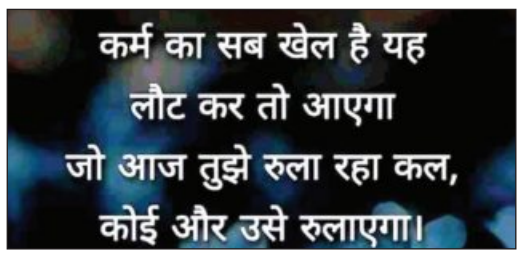

एग्जिट पोल के नतीजों का जनता को ही नहीं शेयर बाजार को भी रहता है इंतजार

चुनाव परिणाम के दिन तो शेयर बाजार रिएक्ट करेगा ही, लेकिन उससे पहले 3 जून यानी सोमवार को शेयर बाजार पर इन एग्जिट पोल का कुछ असर देखने को मिलेगा? अगर साल 2004 के लोकसभा चुनाव से लेकर साल 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो और एग्जिट पोल के आंकड़ें आने के बाद शेयर बाजार पर असर साफ दिखाई देता है। यदि हम सिलसिलेवार बीते चार लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार के आंकड़ों को देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर इन अनुमानित आंकड़ों का कितना असर देखने को मिला है।

अशोक भाटिया

लोकसभा चुनाव 2024 के तहत सातवां और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को समाप्त हो गया जिसमे 8 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सहित 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो गया , जिसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे लेकिन इससे पहले अंतिम चरण की वोटिंग के बाद सभी का नजरें एग्जिट पोल पर ही रही , जो चुनावों के बाद संभावित सरकार की भविष्यवाणी करते हैं। क्योकि चुनाव और उसके नतीजे शेयर बाजार पर किस तरह का असर डालते हैं, वो हम पहले भी काफी देख चुके हैं। फिर चाहे वो साल 2019 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर पिछले साल पांच विधानसभा चुनाव के नतीजे हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एग्जिट पोल शेयर बाजार पर असर डालते हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें फेज का मतदान खत्म होने के बाद टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स पर तमाम एग्जिट पोल्स के आंकड़ें रेंगने शुरू हो गए । इन आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि 4 जून के नतीजे किस तरह के देखने को मिल सकते हैं।

साल 2004 के लोकसभा चुनाव का आखिरी फेज 10 मई को हुआ था। उसके बाद करीब 5 एग्जिट पोल सामने आए थे। इनमें से 3 पोल्स ने जो संकेत दिए गए थे, वो हंग पार्लियामेंट के थे। इसका मतलब था कि किसी भी गठबंधन को फुल मैज्योरिटी नहीं मिल रही। सिर्फ दो ही ऐसे सर्वे थे जो एनडीए को फुल मैज्योरिटी दिखा रहे थे। उसके बाद जब 11 मई को शेयर बाजार ओपन हुआ तो सेंसेक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 10 मई को जब शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 5,555.84 अंकों पर बंद हुआ था। 11 मई को ये आंकड़ा 5,325 ।90 अंकों पर आ गया। यानी सेंसेक्स में 229.94 अंकों की गिरावट देखी गई थी। इसका मतलब है कि निवेशकों को 4.14 फीसदी का नुकसान हुआ था। साल 2009 के लोकसभा चुनाव का आखिरी फेज 13 मई को था और शाम को एग्जिट पोल आए थे। उसमें कुछ पोल यूपीए को 190 से 200 सीट मिलने का अनुमान लगा रहे थे। तो एनडीए को 180 से 195 सीटें मिलने का अनुमान लगा गया था। मतलब साफ था कि लगातार दूसरी बार एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव के परिणाम का अनुमान हंग पार्लियामेंट लगा रहे थे। लेकिन इसका असर शेयर बाजार पर वैसा नहीं देखा गया जैसा कि साल 2004 में देखने को मिला था।अगर बात सेंसेक्स की करें तो 13 मई 2009 में 12,019.65 अंकों पर बंद हुआ। जबकि उसके बाद सेंसेक्स 11,872.91 अंकों पर आ गया। इसका मतलब है कि सेंसेक्स 1.22 फीसदी यानी 146.74 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज हुआ था। जबकि निफ्टी 3,635.25 अंकों से गिरकर 3,593.45 अंकों पर आ गया था। यानी निफ्टी एग्जिट पोल के असर से 1.15 फीसदी यानी 41.8 अंक टूटा था। साल 2004 और 2009 के विपरीत इस बार एग्जिट पोल्स ने पहली बार फुल मैज्योरिटी के संकेत दिए। साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार केंद्र की राजनीति में देखे गए। 12 मई को आखिरी फेज के मतदान हुए थे। उसके बाद जो एग्जिट पोल के आंकड़ें आए उससे किसी को कोई हैरानी नहीं हुई। कोई ऐसा एग्जिट पोल नहीं था जो एनडीए को फुल मैज्योरिटी देता हुआ ना दिखाई दिया हो। सभी ने एनडीए को 272 से लेकर 340 तक सीटें दीं। वहीं यूपीए का एग्जिट पोल में आंकड़ा 150 सीटें भी देता हुआ दिखाई नहीं दिया। कुछेक ने तो यूपीए को 100 से नीचे भी उतार दिया। एग्जिट पोल के आंकड़ें एक्सपेक्टिड थे। इसलिए इन आंकड़ों को शेयर बाजार पहले ही डाइजस्ट कर चुका था। ऐसे में एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में कुछ ज्यादा हरकत देखने को नहीं मिली। 12 मई को सेंसेक्स 23,551 अंकों पर बंद हुआ। उसके बाद 13 मई को सेंसेक्स में 1.36 फीसदी यानी 320.23 अंकों की तेजी देखने को मिली। वहीं निफ्टी 7,014.25 अंकों से 7,108.75 अंकों पर आ गया। यानी निफ्टी 1.35 फीसदी यानी 94 ।5 अंक बढ़त के साथ दिखाई दिया ।साल 2019 लोकसभा चुनाव कई मामलों में दिलचस्प रहा। उससे पहले देश में डिमॉनेटाइजेशन हुआ था। जीएसटी को लागू किया गया था। जिसे विपक्ष ने काफी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। चुनाव से पहले देश में बालाकोट हमला हुआ। उस वक्त केंद्र ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। उसके बाद देश में एक लहर चली जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। चुनाव का आखिरी फेज 17 मई 2019 को हुआ था। उसके बाद एग्जिट पोल सामने आए वो अपने आपमें काफी अप्रत्याशित थे। एग्जिट पोल में भाजपा को 300 से ज्यादा और एनडीए को 350 से ज्यादा मिलती हुई दिखाई गई। वहीं यूपीए 2014 के एग्जिट पोल के आंकड़ों से भी नीचे लुड़कता हुआ दिखाई दिया ।इसका असर भी शेयर बाजार में काफी बड़ा दिखाई दिया। एग्जिट पोल आने के दो दिन के बाद जब शेयर बाजार ओपन हुआ था तो पौने चार फीसदी की तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 17 मई को 37,930.77 पर था। 20 मई को जब बाजार खुला तो सेंसेक्स 3.75 फीसदी यानी 1,421.9 अंकों की तेजी देखने को मिली और 39,352 ।67 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 20 मई को 3.69 फीसदी यानी 421.1 अंकों की तेजी के साथ 11,828.25 अंकों पर बंद हुआ।

अब सभी की नजरें 3 जून को शेयर बाजार पर रहेंगी। एग्जिट पोल आने के बाद पहली बार शेयर बाजार उसी दिन ओपन होगा। अगर ऊपर दिए चार चुनाव के एग्जिट पोल और उसके बाद शेयर बाजार पर पड़े असर को मानें तो 3 जून को शेयर बाजार तेजी और नुकसान दोनों तरफ जा सकता है। अगर एग्जिट पोल में आंकड़ें हंग पार्लियामेंट के दिखाई देते हैं तो शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर किसी एक गठबंधन यानी एनडीए या इंडिया में किसी एक को फुल मैज्योरिटी मिलती है तो शेयर बाजार पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। वहीं शेयर बाजार की नजरें पोल्स में भाजपा के परफॉर्मेंस पर भी टिकी होंगी। अगर भाजपा को पोल्स में बहुमत के आंकड़ें को ही नहीं करती बल्कि अपने पिछले आंकड़ों को भी पार करती हुई दिखाई देती है तो शेयर बाजार में तेजी बन सकती है। अगर भाजपा पोल्स में बहुमत के आंकड़ें से नीचे रहती है तो शेयर बाजार डगमगा सकता है।

आज का इतिहास

2 जून की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- रूस और ऑस्ट्रिया ने 1746 में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
- कैथोलिक विरोधी प्रदर्शनकारियों ने लंदन में पार्लियामेंट पर 1780 में हमला कर दिया।
- अमेरिका में पहली बार मैने प्रांत में मद्यपान निषेध कानून 1851 को लागू किया गया।
- गुगलिएलमो मार्कोनी ने रेडियो को अपने नाम पर पेटेंट कराने के लिये आवेदन 1896 में दिया जो बाद में दो जुलाई 1897 को स्वीकार कर लिया गया।
- एलफ्रेड डेकिन लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 1909 में चुने गए।
- लार्ड लुई माउंटबेटन ने 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की।
- ब्रिटिश राजगद्दी पर महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय की 1953 में ताजपोशी हुई।
- अमेरिका ने 1966 में अपने पहले ही प्रयास में चांद पर अंतरिक्षयान उतारा।
- माली ने अपना संविधान 1974 में अपनाया।
- उक्रेन अपने अंतिम परमाणु युद्धास्त्र रूस को सौंपने के साथ ही परमाणु मुक्त देश 1996 को बना।
- दक्षिण एवं उत्तर कोरिया के बीच उच्च स्तरीय वार्ता पर सहमति, भूटान में टी.वी. प्रसारण की शुरुआत 1999 में हुई।
- म्यांमार की जनतांत्रिक नेता आन सांग सूची की गिरफ़्तारी के बाद देश की सभी शिक्षण संस्थाएँ 2003 में बन्द।
- आस्ट्रेलियाई मॉडल जेनिफ़र हॉकिन्स मिस यूनिवर्स 2004 को बनीं।
- भारत, रूस और चीन का ब्लादीवोस्तोक सम्मेलन 2005 में समाप्त हुई।
- अमेरिका ने दाऊद इब्राहीम तथा उसके संगठन पर 2006 को प्रतिबंध लगाया।
- ई-कोलाई बैक्टीरिया के संक्रमण से 2011 को यूरोप में 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1600 से अधिक लोग बीमार हो गए।
- भारत सरकार ने 2011 को शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपडियों से मुक्ति दिलाने और गरीबों को अपने घर का सपना पूरा कराने में सहायता के लिए राजीव गांधी आवास योजना के पहले चरण को मंजूरी दी।
- मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को 2011 की अरब क्रांति के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश देने के आरोप में उम्रकैद की सजा 2012 में सुनाई गई।
- सन 2014 में आज ही के दिन तेलंगाना भारत का 29 राज्य बने।

2 जून को जन्मे व्यक्ति

- 'भारतीय जनता पार्टी' के नेता और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का जन्म 1930 में हुआ।
- प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ अनंत गीते का जन्म 1951 में हुआ।
- भारत के प्रसिद्ध फ़िल्म निर्माता-निर्देशकों में से एक मणिरत्नम का जन्म 1955 में हुआ।
- भारतीय उपक्रमी, नौकरशाह, नेता और प्रसिद्ध सॉफ़्टवेयर कम्पनी 'इन्फ़ोसिस' के सह-संस्थापक सदस्यों में से एक नन्दन नीलेकणी का जन्म 1955 में हुआ।
- तीरंदाज़ महिला खिलाड़ी डोला बनर्जी का जन्म 1980 में हुआ।
- बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 1987 में आज ही के दिन हुआ।

विशेष आलेख

रिश्तों की दरकती बुनियाद

विजय गर्ग

परिवार को समाज की नींव का पत्थर कहा जाता है। पर अब कुछ समाजशास्त्रियों ने पारिवारिक जीवन और परिवार के महत्त्व को लेकर सवालिया निशान लगाए हैं। परिवार में जहां एक तरफ सदस्यों को प्रतिबद्धता के मूल्य सिखाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में प्रविष्ट करा कर व्यक्तिवादिता के मूल्यों से परिचित कराया जाता है, ताकि वे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र और स्वायत्तशासी बन सकें। परिवार में कुछ और परिवर्तन प्रौद्योगिकीय विकास और अन्य विकास प्रक्रियाओं के कारण उभरने लगे हैं। उदारवादी दौर में गतिशीलता बढ़ने से अनेक बार परिवार करिअर में बाधक नजर आता है, क्योंकि संबंधों में उदारवाद उभरा है। संतानोत्पत्ति को स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में बाधक माना जाने लगा है। परिवार में निजता का दायरा भी बदल गया है। अब निजता में हम केवल उन्हें शामिल करते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं और जिन्हें हम परिवार में नहीं चाहते हैं उनके साथ तनावपूर्ण संबंध होते हैं। यानी पति या पत्नी के माता- -पिता और भाई बहन भी इस निजता के दायरे में शामिल नहीं होते।

तेजी से उभरते भौतिकतावाद ने परंपरागत परिवार संरचना के सामने अनेक संकट उत्पन्न कर दिए हैं। तलाक दर में वृद्धि, विवाह के पूर्व सहजीवन, एकल अभिभावक परिवार और एकल व्यक्ति गृहस्थी वे प्रवृत्तियां हैं, जो परंपरागत परिवारों के सम्मुख अनेक सवाल पैदा करती हैं। समाज वैज्ञानिकों का मत है कि यह परिवर्तन आधुनिक समाजों में व्यक्तिवाद के बढ़ते प्रभाव को बताते हैं। यह व्यक्तिवादिता परंपरागत परिवार को अस्थिर बना देती है। कुछ विचारकों का यह भी मानना है कि समाज में हो रहे परिवर्तनों ने अस्थिरता और असुरक्षा को व्यवस्था का हिस्सा बना दिया है, जिसकी अभिव्यक्ति परिवार में अस्थिरता के रूप में होती है। पूर्व के समाजों में परिवार विस्तृत नातेदारी का एक हिस्सा था, जबकि आधुनिक समाज में परिवार नातेदारों और संबद्ध समुदाय से कमोबेश कट से गए, जिसके फलस्वरूप भावनात्मक दबाव परिवार का एक आवश्यक, पर नकारात्मक अवयव बनकर उभरा है।

हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में घटित कुछ घटनाओं के आधार पर इन विभिन्न पक्षों को समझा जा सकता है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक महिला ने अपनी तीन साल की बेटी की हत्या कर दी। पति-पत्नी में किसी बात पर झगड़ा हुआ था, इस बीच उनकी बच्ची रोने लगी, तो गुस्से में पत्नी ने बच्ची को एक पेड़ के नीचे ले जाकर उसका गला घोंट दिया। इसी तरह बंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ ने गोवा के एक होटल में अपने चार साल के बेटे की हत्या कर दी थी। पति से तलाक के बाद वह नहीं चाहती थी कि उसका पति बेटे से मिले। एक और घटना राजस्थान के बारां जिले की है, जिसमें बेटे ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने बुजुर्ग माता-पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के बड़ौत में एक बेटे ने संपत्ति से बेदखल किए जाने के बाद गुस्से में अपने पिता और दो सगी बहनों को मौत के घाट उतार दिया।

इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि भोगवादी संस्कृति के प्रसार ने लोगों को इतना व्यक्तिवादी और स्वार्थ केंद्रित बना दिया है कि अपने छोटे से लाभ के लिए जीवनसाथी, अपने बच्चों या माता-पिता की हत्या करने तक से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। किसी की हत्या करना और खासकर किसी अपने की हत्या करना मानो एक खेल सा हो गया है। और ऐसा तभी संभव है, जब रिश्तों में भावनाएं, प्यार, लगाव समाप्त हो जाएं। या यों कहें कि आजकल के संबंधों में अपनत्व और प्रेम का स्थान पैसे ने ले लिया है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आधे रिश्ते तो लोग इसीलिए निभा रहे हैं कि उनसे कभी न कभी काम पड़ सकता है। कहा जाता था कि दुनिया में भाई- ई-बहन का

रिश्ता सबसे निकट का और सबसे ज्यादा प्यार भरा होता है, लेकिन अब यह रिश्ता भी संपत्ति और उपहारों की भेंट चढ़ गया है। जिस दिन बहन ने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा मांगा उसी दिन से वह सबसे बड़ी शत्रु दिखाई देने लगती है। बहन का घर आना भी खलने लगता है, जबकि शादी से पहले यही बहन उसकी सबसे बड़ी दोस्त और हमदर्द हुआ करती थी ।

यह कैसा विकास है, जहां मशीनें 'स्मार्ट' बनने लगी हैं और इंसान अपनी 'स्मार्टनेस' खोते जा रहे हैं। अपना अधिकांश समय 'स्मार्ट गजेट्स' के साथ बिताने के कारण लोगों में अपने परिवार और मित्रों के साथ संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी रिश्ते या संबंध में संवाद होना महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचना क्रांति के इस दौर में 'स्मार्ट फोन' ने रिश्तों की गर्माहट को ही खत्म कर दिया है। पहले हर रिश्ते हर दोस्त में अलग भावनात्मक लगाव हुआ करता था और उनकी अभिव्यक्ति भी भिन्न-भिन्न होती थी, लेकिन स्मार्ट फोन के जमाने में एक ही संदेश हर किसी को भेज दिया जाता है। जब तक किसी से काम न पड़े, तब तक उससे संपर्क भी करने की जरूरत अनुभव नहीं की जाती। आज लोगों के जीवन में धन-संपत्ति इतनी महत्त्वपूर्ण हो गई है कि अपने ही खून के रिश्तों का कत्ल करने से भी वे नहीं चूकते ।

विवाह संस्था में विश्वास की समाप्ति, परिवारों में विघटन, भौतिक वस्तुओं को अधिक से अधिक पाने की लालसा, स्वयं को श्रेष्ठ और अन्यों को हीन मानने की प्रवृत्ति ने लोगों को अवसाद और निराशा के गर्त में धकेल दिया है। इसके अलावा जबसे हर चीज का बाजारीकरण हो गया है, तबसे रिश्तों का महत्त्व और भी कमजोर हुआ है। आधुनिक विकसित तकनीक के माध्यम से बच्चे पैदा हो जाना, उनका पालन- पोषण करने के लिए अनेक सार्वजनिक संस्थानों की मौजूदगी, जिससे मां का स्थान स्मार्ट मशीन लेने लगी है। घर और दफ्तर के हर काम के लिए रोबोट के इस्तेमाल ने रिश्तों को बाजार की वस्तु बना दिया है। ऐसे में जब मानव जीवन के अस्तित्व की निरंतरता ही खतरे में हो, तो रिश्तों की समाप्ति का संकट हैरानी की बात नहीं।

जबसे इंसान ने उपभोक्तावाद और बाजारवाद की संस्कृति को जीवन का अहम हिस्सा बनाया है, तबसे मानव समाज अनेक तरह के जोखिमों से घिर गया है। जबसे लोगों ने परिवार के बड़े-बुजर्गों का स्थान गूगल और सोशल मीडिया को देना शुरू किया है, तबसे वह दिग्भ्रमित हो गया है। किसी ने सच ही कहा है कि जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे। हैं तबसे दामन में अपने दुआएं कम और दवाएं ज्यादा भरने लगे हैं। मानव समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इस विषय पर गंभीर विमर्श किया और हर संभव कोशिश की जाए, ताकि रिश्तों के समाज को मशीनी समाज में बदलने से रोका जा सके।

पहली बार अमेरिका का कोई पूर्व राष्ट्रपति 34 मामलों में दोषी करार

रामस्वरूप रावतसरे

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क कोर्ट में गुरुवार (30 मई 2024) को करीबन 34 मामलों में दोषी करार दिया गया है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि कोई पूर्व राष्ट्रपति, कोर्ट में दोषी पाया गया हो। करीबन 6 हफ्ते चली सुनवाई के बाद न्यूयॉर्क की कोर्ट ने अपना यह निर्णय दिया।

ट्रंप के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल को पैसे देकर चुप कराया ताकि उनके चुनावों पर प्रभाव न पड़े। इसके अलावा चुनावी प्रचार के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी भी की ताकि उसका मुनाफा वो चुनाव प्रचार में ले सकें। ट्रंप के विरुद्ध ये सारे मामले राष्ट्रपति बनने से पहले दर्ज हुए थे। 2016 में इन केसों को शुरू किया गया था।

इसके बाद उनके ऊपर आपराधिक केस चला। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने 6 हफ्तों में 22 गवाहों को सुनने के बाद अपना निर्णय दिया है। इन गवाहों में स्टॉर्मी डेनियल्स का नाम भी था। उन्होंने तो कोर्ट में बाथरूम और बेडरूम से जुड़ी ऐसी बातें बता डाली थीं कि जज को खुद उन्हें चुप होने को कहना पड़ा था। जजों ने इस मामले में फैसला सुनाने के बाद दो दिन तक विचार विमर्श किया, फिर 12 मेंबर की ज्यूरी ने ट्रंप को दोषी करार दिया। अब पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को सजा क्या दी जाएगी इस पर कोर्ट 11 जुलाई 2024 को अपना फैसला देगा, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि क्या इन आरोपों के सिद्ध होने के बाद ट्रंप को अमेरिका में चुनाव लड़ने का अधिकार होगा या फिर नहीं? रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट के निर्णय से ट्रंप के चुनाव लड़ने न लड़ने के फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अमेरिका में ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है जो उन्हें जेल से बतौर राष्ट्रपति सेवा देने से रोके। तो अगर, ऐसी स्थिति आती है, ट्रंप चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं तो उनके लिए पद छोड़ने का कोई संकट नहीं आएगा। ये बात अलग है कि न्यायिक व्यवस्था इस पर अपने हिसाब से निर्णय लेकर कोई और रास्ते का सुझाव दे। अप्रैल में आए एक एमर्सन पोल के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए 43 फीसद लोगों ने डॉनल्ड ट्रंप को पंसद किया था वहीं 42 ने बाइडेन को। ऐसे में दोनों के बीच आगामी चुनावों में कड़ाके की टक्कर हो सकती है। 11 जुलाई के बाद ट्रंप अगर जेल जाते भी हैं तो उन्हें चुनाव कैंपेन करने का अधिकार होगा, लेकिन दोषी पाए जाने के बाद वो चुनावों के मतदान में शामिल हो पाएँगे या नहीं, ये अभी पुष्टि नहीं हो सकती।

दरअसल, ट्रम्प अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के निवासी हैं और वहाँ का नियम कहता है कि अगर कोई शख्स किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है तो उससे वोट करने का अधिकार छीन लिया जाता है। हालाँकि सजा पूरी होने के बाद उसे वो अधिकार वापस मिल जाता है। ट्रंप के मामले में सजा मुकर्रर होने के बाद निर्णय आने के बाद फैसला होगा कि उनके अधिकार छिनेगा या उनके पास ये अधिकार रहेगा। बता दें कि ट्रंप से पूर्व अमेरिका में सदी पहले सिर्फ 'यूजीन वी डेब्स' एकलौते ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने जेल में रहकर राष्ट्रपति बनने के लिए कैंपेन चलाया था। उनके बाद से अमेरिका के इतिहास में अब तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसमें कोई दोषी करार शख्स चुनाव लड़ रहा हो। देखना है कि इस बार प्रथा बदलती है या वही रहेगी।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
अविवाहित लोगों के विवाह के योग बनेंगे। आपको पत्नी अथवा संतान से लाभ हो सकता है। व्यापार के लिए होने वाला प्रवास लाभदायक साबित होगा। आपके उच्च अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। पदोन्नति होने की संभावना है।

वृष
आमोद-प्रमोद की प्रवृत्तियों में पैसे खर्च होंगे। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ निकटता के पल व्यतीत कर सकेंगे। कोर्ट-कचहरी के मामलों में संभलकर कार्य करना उचित रहेगा। ऑफिस में स्त्री वर्ग से लाभ होने की संभावना है।

मिथुन
पारिवारिक जीवन में उत्साह का वातावरण रहेगा। संतान की प्रगति से आपको संतोष का अनुभव होगा। आज आपको बेचैनी, थकान का अनुभव होगा। शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा। इससे काम करने का उत्साह नहीं रहेगा।

कर्क
परिवार में आज आनंद का वातावरण रहेगा। वाणी की मधुरता और न्यायप्रिय व्यवहार से आप लोकप्रियता प्राप्त करेंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। विद्यार्थियों के विद्याध्ययन के लिए अनुकूल समय है। मित्रों के साथ घूमना-फिरना होगा।

सिंह
आपका आज का दिन शुभ फलदायी साबित होगा। निर्धारित काम सफलता से पूरे होंगे। अधूरे काम पूरे होंगे। ननिहाल पक्ष से आनंददायक समाचार मिलेंगे। बीमारी में राहत महसूस होगी। नौकरीपेशा वर्ग को नौकरी में लाभ होगा।

कन्या
अपनी कला को बाहर लाने के सुनहरे अवसरों को हाथ से न जाने दें। आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्ति अधिक निखरेगी। शारीरिक, मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी। मनोरंजन की प्रवृत्ति में दोस्तों तथा परिजनों के साथ भाग लेंगे। दांपत्य जीवन में विशेष मधुरता रहेगी।

तुला
शारीरिक- मानसिक अस्वस्थता का अनुभव होगा। छाती में दर्द या किसी विकार से परिवार में अशांति होगी। महिलाओं के साथ मनमुटाव और तकरार होने की संभावना है। सार्वजनिक रूप से मानहानि होने से दुख होगा।

वृश्चिक
सुंदर भोजन, वस्त्र और वाहन सुख की प्राप्ति होगी। प्रिय व्यक्ति की मुलाकात तथा काम में सफलता का योग है। आज आपके विदेश में बसने वाले स्नेहीजन या मित्रों से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। समय से भोजन नहीं मिलेगा।

धनु
आज संतान और जीवनसाथी के संबंध में चिंता होगी। वाद-विवाद या चर्चाओं में गहरे न उतरना हित में रहेगा। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। मित्रों के लिए खर्च की संभावना है। पेट संबंधी बीमारियों से तकलीफ होगी।

मकर
कार्य सफलता और विरोधियों पर विजय का नशा आपके दिलो-दिमाग पर छाया रहेगा, इससे प्रसन्नता अनुभव करेंगे। भाई-बहनों के साथ मिलकर घर पर कोई आयोजन करेंगे। ऑफिस तथा काम-काज की जगह अधिकारियों की नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा।

कुंभ
आज आप आर्थिक लाभ के साथ समाज में आदर प्राप्त कर सकेंगे। आपके परिवार में सुख और संतोष बना रहेगा। आपकी आय बढ़ेगी और व्यापार में भी लाभ होगा। प्रिय व्यक्ति के साथ सुखद समय बिताएंगे।

मीन
आज आपका दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। आयात निर्यात से जुड़े व्यापारियों को धंधे में लाभ और सफलता मिलेगी। आपकी खोई हुई वस्तु वापस मिलने की संभावना है। प्रवास आर्थिक लाभ और वाहन सुख की संभावना है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीदपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 ''प्रतीक्षा'' सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

आर्थिक मोर्चे की दो शानदार खबरों से सशक्त होता भारत

-ललित गर्ग

एक जून को आम चुनाव के सातवें व अंतिम चरण के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 57 सीटों पर मतदान चल रहा है, चुनाव से पहले कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान को लेकर विपक्ष की धमासान राजनीति हो रही है, कांग्रेस मामले को लेकर अदालत भी पहुंच गई है, इस राजनीतिक गर्मा-गर्मी के बीच मतदान से ठीक एक दिन पहले आर्थिक मोर्चे पर दो शानदार खबरें आई है, जो न केवल चौंका रही है, आश्चर्यचकित कर रही है बल्कि अपूर्व खुशी का अहसास करा रही है। भारत भूमि पर भारतीय रिजर्व बैंक के खजाने में 100 टन से कुछ ज्यादा स्वर्ण का शामिल होना सुखद और गौरवान्वित करने वाली खबर है। इसी तरह दूसरी महत्वपूर्ण खबर है पूर्व के सभी अनुमानों को ध्वस्त करते हुए देश की अर्थव्यवस्था ने 8.2 फीसदी की दर से उड़ान भरी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी-मार्च चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, पहली तिमाही अप्रैल-जून में 7.8 फीसदी, दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर में 7.6 प्रतिशत और तीसरी तिमाही अक्टूबर- दिसंबर में 8.6 फीसदी की दर से बढ़ी थी। इसके साथ ही पूरे वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गई। जीडीपी की यह रफ्तार दुनिया के सभी विकसित एवं विकासशील देशों में सर्वाधिक है। उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की यह तेज गति सशक्त अर्थव्यवस्था को एवं दुनिया की तीसरी आर्थिक महाताकत बनने के संकल्प को बल देगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की एक मौलिक सोच एवं दृष्टि से ही भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में एक चमकते सितारे के रूप में उभरी है, सुदृढ़ आर्थिक विकास के सुनहरे परिदृश्य प्रस्तुत कर रही है एवं ह्लमजबूत आर्थिक विकासह्व को दर्शा रही है।

जीडीपी की शिखर की ओर बढ़ने की गति भारत के शक्तिशाली बनने का आधार है। विनिर्माण, निर्माण, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं द्वारा प्रोत्साहित, चौथी तिमाही की 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर अर्थशास्त्रियों द्वारा लगाए गए 7.3-7.4 प्रतिशत के उच्चतम अनुमान से कहीं अधिक रही। और 8.2 प्रतिशत की पूर्ण वर्ष की वृद्धि दर आरबीआई द्वारा अनुमानित 7 प्रतिशत और एनएसओ द्वारा 2023-24 के लिए 7.6 प्रतिशत के दूसरे अग्रिम अनुमान से अधिक है। यह आंकड़ा सभी अनुमानों एवं पूवार्नुमानों से ऊपर है। जीडीपी की गति इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल और सामाजिक विकास की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाने की रफ्तार को भी गति देगी। यह आर्थिक विकास देश को न केवल विकसित देशों में बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर तीसरे स्थान दिलाने के संकल्प को बल देने में सहायक बनेगा। यह जीडीपी इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, न कि लोकलुभावन योजनाओं के जरिये प्रशंसा पाने अथवा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। राजनीतिक हितों से ज्यादा देशहित को सामने रखने की यह पहल अनूठी है, प्रेरक है। अमृत काल यानी 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का विजन निश्चित ही हम हासिल करेंगे।

ध्यान देने की बात है कि आजादी के बाद की अधिकतम शासन करने वाली सरकारों ने आर्थिक संकट ही खड़े किये थे। साल 1991 में जब भारत पर आर्थिक संकट आया था, तब शायद भारतीय अर्थव्यवस्था से दुनिया के ज्यादातर देशों को विश्वास कुछ डिग गया था। मजबूरी में देश को अपना सोना विदेश भेजना पड़ा था। तब कर्ज का जाल भारी हो गया था, लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है और कर्ज चुकाना अब समस्या नहीं है। ऐसे में, इतने बड़े पैमाने पर विदेश से सोना लाने की प्रशंसा ही की जा सकती है। मार्च के अंत तक रिजर्व बैंक के पास 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेश में था। वास्तव में, अपना सोना किसी अन्य देश में रखने को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। रिजर्व बैंक शायद संदेश देना चाहता है कि भारत अब शक्तिशाली है और वह अपने सोने की हिफाजत खुद कर सकता है। आज अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हम ब्रिटेन से आगे निकल गए हैं, तो हमें अपनी नीतियों में गरिमा के अनुरूप परिवर्तन करना ही चाहिए। वैसे, भारत की स्थिति अचानक नहीं सुधरी है। एक खास बात यह भी है कि भारत चालू वित्त वर्ष में ऐसे चंद देशों में शुमार है, जिन्होंने सोना खरीदा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ ही महीनों में 27.5 टन सोना खरीदकर अपने स्वर्ण भंडार में जमा किया है।

स्वर्ण भंडार के मामले में भारत 822.1 टन के साथ दुनिया में नौवें स्थान पर है और अमेरिका के पास सर्वाधिक 8,133 टन से ज्यादा सोना है। जर्मनी के पास 3,352 टन सोना है। उसके बाद इटली, फ्रांस, रूस, चीन (2,262 टन), स्विट्जरलैंड और जापान का स्थान है। समय के साथ सोने का भाव बढ़ता ही रहा है, बीस साल पहले जो सोना 6,307 रुपये प्रति दस ग्राम का था, वही सोना आज 73,390 रुपये प्रति 10 ग्राम का हो गया है। जाहिर है, सोने की मांग नहीं घटने वाली, पर ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को अपनी बुद्धि, कौशल और श्रम से सोना खरीदने में सक्षम होना पड़ेगा, तभी देश के स्वर्ण भंडार की खनक-चमक बढ़ेगी। कई उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे जीएसटी संग्रह, बिजली खपत, माल ढुलाई आंकड़े आदि संकेत देते हैं कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली और उत्साही बनी हुई है। मोदी यदि तीसरे कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो भारत की आर्थिक विकास गति जारी रहेगी। जीडीपी एवं आर्थिक गति मूडीज, फिच, एसएंडपी, नोमुरा, रिजर्व बैंक, आईएमएफ आदि दिग्गज वित्तीय संस्थानों के अनुमानों को ठुकराते हुए नई छलांगे लगायीं है।

प्रधानमंत्री ने देश में आतंकवादी वारदातें कम होने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने, सरकार के ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करने का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्च किया है और 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। निश्चित ही भारत से गरीबी दूर हो रही है। उन्होंने देशवासियों को ?इस बात का अहसास कराया कि जब देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो तिजोरी ही नहीं भरती बल्कि देश का सामर्थ्य भी बढ़ता है।?उन्होंने देशवासियों से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के खिलाफ लड़ने का आह्वान भी किया क्योंकि ये गरीब, पिछड़े, आदिवासियों और दलितों का हक छीनते हैं। यह उल्लेखनीय एवं संतोष का विषय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हाईडियन इकॅनमी- अ रिव्यूह में यह उम्मीद जताई गई है कि भारत 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की इकॅनमी बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। भारत फिलहाल दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक वित्तीय संस्थान मॉर्गन स्टेनली ने भी ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। तमाम तरह की अनुकूलताओं एवं गुलाबी अर्थ रंगों के बावजूद हमें आर्थिक गति की बाधाओं पर भी ध्यान देना होगा। तेज विकास दर के बावजूद रोजगार के मोर्चे पर खास प्रगति नहीं हुई है। आज भी युवा बेरोजगारी का स्तर 40 फीसदी तक बताया जाता है। यह स्थिति गंभीर इसलिए भी है कि यह तेज विकास दर के फायदों को सीमित करती है। एक बड़ी चुनौती यह भी है कि निजी पूंजी निवेश में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। श्रम-शक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी आर्थिक ही नहीं सामाजिक और अन्य दृष्टियों से भी चिंता की बात है। इस मामले में हम पड़ोस के बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। अर्थव्यवस्था से जुड़ी दो खबरों ने राहत की सांसें है जिससे नया भारत- सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प भी बलशाली बन सकेगा। सच्चाई यही है कि जब तक जमीनी विकास नहीं होगा, तब तक आर्थिक विकास की गति सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी।

एग्जिट पोल के नतीजों का जनता को ही नहीं शेयर बाजार को भी रहता है इंतजार

अशोक भाटिया

लोकसभा चुनाव 2024 के तहत सातवां और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को समाप्त हो गया जिसमे 8 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सहित 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा , जिसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे लेकिन इससे पहले अंतिम चरण की वोटिंग के बाद सभी की नजरें एग्जिट पोल पर ही रही , जो चुनावों के बाद संभावित सरकार की भविष्यवाणी करते हैं। क्योंकि चुनाव और उसके नतीजे शेयर बाजार पर किस तरह का असर डालते हैं, वो हम पहले भी काफी देख चुके हैं। फिर चाहे वो साल 2019 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर पिछले साल पांच विधानसभा चुनाव के नतीजे हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एग्जिट पोल शेयर बाजार पर असर डालते हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें फेज का मतदान खत्म होने के बाद टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स पर तमाम एग्जिट पोल्स के आंकड़े रंगने शुरू हो गए । इन आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि 4 जून के नतीजे किस तरह के देखने को मिल सकते हैं। चुनाव परिणाम के दिन तो शेयर बाजार रिएक्ट करेगा ही, लेकिन उससे पहले 3 जून यानी सोमवार को शेयर बाजार पर इन एग्जिट पोल का कुछ असर देखने को मिलेगा? अगर साल 2004 के लोकसभा चुनाव से लेकर साल 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो जो एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद शेयर बाजार पर असर साफ दिखाई देता है। यदि हम सिलसिलेवार बीते चार लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार के आंकड़ों को देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर इन अनुमानित आंकड़ों का कितना असर देखने को मिला है।

साल 2004 के लोकसभा चुनाव का आखिरी फेज 10 मई को हुआ था। उसके बाद करीब 5 एग्जिट पोल सामने आए थे। इनमें से 3 पोल्स ने जो संकेत दिए गए थे, वो हंग पार्लियामेंट के थे। इसका मतलब था कि किसी भी गठबंधन को फुल मैज्योरिटी नहीं मिल रही। सिर्फ दो ही ऐसे सर्वे थे जो एनडीए को फुल मैज्योरिटी दिखा रहे थे। उसके बाद जब 11 मई को शेयर बाजार ओपन हुआ तो सेंसेक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 10 मई को जब शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 5,555.84 अंकों पर बंद हुआ था। 11 मई को ये आंकड़ा 5,325.90 अंकों पर आ गया। यानी सेंसेक्स में 229.94 अंकों की गिरावट देखी गई थी। इसका मतलब है कि निवेशकों को 4.14 फीसदी का नुकसान हुआ था।

साल 2009 के लोकसभा चुनाव का आखिरी फेज 13 मई को था और शाम को एग्जिट पोल आए थे। उसमें कुछ पोल यूपीए को 190 से 200 सीट मिलने का अनुमान लगा रहे थे। तो एनडीए को 180 से 195 सीटें मिलने का अनुमान लगा गया था। मतलब साफ था कि लगातार दूसरी बार एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव के परिणाम का अनुमान हंग पार्लियामेंट लगा रहे थे। लेकिन इसका असर शेयर बाजार पर वैसा नहीं देखा गया जैसा कि साल 2004 में देखने को मिला था।

अगर बात सेंसेक्स की करें तो 13 मई 2009 में 12,019.65 अंकों पर बंद हुआ। जबकि उसके बाद सेंसेक्स 11,872.91 अंकों पर आ गया। इसका मतलब है कि सेंसेक्स 1.22 फीसदी यानी 146.74 अंकों की गिरावट के साथ क्लोज हुआ था। जबकि निफ्टी 3,635.25 अंकों से गिरकर 3,593.45 अंकों पर आ गया था। यानी निफ्टी एग्जिट पोल के असर से 1.15 फीसदी यानी 41.8 अंक टूटा था। साल 2004 और 2009 के विपरीत इस बार एग्जिट पोल्स ने पहली बार एक मैज्योरिटी के संकेत दिए। साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार केंद्र की राजनीति में देखे गए। 12 मई को आखिरी फेज के मतदान हुए थे। उसके बाद जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए, उससे किसी को कोई हैरानी नहीं हुई। कोई ऐसा एग्जिट पोल नहीं था जो एनडीए को फुल मैज्योरिटी देता हुआ ना दिखाई दिया हो। सभी ने एनडीए को 272 से लेकर 340 तक सीटें दीं। वहीं यूपीए का एग्जिट पोल में आंकड़ा 150 सीटें भी देता हुआ दिखाई नहीं दिया। कुछेक ने तो यूपीए को 100 से नीचे भी उतार दिया।

एग्जिट पोल के आंकड़ें एक्सपेक्टिड थे। इसलिए इन आंकड़ों का शेयर बाजार पहले ही डाइजस्ट कर चुका था। ऐसे में एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में कुछ ज्यादा हरकत देखने को नहीं मिली। 12 मई को सेंसेक्स 23,551 अंकों पर बंद हुआ। उसके बाद 13 मई को सेंसेक्स में 1.36 फीसदी यानी 320.23 अंकों की तेजी देखने को मिली। वहीं निफ्टी 7,014.25 अंकों से 7,108.75 अंकों पर आ गया। यानी निफ्टी 1.35 फीसदी यानी 94।5 अंक बढ़त के साथ दिखाई दिया।

साल 2019 लोकसभा चुनाव कई मामलों में दिलचस्प रहा। उससे पहले देश में डिमॉनिटाइजेशन हुआ था। जीएसटी को लागू किया गया था। जिसे विपक्ष ने काफी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। चुनाव से पहले देश में बालाकोट हमला हुआ था। उस वक्त देश ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। उसके बाद देश में एक लहर चली जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। चुनाव का आखिरी फेज 17 मई 2019 को हुआ था। उसके बाद एग्जिट पोल सामने आए वो अपने आपमें काफी अप्रत्याशित थे। एग्जिट पोल में भाजपा को 300 से ज्यादा और एनडीए को 350 से ज्यादा मिलती हुई दिखाई गई। वहीं यूपीए 2014 के एग्जिट पोल के आंकड़ों से भी नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दिया।

इसका असर भी शेयर बाजार में काफी बड़ा दिखाई दिया। एग्जिट पोल आने के दो दिन के बाद जब शेयर बाजार ओपन हुआ था तो पौने चार फीसदी की तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 17 मई को 37,930.77 पर था। 20 मई को जब बाजार खुला तो सेंसेक्स 3.75 फीसदी यानी 1,421.9 अंकों की तेजी देखने को मिली और 39,352.67 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 20 मई को 3.69 फीसदी यानी 421.1 अंकों की तेजी के साथ 11,828.25 अंकों पर बंद हुआ।

अब सभी की नजरें 3 जून को शेयर बाजार पर रहेंगी। एग्जिट पोल आने के बाद पहली बार शेयर बाजार उसी दिन ओपन होगा। अगर ऊपर दिए चार चुनाव के एग्जिट पोल और उसके बाद शेयर बाजार पर पड़े असर को मानें तो 3 जून को शेयर बाजार तेजी और नुकसान दोनों तरफ जा सकता है। अगर एग्जिट पोल में आंकड़े हंग पार्लियामेंट के दिखाई देते हैं तो शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर किसी एक गठबंधन यानी एनडीए या इंडिया में किसी एक को फुल मैज्योरिटी मिलती है तो शेयर बाजार पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। वहीं शेयर बाजार की नजरें पोल्स में भाजपा के परफॉर्मेंस पर भी होंगी। अगर भाजपा को पोल्स में बहुमत के आंकड़ें को ही नहीं बल्कि अपने पिछले आंकड़ों से भी पार करती हुई दिखाई देती है तो शेयर बाजार में तेजी बन सकती है। अगर भाजपा पोल्स में बहुमत के आंकड़ें से नीचे रहती है तो शेयर बाजार डगमगा सकता है।

शेयर बाजार के एक जानकार बताते है कि ये पता नहीं होगा कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन संभव है कि भाजपा या एनडीए के गठबंधन वाली सरकार बनेगी। लेकिन ये एडजस्टमेंट वाली सरकार बनेगी, जोकि बाजार को पसंद नहीं। इससे बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है। बाजार में 10 पर्सेंट तक की गिरावट आ सकती है।

ऊपरवाला अब छप्पड़ नहीं जमीं फाड़ के देता है?

-आत्माराम यादव पीव वरिष्ठ पत्रकार

एक बहुत पुरानी कहावत है ऊपरवाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर मुझे यकी नहीं, हाँ मुझे कपड़ा फाड़ के जरूर मिला है। जब भी पिताजी के कपड़े पुराने हो जाते उन्हे फाड़ कर मेरे लिए नए कपड़े सिल जाया करते थे। कपड़ा फाड़ के आपको भी मिला होगा किन्तु छप्पड़ फाड़ के मिलने वाली बात इसलिए विश्वासयोग्य नही होती कि लोग पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके मरखप जाते है पर वे बिचारे छप्पड़ ही नहीं बना पाते फिर छप्पड़ फाड़ के मिलने कि बात ही निराली है। यदि कहावत है तो इस पर वे यकीन करे जिन्हे मिला है, अगर आपको मिला हो तो आप यकी कर सकते है। मजेदार बात यह है कि लोग छप्पड़ फाड़ के लेने का इंतजार कर रहे है पर हमारे यहा जमी फाड़ के, नदी चीर के, जंगल काट के लेने का चलन है। भगवान जमी फाड़ के देता नहीं, पर हाँ वह जमी को हिलाता डुलाता है, जिसमें हजारो लोग मर जाते है, लाखों छप्पड़ जमी में मिल जाते है फिर सोचिएगा अगर उसके जमी हिलाने से इतना विनाश है ओर वह जमी को उलट-पुलट कर देखना चाहे तो समझिए फिर कोई जमी फाड़ने/खोदने वाला, नदी का सीना छलनी करने ओर जंगल काटने वाले या हम तब हाँ होंगे? हमारे यहा जंगल है, नदी है पहाड़ है, खेत है खलियान है जिनसे लोगों को मिलता है, पर छप्पड़ फाड़ के जैसा नहीं, क्योकि अगर छप्पड़ फटेगा तो एक ही बार मिलेगा, इसलिए हमारे यहा के लोग चतुर चालक है ओर वे लेने का मामले में सबके बाप है। वे जिस जंगल को, पहाड़ को नदी को देख ले तो वह सब कुछ उन्हे अपने बाप की ही लगता है, उनका लेना लेना नहीं लूटना है ओर तब तक लूटना है जब तक वह मिट न जाये। पर प्रकृति का स्वभाव है अगर नदी के रेत के साथ नदी खोदोगे तो वह बरसात में मिट्टी साथ लाकर रिक्त स्थान भर लेगी।

इनके बाप दादे प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति में नदी , जंगल, पहाड़ ओर भूमि को ये लोग पूजते थे ओर अपनी जरूरत के हिसाब से ऐसे लेते की किसी को पता ही नहीं चलता था पर इनका मानना है हमारे बाप दादों ने अगर इन्हे पूजा है तो ये सभी भले सरकारी मिल्कियत हो पर हमारी ही रहेगी। हम खुद सरकार है या कहिए हमारी सरकार है तो सरकार के नुमाइंदे हमारे हुये इसलिए हम दिनदहाड़े सबकी आँखों के सामने ट्रालियों से ट्रकों से डंफरो से अपना हिस्सा ले रहे है, तुम्हें चोरी लगता है तो अपनी आँखों का अपने दिमाग का इलाज कराओ। अपना हिस्सा ऊपरवाले से लेते समय अगर नदी के किनारों सहित नदी के तल के रेत को मशीनों से उठवाये, जंगलों के पेड़ काटकर उसे नंगा करें , पहाड़ो में क्रेशर लगाकर गिट्टिया के अंबार लगाये, सरकारी रकबो की जमीन से मिट्टी खोद हजारो डंफर मिट्टी से रोजाना निचले क्षेत्रो में भरपाई कर विकसित करे तो आपका पेट क्यो दुखता है। ये सब इनके बाप की है इसलिए सरकार की सारी मिसनरी इनकी सेवा में खड़ी है। ये चोबीसों घंटे पूरी टीम के साथ नदी के हर तट को खोद रहे है ओर तय है कि इनके बाप दादों के तरह ये दिनरात खोदकर मरखप जाएँगे किन्तु नदी उन्हे इतना दे देगी कि उनकी पीढ़िया मौज करती रहे। जो अपार असीमित दौलत नदी खोदने से मिलती है उसी प्रकार जंगल काटने से, पहाड़ से पत्थर-गिट्टी लेने से, खेत खलियानों को खोदकर भसुया मिट्टी खोद वह कुए बनाकर सड़क किनारे 40 फिट तक का समतल करने में हजारो डंफर दिनरात लगे रहते है, सरकार गांधारी कि तरह पट्टी बांधे रहती है ओर इन प्राकृतिक संसाधनों के नाजायज बाप बने लोग सोने कि चम्मच से खा रहे है। हमारे यहा तो पहाड़ खोद के, जंगल काटकर ओर नदी का सीना चीरकर लेने का रिवाज है फिर ऊपरवाला जब भी देता,देता छप्पड़ फाड़ के कहावत कब से प्रचलित है किसी को ज्ञात नही है ? ओर दुनिया में पहली बार किसे छप्पड़ फाड़ के मिला है ओर उसके बाद कब-कब किसका छप्पड़ फटा ओर उसे मिला है इसका कोई एतिहासिक प्रमाणित लेखा जोखा कही अंकित नहीं है। चलिये हम मनुष्यों के इतिहास की किसी किताब में इसका जिक्र नहीं, पर हमारे ऋषि मुनियों के लिखे वेद पुराण आदि में भी ऐसा एक भी प्रसंग नहीं आया जिससे गर्व से कहा जा सकता था की सच में ऊपरवाला छप्पड़ फाड़ के देता है। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह कहावत किसने किसके लिए लिखी है, यह मुझे पता नहीं ? अगर आपको पता हो ओर इस कहावत के तहत छप्पड़ फाड़ के ऊपरवाले ने आपको या किसी को दिया हो तो प्लीज ज्ञानवर्धन के लिए मेरी जानकारी को तरोताजा अवश्य कीजिएगा।

मुझे ज्ञान है कि जब हमारे घर छप्पड़ था तब हम दादी माँ बड़ी माँ के सयुंक्त परिवार सहित का हिस्सा थे जिसमे हमारे परिवार के 11 सदस्यों सहित बड़ी माँ के परिवार के 15 सदस्य थे ओर कमाने वाले पिताजी, मँझले काका जी थे, बड़ी अम्मा पटेल साहब जिन्हे घर पर सभी पलेटियर के घर गाय दुहने, गोबर उठाने ओर कंडे/उपले थोपने पर मजदूरी ओर रात का बचा खाना मिलता था , यानि पूरा परिवार गरीबी-तंगहाली में जीता रहा। जिन्हे भरपेट खाने को न मिले, फिर ढंग का छूप्पड भी नहीं था, जिन्हे बरसात में टपकों के थेगड़े लगाने में पसीना आता हो, उन्हे मेरे देखते हुये कभी भी छप्पड़ फाड़ के नही मिला। मैं अपने घर में मंझला बेटा हूँ जिसका विवाह कर घर के छप्पड़ से बाहर कर दिया 25 साल किराए के छप्पड़ में गुजारे पर ऊपरवाले ने इतनी औकात नहीं दी कि कहने के लिए अपना छप्पड़ बना लूँ। एक बड़ा बेटा सरकारी नौकरी के बाद सेवानिर्वृत है,उन्होने जरूर घर से बाहर अपनी हैसियत का भवन बना लिया, जीवन भर वे पक्के सरकारी क्वाटर में थे इसलिए उनका छप्पड़ फाड़ कर कुछ मिला हो इसकी खबर नहीं। हाँ एक छोटा बेटा वकालत पास करने के बाद घर में वकील बन घर को ही अदालत बना पिताजी के बनाए पक्के मकान में रह अपनी काबलियत पर विश्वास न कर खाक छान रहा है। चार बहने है सबके घर है। मजाल है किसी कि छप्पड़ फटी हो ओर उन्हे मिला हो, पूरी उम्र बीती जा रही है पर किसी को भी इस कहावत का लाभ नही मिला?

छप्पड़ फाड़ कर मिलने को कोई भाग्य से जोड़ते थे जिनमें मैं भी शामिल था इसीलिए मैं बचपन से अपने भाग्य को आजमाता ओर दुकानों पर चिट निकालकर इनाम जीतने कि शुरूआत करता, तब एक चार्टनुमा बड़ा सा केलेण्डर कि आकृति का चार- पाँच सो कि पचीर्खाना ओर बच्चो को पाँच रुपए जीतने का सुनहर अवसर के नाप पर चलने वाले लाटरीखाना के लिए पाँच पैसे में एक पर्ची निकालकर भाग्य आजमाने का था,उस में कुछ नंबरो पर पाँच पैसे से लेकर पाँच रुपए तक चिपके होते, अगर वे अंक आ जाये तो आप उस राशि को जीत सकते थे, जब भी कोशिश कि पर्ची में 50 पैसे से ज्यादा नही जीते, पाँच रुपए तो भाग्य मे थे ही नही, ओर दुकानदार भी होशियार हुआ करते थे जो किसी बच्चे द्वारा एक दो रुपए जीतने के बाद उसे पैसे नहीं देते ओर पाँच का नोट जीतने का लालच देकर जीते हुये सारे पैसे कि पर्ची निकलवा कर जीता हुआ पैसा हरवा देते थे। छात्र जीवन में सायकाल मोटर साइकल ओर वाइक के लिए स्थानीय दुर्गा कमेटी झकाली कमेटी कि सौ- दो सौ रुपए कि टिकिट खरीदने के बाद भी हार गए ओर बड़े होने पर लाटरी में हजारो रुपए लगाकर ठनठन पाल मदन गोपाल बने रहे। जल बनाया नहीं जा सकता पर बर्बाद कर मिटाया जा सकता है। नर्मदा, गंगा, यमुना सहित सभी जलदायिनी नदिया जीवित इकाई के रूप में है जिसे हम माँ कहते है, पर इन जीवित नदियों की कोख को छलनी कर बड़ी बड़ी मशीनों से रेत निकालने के लिए उनका पेट चीर रहे है। जंगल की कटाई ने पर्यावरण को ध्वस्त कर पहाड़ों ओर जंगलों को पेड़विहीन कर धरती को तवे के माफिक तपने ओर सूर्य को आग उगलने के लिए सारे प्रबंध हम कर चुके है जिसे गंभीरता से लिया जाकर धरती का श्रृंगार की आवश्यकता है। जंगलों को हरा भरा ही नही अपितु फलदार वृक्षों से घना कर जलवायु की शुद्धता के साथ जंगली जानवरों को जंगल में भी भोजन की व्यवस्था कर उनका आवासीय ग्राम शहर की ओर हो रहे पलायन को रोकने से लिए देश की धरा को 100 करोड़ वृक्षो का उपहार देकर उनकी सुरक्षा के सारे इंतजाम करना होगा ओर विशेषकर सभी नदियों में अवैध, अनुचित एवं क्षमता से अधिक उत्खनन पर रोक लगाने की जागरूकता के साथ वे सारे बेहतर उपाय जरूरी है जिससे देश के जंगल, पहाड़, जमीन के साथ सभी जल संसाधनो नदियों, तालाबों की सुरक्षा की जाये तथा जो इसमें जरा सी चूक करे उसे कठोर दंड से दंडित किया जाए ताकि इस प्रकार का अपराध करने का साहस को भी न कर सके।

आत्मनिर्भरता ही मनुष्य के स्वाधीनता की प्ररणा

संजीव ठाकुर

पराधीन सपने हूं सुख नाहीं₹यह लोकोक्ति हर स्वाभिमानी आदमी और स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति को याद रहती है। स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता ही मनुष्य को स्वाधीन बढ़ने की प्रेरणा देती है। आत्मनिर्भरता की स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपनी सुविधा अनुसार पूरा कर सकता है, इसके लिए दूसरों की तरफ मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आत्मनिर्भरता केवल मनुष्य के लिए व्यक्तिगत रूप से ही जरूरी नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए भी अति आवश्यक है ।एक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी जनता को अपनी क्षमता के अनुसार सारी सुविधाएं तथा अन्य जीवन उपयोगी साधन उपलब्ध करा सकता है। भारत स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति सातवें दशक के प्रारंभ के बाद ही खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सका, इसके साथ ही भारत में खुशहाली की स्वाभाविक तौर पर वृद्धि हुई, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि ₹एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है दूसरों से उधार लेकर काम चलाने में नहीं₹,पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है वह अभी तक स्वतंत्रता के बाद से 75 वर्ष के बाद भी संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है, वह कर्जे से डूब गया है और अपने देश में खर्चा चलाने के लिए पूरी दुनिया से उधार मांगते हुए घूम रहा है। पाकिस्तान आत्मनिर्भर नहीं होने का एवं उधार की जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जबकि भारत देश विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस,इंजीनियरिंग और कृषि सेवा, खनिज,स्पेस रिसर्च में पूर्णता आत्मनिर्भर होकर विकसित देशों के बराबर खड़ा हुआ है। यह देशवासियों और देश के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन किसी भी देश की प्रगति विकास तथा और उसके नागरिकों की जिंदगी की जिजीविषा है जिससे वह संघर्ष कर आगे बढ़ता है। इतिहास गवाह है कि किसी भी महान लेखक को महान बनने तक निरंतर मेहनत कर किताबें लिखने का का श्रम करना पड़ा एवं आत्मनिर्भरता की स्थिति में विचार कर अपने विचारों को लिपिबद्ध करना पड़ा तब जाकर वह महानता की श्रेणी को प्राप्त कर सका। इसी तरह कोई छात्र अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे स्वयं परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा एवं परीक्षा में मनोवांछित सफलता प्राप्त कर उसे स्वयं अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में भी मनुष्य को आत्मनिर्भर होकर मेहनत कर दीक्षित सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी।

हमारा देश भारत भी आजादी के बाद से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रेषित हुआ आज स्थिति यह है कि वह विश्व में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। तमाम महापुरुषों के जीवन से भी हमें आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन की शिक्षा मिलती रहती है ।महात्मा गांधी अपना कार्य स्वयं किया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ₹दैव दैव आलसी₹ पुकारा है, तब जाकर उनकी जिंदगी पटरी पर आई और हमें परिश्रम कर आत्म निर्भर होने की शिक्षा प्रदान की थी। दूसरों पर निर्भरता हमें दूसरों का अनुसरण करने के लिए मजबूर करती है। दूसरों पर निर्भर होने से हमें के अनुरूप ही जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। पराधीनता हमारा आत्मविश्वास सृजनशीलता सोचने की शक्ति को नष्ट कर देती है। गुलामी एक अभिशाप होती है, आत्मनिर्भरता की कमी हमें किंकर्तव्यविमूढ़ बना देती है। दूसरों की कृपा पर जीने वाला व्यक्ति जीवन के अक्षय आनंद से वंचित रहता है। खुद के परिश्रम श्रम से आगे बढ़ने वाला देश या व्यक्ति या समाज सदैव प्रफुल्लित आत्म विश्वासी तथा विकास की ओर सदैव अग्रसर रहता है। हमें सदैव अपने अंदर के आत्मविश्वास, छिपी हुई क्षमताओं मनोबल का सहारा लेकर आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को मनुष्य होने का अधिकार प्राप्त होता है। पराधीन देश सामान्य व्यक्ति सदैव पशु तुल्य होते हैं। जिनका अपना कोई विचार या व्यक्तित्व नहीं हो सकता है। कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता -

राम सहायक उनके होते,
जो होते हैं, आप सहायक,
हम सबको स्वयं पर भरोसा रखना आत्मबल बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा देती रहती हैं।आत्मनिर्भरता ही मनुष्य के स्वाधीनता की प्ररणा।

(श्रेष्ठ होने के प्रमुख अवयव)

पराधीन सपने हूं सुख नाहीं₹यह लोकोक्ति हर स्वाभिमानी आदमी और स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति को याद रहती है। स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता ही मनुष्य को स्वाधीन बढ़ने की प्रेरणा देती है। आत्मनिर्भरता की स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपनी सुविधा अनुसार पूरा कर सकता है, इसके लिए दूसरों की तरफ मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आत्मनिर्भरता केवल मनुष्य के लिए व्यक्तिगत रूप से ही जरूरी नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए भी अति आवश्यक है ।एक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी जनता को अपनी क्षमता के अनुसार सारी सुविधाएं तथा अन्य जीवन उपयोगी साधन उपलब्ध करा सकता है। भारत स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति सातवें दशक के प्रारंभ के बाद ही खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सका, इसके साथ ही भारत में खुशहाली की स्वाभाविक तौर पर वृद्धि हुई, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि ₹एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है दूसरों से उधार लेकर काम चलाने में नहीं₹,पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है वह अभी तक स्वतंत्रता के बाद से 75 वर्ष के बाद भी संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है, वह कर्जे से डूब गया है और अपने देश में खर्चा चलाने के लिए पूरी दुनिया से उधार मांगते हुए घूम रहा है। पाकिस्तान आत्मनिर्भर नहीं होने का एवं उधार की जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जबकि भारत देश विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस,इंजीनियरिंग और कृषि सेवा, खनिज,स्पेस रिसर्च में पूर्णता आत्मनिर्भर होकर विकसित देशों के बराबर खड़ा हुआ है। यह देशवासियों और देश के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन किसी भी देश की प्रगति विकास तथा और उसके नागरिकों की जिंदगी की जिजीविषा है जिससे वह संघर्ष कर आगे बढ़ता है। इतिहास गवाह है कि किसी भी महान लेखक को महान बनने तक निरंतर मेहनत कर किताबें लिखने का का श्रम करना पड़ा एवं आत्मनिर्भरता की स्थिति में विचार कर अपने विचारों को लिपिबद्ध करना पड़ा तब जाकर वह महानता की श्रेणी को प्राप्त कर सका। इसी तरह कोई छात्र अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे स्वयं परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा एवं परीक्षा में मनोवांछित सफलता प्राप्त कर उसे स्वयं अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में भी मनुष्य को आत्मनिर्भर होकर मेहनत कर दीक्षित सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी।

हमारा देश भारत भी आजादी के बाद से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रेषित हुआ आज स्थिति यह है कि वह विश्व में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। तमाम महापुरुषों के जीवन से भी हमें आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन की शिक्षा मिलती रहती है ।महात्मा गांधी अपना कार्य स्वयं किया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ₹दैव दैव आलसी₹ पुकारा है, तब जाकर उनकी जिंदगी पटरी पर आई और हमें परिश्रम कर आत्म निर्भर होने की शिक्षा प्रदान की थी। दूसरों पर निर्भरता हमें दूसरों का अनुसरण करने के लिए मजबूर करती है। दूसरों पर निर्भर होने से हमें के अनुरूप ही जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। पराधीनता हमारा आत्मविश्वास सृजनशीलता सोचने की शक्ति को नष्ट कर देती है। गुलामी एक अभिशाप होती है, आत्मनिर्भरता की कमी हमें किंकर्तव्यविमूढ़ बना देती है। दूसरों की कृपा पर जीने वाला व्यक्ति जीवन के अक्षय आनंद से वंचित रहता है। खुद के परिश्रम श्रम से आगे बढ़ने वाला देश या व्यक्ति या समाज सदैव प्रफुल्लित आत्म विश्वासी तथा विकास की ओर सदैव अग्रसर रहता है। हमें सदैव अपने अंदर के आत्मविश्वास, छिपी हुई क्षमताओं मनोबल का सहारा लेकर आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को मनुष्य होने का अधिकार प्राप्त होता है। पराधीन देश सामान्य व्यक्ति सदैव पशु तुल्य होते हैं। जिनका अपना कोई विचार या व्यक्तित्व नहीं हो सकता है। कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता -

राम सहायक उनके होते,
जो होते हैं, आप सहायक,
हम सबको स्वयं पर भरोसा रखना आत्मबल बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा देती रहती हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

हादसों की हद

एक बार फिर वीरवार को जम्मू-कश्मीर में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिर गई। इसमें बाईस लोगों की मौत हो गई और 57 घायल हो गए। डेढ़ सौ फुट गहरी खाई में बस गिरने से राहत-बचाव कार्य में बाधा आई। इतनी गहराई में बस गिरने से यात्रियों के पीड़ा व कष्ट का अहसास किया जा सकता है। ऐसे छोटे-बड़े हादसों में निर्दोष लोगों की मौत की खबरें रोज अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही बस तेज गति के चलते एक कार को बचाने के प्रयास में एक तीव्र मोड़ पर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कतिपय सूचना माध्यमों में चालक को नींद आने की बात भी कही गई। निस्संदेह, ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं के मूल में मानवीय लापरवाही ही होती है। यह विचारणीय तथ्य है कि मैदानी इलाकों से जटिल पर्वतीय मार्गों पर बस ले जाने वाले चालकों को क्या पहाड़ी रास्तों पर बस चलाने का पर्याप्त अनुभव होता है? जो तीखे मोड़ पर वाहन को नियंत्रित कर सकें। दरअसल, जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के चलते पहाड़ी इलाकों में होने वाली दुर्घटनाओं में मानवीय क्षति ज्यादा होती है। वजह साफ है कि गहरी खाई बचने के मौके कम ही देती हैं। यह विडंबना है कि बड़े हादसों के बाद शासन-प्रशासन की तरफ से मुआवजे व संवेदना का सिलसिला तो चलता है लेकिन हादसों के कारणों की तह तक नहीं जाया जाता। यदि हादसों के कारणों की वास्तविक वजह सार्वजनिक विमर्श में आए तो उससे सबक लेकर सैकड़ों लोगों की जान बचायी जा सकती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है। वहीं करीब साढ़े चार लाख लोग इन दुर्घटनाओं में घायल हो जाते हैं। इनमें कई लोग तो जीवन भर के लिये विकलांगता का शिकार हो जाते हैं।

भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों का आंकड़ा पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में नीति-नियंताओं की तरफ से बेमौत मरते लोगों का जीवन बचाने की ईमानदार पहल नहीं होती। हाल के वर्षों में देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हुआ। सड़कें चौड़ी और सुविधाजनक हुई। लेकिन रफ्तार का बढ़ना जानलेवा साबित हो रहा है। कहींङ्ककहीं सड़क निर्माण तकनीकी में चूक भी हादसों की वजह बनने की खबरें आई हैं। वहीं बड़ी संख्या में हादसों की वजह अनियंत्रित रफ्तार, यातायात नियमों का उल्लंघन तथा शराब पीकर वाहन चलाना रहा है। यदि दुर्घटनाओं के कारणों में विस्तार से जाएं तो वाहन चलाने के अनुभव के बिना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना व ट्रक चालकों की आंखों की नियमित जांच न होना भी सामने आता है। दरअसल, वाहनों की फिटनेस, सार्वजनिक वाहन चालकों के स्वास्थ्य की नियमित जांच तथा निर्धारित समय तक ही वाहन चलाने की अवधि भी तय की जानी चाहिए। कई सर्वेक्षण बताते हैं कि चालक की नींद पूरी न होने और उसे पर्याप्त आराम न मिलने से हादसा हुआ। चिंता की बात यह भी है कि लोग रात में सफर करना सुविधाजनक मानने लगे हैं। जबकि रात को वाहन चलाना कई मायनों में असुरक्षित होता है और किसी हादसे के बाद पर्याप्त सहायता व उपचार न मिलना जानलेवा साबित हो सकता है। इन दुर्घटनाओं का दुखद पहलू यह है कि मरने वाले में अधिकांश युवा व परिवार के कमाने वाले सदस्य होते हैं। हादसे के बाद पूरा परिवार गरीबी के दलदल में चला जाता है। यह राष्ट्र की बड़ी आर्थिक क्षति होती है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि यदि भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या रोकी जा सके तो देश के सकल घरेलू उत्पाद में तीन फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। नीति-नियंताओं को इस बात पर भी विचार करना होगा कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में वाहन कम होने के बावजूद सड़क दुर्घटनाएं इतनी बड़ी संख्या में क्यों होती हैं?

कारगर योजना ही कर सकेगी तापमान से मुकाबला

भारत के 114 शहरों पर आधारित आईआईटी भुवनेश्वर द्वारा किया हालिया सर्वेक्षण बताता है कि शहरों में गर्मी की तीव्रता भारत के शेष भूभाग की आबादी वाले इलाकों की अपेक्षा लगभग दोगुणी महसूस होती है। उत्तर-पश्चिमी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी भारत में भूमि सतह के रात्रि-तापमान में बढ़ोतरी अधिक पाई गई है। आईआईटी-गांधीनगर द्वारा करवाए अध्ययन में चेतावनी दी गई कि तेजी से हो रहे शहरीकरण की वजह से बने 'शहरी गर्म टापुओं' से भारतीय नगरों में गर्मी की तीव्रता और बदतर होगी।

भारत के उत्तर पश्चिमी, मध्य, हिमालयी अंचल और महाराष्ट्र में इन दिनों झुलसाने वाली ग्रीष्म लहर चल रही है। मंगलवार को हरियाणा के सिरसा और राजस्थान के चुरू में पारा 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के अधिकांश भाग में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। अनेक सूबों में अस्पतालों में गर्मी संबंधित मामलों में उछाल आया है और कुछ राज्यों में लू लगने से मौतें भी दर्ज हुई हैं। फिल्मी सितारे शाहरुख खान को भी गर्मी से पीड़ित होने के बाद अहमदाबाद के अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के अलावा तीव्र गर्मी का असर अनेकानेक क्षेत्रों की उत्पादकता पर होने लगा है, जिसका आगे अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव होगा। महज यह हिदायतें जारी करना कि लोग घर के अंदर बने रहें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, नाकाफी है। तापमान के उछाल को नाथने के लिए हमें बृहद नीति बनाने की जरूरत है, जो आज की तारीख में नदारद है।

अलबत्ता तापमान संबंधी सटीक पूर्वानुमान और चेतावनियों के साथ मौसम विभाग का काम प्रशंसनीय है। एक मार्च को इस विभाग ने मार्च से मई की अवधि के लिए तापमान संबंधी अग्रिम पूर्वानुमान जारी किया था। इसमें देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहना बताया गया था। एक अप्रैल को जारी किए संशोधित पूर्वानुमान में जून माह तक के लिए सामान्य से अधिक गर्मी रहने का अनुमान वाले अंचलों की इलाकावार जानकारी अधिक तफ्सील से दी गई। इसमें चेतावनी दी गई कि लंबे समय तक खिंचने वाली अत्याधिक गर्मी के सत्र से शरीर में जल की कमी हो सकती है और बुनियादी तंत्र जैसे कि पॉवर ग्रिड और परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इन चुनौतियों का हल निकालने के लिए, यह जरूरी है कि प्रशासन सक्रिय होकर उपाय करे। सरकारी की एक अन्य एजेंसी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, मौसम में बदलावों एवं मानव स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित करती है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जारी परामर्श पत्र में एक भाग गर्मी संबंधित रोग पर है, इसमें ध्यान का केंद्र लोगों की भीड़ वाले आयोजन और खेल प्रतियोगिताओं पर है जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग, जो 22 मार्च को शुरू होकर 26 मई को खत्म हुई। इस दौरान सात चरणों वाली लोकसभा चुनावी प्रक्रिया 19 अप्रैल से आज तक चलनी है। अत्यधिक गर्मी झेल रहे इलाकों में मतदाताओं की संख्या उम्मीद से कम रही। कुछ मौकों पर चुनाव प्रचार कर रहे प्रत्याशी तीव्र तापमान की वजह से बेहोश भी हुए हैं। बेशक आईपीएल के मैच देर शाम को शुरू होते हैं लेकिन अधिकतर वक्त दर्शक आमतौर पर दोपहर से ही दीर्घा में जमने शुरू हो जाते हैं। इस समय तापमान सबसे ज्यादा उरोज पर होता है और खिलाड़ी भी अभ्यास दिन में करते हैं। बड़ी भीड़ वाले आयोजनों के लिए जारी हिदायतों की भांति शहरों को अपनी ग्रीष्म कार्य योजना बनाकर अमल में लाना चाहिए। इस किस्म की योजनाओं में लू का स्वास्थ्य पर प्रभाव संबंधी सार्वजनिक जागरूकता बनाना, जरूरत बनने पर गर्मी संबंधित रोग से निपटने को पूर्व तैयारी करना शामिल हो। संबंधित तमाम सरकारी एजेंसियों को आपसी तालमेल बनाकर, लोगों में लू लगने की संभावना में कमी लाने संबंधी जागरूकता बनाना एवं निदान उपाय अपनाने का अभियान चलाना चाहिए। छांव देने वाले ढांचे तैयार किए जाने चाहिए। खुले में शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों के काम करने के घंटे इस तरह तय हों ताकि वे तीव्र धूप का शिकार बनने से बचें। केंद्र सरकार के कहने पर भीड़भाड़ वाले आयोजनों के लिए जिस किस्म की निर्देशावली बनी है, वैसी बहुत से शहर और सूबे अपने यहां नहीं कर पाए। जबकि अहमदाबाद का प्रमाण प्रत्यक्ष है, जहां पर 2013 से अपनाई कार्य योजना से तीव्र गर्मी संबंधित मृत्यु दर में कमी आई है। तेलंगाना और ओडिशा ने भी अपनी तापमान कार्ययोजना बना रखी है लेकिन इन योजनाओं का असर इन पर अमल करने की दक्षता पर निर्भर करता है।

यह तथ्य है कि शहरों में गर्मी की तीव्रता स्थानीय कारक जैसे कि जनसंख्या घनत्व, कंक्रीट ढांचों की सघनता, पेड़ों की संख्या में कमी इत्यादि से भी संबंधित है। कई सालों से वैज्ञानिक 'शहरी गर्म टापू' के बारे में कहते आए हैं, जिसमें शहर का एक भाग विशेष अन्य इलाकों की अपेक्षा ज्यादा तप जाता है। इन 'शहरी गर्म टापुओं' के पीछे स्थानीय अवयव जैसे कि हरियाली और तालाबों की कमी, स्थानीय औद्योगिक गतिविधियां, गर्मी सोखने वाले कंक्रीट के भवन, हवा के आरपार निकलने के इंतजाम में कमी और एयर कंडीशनरों से निकली गर्म हवा तापमान बढ़ाती है। मसलन, दिल्ली की घनी आबादी वाला सीताराम बाज़ार हो या फिर कनाट प्लेस या भीकाजी कामा प्लेस, वहां पारा आसपास के इलाकों से कुछ अधिक ही दर्ज होता है, जिससे कि यह भाग 'शहरी गर्म टापुओं' में तबदील हो जाते हैं।

भारत के 114 शहरों पर आधारित आईआईटी भुवनेश्वर द्वारा किया हालिया सर्वेक्षण बताता है कि शहरों में गर्मी की तीव्रता भारत के शेष भूभाग की आबादी वाले इलाकों की अपेक्षा लगभग दोगुणी महसूस होती है। उत्तर-पश्चिमी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी भारत में भूमि सतह के रात्रि-तापमान में बढ़ोतरी अधिक पाई गई है। आईआईटी-गांधीनगर द्वारा करवाए अध्ययन में चेतावनी दी गई कि तेजी से हो रहे शहरीकरण की वजह से बने 'शहरी गर्म टापुओं' से भारतीय नगरों में गर्मी की तीव्रता और बदतर होगी।

पर्याप्त सबूत बताते हैं कि इस असर को नियंत्रित करने के लिए सरकारी एजेंसियों को गर्मी-कार्य योजना शुरू करनी ही होगी। यह देखते हुए कि ग्रीष्म लहर के दौरान रात के तापमान में इजाफा काफी हुआ है, अप्रत्यक्ष ठंडक उपाय करना जैसे कि हवा की आरपार निकासी, छांव बनाना, गर्मीरोधी एवं सूर्य किरण परावर्तित करने वाली परत चढ़ाना इत्यादि से भवन के अंदरूनी तापमान को नीचे लाया जा सकता है। भवन निर्माण संहिता में ऐसी निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने को बढ़ावा देना चाहिए, जो कम गर्मी सोखने वाली हो। साथ ही यह खूबी लंबे वक्त तक कायम रखने वाली हो ताकि गर्मी सोखने से बने तापमान का स्तर नीचे लाया जा सके। तालाबों की उपस्थिति और हरियाली रात्रिकालीन गर्मी में अतिरिक्त कमी लाने में मददगार हो सकती है। गर्मीरोधक योजना में सुझाव दिया गया है कि निम्न आयवर्ग के घरों की छत ठंडी रहने वाली सामग्री से बनी हो ताकि कमरे के अंदर का तापमान नीचा रहे। हमें ऐसी जन कल्याणकारी नीतियों की जरूरत है जो इस किस्म के गर्मीरोधक उपायों की रूपरेखा और क्रियान्वयन हेतु समन्वित कार्ययोजना को बढ़ावा देते हों। यह नीतियां अनेकानेक क्षेत्रों के लिए विकसित की जाएं जैसे कि स्वास्थ्य, नगर योजना, पर्यावरण, परिवहन, शिक्षा, श्रम, बुनियादी ढांचा, निर्माण, वित्त इत्यादि। क्रियान्वन के लिए, नगर निगमों और शहरी निकायों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाए। वैज्ञानिक बिरादरी, स्थानीय लोगों और सिविल सोसायटी को साथ जोड़ना अहम है। भीषण गर्मी में बढ़ोतरी से निपटने के उपाय केवल मौसम विभाग या स्वास्थ्य क्षेत्र के जिम्मे छोड़ने से यह काम नहीं बनने वाला।

आज का इतिहास

- रूस और ऑस्ट्रिया ने 1746 में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
- कैथोलिक विरोधी प्रदर्शनकारियों ने लंदन में पार्लियामेंट पर 1780 में हमला कर दिया।
- अमेरिका में पहली बार मैने प्रांत में मद्यपान निषेध कानून 1851 को लागू किया गया।
- गुगलिएलमो मार्कोनी ने रेडियो को अपने नाम पर पेटेंट कराने के लिये आवेदन 1896 में दिया जो बाद में दो जुलाई 1897 को स्वीकार कर लिया गया।
- एलफ्रेड डेकिन लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 1909 में चुने गए।
- लार्ड लुई माउंटबेटन ने 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की।
- ब्रिटिश राजगद्दी पर महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय की 1953 में ताजपोशी हुई।
- अमेरिका ने 1966 में अपने पहले ही प्रयास में चांद पर अंतरिक्षयान उतारा।
- माली ने अपना संविधान 1974 में अपनाया।
- उक्रेन अपने अंतिम परमाणु युद्धास्त्र रूस को सौंपने के साथ ही परमाणु मुक्त देश 1996 को बना।
- दक्षिण एवं उत्तर कोरिया के बीच उच्च स्तरीय वार्ता पर सहमति, भूटान में टी.वी. प्रसारण की शुरुआत 1999 में हुई।
- म्यांमार की जनतांत्रिक नेता आन सांग सूची की गिरफ़्तारी के बाद देश की सभी शिक्षण संस्थाएँ 2003 में बन्द।
- आस्ट्रेलियाई मॉडल जेनिफ़र हॉकिन्स मिस यूनिवर्स 2004 को बनीं।
- भारत, रूस और चीन का ब्लादीवोस्तोक सम्मेलन 2005 में समाप्त हुई।
- अमेरिका ने दाऊद इब्राहीम तथा उसके संगठन पर 2006 को प्रतिबंध लगाया।
- ई-कोलाई बैक्टीरिया के संक्रमण से 2011 को यूरोप में 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1600 से अधिक लोग बीमार हो गए।
- भारत सरकार ने 2011 को शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपडियों से मुक्ति दिलाने और गरीबों को अपने घर का सपना पूरा कराने में सहायता के लिए राजीव गांधी आवास योजना के पहले चरण को मंज़ूरी दी।
- मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को 2011 की अरब क्रांति के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश देने के आरोप में उम्रकैद की सजा 2012 में सुनाई गई।
- सन 2014 में आज ही के दिन तेलंगाना भारत का 29 राज्य बने।
- 'भारतीय जनता पार्टी' के नेता और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का जन्म 1930 में हुआ।
- प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ अनंत गीते का जन्म 1951 में हुआ।
- भारत के प्रसिद्ध फ़िल्म निर्माता-निर्देशकों में से एक मणिरत्नम का जन्म 1955 में हुआ।
- भारतीय उपक्रमी, नौकरशाह, नेता और प्रसिद्ध सॉफ़्टवेयर कम्पनी 'इन्फ़ोसिस' के सह-संस्थापक सदस्यों में से एक नन्दन नीलेकणी का जन्म 1955 में हुआ।

जैव विविधता बचाने को प्राकृतिक खेती की राह

जैव विविधता को नष्ट करने में ज़हरीले रसायनों का हाथ प्रमुख है। इसी तरह मिट्टी की गुणवत्ता और वातावरण की सात्विकता का नाश भी कीटनाशकों से हो रहा है। इसलिए भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उन्हें कई सहूलियत भी दे रही हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती के उत्पाद महंगे होने की वजह से इनकी बिक्री बहुत कम होती है। सरकारों को इस तरफ गौर करना चाहिए। इससे जहां इन रसायनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है, वहीं जानवरों और पक्षियों को बीमारियों से बचाकर जैव विविधता को बचाने में मदद मिल सकती है।

जैविक खेती के उत्पादों को छोड़ दिया जाये तो भी पीने और खाने की हर वस्तु में कीटनाशक मिलाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक देश का पर्यावरण कीटनाशकों के इस्तेमाल से ज़हरीला ही नहीं हो गया है बल्कि हमारा पीने वाला पानी और भोजन भी ज़हरीला हो गया है। इससे शारीरिक, मानसिक बीमारियां और अपंगता की समस्याएं भी लगातार बढ़ती रहती हैं। एम्स के फार्माकोलॉजी विभाग के अध्ययन के अनुसार, घरों में मच्छरों और काकरोचों को मारने के लिए छिड़के जाने वाले कीटनाशकों का 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर असर बहुत गहरे तक पड़ता है।

बिडम्बना यह कि शिक्षित घरों में भी इसके प्रति कोई खास जागरूकता नहीं है। घरों में महंगे चमकीले सेब, केले, आम, बैंगन, भिंडी, लौकी जैसी इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल, एक नहीं दो-तीन स्तरीय होने लगा है। खेत में जहां इनका उपयोग फसल की वृद्धि के लिए करते हैं, वहीं फसलों के रोगों से बचाव के लिए भी किया जाता है। वहीं चमकदार बनाने के लिए फोलिडज नामक रसायन में इन्हें डुबोया जाता है। इन तीन स्तरों पर कीटनाशकों और रसायनों के इस्तेमाल से जीवन, पर्यावरण, जैव विविधता और कृषि की जमीन पर कितना असर पड़ता होगा?

एक आंकड़े के मुताबिक, 2013-14 में देश के करीब 90 लाख हेक्टेयर जमीन में कीटनाशकों को

छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया, जो उपयोग बढ़कर 2017-18 में 94 लाख से अधिक हेक्टेयर तक में हो गया। इसके अलावा बागवानी और औषधीय खेती में भी कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है जिससे कोई भी फल और जड़ी-बूटी जहरीले रसायनों से सुरक्षित नहीं रह गयी है। ऐसा लगता है जैसे यह मान लिया गया हो कि बगैर जहरीले रसायनों के इस्तेमाल के फसल, विविध उत्पाद और भोजन को खराब होने से बचाया ही नहीं जा सकता है।

मसलन, कई राज्यों में टमाटर की अनेक किस्मों की फसलें उगाई जाती हैं। इनमें रश्मि और रूपाली प्रमुख हैं। हेल्योशिस आर्मिजरा नामक कीड़ा इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस कीड़े की रोकथाम के लिए इसमें रेपलीन, चैलेंजर, रोगर हाल्ट का छिड़काव कई चरणों में किया जाता है। नये वैज्ञानिक शोधों से यह भी पता चला है कि कीटनाशकों के इस्तेमाल से खाद्यान्नों, फलों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों पर भी असर पड़ रहा है। इनकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। नई-नई बीमारियों का जहां जन्म हो रहा है, वहीं पर इंसान असमय बूढ़ा हो रहा है।

भोजन के अलावा पानी को शुद्ध करने के नाम पर भी रसायनों का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। देश के कई शहरों में पीने के पानी में डीडीटी और बीएसजी की मात्रा पाई जाती है। महाराष्ट्र के बोतलबंद दूध के 70 नमूनों में डीडीटी और एल्ड्रिन की मात्रा 4.8 से 6.3 भाग प्रति दस लाख तक पाई जाती है। दिल्ली के लोगों के शरीर में डीडीटी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इसका कारण यमुना का दूषित पानी और रसायनों से दूषित आहार है।

कीटनाशकों के बढ़ते असर का परिणाम यह हुआ है कि जैव विविधता की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगने लगा है। शोध के मुताबिक जिन क्षेत्रों की फसलों में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है, वहां पिछले 50 सालों में कई वनस्पतियां और कीट-पतंगे हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। कई इलाकों का पर्यावरण कीटनाशकों के कारण इतना दूषित हो गया है कि श्वास, त्वचा, दिल और दिमाग संबंधी तमाम बीमारियां आमतौर पर होने लगी हैं। देश के जाने-माने वैज्ञानिक, पर्यावरणविद् और चिकित्सकों के अनुसार कीटनाशकों से शोधित और छिड़काव किये टमाटर, बैंगन और सेब के खाने से किडनी, छाती, स्नायुतंत्र, पाचन अंग और मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ने लगा है।

सेहत के मामले में बच्चों के शारीरिक, मानसिक विकास में उनको दिया जा रहा कीटाणुयुक्त पानी और भोजन बहुत खतरनाक पाया गया है। चिंता की बात यह है कि विज्ञापनों के मकड़जाल में किसान और उद्योग जगत ही नहीं उन परिवारों के लोग भी हैं जो स्वयं को तो वैज्ञानिक सोच का कहते हैं, लेकिन जब पानी और आहार की शुद्धता की बात आती है तो वह भी समझौता कर लेते हैं।

स्थिति यह हो गई है कि परिवार के परिवार कीटनाशकों के असर के कारण कई गम्भीर बीमारियों के चपेट में हैं। लोगों का तर्क यह है कि यदि सभी खाद्यों और पेयों में कीटनाशक इस्तेमाल किये जा रहे हैं तो वे कहां से जैविक खाद्य लाएं। गौरतलब यह भी कि अधिक महंगे जैविक खाद्य को यदि इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए तो गरीब आदमी तो इसके उपयोग करने की बात सोच भी नहीं सकता।

हिमाचल उपचुनाव भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती

जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव सातवें और अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, ध्यान यूपी में 'गैर-यादव' ओबीसी मतदाताओं पर केंद्रित हो गया है, जिनके समर्थन से 1 जून को होने वाले मतदान में 13 सीटों पर मुकाबले के नतीजे सामने आ सकते हैं। अंतिम चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें वाराणसी, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, गाजीपुर, बलिया, सलेमपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश में छह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव एक जून को होंगे, साथ ही चार लोकसभा सीटों के लिए मतदान कांग्रेस के लिए अपनी सरकार बचाने और भाजपा के लिए सत्ता में वापस आने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे उनमें लाहौल और स्पीति, धर्मशाला, सुजानपुर, बड़सर, गगरेट और कुटलेहड़ शामिल हैं। कांग्रेस के सभी छह बागी विधायक फिर से भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। मैदान में छह विद्रोही नेता राजिंदर राणा, सुधीर शर्मा, देविंदर कुमार भुट्टो, चैतन्य शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल और रवि ठाकुर हैं। यदि कांग्रेस के छह दलबदलू विधायक जीत जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भाजपा की संख्या बढ़कर 31 हो जाएगी। हालांकि, यह बहुमत के आंकड़े 35 से अभी भी कम है। ऐसी स्थिति में तीन निर्दलीय विधायकों के समर्थन से भाजपा के सदस्यों की संख्या 34 हो जाएगी। कांग्रेस के बराबर। यही कारण है कि ये छह सीटें मुख्य रूप से मायने रखती हैं। यह हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी पासा पलट सकता है, यह इस पर निर्भर करेगा कि दांव पर लगी इन छह सीटों में से कौन कितनी सीटें जीतता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक सच्चे समाजवादी हैं जो अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में कुछ पुरानी यादें ताजा की कि कैसे जातिगत भावनाओं और परंपराओं ने दूसरी जाति की लड़की से शादी करने के उनके प्रयास को विफल कर दिया था। एक समारोह में बोलते हुए अंतरजातीय जोड़ों के पंजीकरण के लिए वेबसाइट पर सिद्धारमैया ने कहा, 'मैं अंतरजातीय विवाह करना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़की ने इसे स्वीकार नहीं किया' हालांकि, सिद्धारमैया ने अंतरजातीय विवाह की वकालत की और कहा कि अधिक अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि समाज से जातिगत असमानताएं दूर हो जाएं।

जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव सातवें और अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, ध्यान यूपी में 'गैर-यादव' ओबीसी मतदाताओं पर केंद्रित हो गया है, जिनके समर्थन से 1 जून को होने वाले मतदान में 13 सीटों पर मुकाबले के नतीजे सामने आ सकते हैं। अंतिम चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें वाराणसी, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, गाजीपुर, बलिया, सलेमपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। हालांकि, मिर्ज़ापुर में अपना दल के संस्थापक और ओबीसी नेता सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल को भदोही से मौजूदा भाजपा सांसद रमेश बिंद के खिलाफ मैदान में उतारा गया है, जो भाजपा द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद सपा में शामिल हो गए थे। अनुप्रिया के हालिया बयान कि ÷अब राजा ईवीएम से पैदा होते हैं, न कि रानियों की कोख से÷ ने विवाद पैदा कर दिया क्योंकि इसकी व्याख्या शक्तिशाली ठाकुर राजनेता रघुराज प्रताप सिंह पर निशाना साधने के रूप में की गई। पटेल का मुख्य समर्थन पटेल समुदाय से आता है, जो लगभग 3.5 लाख वोटों के साथ मिर्ज़ापुर के मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) ने ब्राह्मण उम्मीदवार मनीष त्रिपाठी को मैदान में उतारा है, जिससे संभावित रूप से ब्राह्मण वोट में विभाजन हो सकता है, जो आमतौर पर भाजपा के पक्ष में है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने परिवार और दोस्तों के साथ दोपहर के भोजन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जो सुर्खियों में है और राजनीतिक परिदृश्य में चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो क्लिप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में दिखाया गया है और भोजन के दौरान बातचीत में, तेजस्वी ने कहा, कि राहुल ने अब तक दो बार मटन खाया है, संभवतः उस समय का जिक्र है जब बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने खाना बनाया था। राहुल गांधी के लिए चंपारण मटन और उन्हें इसकी बारीकियां सिखाई, इस पूरे प्रकरण के दौरान राहुल और तेजस्वी के बीच राजनीतिक चर्चा हुई ।

स्वामी विवेकानंद के सहारे बंगाल पर नजर

इंडिया गठबंधन की चुनाव के बाद की बैठक में मोदी विरोधी गठबंधन के भीतर खींचतान और दबाव का संकेत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून को एक बैठक की घोषणा की थी। इसे तब रद्द कर दिया गया जब ममता बनर्जी ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और यह याद दिलाया कि यह पश्चिम बंगाल में मतदान का दिन है और उन्हें खुद अपने निर्वाचन क्षेत्र कोलकाता दक्षिण में मतदान करना है। जाहिर है, खड़गे बनर्जी के लिए 1 जून की तारीख के महत्व को भूल गए।

ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर पश्चिम बंगाल पर थी जब उन्होंने 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी के प्रतिष्ठित विवेकानंद रॉक मैमोरियल में दो दिनों के ध्यान के साथ अपने व्यस्त चुनाव प्रचार को समाप्त करने का फैसला किया। याद रखें मतदान का आखिरी चरण एक जून को पश्चिम बंगाल में विवेकानन्द स्मारक पर ध्यान करते मोदी की टेलीविजन छवियों के बीच होगा। उस दिन जिन सीटों पर मतदान होगा, वे कोलकाता और उसके आसपास हैं, जहां विवेकानन्द के प्रति गहरी श्रद्धा है। भाजपा पश्चिम बंगाल में पर्याप्त लाभ के लिए प्रयास कर रही है और राज्य के शहरीकृत कोलकाता क्षेत्र में हिंदू वोटों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कोलकाता में मोदी का अंतिम प्रचार अभियान विवेकानन्द के प्रतीकवाद से परिपूर्ण था। उन्होंने श्री शारदा मेयर बारी में पूजा-अर्चना की, जो एक मंदिर है जो शारदा देवी की स्मृति में बनाया गया है, जिन्होंने विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोलकाता से होते हुए पीएम का रोड शो विवेकानंद के पैतृक घर पर समाप्त हुआ जहां उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्रीराम के नारे लगाए। यह सब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के एक वर्ग के बीच हालिया तनाव की पृष्ठभूमि में आता है। उन्होंने इस वर्ग पर दिल्ली में भाजपा नेताओं के प्रभाव में उनके खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। 1 जून को कन्याकुमारी से बंगाल के मतदाताओं के लिए संदेश स्पष्ट और स्पष्ट है।

यह विडंबना है कि कान्स फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतकर भारत को गौरवान्वित करने वाली फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया एक समय अपने मातृ संस्थान फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जाति से बहिष्कृत थीं। 2015 में, गजेंद्र चौहान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए कपाड़िया को निलंबित कर दिया गया था और उनके खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया गया था, जिन्हें मोदी सरकार ने हाल ही में एफटीआईआई निदेशक नियुक्त किया था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि चौहान के पास एफटीआईआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक दृष्टि और अनुभव का अभाव है।

कपाड़िया के अलावा, 35 अन्य छात्रों को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ पुलिस मामले दर्ज किए गए। बाद में निलंबन रद्द कर दिया गया और कपाड़िया को पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी गई। लेकिन कुछ अजीब कारणों से मामले वापस नहीं लिए गए हैं। अब जबकि कान्स पुरस्कार के बाद वह शहर की मशहूर हस्ती बन गई हैं। एफटीआईआई उनकी महिमा का आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। इसने एक बयान जारी कर इसे गर्व का क्षण बताया कि संस्थान के एक पूर्व छात्र ने कान्स में इतिहास रचा है। यह बयान खटास भरा है क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि इतने वर्षों के बाद भी कपाड़िया और उनके सह-छात्रों के खिलाफ मामले वापस क्यों नहीं लिए गए। दरअसल, मामले में अगली सुनवाई 26 जून को होनी है।

इंडिया गठबंधन की चुनाव के बाद की बैठक में मोदी विरोधी गठबंधन के भीतर खींचतान और दबाव का संकेत है। कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने 1 जून को एक बैठक की घोषणा की थी। इसे तब रद्द कर दिया गया जब ममता बनर्जी ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और यह याद दिलाया कि यह पश्चिम बंगाल में मतदान का दिन है और उन्हें खुद अपने निर्वाचन क्षेत्र कोलकाता दक्षिण में मतदान करना है। जाहिर है, खड़गे बनर्जी के लिए 1 जून की तारीख के महत्व को भूल गए।

ऐसा प्रतीत होता है कि वह 1 जून को बैठक बुलाने के लिए दौड़ पड़े क्योंकि उस दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत समाप्त हो रही थी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी जमानत अवधि बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली है और अदालतों ने उनकी याचिका पर ज्यादा सहानुभूति नहीं दिखाई है, तो अब, जब भी इंडिया गठबंधन चुनाव के बाद की रणनीति की योजना बनाने के लिए बैठक करेगा, केजरीवाल गायब हो सकते हैं। यह केजरीवाल और बनर्जी के बीच चयन था और बाद वाला अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

पायनियर
नई दिल्ली, रविवार, 2 जून, 2024

एक बार फिर प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार बननी तयः योगी

सातवें चरण के चुनाव में वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया दावा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश की जनता जनार्दन के प्रबल समर्थन और आशीर्वाद से 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के अलग अलग चरणों मे हुए मतदान का फैसला आएगा तो एक बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बननी तय है। जनता ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में शनिवार को 'पहले मतदान फिर जलपान' के मंत्र का अनुसरण करते हुए गोरखनाथ स्थित प्राथमिक विद्यालय कन्या इंग्लिश मीडियम) के बूथ संख्या 249 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह सात बजे ही बूथ पर पहुंचे मुख्यमंत्री अपने बूथ के पहले वोटर भी बने। मतदान करने के

बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और फिर गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर जलपान किया।

मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों की 57 सीटों पर हो रहा है। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की 13 सीटों महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, घोसी, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली व मिर्जापुर पर भी आज वोट डालें जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आमजन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने-अपने मुद्दे रखे। अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखा। देश के अंदर नई सरकार का गठन करने के लिए मतदाताओं ने सभी राजनीतिक दलों के शासनकाल और कुछ दलों की पूर्व सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए उनका मूल्यांकन किया है। देश के अंदर जो समर्थन मिला है उसको ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, विरासत भी-विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी और युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है, उनको जनता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जनता को यह सुखद अनुभूति होगी देश में मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का पूरी मजबूती से निर्वहन करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोगों ने 10 वर्षों में बदलते हुए भारत को तथा पिछले 7 वर्षों में डबल इंजन की सरकार में नए उत्तर प्रदेश का दर्शन किया है। यहां युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के हर तबके के लिए सुरक्षा, सम्मान और विकास की भावना से जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उससे जनता का आशीर्वाद मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश के अंदर देश के अंदर प्राप्त हुआ है और हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र की इस महापुर में आदि आबादी का शत प्रतिशत आशीर्वाद मोदी को मिल रहा है इसके लिए कारण गिनाते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने शक्ति वंदन अधिनियम, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना आदि योजनाओं से नारी सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि जो दल, जो लोग अपनी हार से पस्त होकर युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य में ही हम सबका भविष्य उज्जवल है और युवाओं को भी इसी लक्ष्य के प्रति मतदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी ने सिर्फ चार जातियों को माना है, युवा, गरीब, महिला व किसान। इनके लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं, उसके लिए जनता पूरा आशीर्वाद दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक-राष्ट्र साधना पर विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे बयानों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिना थके, बिना डिगे, बिना रुके भारत माता की सेवा करने वाले पीएम मोदी की आध्यात्मिक आराधना पूरी तरह राष्ट्र आराधना है। पर जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार और दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की धज्जियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था, जिनके कारनामों से जनता ने उन्हें बार-बार ठुकराया, वे लोग मोदी जी के ध्यान साधना और राष्ट्र आराधना का मखौल भले उड़ा सकते हैं लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में पूरे समर्पण भाव के साथ जुड़ी हुई है। सीएम योगी ने कहा कि मोदी जी की ध्यान साधना का कार्यक्रम राष्ट्र आराधना का हिस्सा है और इसका लाभ भी देश को प्राप्त होगा।

इंडी गठबंधन के दलों की आज होने वाली समीक्षा बैठक के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छा है कि इंडीगठबंधन के दलों के नेता 4 जून के पहले आज बैठकर ठंडई पी लें। क्योंकि, इस गठबंधन में जितने दल हैं 4 जून के बाद उतने ही फाड़ होने वाले हैं। ये सभी तब एक-दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। अच्छा है उससे पहले एक बार ठंडई पी लें, जिससे गालीगलौज कम हो।

समाजवादी पार्टी की तरफ से मतगणना से पहले अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से ईवीएम की रखवाली कराने, निर्वाचन आयोग की मंशा पर प्रकारणतर में उठाए गए सवाल पर भी मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। सीएम योगी ने कहा कि जिनको प्रदेश में 80 सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिले उन्हें किसी न किसी पर दोषारोपण तो करना ही है। ये लोग ईवीएम पर दोषारोपण करते करते थक चुके हैं। अब निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाकर लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि कौन नहीं जानता है कि लोकतंत्र में इनकी कोई निष्ठा नहीं है। यह हल्ला बोल माध्यम से अराजकता फैलाने वाले लोग हैं।

सातवें चरण के दौरान गर्मी से एक पीएसी जवान सहित आठ निर्वाचन कर्मियों की मौत

- मृतक आश्रितों को 15-15 लाख रुपए मिलेगा मुआवजा
- बीते शुक्रवार को भी 25 कर्मियों की गई थी जान

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लोकसभा चुनाव के सातवें व अंतिम चरण के मतदान के लिए तैनात होमगार्ड व पोलिंग पार्टियों में शामिल कर्मियों में से कुल 33 लोगों की मौत की पुष्टी की गई है। लखनऊ में शनिवार को ईवीएम के स्ट्रांग रूम की निगरानी में तैनात एक पीएसी जवान की भी मौत हो गयी। पूर्वांचल में शनिवार को चुनाव ड्यूटी में लगे तीन मतदानकर्मियों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। इनमें दो कर्मचारी मिर्जापुर और एक गाजीपुर का है। शुक्रवार को भी पोलिंग पार्टियों के रवानगी के दौरान बढ़े तापमान से 25 कर्मचारियों की मौत हो गई थी।

मिर्जापुर में कटरा निवासी 48 वर्षीय उमाशंकर नपा में सफाईकर्मी था। पालीटेक्निक में उसकी ड्यूटी लगी थी। वहां लू लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं चील्ह के खुलुआ गांव निवासी सफाईकर्मी 48 वर्षीय लालबहादुर यादव की मझवां के आही मतदान केंद्र पर ड्यूटी थी। अचानक वह जमीन पर गिरा, कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। मिर्जापुर में ही अलग-अलग क्षेत्रों में चार अन्य की गर्मी से मौत हुई है। इधर, गाजीपुर के खानपुर में तैनात सफाई कर्मचारी प्रमोद कुमार की जंगीपुर में चुनाव ड्यूटी के दौरान तबीयत खराब हो गई। वह अचेत होकर गिर गया। जिला अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उधर, बलिया में पंदह ब्लॉक के चक बहाउद्दीनपुर बूथ पर वोट देने आए 60 वर्षीय रामबचन की जान चली गई। वह कतार में खड़े थे, तभी गश खाकर गिर गए। गौरतलब है कि पिछले तीन दिन से लगातार गर्मी की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो रहीं हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि केन्द्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव ड्यूटी में लगे इन कार्मिकों की मौत के बाबत सम्बंधित जिलाधिकारियों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज मिलने के बाद इनके आश्रितों को 15-15 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। शनिवार को गोरखपुर में मतदान के दौरान दो पीठासीन अधिकारियों समेत 12 लोग बेहोश हो गये। प्राथमिक उपचार के बाद अब यह लोग स्वस्थ बताये गये हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बलिया लोकसभा सीट के बूथ संख्या 257 पर मतदान के लिए कतार में लगे एक मतदाता राम बदन सिंह पुत्र गणेश की अचानक मौत हो गयी।

हर चरण में जनता का मोदी के प्रति स्नेह उमड़ता रहाः भूपेन्द्र चौधरी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने शनिवार को भाजपा के राज्य मुख्यालय पर प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के सात चरण शनिवार को संपन्न हो गये हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए गठबंधन के प्रति जो प्रेम दिखाया है उससे मन आह्लादित है। जनता जनार्दन के इस विश्वास के प्रति उनका कोटि-कोटि वंदन और अभिनंदन है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि लोकतन्त्र के इस महापर्व में लगे हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों, सभी मतदान कार्मिकों, सुरक्षाबलों, पुलिसबल के जवानों का भी अभिनंदन है कि उन्होंने निर्बाध रूप से मतदान को संपन्न कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्रीद्वय केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर के पदाधिकारियों तथा भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी ज़िम्मेदारी के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर कमल खिलाने के लिए अपना अनथक परिश्रम किया। मैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सभी का अभिनंदन करता हूँ।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा को मिले जनाशीर्वाद की अनुभूति पहले चरण से ही होने लगी थी। हर चरण में जनता जनार्दन का मोदी के प्रति स्नेह उमड़ता रहा। चार जून को हमें मिलने वाले वोट से इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। चुनाव में जिस तरह से विपक्षी गठबंधन ने बँटवारे की राजनीति की, निम्न स्तर पर उतर कर भाषाई मर्यादायें लांघीं, उसका जवाब जनता ने भाजपा के समर्थन में मतदान करके दिया। चुनाव में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण और युवाओं के लिए किए गये कार्यों के नाम पर चुनाव में जनता के बीच गये थे, जबकि नेता और नेतृत्व विहीन विपक्ष भ्रष्ट नीयत और नीति के नाम पर वोट माँगने निकला था।

चौधरी ने कहा कि भाजपा के नेताओं को जनता ने हाथों हाथ लिया और हर बूथ तक पार्टी के नेता पहुँचे। भाजपा का ही प्रचार चहुंओर रहा। विपक्षी गठबंधन के नेताओं में साहस की कमी रही इस कारण राहुल गांधी और अखिलेश यादव सभी 80 लोकसभा सीटों पर जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाये। भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में किए गये जनहित के कल्याणकारी कार्यों का समर्थन किया और भाजपा के पक्ष में दनादन कमल का बटन दबाया।

अपार जनविश्वास की बदौलत भाजपा प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। बहुत सी सीटों पर विपक्ष की जमानत भी जब्त होने जा रही है। चुनाव में मतदान करने की अपनी सबसे महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी निभाने के लिए प्रदेश और देश की जनता जनार्दन का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन एवं नमन करता हूँ।प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने इंडी गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक के सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक में हार ठीकरा फोड़ने के लिए ईवीएम, सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग तथा चुनाव आयोग की भूमिका को घेरने के लिए चर्चा हुई।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से किया गया अनुपालनः नवदीप

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया गया। 16 मार्च को लोकसभा सामान्य निर्वाचन की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जाँच के लिए 464 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1730 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। 16 मार्च से 31 मई, 2024 तक पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 537 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 4768 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार शांति भंग की आशंका में सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 28,41,285 लोगों को पाबन्द किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये है, जिनमें से 27,02,473 लोगों को पाबन्द किया जा चुका है।

लोकसभा चुनाव-2024

18 दिन अन्य राज्यों में पहुंचे योगी ने 46 कार्यक्रमों में की शिरकत

- कई केंद्रीय मंत्रियों समेत भाजपा के बड़े नेताओं के लिए भी योगी ने पसीना बहाया

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली के दौरान 18 दिन अन्य राज्यों में भी पहुंचे। 12 राज्यों व दो केंद्रशासित प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 46 चुनावी कार्यक्रम किए। इनमें से 44 जनसभा और दो रोड शो शामिल है।

भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ ने कई केंद्रीय मंत्रियों समेत राजग के राष्ट्रीय नेताओं के लिए भी रैली-रोड शो किया। सीएम योगी ने सर्वाधिक 9-9 रैली महाराष्ट्र व बिहार में की। वहीं राजस्थान व छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने यूपी के मुखिया को सिर आंखों पर बैठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को सत्ता सौंपी। राजस्थान में सीएम योगी ने चार जनसभा व दो रोड शो किया, जबकि छत्तीसगढ़ में उनकी तीन रैली हुई।

योगी आदित्यनाथ ने सर्वाधिक रैली महाराष्ट्र और बिहार में की। दोनों जगहों पर उनकी 9-9 रैलियां हुईं। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ तीन दिन पहुंचे, जबकि बिहार में उनकी जनसभा पांच दिन हुई। सीएम योगी ने बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट से सांसद, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के लिए एक ही दिन में दो-दो रैली भी की। महाराष्ट्र में भाजपा के साथ ही शिवसेना प्रत्याशियों के लिए भी उन्होंने वोट मांगा। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के साथ ही बाहर के राज्यों में चुनाव लड़ने वाले केंद्रीय मंत्रियों के पक्ष में जनसभा व रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री व महाराष्ट्र की नागपुर सीट से प्रत्याशी नितिन गडकरी, जम्मू की उधमपुर सीट से जितेंद्र सिंह, उत्तराखंड की नैनीताल-उधम सिंह नगर सीट से प्रत्याशी अजय भट्ट, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री व मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट पर चार मई को प्रचार करते हुए योगी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिताने की अपील की। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पक्ष में भी योगी की जनसभा हुई। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के लिए वोट मांगा।

योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के कई बड़े नेताओं के लिए भी पसीना बहाया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए हरिद्वार में पहुंचे। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ सीट से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के लिए रोड शो किया। छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट से भाजपा उपाध्यक्ष सरोज पांडेय के लिए भी योगी ने जनसभा की। पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री व कद्दावर नेता एसएस अहलूवालिया के पक्ष में सीएम ने रैली की। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रुड़ी के लिए सीएम योगी 17 मई को सारण पहुंचे। वहीं नामचीन अधिवक्ता व मुंबई उत्तर मध्य से प्रत्याशी उज्ज्वल निकम के लिए भी उन्होंने वोट मांगा। हरियाणा की दोनों सीट कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और सिरसा से अशोक तंवर के लिए भी योगी 20 मई को पहुंचे। 23 मई को ओडिशा के पुरी से प्रत्याशी व भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा, केंद्रपाड़ा से बैजयंत जय पांडा, पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्वी चंपारण से उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के लिए भी योगी पहुंचे। 28 मई को सीएम योगी ने पटना साहिब लोकसभा सीट पर एक ही दिन में दो बार जनसभा की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के पक्ष में हिमाचल प्रदेश की मंडी में जनसभा की।

सीएम योगी ने यूपी के बाहर भी कई कार्यक्रम कर कमल खिलाने की अपील की। सीएम योगी ने 12 राज्य व दो केंद्रशासित प्रदेश में भी प्रचार किया। इसमें उन्होंने 44 जनसभा और दो रोड शो किया। दोनों रोड शो राजस्थान में हुए। चित्तौड़गढ़ से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी व जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए रोड शो कर सीएम योगी ने कमल खिलाने का संकल्प दिलाया।

मतदाताओं ने लिख दी है भाजपा के पराजय की पटकथाः अखिलेश

सपा प्रमुख ने मतदाताओं का जताया आभार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के सातवें चरण के अंतिम मतदान के दिन मतदाताओं ने भाजपा के विरुद्ध मतदान कर सत्ता से हटाने के लिए पूरी तरह से अपना पूरा आक्रोश निकाल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की पराजय की पटकथा लिखने के साथ ही मतदाताओं ने केन्द्र की सत्ता में आने का मार्ग समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए प्रशस्त कर दिया।

अखिलेश यादव ने कहा कि आज महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बासगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर एवं राबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो गया। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भी मतदाताओं ने उनके प्रति घोर उदासीनता दिखाई। यादव ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण से ही सत्ता परिवर्तन की लहर दिखी। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण अन्याय, अत्याचार, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेतहाशा बेरोजगारी से क्षुब्ध मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर वोट डाला। महंगाई से बुरी तरह परेशान जनता ने भाजपा हटाओं अभियान के तहत पश्चिम से लेकर पूरब तक भाजपा का पूरी तरह से सूपड़ा साफ कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पीडीए इंडिया गठबंधन के पक्ष में पश्चिम से जो हवा चली थी वह सातवें चरण में सुनामी में बदल गयी। किसान, नौजवान, व्यापारी, शिक्षक, कर्मचारी, अधिवक्ता, सहित समाज के सभी वर्गों ने भाजपा को हटाने के लिए वोट डाला। यादव ने कहा कि आज जब मतदान का अंतिम चरण था, भाजपा शासन-प्रशासन का आदतन दुरुपयोग करने से बाज नहीं आई। सत्ता के बल पर मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान में बाधा डालने के साथ पोलिंग एजेंट को धमकाने या भगा देने की तमाम शिकायतें भाजपा के खिलाफ दर्ज हुई है। मिर्जापुर छानवे विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 430, 431 पर प्रशासन ने सीसीटीवी क्यों बंद करा दिया? धीमी गति से मतदान के खिलाफ आवाज उठाने पर पडरौना में पूर्व प्रधान को गिरफ्तार करा दिया गया। बलिया में खराब ईवीएम में मतदान कराया गया। शिकायत पर महिला को धक्का मार कर बाहर कर दिया गया।

वाराणसी के रोहनियां विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 191, 192, 193 पर कांग्रेस के बटन पर टेप लगा दिया गया। बरहज के भाजपा विधायक स्वयं चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ समाजवादियों को धमकाते रहे। फर्जी मतदान की भी शिकायतें बदस्तूर जारी रहीं।

अखिलेश यादव ने कहा कि कई जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अभद्रता की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रशासन की मंशा समाजवादी पार्टी के समर्थकों को मतदान न करने देने की थी। खेद है कि निर्वाचन आयोग कार्रवाई के मामले में बहुत सुस्त रहा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग के कार्यों में जो पारदर्शिता दिखनी चाहिए थी, उसका अभाव लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। फिलहाल जनता जागरूक है, उसने स्वयं जगह-जगह प्रतिरोध किया है।

हर रैली में दहाड़े योगी, जनता भी लगाती रही जय श्रीराम का जयघोष

- माफिया को उलटा लटकाने से लेकर पाकिस्तान की पैंट गीली जैसे भाषणों ने पार्टी में भरा उत्साह

माफिया, पाकिस्तान और औरंगजेब पर जब-जब गरजे योगी, तालियों, सीटियों और योगी-योगी से गूंजा पंडाल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

दो माह से भी अधिक चले चुनाव प्रचार कार्यक्रम और सात चरण के मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी की नजर 4 जून को आने वाले जनता के फैसले पर है। वहीं इससे पहले 61 दिन में 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में कुल 204 चुनावी कार्यक्रमों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी का जलवा कायम रहा। न केवल जनता उन्हें देखने के लिए घंटों तपती धूप की परवाह किये बगैर जनसभा स्थलों पर डटी रही, बल्कि योगी के मुख से विपक्षियों के लिए निकली हर एक ललकार को भी पब्लिक ने हाथों हाथ लिया और जय श्रीराम के जयघोष से जनसभाओं में जोश में भर दिया। विगत सात साल से यूपी की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक कठोर प्रशासक की भी बनकर उभरी है। प्रदेश से दुर्दांत माफिया साम्राज्यों को उखड़ने वाले योगी के भाषणों में भी उनका यही तेवर देखने को मिला। हर जनसभा में योगी ने माफिया तत्वों को मिट्टी में मिलाने और बेटी व व्यापारी को अभय प्रदान करने की बात कही। मंच से माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात सुनते ही जनता भी जयश्रीराम और योगी-योगी के जयघोष से अपने जोश का हाई पारा दर्ज कराती रही। पश्चिमी यूपी में कभी सक्रिय रहे माफिया तत्वों को शिमला की ठंड याद दिलाने वाले योगी पूर्वांचल में भी गुंडे, बदमाशों और अपराधी तत्वों के खिलाफ जमकर गरजे। यही हाल बुंदेलखंड में हुई चुनावी जनसभाओं में भी देखने को मिला, जब योगी ने सैंड से लेकर लैंड माफिया और डकैतों की नकेल कसने की बात कही। जनता ने हर जगह माफिया के खिलाफ छेड़े गये योगी के संग्राम का एक स्वर से साथ दिया। योगी ने अपनी प्रत्येक रैली में प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल का बखान तो किया ही, इस बीच पाकिस्तान के हालात को भी सीएम ने अपनी जनसभाओं में बखूबी बयां किया। योगी के मुंह से पाकिस्तान के लिए निकलने वाली हर चुनौती ने जनसभा में आई जनता को भरपूर जोश से भर दिया। सीएम ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में बताते हुए अपनी हर रैली में कहा कि मोदी राज में भारत के भीतर अगर कहीं पटाखा भी जोर से फट जाता है तो पाकिस्तान बिना देर किये सफाई देने लगता है, कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ये नया भारत है जो छेड़ता नहीं है और अगर किसी ने छेड़ने की कोशिश की तो उसे छोड़ता भी नहीं है। यही नहीं योगी लगे हाथ देश के अंदर बैठे उन लोगों पर भी निशाना साधते, जो पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं। योगी ऐसे लोगों को मंच से ही सलाह दे डालते कि वो पाकिस्तान जाकर भीख मांगे। इसके बाद तो जनता भी योगी-योगी के नारों से पूरे पंडाल को जोश से भर देती। 2024 के चुनावी महासमर में योगी ने इतिहास के सबसे क्रूर मुगल बादशाह की भी जमकर लानत-मलामत की। कांग्रेस को उसके घोषणापत्र के आधार पर घेरते हुए योगी ने अपनी तकरीबन हर जनसभा में औरंगजेब का जिक्र किया। उन्होंने एक तरफ कांग्रेस के घोषणापत्र को औरंगजेब का जजिया कर बताया, तो वहीं यूपी में औरंगजेब को अपना रोल मॉडल मानने वाले माफिया तत्वों को मिट्टी में मिलाने और कब्र में गाड़ देने वाला भाषण देकर जनता का भारी जोश बटोरा। योगी ने औरंगजेब को काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर का ध्वंसक बताते हुए जनता से भी अपील की कि देश में दोबारा औरंगजेब जैसी मानसिकता वालों को जिंदा नहीं होने देना है। उन्होंने औरंगजेब के लिए यहां तक कहा कि आज कोई भी सभ्य मुसलमान अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसने अपने बाप को जीते जी कैद करके पानी-पानी के लिए तरसाया था और अपने भाई की निर्मम हत्या की थी। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ जहां भी गये वहां के प्रमुख मंदिरों, देवी-देवताओं और वीर स्वतंत्रता सेनानियों को सबसे पहले नमन किया। सीएम योगी का ये अंदाज हर किसी ने हाथों हाथ लिया और उनका सभी जगह

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा | नई दिल्ली। रविवार • 2 जून • 2024 | www.rashtriyasahara.com

पेड़ों का क्या है फिर उग जाएंगे 2047 तक। अभी तो कांवड़ यात्रियों को खुश करना जरूरी है, लेकिन मान लो नहीं भी उगे फिर पेड़, धरती बंजर भी हो गई, और तुम सब गर्मी से मर भी गए, तुम्हारी औलादें हीट-वेव से झुलस ही गईं, पानी के सब सोत सूख भी गए, तब भी धर्म बचा रहेगा यह क्या कम है?
— सुजाता, लेखिका @Sujata1978

विचार

कृषि

भारत डोगरा

किसान हितों की रक्षा करने वाले वैज्ञानिक

आज विश्व स्तर पर कृषि नीति बहुत विवाद के दौर से गुजर रही है। अनेक पश्चिमी देशों में कृषि उत्पादकता अधिक है, पर वहां के साधारण किसान संकट में हैं और हाल में उन्होंने आंदोलन भी किए हैं। उधर, मैक्सिको में सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों से रक्षा के लिए अपने किसानों के साथ आ गई है। किसानों तथा खाद्य सुरक्षा के हितों में सरकार ने जीएम (जेनेटिकली मोडीफाइड) फसलों से स्थानीय खेती को बचाने के लिए एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसमें विश्व के अनेक ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों के कार्य से सहायता मिली है। इस स्थिति में यह स्पष्ट हो गया कि जहां कुछ वैज्ञानिक छोटे किसानों और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं तो कुछ वैज्ञानिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़ गए हैं।

इन स्थितियों में हमें भारत के ऐसे दो कृषि वैज्ञानिकों को याद करना जरूरी है, जो पर्यावरण और छोटे किसानों से जुड़े। वे आज हमारे बीच नहीं हैं पर उनके कार्य से आज भी कृषि की सही राह अपनाने में हमें बहुत मदद मिल सकती है। इनमें से एक महान वैज्ञानिक थे प्रो. पुष्प भार्गव। कुछ समय पहले उनका निधन हुआ। वे सेंटर फॉर सेलयुलर एंड मॉलीक्यूलर बॉयलाजी हैदराबाद के संस्थापक निदेशक रहे और नेशनल नॉलेज कमीशन के उपाध्यक्ष रहे। उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां बहुचर्चित रही हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ यह भी जरूरी है कि जिन बहुत गंभीर खतरों के प्रति उन्होंने बार-बार चेतावनियां दीं, उन खतरों के प्रति हम बहुत सावधान बने रहें। विशेषकर जीएम फसलों के विरुद्ध उनकी चेतावनी बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रो. भार्गव को जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) के कार्य पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया। इस विश्व ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक ने देश को चेतावनी दी कि चंद शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा अपने और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को जेनेटिक रूप से बदली गई (जीएम) फसल के माध्यम से आगे बढ़ाने के प्रयासों से सावधान रहें। उन्होंने इस चेतावनी में आगे कहा है कि इस प्रयास का अंतिम लक्ष्य भारतीय कृषि और खाद्य उत्पादन पर नियंत्रण प्राप्त करना है।

एक लेख बहुचर्चित लेख में प्रो. भार्गव ने लिखा था कि लगभग 500 अनुसंधान प्रकाशनों ने जीएम फसलों के मनुष्यों, अन्य जीव-जंतुओं और पौधों के स्वास्थ्य पर हानिकारक असर को स्थापित किया है और ये सभी प्रकाशन ऐसे वैज्ञानिकों के हैं जिनकी ईमानदारी के बारे में कोई सवाल नहीं उठा है। इस विख्यात वैज्ञानिक ने आगे लिखा है कि दूसरी ओर जीएम फसलों का समर्थन करने वाले लगभग सभी पेपर या प्रकाशन उन वैज्ञानिकों के हैं जिन्होंने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्वीकार किया है, या जिनकी विश्वसनीयता और ईमानदारी के बारे में सवाल उठ सकते हैं। प्रायः जीएम फसलों के समर्थक कहते हैं कि वैज्ञानिकों का अधिक समर्थन जीएम फसलों को मिला है पर प्रो. भार्गव ने इस विषय पर समस्त अनुसंधान का आकलन कर स्पष्ट बता दिया कि अधिकतम निष्पक्ष वैज्ञानिकों ने जीएम फसलों का विरोध ही किया है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि जिन वैज्ञानिकों ने समर्थन दिया है उनमें से अनेक किसी न किसी स्तर पर जीएम बीज बेचने वाली कंपनियों या इस तरह के निहित स्वार्थों से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं, या प्रभावित रहे हैं। आज जब शक्तिशाली स्वार्थों द्वारा जीएम खाद्य फसलों को भारत में स्वीकृति दिलवाने के प्रयास अपने चरम पर हैं, इस समय यह बहुत जरूरी है कि इस विषय पर शीर्ष के विशेषज्ञ प्रो. पुष्प भार्गव की तथ्य और शोध आधारित चेतावनियों पर समुचित ध्यान दिया जाए। दूसरे शीर्ष के कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने किसानों और पर्यावरण की बहुत रक्षा की वे थे डॉ. आर.एच. रिछारिया। डॉ. रिछारिया को भारत में विज्ञान के एक अति प्रतिभावान छात्र के रूप में मान्यता मिली। उनकी विलक्षण प्रतिभा के आधार पर उन्हें कम उम्र में ऊंची कक्षा में दाखिला मिल जाता था तो उनके कद के मुताबिक उनके लिए विशेष सीट की व्यवस्था कक्षा में करनी पड़ती थी।

23 वर्ष की उम्र में वे बिना जरूरी कागज-पत्र के ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट के लिए पहुंच गए। एक बार फिर विशेष प्रतिभा की पहचान के आधार पर उन्हें दाखिला मिला और वे वहां अपनी मेहनत, निष्ठा और प्रतिभा के लिए चर्चित हुए। मात्र 2 वर्ष में उन्होंने डाक्टरेट अर्जित कर ली पर बाद में भारत लौटने के किराए के लिए भी उन्हें सहायता का प्रबंध करवाना पड़ा। कुछ वर्षों पश्चात वर्ष 1959 में वे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के निदेशक नियुक्त हुए और वर्ष 1967 तक इस पद पर रहे। वर्ष 1971 में वे मध्य प्रदेश के चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक नियुक्त हुए और वर्ष 1976 तक इस पद पर रहे। जब भी वे शीर्ष पदों पर नियुक्त हुए उन्होंने बड़ी संभावनाओं वाली नई दिशा दिखाई, सदा याद रहने वाला कार्य किया पर शीघ्र ही षड्यंत्रों का शिकार हुए और ऐसे हालात उत्पन्न किए गए कि उन्हें पद से हटना पड़े।

फिर भी भारतीय सरकार को उनकी जरूरत पड़ती थी तो उन्हें विशेष जिम्मेदारी के लिए बुलाया जाता था। वर्ष 1979 में जब हरित क्रांति की चावल की किस्में विफल होने लगीं तो भारतीय सरकार ने 'टास्क फोर्स ऑन राइस ब्रीडिंग' का गठन किया जिसकी बैठक फरवरी, 1979 में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में रखी गई। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता के लिए विशेष तौर पर डॉ. रिछारिया को बुलाया गया क्योंकि वही ऐसे शीर्ष के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन समस्याओं के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी। इसके बाद फिर वर्ष 1983 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने डॉ. रिछारिया को पत्र लिख कर उन्हें चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना तैयार करने के लिए कहा। डॉ. रिछारिया ने बहुत उम्मीद से यह योजना तैयार कर भेज दी थी पर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक डॉ. रिछारिया चावल की लगभग 20000 किस्मों और उप किस्मों का कोष तैयार करने, क्रन्तक प्रसार विधि का प्रचार करने जैसे बेहद सार्थक कार्यों में लगे रहे, हालांकि उन्हें उनके लिए सरकारी सहयोग पूरी तरह रुक चुका था। इतना ही नहीं, जिन संस्थानों में वे प्रयासरत रहे और जहां उन्होंने चावल की अमूल्य किस्में बड़ी संख्या में एकत्र कीं, उन्हें भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को सुपुर्द कर देने के घिनौने प्रयास भी होते रहे।

आज बहुत जरूरी है कि उनकी मृत्यु के अनेक वर्ष बाद भी उनके योगदान और विचारों को हम याद रखें क्योंकि उनके विचार खेती-किसानी के संकट के समाधान के संदर्भ में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। डॉ. रिछारिया चावल के विशेषज्ञ थे और इस संदर्भ में उन्होंने निरंतरता से एक बात कही कि चावल की खेती का विकास स्थानीय प्रजातियों के आधार पर ही होना चाहिए। चावल की बहुत समृद्ध जैव-विविधता हमारे देश में मौजूद है और किसानों को इस बारे में बहुत परंपरागत ज्ञान है। वे कई पीढ़ियों से इन विविध किस्मों को अपने खेतों पर उगाते आ रहे हैं पर हाल के वर्षों में अनुचित नीतियों के कारण वे परंपरागत बीज तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं अतः इनका संरक्षण अब बहुत आवश्यक है जो किसानों के खेतों पर ही जीवंत रूप से संभव है। उन्होंने रासायनिक कीटनाशक दवाओं को त्यागने और रासायनिक खादों के उपयोग को बहुत कम करने के लिए कहा। उन्होंने रासायनिक खाद और कीटनाशक दवा के अनुकूल नई किस्में लाने के स्थान पर परंपरागत किस्मों में ही बहुत अच्छी उत्पादकता देने वाली किस्मों की पहचान की। ये किस्में रासायनिक खाद और कीटनााक दवाओं के उपयोग के बिना ही अच्छी उत्पादकता देती रही हैं जो तथाकथित हरित क्रांति की अधिक रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग करने वाली किस्मों के बराबर है, या अधिक है।

अपने जीवन के अंतिम दिनों तक डा. रिछारिया चावल की लगभग 20000 किस्मों और उप किस्मों का कोष तैयार करने, क्रन्तक प्रसार विधि का प्रचार करने जैसे बेहद सार्थक कार्यों में लगे रहे, हालांकि उन्हें उनके लिए सरकारी सहयोग पूरी तरह रुक चुका था। इतना ही नहीं, जिन संस्थानों में वे प्रयासरत रहे और जहां उन्होंने चावल की किस्में बड़ी संख्या में एकत्र कीं, उन्हें भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को सुपुर्द कर देने के घिनौने कुप्रयास भी होते रहे। जरूरी है कि उनकी मृत्यु के अनेक वर्ष बाद भी उनके योगदान और विचारों को हम याद रखें क्योंकि उनके विचार खेती-किसानी के संकट के समाधान के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं। डा. रिछारिया चावल के विशेषज्ञ थे और इस संदर्भ में उन्होंने निरंतरता से एक बात कही कि चावल की खेती का विकास स्थानीय प्रजातियों के आधार पर ही होना चाहिए

मीडिया का बनाया जनतंत्र

मीडिया

सुधीश पचौरी

मीडिया ने हर बंदे को 'डेली राजनीति' का खिलाड़ी बना दिया है, और अपने को देश को 'बनाने' वाला समझता है। यही मीडिया का बनाया जनतंत्र है। जब हर आदमी अपने 'अनुमान' के 'सही' होने का दावा करता हो तो यही कहा जा सकता है कि चुनाव अब मात्र चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि एक 'गेम' की तरह हो गया है

इस चुनाव को मीडिया ने जिस व्यापकता से कवर किया है उससे साफ नजर आता है कि अब अपना जनतंत्र नेताओं और दलों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका नियंता आम वोटर है। लगभग सभी चैनलों ने अपने कैमरों और रिपोर्टरों को विभिन्न संसदीय चुनाव क्षेत्रों में भेजकर चुनाव को 'महोत्सव' की तरह बना दिया है। एक चैनल ने 'हेलीकॉप्टर शॉट' तक दिए हैं जबकि एक ने 'रेल रिक्शा रोड' के जरिए इस चुनाव को कवर किया है।

चुनाव की रिपोर्टिंग बताती है कि आज का वोटर खामोश वोटर नहीं है, बल्कि एकदम वोकल वोटर है। विकास, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, आरक्षण बरक्स आरक्षण, जनतंत्र, संविधान आदि मुद्दों पर राय रखता है, और बहस भी करता है। यों अधिकांश वोटरों की भाषा लगभग वही है जो नेताओं के भाषणों और रिपोर्टों में इस्तेमाल की जाती है। हर वोटर के पास वैसे ही तर्क, वैसे ही तथ्य होते हैं जो मीडिया में आ चुके होते हैं। यह समकालीन चुनावी राजनीति का 'जनतंत्रीकरण' है। यहां हर मुद्दा विवादास्पद है और हर आदमी 'राजनीति का पंडित' है। कोई मोदी के 'सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास' में यकीन करता है और कहता है कि मोदी ने गरीबों को 'अभेदभाव' से इतने करोड़ मकान, शौचालय, गैस कनेक्शन, नल से जल, बिजली, पीएम सम्मान निधि, गरीबों को फ्री अनाज आदि दिया तो दूसरा तुरंत प्रति प्रश्न करता है कि क्या दो करोड़ नौकरियां दीं? क्या पंद्रह लाख दिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती सरकार एक से एक बड़े भ्रष्टाचारी के पाप क्यों धो दे रही है...भाजपा हिंदू मुसलमान करती है...विभाजन करती है...संविधान और जनतंत्र को खत्म करना चाहती है...हमें उसे बचाना है...इस तरह हर बहस एक 'विभक्त बहस' है।

हर बहस में वही तर्क दोहरते हैं जिनको नेता-प्रवक्ता बोल चुके होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अपनी सारी सीमाओं के बावजूद मीडिया ने हर आदमी को 'वाणी' दे दी है। हर बंदा उसी मुहावरे में बात करता है जिसे मीडिया ने 'पॉपूलर' कर दिया है। 'जनतंत्र' की भाषा नीचे तक पहुंच गई है। इनमें 'औरतों' की बोली-बानी कुछ अलग नजर आती है। एक चैनल की एक रिपोर्टर अक्सर किसी बस या किसी ट्रेन के डिब्बे में बैठी औरतों से बात करने लगती है। औरतें पहले उसे सुनती हैं, लेकिन तुरंत जवाब नहीं देती। जब रिपोर्टर पूछती है कि क्या विकास हुआ है? तो जवाब में एक शून्य सा उनके चेहरे पर पसर जाता है लेकिन जैसे ही रिपोर्टर पूछती है कि कौन जीत रहा है तो सकुचाते हुए जवाब आता है कि 'मोदी ही आएंगे...'।

इससे स्पष्ट है कि मोदी का नाम नीचे तक पहुंच गया है लेकिन विपक्ष के नेता का नाम नहीं पहुंचा। यदि विपक्ष किसी चेहरे का नाम चलाता तो लोग शायद उसे जान पाते। अब विपक्ष चाहे मीडिया को, उसके संपादकों, एंकरों, रिपोर्टरों आदि को कितना ही 'बिका हुआ', 'सत्ता का दलाल' और 'सत्ता का एजेंडा चलाने वाला', 'सत्ता का रक्षक' बताए, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपनी बहुत सी सीमाओं के बावजूद मीडिया ने उन तमाम मुद्दों को हर व्यक्ति की जुबान पर ला दिया है जिनके बारे में कभी कुछ 'पत्रकार' या 'सेफॉलॉजिस्ट ही अधिकार से बातें किया करते थे/करते हैं। मीडिया द्वारा इस चुनाव के 'चौबीस बाई सात' के कवरेज ने हर व्यक्ति को अपनी तरह का 'चुनाव विशेषज्ञ' बना दिया है। आप कहीं भी जाइए हर बंदा यही पूछता नजर आता है कि कौन जीत रहा है? किसको कितनी सीट मिल रही हैं? एनडीए 'चार सौ पार' होगा कि नहीं? मोदी 'हैट ट्रिक' लगाएंगे कि नहीं? या कि इस बार 'इंडी' गठबंधन ही सरकार बनाएगा? और यदि बनाएगा तो उसे कुल कितनी सीटें मिलेंगी?

इस तरह मीडिया ने हर बंदे को 'डेली राजनीति' का खिलाड़ी बना दिया है, और अपने को देश को 'बनाने' वाला समझता है। यही मीडिया का बनाया जनतंत्र है। जब हर आदमी अपने 'अनुमान' के 'सही' होने का दावा करता हो तो यही कहा जा सकता है कि चुनाव अब मात्र चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि एक 'गेम' की तरह हो गया है, जिसे हर बंदा खेल रहा है। चुनाव परिणामों के बारे में ऐसी आम दिलचस्पी साफ कर देती है कि अब वे जमाने गए जब लोग कहा करते थे कि 'कोउ नृप होइ हमें का हानी...'। अब सब के हित-अहित चुनाव से जुड़े हैं। इसलिए यह चुनाव एक बेहद 'कंटेस्टेड' चुनाव है। तब भी अगर कोई कहता है कि चुनाव में 'गड़बड़' की गई है, कि 'ईवीएम' ने गड़बड़ की है, तो उसे 'जनतंत्र विरोधी न कहा जाए तो क्या कहा जाए?

नौतपा के ये नौ दिन

हीटवेव

डॉ. आर.के. सिन्हा

हीटवेव तब मानी जाती है जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो। हालांकि, यह भी ध्यान दिया जाता है कि जिस तापमान पर हीटवेव घोषित की जाती है, वह क्षेत्र की तापमान जलवायु के आधार पर अलग-अलग होता है

चिलचिलाती गर्मी के कारण देश का एक बड़ा हिस्सा फिलहाल उबल रहा है। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि यह तीव्र गर्मी जून महीने तक जारी रहेगी, और 'महसूस होने वाला तापमान' 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में लू की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। लगभग पूरे देश में यह महसूस होने लगा है। आजकल जब सूरज देवता आग उगल रहे हैं, तब नौतपा शब्द बहुत सुनने में आ रहा है। कुछ लोगों को यह शब्द नया लग रहा है। हालांकि यह बात नहीं है। नौतपा वो नौ दिन होते हैं जब देश में गर्मी अपने चरम पर होती है। इसे 'नवताप' भी कहा जाता है। ये दिन साल के सबसे गर्म दिन भी होते हैं।

2024 में, नौतपा 25 मई को शुरू हुआ और 2 जून तक जारी रहेगा। नौतपा के दौरान, सूर्य सीधे मध्य भारत के ऊपर होता है, जिससे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाती है। इससे अधिक सीधे और तीव्र सौर विकिरण उत्पन्न होते हैं, जिससे भीषण गर्मी पड़ती है। कुछ क्षेत्रों खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। हीटवेव एक लंबी अवधि की अत्यधिक गर्मी होती है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। हीटवेव के दौरान, तापमान किसी विशेष क्षेत्र और समय के लिए औसत तापमान से काफी अधिक हो जाता है। हीटवेव थकावट, स्ट्रोक और गंभीर मामलों में मृत्यु का कारण बन सकती है। याद रख लें कि हीटवेव सिर्फ उच्च तापमान नहीं होती, बल्कि असामान्य तापमान वृद्धि से परिभाषित होती है। उदाहरण के लिए, एक स्थान जहां गर्मियों में सामान्यतः 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, वहां हीटवेव नहीं मानी जाती है, भले ही तापमान 42 या 43 डिग्री तक पहुंच जाए। इसके विपरीत, एक जगह जहां सामान्य तापमान 27 या 28 डिग्री है, वहां हीटवेव मानी जाएगी यदि तापमान 35 डिग्री तक पहुंच जाए।

हीटवेव तब मानी जाती है जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो। हालांकि, यह भी ध्यान दिया जाता है कि जिस तापमान पर हीटवेव घोषित की जाती है, वह क्षेत्र की तापमान जलवायु के आधार पर अलग-अलग होता है।

भारत के कुछ क्षेत्र अपने स्थान और जलवायु के कारण हीटवेव के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। देश के उत्तर-पश्चिमी और मध्य भाग इनमें शामिल हैं। शोधकर्ता बताते हैं कि हीटवेव तब होती है जब वायुमंडल में उच्च दबाव होता है, जो गर्म हवा को नीचे की ओर धकेलता है और इसे जमीन के पास फंसा देता है। यह उच्च दबाव प्रणाली एक ताले की तरह काम करता है जो गर्म हवा को ऊपर उठने से रोकता है, जिससे तापमान और बढ़ जाता है। जब हवा नीचे डूबती है तो वह गर्म हो जाती है, जिससे अत्यधिक गर्मी की स्थिति उत्पन्न होती है।

जलवायु परिवर्तन वैश्विक मौसम पैटर्न में बदलाव करके और लंबी अवधि तक उच्च दबाव की संभावना बढ़ाकर अधिक बार और तीव्र हीटवेव में योगदान देता है। भारत में गर्मियों का तापमान आम तौर पर मई में चरम पर होता है। पाकिस्तान से आने वाली गर्म पश्चिमी हवाएं भी गर्मी में योगदान दे रही हैं। भारत के अन्य हिस्सों में, गर्मियों का तापमान पहले ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है, खासकर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में, जहां अप्रैल का तापमान रिकॉर्ड में सबसे अधिक था। अत्यधिक गर्मी का स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हालिया शोध बताते हैं कि तीव्र और लंबी अवधि तक चलने वाली हीटवेव के दौरान समय से पहले जन्मों में वृद्धि होती है। हीटवेव के कारण सांस लेने में तकलीफ और श्वसन संबंधी स्थितियां बिगड़ने की भी जानकारी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हवा की गुणवत्ता खराब है। उच्च तापमान हृदय और परिसंचरण तंत्र पर भी दबाव डाल सकता है, जिससे दिल का दौरा और अन्य हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। यह भी ध्यान रखा जाए कि जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, हीटवेव के आर्थिक प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। नकारात्मक प्रभाव केवल मानवीय पीड़ा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को भी प्रभावित करते हैं।

नये और विकसित भारत की बड़ी बाधा

भ्रष्टाचार

ललित गर्ग

लोक सभा के सातवें चरण के चुनाव होने के बाद सबकी नजरें चुनाव परिणामों पर जा टिकी हैं। चुनाव परिणाम ही तय करेंगे कि नये भारत, विकसित भारत एवं समृद्ध भारत की तस्वीर क्या करवट लेगी। भ्रष्टाचार एवं उससे उपजे हादसों ने चुनाव के दौरान ही ऐसे वीभत्स दृश्य उपस्थित किए, जो चुनावी मुद्दा न बनना एवं राजनेताओं के बीच इनकी चर्चा न होना, दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा चिंताजनक यह है कि हमारी राजनीति अभी भी विकसित भारत के सपने को आकार देने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट ने भ्रष्टाचार की इतने परतें खोली दी हैं कि उसमें न्यायालय, पुलिस, राजनेता, डाक्टर सभी अपना जमीर बेचते दिखाई दिए हैं। इसी तरह राजकोट एवं दिल्ली की अग्निकांडों ने प्रशासन एवं व्यवसाय में पसरे भ्रष्टाचार की काली परतों को उजागर किया है। इस तरह अस्पताल हो चाहे होटल, गेम जोन या मॉल, सुरक्षा इंतजामों, प्रशासनिक जिम्मेदारी एवं ईमानदारी की खुलकर धज्जियां उड़ती रहेंगी या पुणे की तरह अब बिकते रहेंगे तो विकसित भारत का सपना कैसे आकार लेगा?

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एवं बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरकारी तंत्र की लापरवाही एवं भ्रष्टता से रह-रहकर हादसे होते रहें और उनमें बड़ी संख्या में लोग मरते रहें। दुर्भाग्य से अपने देश में यही हो रहा है। जब कोई बड़ी घटना घट जाती है और उसमें अधिक संख्या में लोग मारे जाते हैं तो शोक संवेदनाओं का तांता लग जाता है और तत्काल कार्रवाई करने के नाम पर उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हीं कारणों से वैसी ही घटना फिर सामने आती है, जैसी पहले हो चुकी होती है, इसका मतलब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से नहीं कर रहा है। व्यवसायी प्रशासन की इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाते हुए मौत के सौदागर बने रहते हैं। यही कारण है कि न तो हादसे कम हो रहे हैं, और न ही उनमें जान गंवाने वालों की संख्या में कमी आ रही है। हादसे दुनिया में हर कहीं होते हैं, लेकिन विकसित और विकासशील देश कम से कम उनसे सबक लेते हैं, और ऐसी व्यवस्था करते हैं, जिससे बार-बार एक जैसे कारणों से हादसे न हों।

लोकतंत्र एक पवित्र प्रणाली है। पवित्रता ही इसकी ताकत है। इसे पवित्रता से चलाना पड़ता है। अपवित्रता से यह कमजोर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अपराध के पैर कमजोर होते हैं पर अच्छे आदमी की चुप्पी उसके पैर बन जाती है। अपराध, भ्रष्टाचार अंधेरे में दौड़ते हैं। रोशनी में लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। हमें रोशनी बनना होगा और रोशनी भ्रष्टता एवं घोटालों से प्राप्त नहीं होती। अपने देश में हर तरह के नियम-कानून हैं, राजनेताओं के बड़े-बड़े संकल्प भी हैं, लेकिन उनके उल्लंघन की जैसी सुविधा यहां है, वैसी शायद ही किसी विकासशील और विकसित राष्ट्र का स्वप्न देखने वाले देश में हो। भारत में लोग किस कदर कदम-कदम पर नियम-कानूनों का धडल्ले के साथ उल्लंघन करते हैं, और सरकारी तंत्र में बैठे लोग उनकी मदद करने या फिर उनके अपराध को ढकने के लिए तैयार रहते हैं, इसका शर्मनाक एवं दर्दनाक उदाहरण पुणे का कार हादसा भी है। यह स्वीकारते कठिनाई हो रही है कि कानून एवं व्यवस्था को संभालने वाले सभी हाथ दागदार हो गए हैं।

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

अब कोई तीसरा निकलकर आये

बतंगड़ बेतुक

विभांशु दिव्याल

जब हम ठीये पर पहुंचे तो झल्लन आंख से अखबार पढ़ रहा था और हाथ से सुरती रगड़ रहा था। हमें देखते ही बोला, 'जुहार ददाजू, आज हमें बड़ी राहत महसूस हो रही है, हमारे मन में सुकून के बीज बो रही है। आप बताइए ददाजू, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, चुनावी चांय-चांय की चकराहट से कुछ परे हट रहे हैं या नेताओं के चलाए बम-बारूद अब भी आपके दिमाग में फट रहे हैं?' हमने कहा, 'हमीं जानते हैं कि नेताओं की दो महीने तक चली गंद उछाल से हमने अपने दिमाग को कैसे बचाया है और जब आखिरी चरण खत्म हो गया है तब जाकर कुछ चैन पाया है। वैसे तू बता, इस बार जनता किसका नगाड़ा बजाएगी, मोदी सरकार रहेगी या जाएगी? मोदी खेमा लगातार दावा कर रहा है कि चार सौ पार जाएंगे और इंडी गठबंधन कह रहा है इस बार इनके डेढ़ सौ भी नहीं आएंगे।' झल्लन बोला, 'ददाजू, अगर हमारे मन की पूछ रहे हो तो हम चाहते हैं कि न इन्हें आना चाहिए न उन्हें आना चाहिए और इन दोनों को ही बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए।' हमने कहा, 'पर झल्लन, चुनाव हो गये हैं तो कुछ न कुछ परिणाम तो आएगा ही, कोई न कोई तो सरकार बनाएगा ही, जब एक बाहर जाएगा तो दूसरा अंदर आएगा ही। और वैसे भी तू भी तो किसी को वोट देकर आया होगा और जिसको वोट देकर आया होगा उसको जिताने का मन भी बनाया होगा।

तो हम वही पूछ रहे हैं कि इस बार तू किसको वोट देकर आया है और तूने किसकी जीत पर दांव लगाया है?' झल्लन बोला, 'ददाजू, न हमने इसकी जीत का दांव लगाया है और न उसकी हार का अंदाज लगाया है और हमारी बात तो ये है ददाजू कि हमने अपने तईं सिर्फ नोटा का बटन दबाया है।' हमने कहा, 'नोटा का बटन तो वो दबाता है जिसे न ये पसंद आता है न वो भाता है। अगर तू नोटा दबाकर आया है तो इसका मतलब हुआ कि न तो तुझे इंडी गठबंधन पसंद आया है और न राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तुझे रास आया है।' झल्लन बोला, 'सही पकड़े हो ददाजू, न हमें इस गठबंधन वाले पसंद आ रहे हैं न उस गठबंधन वाले पसंद आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों अपने बेलगाम, बेहूदे, बेसिरपैर के वादे-बयानों से हमारे दिमाग का दही बना रहे हैं।'

हमने कहा, 'हम चाहते हैं कि तू थोड़ा साफ-साफ बताए और दोनों में से तुझे कोई रास क्यों नहीं आ रहा है, हमें थोड़ा ठहरकर समझाए।' झल्लन बोला, 'ददाजू, हमें लगता है इस चुनाव में दोनों ने ही झूठ की नदियां बहायी हैं और दोनों ने ही एक-दूसरे पर अभद्र बोली-वाणी की गोलियां चलायी हैं। एक पक्ष ने हिंदुओं के पक्ष में खड़े होकर नफरत फैलायी है तो दूसरे ने मुसलमानों को साधने के लिए नफरत बढ़ायी है। दोनों ही तरफ के नेताओं ने अपनी जुबान को लगाम नहीं लगायी, न भाषा की मर्यादा दिखायी न शिष्टता-शालीनता की परंपरा निभायी। दोनों ही पक्ष के नेता एक-दूसरे को चोर बताते रहे, एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे, दूसरे को गद्दार तो खुद को सच्चा देशभक्त बताते रहे। दोनों ही पक्ष जनता को डराते रहे कि ये सत्ता में आ जाएगा तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा और अगर वो सत्ता में आ गया तो लोकतंत्र मिट जाएगा।

दोनों ही जनता के आगे ऐसे-ऐसे लुभावने लालच फेंकते रहे कि जनता उन्हें जिता दे तो जनता के लिए स्वर्ग उतार लाएंगे, खटाखट गरीबी मिटाएंगे, फटाफट रोजगार दिलाएंगे, जनता के मौजूदा दुख-दर्द अतीत की बात हो जाएंगे। दोनों ने ही जनता को बेवकूफ बनाने में, उसे असंभव सपने दिखाने में और सच्चाई से दूर हटाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और ऐसा करने में दोनों ने ही सभ्य व्यवहार की हर परंपरा तोड़ी है...।' हमने झल्लन को टोका, उसकी रौ में उसे रोका और कहा, 'झल्लन, तू तो अपनी ही हांके जा रहा है, अपनी दुनाली बंदूक दोनों तरफ दागे जा रहा है पर तेरी इस सोच से आखिर निकलकर क्या आएगा, दोनों को गरियाकर तू क्या पाएगा? माना दोनों पक्ष ही राजनीति के स्तर को गिरा रहे हैं, लोकतंत्र की गरिमा घटा रहे हैं, समूहों-सम्प्रदायों के बीच नफरत बढ़ा रहे हैं, विरोधी को गिराने के लिए खुद को आसमान पर चढ़ा रहे हैं, जनसमूहों को समझदार नहीं मूर्ख, उग्र और उद्दंड बना रहे हैं, पर सत्ता में तो इन्हीं में से कोई एक आएगा, इन्हीं में से कोई एक देश चलाएगा। तुझे काम तो इन्हीं दोनों में से किसी एक से चलाना पड़ेगा, तुझे राहत देने कोई तीसरा तो नहीं आएगा।'

झल्लन बोला, 'सच कहें ददाजू, यही तो हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं पर करें क्या, इसी सवाल पर फंस जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश में सचमुच कोई तीसरी ताकत उभर आये जो समूची राजनीतिक बेहू्दी को झाड़-बुहारकर ठिकाने लगाए और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चालाकी-मक्कारी के जनता के हितों को आगे बढ़ाए, लोगों को ललचाए-फुसलाए नहीं बल्कि उन्हें बेहतर भविष्य के संघर्ष का भागीदार बनाए।' हमने कहा, 'तथास्तु वत्स! तेरा सपना साकार हो, देश का उद्धार हो।'

झल्लन बोला, 'ददाजू, हमें लगता है इस चुनाव में दोनों ने ही झूठ की नदियां बहायी हैं और दोनों ने ही एक-दूसरे पर अभद्र बोली-वाणी की गोलियां चलायी हैं। एक पक्ष ने हिंदुओं के पक्ष में खड़े होकर नफरत फैलायी है तो दूसरे ने मुसलमानों को साधने के लिए नफरत बढ़ायी है। दोनों ही तरफ के नेताओं ने अपनी जुबान को लगाम नहीं लगायी, न भाषा की मर्यादा दिखायी न शिष्टता-शालीनता की परंपरा निभायी। दोनों ही पक्ष के नेता एक-दूसरे को चोर बताते रहे, एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे, दूसरे को गद्दार तो खुद को सच्चा देशभक्त बताते रहे। दोनों ही पक्ष जनता को डराते रहे कि ये सत्ता में आ जाएगा तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा और अगर वो सत्ता में आ गया तो लोकतंत्र मिट जाएगा। दोनों ही जनता के आगे ऐसे-ऐसे लुभावने लालच फेंकते रहे कि जनता उन्हें जिता दे...

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-33, अंक 289
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

जीवन की बैलेंस शीट : अचल संपत्ति-स्वास्थ्य, संबंध, चरित्र; निवेश-समय, ज्ञान, प्रयास; जमापूंजी एवं अतिरिक्त कोष-ऊर्जा, प्रतिभा, इच्छा; व्यय एवं क्षति-नाकामी, अवसर की चूक, दुख; लाभ-खुशी; मूल्यह्रास-आयु/*अच्छी बैलेंसशीट बनाएं।*

—हर्ष गोयनका उद्योगपति@hvgoenka

विमर्श

अनिल चमड़िया

सोने के बदले कर्ज की चमक का सच

एक समाचार एजेंसी ने कुछ समय पहले इंदौर की एक खबर प्रसारित की। इंदौर के 1000 दुकान वाली सर्राफा मंडी में निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवार के सदस्य घरों में रखे सोने के गहने बेचने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मंडी में 100 में साठ लोग गहना बेचने वाले होते हैं। वे ऐसे लोग हैं, जो कोविड -19 के इलाज में अपनी जमा पूंजी खो चुके हैं, या फिर कोविड-19 से निपटने के नाम पर किए गए लॉकडाउन से अपनी नौकरियां खो चुके हैं, या फिर नौकरी करने वालों की पगार मालिक ने आधी-अधूरी कर दी है।

सोना बेचने क्यों निकल रहे हैं लोग : पूरे देश में वही स्थिति है जो इंदौर की खबर में बताई गई है। सोना बेचने से पहले भी एक स्थिति से हम गुजर चुके हैं लेकिन उसकी खबर नहीं बनी थी। होता यही है कि चेतावनी को हम नहीं भांप पाते हैं तो झटके सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। बेचने से पहले की स्थिति सोने की गिरवी रखने की है। बड़ी संख्या में निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों ने कर्जा लेने के लिए अपने घरों में कड़ी सुरक्षा में रखे गए सोने के गहने गिरवी रख दिया है। पहले लोग अपने सोने के गहने अपने आसपास के महाजनों और सर्राफा बाजार में रखते थे। गहनों को किसी घर में आई किसी खास विपत्ति या समस्या के कारण गिरवी रखा जाता था। लेकिन नई अर्थव्यवस्था बनाई गई है। यह कि सोना छोटे हजारों महाजनों और सर्राफा बाजार में जो रखा जा रहा है उन गहनों को गिरवी रखवाने के बैंक खोल दिए जाने चाहिए। देश में दनादन कई गोल्ड लोन बैंक खुल गए हैं। बैंक मतलब हजार महाजन की जगह एक बड़ा महाजन। जैसे सैकड़ों छोटे-मोटे अमीरों की जगह कोई एक अंबानी और अडानी।

सोना गिरवी रखने वाले इन्हीं निजी बैंकों के विज्ञापन दनादन हाल के दिनों में निकले हैं। एक बार के विज्ञापन में हजारों परिवारों के सोने के गिरवी रखे गए गहनों की नीलामी की सूचना होती है। सामान्य दिनों में जब गहने गिरवी रखे जाते हैं तो यह उम्मीद होती है कि गिरवी रखी चीजें छुड़ा ली जाएंगी। इस तरह की उम्मीद कोई व्यक्ति तब कर सकता है जब अर्थव्यवस्था में संभलने का उसे भरोसा हो। लेकिन जब गिरवी रखने वालों के लिए बैंक खुलने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए हालात ठीक नहीं रह गए हैं यानी व्यक्ति नहीं, समाज का बड़ा हिस्सा संकट के अर्थ ढांचे में फंस चुका है। भले ही गिरवी रखी चीजों को छुड़ा लेने की उम्मीदें एक साथ सभी ऐसे लोग करें लेकिन वे सच को झुठलाने के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि गिरवी रखने की नौबत से यदि आबादी का बड़ा हिस्सा घिर गया है तो जाहिर है कि अर्थव्यवस्था उसकी इस उम्मीद के लिए नाकाफी हो चुकी है।

इस तरह गिरवी रखने वालों की तादाद का बढ़ना, बैंकों का खुलना, गहनों की नीलामी का विज्ञापन छपना एक नई अर्थव्यवस्था के ढांचे की पहचान बनती है। इसे आगे नोटबंदी और कृषि कानूनों के संदर्भ में भी समझने में मदद मिल सकती है। गिरवी के गहनों की नीलामी के हालात के बाद गहनों की ब्रिक्री के लिए निकली भीड़ यह बताती है कि गिरवी गहनों को छुड़ा लेने की उम्मीद भी नहीं बची। यह भी बताती है कि लोगों के पास अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की लाचारी में गहनों को बेच देने के अलावा कुछ और सूझ रहा है। घर में पहले बचत के पैसे खर्च किए जाते हैं। फिर जमीन-घर बिकती है। फिर गहनों की बारी आती है।

अर्थव्यवस्था खुद नहीं बनती, अर्थव्यवस्था बनाई जाती है। एक तरह की अर्थव्यवस्था यह बनाई जा सकती है कि घरों में बचत हो, लोगों को रोटी, कपड़ा, घर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा की सुविधा हो। दूसरी अर्थव्यवस्था यह बनाई जा सकती है कि घरों में जो बचत है, जमीन-जायदाद है, सोना-चांदी है, परिवारों के पास उत्पादन का कोई तंत्र है, उन्हें कैसे एक दो बड़े महाजनों के नियंत्रण में लाया जा सकता है।

सोना गिरवी रखने से पहले आम घरों की स्थिति : लोग भविष्य की सुरक्षा और बेहतरी के लिए मुख्यत जमीन या घर, नगदी बचत और सोने चांदी जैसी चीजों को सेहज कर रखते हैं। मोटे तौर पर देखा जाता है कि जिसके पास बचत करने की गुंजाइश थी, वह धीरे धीरे खत्म होती चली गई। बड़ी आबादी से सुरक्षा के लिए रखे गए गहने और जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। किसानों के बीच सक्रिय संगठनों ने कृषि कानूनों का मतलब एक साथ करोड़ों परिवारों से जमीन झटक लेना समझा और समझाया। अर्थव्यवस्था में यह दौर भारतीय मध्यम वर्ग के बड़े हिस्से और निम्न वर्ग के परिवारों को पूरी तरह खाली करवाने का रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने की 'उपलब्धि' नई अर्थव्यवस्था के लिए ताली बजाना है।

जब नई अर्थव्यवस्था शुरू हुई थी तो तर्क दिया गया था कि बड़े व्यापारियों, पैसे लेने-देने का कारोबार करने वाली कंपनियों, उद्योग चलाने वाली कंपनियों आदि को सरकार तरह-तरह की सुविधाएं, मुफ्त की जमीन, टैक्स की छूट दे रही है, कर्ज दे रही है ताकि उसका लाभ नीचे तक रिसते हुए पहुंच सके।

लेकिन तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यह समझ धोखा खा गई। उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है। लेकिन नई अर्थव्यवस्था का यह गुण है कि उसमे सरकार पूंजीपतियों के लिए ज्यादा और आम गरीबों के लिए आय के कम उपाय करती है। अर्थव्यवस्था का जब दूसरा दौर शुरू हुआ तो स्वाभाविक रुप से उसमें बचत में जमा की गई पूंजी बाहर निकलनी शुरू हुई। ज्यादा और जल्दी से बचत को बाहर निकालने के लिए बुनियादी सुविधाओं का तेजी से निजीकरण किया गया। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। आम तौर पर लोगों की संपति, धन, बचत और रोजगार करने और चुकाने की क्षमता को आम कानून के जरिए खत्म करने के प्रयास सामने आने लगे।

सोने के बदले कर्ज और लोकतंत्र का विचार : इस अर्थव्यवस्था का मुख्य गुण वित्तीय पूंजी का है यानी पैसा से पैसा कमाने का है। पैसे के रूप में कर्ज क्यों लिया जाता है। शिक्षा, शादी-ब्याह, स्वास्थ्य। सामाजिक कुरीतियों का दबाव और पूंजीवादी लालसा एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा करती है कि कर्ज सबसे आसान रास्ता दिखने लगता है। खास तौर से जिनके पास वे चीजें उपलब्ध हों जिन्हें पूंजीवादी समाज के लिए भी मूल्यवान माना जाता है। भारतीय समाज के पास गहने सुरक्षित महसूस करने का भाव रहे हैं। समाज में सोने के साथ यह भाव भी गिरवी पर चढ़ रहा है। कर्ज के लिए सोने का गिरवी रखा जाना और लोकतंत्र के विचार का संकट एक दूसरे से किस कदर गुंथे हुए हैं, इसे जाना और समझा जा सकता है। ■

लोग भविष्य की सुरक्षा और बेहतरी के लिए मुख्यतः जमीन या घर, नगदी बचत और सोने-चांदी जैसी चीजों को सेहज कर रखते हैं। मोटे तौर पर देखा जाता है कि जिसके पास बचत करने की गुंजाइश थी, वह धीरे-धीरे खत्म होती चली गई। बड़ी आबादी से सुरक्षा के लिए रखे गए गहने और जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। किसानों के बीच सक्रिय संगठ्नों ने कृषि कानूनों का मतलब एक साथ करोड़ों परिवारों से जमीन झटक लेना समझा और समझाया। अर्थव्यवस्था में यह दौर भारतीय मध्यम वर्ग के बड़े हिस्से और निम्न वर्ग के परिवारों को पूरी तरह खाली करवाने का रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने की 'उपलब्धि' नई अर्थव्यवस्था के लिए ताली बजाना है

राजनीति

प्रेम प्रकाश

क्षेत्रीयता के कंपास से बाहर चुनाव

अब्राहम लिंकन के जमाने में ही लोकतंत्र के संख्यावादी चरित्र की बजाय इसके सामाजिक और वैचारिक पहलुओं को रेखांकित करने का जोर बढ़ गया था। खास तौर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों में बाद के दौर में कई आंदोलनात्मक परिणितियों में यह भी दिखा कि चुनाव और लोकतंत्र सिर्फ सरकार ही नहीं चुनते, बल्कि यह राजनीति का नया विमर्श और देशकाल भी तय करते हैं। इस लिहाज से देखें तो 18वीं लोक सभा का चुनाव अपने मन-मिजाज में कई तरह के सियासी संकेतों को भविष्य के लिए साफ कर रहा है। और ये सब नतीजे से पहले ही तर्क और समझ की गहरी छाप के रूप में सामने हैं। वो दौर तो मौजूदा सदी के पहले ही दम तोड़ गया था जब कांग्रेस और गैर-कांग्रेसवाद की धुरी के बीच पक्ष और विपक्ष का समग्र राजनीतिक समीकरण तय होता था। इस दौरान अस्मिता की राजनीति ने जरूर विपक्ष की राजनीति को क्षेत्रीयता की शक्ल में एक उभार दिया पर बीते एक दशक में यह उभार भी अस्ताचलगामी होता गया है।

भाजपा ने 2014 के बाद देश में राष्ट्रीय राजनीति का एक ऐसा दौर शुरू किया, जिसमें दल और विचार का अनुशासन चमकदार तरीके से दर्ज हुआ। यह बड़ी बात इसलिए भी है कि जिस देश में बच्चे छठी जमात से यह निबंध लिखते हैं कि भारत विविधता के बीच सांस्कृतिक सामासिकता को रचने वाला देश है, वे इसका कोई राजनीतिक साक्ष्य नहीं देख पाते हैं। आज जब लोग अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर से लेकर दिल्ली के लाल किले तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राष्ट्र प्रथम का उद्घोष करते सुनते हैं, तो उन्हें भारत के सांस्कृतिक और भौगोलिक विस्तार और विविधता के बीच राष्ट्रवादी एकता का सूत्र समझ में आता है। यह समझदारी बीते एक दशक की भारतीय राजनीति का निचोड़ है। यह निचोड़ अपने प्रकटीकरण में कितना बड़ा और दिलचस्प है कि छठे चरण में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले देश की राजधानी में जब भाजपा नेताओं का काफिला सड़कों पर उतरा तो उसमें योगी आदित्यनाथ, डॉ. प्रमोद सावंत, पुष्कर सिंह धामी और मोहन यादव जैसे चार अलग-अलग सूबों के मुख्यमंत्री जनता से अपने दल के प्रत्याशी के तौर पर वोट मांग रहे थे। ये चित्र और मंजर तब और भव्य हो जाते हैं, जब हम इसमें प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की साझी शिरकत को देखते हैं। कमाल यह कि मतदान का तीसरा-चौथा दौर बीतते-बीतते राजनीतिक विश्लेषकों और चुनाव समीक्षकों के बीच विमर्श का कंपास इस बात पर तय होने लगा कि मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए बहुमत का गणित किन सूबों से निर्णायक तौर पर तय होगा। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश इस लिहाज से सबसे अहम आंका गया क्योंकि 80 सांसदों को चुन कर भेजने वाले वाले इस सबसे बड़े सूबे को यह फख्र भी हासिल है कि इसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं।

मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी तीसरी बार वाराणसी से चुनावी समर में उतरना यही दिखाता है कि इस प्रदेश का राजनीतिक चरित्र आज भी भारत में केंद्रीय राजनीति का सूत्रधार है। पर यह देखने और समझने वाली बात है कि दो बार से लोक सभा में देश में सबसे ज्यादा सांसद चुन कर भेजने वाले सूबे के मुख्यमंत्री का दायरा महज प्रादेशिक नहीं है। क्षेत्रीयता और परिवारवाद की राजनीति पर आज अगर मोदी सवाल उठाते हैं, तो उसका बड़ा नैतिक और तार्किक कारण यह है कि भाजपा के ऊपर से नीचे तक के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरोकार दिखता है। गोवा जैसे देश के सुदूर सूबे के मुख्यमंत्री अगर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और राजस्थान में राष्ट्रीय सवालों पर जनता से वोट मांगते हैं, तो यह सामान्य बात नहीं है।

बात उत्तर प्रदेश की करें तो कम से कम 15 सूबों में योगी आदित्यनाथ के चुनावी दौरे दिखाते हैं कि सनातन और राष्ट्रवाद के सवाल पर मुखरता के लिए भाजपा महज अपने केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर नहीं है। कमाल तो यह कि योगी की कई सभाएं और दौरे यूपी से बाहर इसलिए आखिरी समय में तय हुए क्योंकि इसके लिए भाजपा काडर और समर्थकों की मांग उठी। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा से लेकर देश की राजधानी तक उनके चुनाव कार्यक्रम का फलित तो खैर बाद में तय होगा, पर यह तो अभी से तय है कि भाजपा अपने इस फायर ब्रांड नेता को लेकर आत्मविश्वास से भरी है।

यह अकारण नहीं है कि जेल से चुनाव प्रचार के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस आत्मविश्वास को अपनी चुनावी राह में सबसे बड़ा रोड़ा माना। उन्होंने इस बात को सार्वजनिक तौर पर बार-बार कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को पीएम बनाने के लिए पिछले डेढ़-दो वर्षों से लगे हुए हैं। लिहाजा, भाजपा अगर चुनाव जीत भी जाती है तो मोदी रिटायमेंट के 75 वर्ष पूरा करने के साथ शाह को गद्दी सौंप देंगे। केजरीवाल के इस फर्जी नैरेटिव की खास बात यह भी रही कि उन्होंने यह भी आशंका जताई कि लोक सभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाएगा। आप सुप्रीमो के बयान को लेकर जो बात समझने की है, वह यह कि वे भाजपा के अखिल भारतीय उभार के साथ दिल्ली से लेकर देश के सूबों तक उसके नेतृत्व में दिख रहे वैचारिक अनुशासन और ताकत से घबराते हैं। यह घबराहट आज की तारीख में भाजपा के खिलाफ खड़े पूरे विपक्षी गठबंधन में है। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि विपक्ष के ज्यादातर नेता अपने क्षेत्रीय दायरे से आगे नहीं निकल पाते।

दिलचस्प है कि जो लोग आज संविधान के मुद्दे को इस पूरे चुनाव की निर्णायक धुरी बता रहे हैं, वे इस मुद्दे पर भाजपा की काउंटर रणनीति को न समझने की भूल कर रहे हैं। दरअसल, इस मुद्दे का मुकाबला भी भाजपा अपने वैचारिक अनुशासन और एकता के साथ जिस तरह कर रही है, वह विलक्षण है। यह भाजपा के आंतरिक ढांचे की मजबूती ही है कि राजनीतिक तौर पर उसकी लाइन इस चुनाव में कहीं से भी बंटी हुई नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम यह नहीं देखते कि नागपुर में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर चुनाव जीतने के बाद संविधान बदलने का सीधा आरोप लगाया तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आगे बढ़कर पहला पलटवार किया। साफ है कि बीते एक दशक में देश की राजनीति में जो बड़ा बदलाव आया है, उसमें भाजपा के शीर्ष उभार के साथ उसकी दिल्ली से लेकर पूरे देश में दिखने वाली राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर अनुशासन के साथ कतारबद्ध नेताओं और समर्थकों की अडिग ताकत भी है। ■

कविता | डॉ. आलोक सक्सेना

मेरी अंतिम इच्छा

मेरी अंतिम इच्छा है कि
मेरा दाह संस्कार,
मेरी देह की बची राख गंगा घाट में
गंगाजल में न मिले
तो कोई बात नहीं/घर के गमलों व कहीं
किसी बाग-बगीचे
में पेड़ों तले डाल देना, निःसंकोच होकर।
मेरा विश्वास है कि,
मेरे बाद
मिलेगा मेरे अंगों से
अनेक जरूरतमंदों
को नवजीवन दान
और
नव पीढ़ी के लिए
एक वृक्ष भी नहीं
जलेगा, मेरी लाश के
साथ।
निःसंदेह इस तरह
वृक्ष संरक्षण होगा...,
निःसंदेह होगा जरूर
और
वह वृक्ष
जो सदैव छाया व
फल देता रहेगा हर नागरिक के लिए,
मेरे न रहने पर भी, कुछ मेरी तरह। ■

राग रंग | आलोक पराड़कर

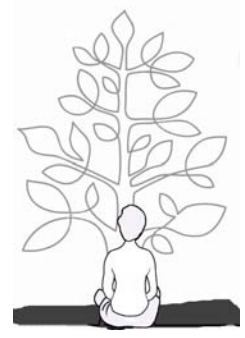

संगम नगर में रंग संस्कार

स्वाधीनता हो या सामाजिक आंदोलन, इलाहाबाद के रंगमंच को हमेशा से प्रेरित करते रहे हैं। बताते हैं कि यहां आधुनिक रंगकर्म के आरंभिक रंगकर्मियों में शामिल पं. माधव शुक्ल ने 'सीता स्वयंवर' नामक नाटक में अभिनय करते हुए जब संवाद बोला-'हा! हा! यह धनुष तो अंग्रेजी राज हो गया जिसे कोई भी नवयुवक न उठा पा रहा है, न इसे तोड़ पा रहा है'। तो यह ऐसा तिलमिला देने वाला संवाद था कि दर्शकों में शामिल स्वतंत्रता आंदोलन के कई नेता वहां बैठे नहीं पाए और उठकर चले गए। अपने साहित्यकारों के लिए प्रसिद्ध इस नगर में सुमित्रानंदन पंत, उपेंद्र नाथ अश्क, इलाचंद जोशी भी रंगमंच से जुड़े रहे। प्रयाग रंगमंच ने यहां के रंगमंच को वैचारिक धरातल दिया जिसे सत्यव्रत सिन्हा की गिरफ्तारी और निधन से धक्का भी लगा था।

इलाहाबाद में रंगकर्म को लेकर सक्रियता बनी रहती है। नगर की कई नाट्य संस्थाएं और रंगकर्मी नाट्य प्रस्तुतियां करती हैं, स्थानीय स्तर पर भी और बाहर जाकर भी। यहां के रंगकर्मियों ने अपने काम से राष्ट्रीय पहचान भी बनाई है। इन सबके बीच नगर एक विद्यालय है, जो है तो दूसरे विद्यालयों जैसा ही लेकिन रंगमंच को लेकर अपने समर्पण में अनूठा भी है। कहना गलत न होगा कि विद्यालयों में पढ़ाते हुए अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर बड़े ख्वाब बुनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी या ऊंचे पदों और अधिक तनख्वाहों के लक्ष्य तय कर लिए जाते हैं, लेकिन करेलाबाग का बेनहर स्कूल एंड कॉलेज छुटपन से ही उनमें रंगकर्म को रोपता है, इस उम्मीद के साथ कि रंगकर्म, संगीत और साहित्य की सृजनात्मकता का उनमें विकास हो, वे कला या लेखन की ओर बढ़ सकें और इन सबके साथ ही संवेदनात्मक स्तर पर अधिक सजग रहने वाले एक बेहतर नागरिक का निर्माण भी हो सके।

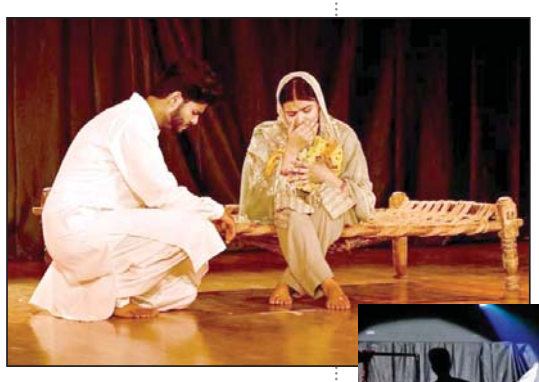

विद्यालय ने इसके लिए बेनहर फोरम फॉर थिएट्रिकल आर्ट्स (बफ्टा) नामक संस्था बना रखी है, पिछले 14 वर्षों से नाटकों की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, और नाट्य उत्सव का आयोजन भी हो रहा है। इस बार 31 मई से शुरू हुए नाट्य उत्सव का यह तीसरा वर्ष था, जो तीन दिनों का है। विद्यालय की कार्यशालाओं में नाटक तैयार कर उनके मंचन करने के साथ ही देश के प्रतिष्ठित रंगकर्मियों को आमंत्रित करना, उनकी नाट्य प्रस्तुतियों को बच्चों को दिखाना इस नाट्य उत्सव का उद्देश्य रहता है। विद्यालय के संस्थापक तारिक खान बताते हैं, 'हमने विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिलाया है और हर साल चार नाटकों को विद्यार्थियों से तैयार कराया जाता है, जिससे उनमें रंगकर्म के प्रति रुझान और प्रेम हो। देश के कई प्रतिष्ठित रंगकर्मी कार्यशालाओं में आ चुके हैं, और हमने प्रसिद्ध कहानियों के मंचन कराए हैं। पिछले 14 वर्षों में 50 से अधिक नाटकों के मंचन में कक्षा एक से बारहवीं तक के विद्यार्थी भाग लेते रहे हैं। हिन्दी के साथ ही अंग्रेजी में भी नाटकों के मंचन होते हैं। हमने रामकथा को उर्दू कविता में ढालकर 'दास्तान-ए-राम' तैयार कराया है, जिसकी अब तक देश में 16 प्रस्तुतियां हो चुकी हैं।'

विद्यालय के अपने सभागार में 31 मई से आरंभ हुए नाट्य उत्सव में पहली संध्या में विद्यालय के विद्यार्थियों ने अमृता प्रीतम के उपन्यास पर 'पिंजर' और चेखव की कथा पर 'द बेट' की प्रभावी प्रस्तुतियां कीं। इन कथाओं के चयन के पीछे विद्यार्थियों को सांप्रदायिकता और भौतिकता के खिलाफ संदेश देने का भी उद्देश्य था। एक जून को मुंबई से आए सलीम शाह द्वारा एकल हास्य नाट्य प्रस्तुति 'भेलपुरी' की गई जबकि दो जून को पुनः विद्यार्थियों द्वारा 'मट्टो की साइकिल' का मंचन किया जाना है। समारोह में उपस्थित प्रसिद्ध रंगकर्मी सलीम आरिफ और वर्धा स्थित महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की रंगमंच और फिल्म विभाग की प्रोफेसर विधु खरे दास ने नाटक में भाग ले रहे विद्यार्थियों में श्रेष्ठ कला का चयन कर उन्हें सम्मानित भी किया। नगर के सक्रिय रंगकर्मी प्रवीण शेखर कहते हैं, 'नगर के मानिचत्र पर देखें तो भौगोलिक रूप से बेनहर स्कूल एक किनारे पर स्थित है लेकिन रंगमंच के प्रति संवेदीकरण और रंग बोध को देखें तो यह इलाहाबाद नगर के केंद्र में है। वैसे ही महत्त्वपूर्ण जैसे समग्र विकास को लेकर एक जिम्मेदार शिक्षा संस्थान को होना चाहिए। वे इस बात को संवेदना के साथ समझते हैं कि शिक्षा के लिए रंगकर्म एक जरूरी उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैंने देखा है कि रंगमंच को लेकर समझ और तैयारी जैसे वहां के विद्यार्थियों में दिखती है, वैसा स्कूली स्तर पर बहुत कम होता है। यह भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि थिएटर की गुणवत्ता और कथ्य की विविधता में बेनहर स्कूल के विद्यार्थी जितने प्रयोगधर्मी हैं, वैसा शहर के बहुत से नाट्य समूह भी नहीं कर पाते। इसके लिए उनके पास बुनियादी संसाधन भी हैं।' ■

कैनवस | जय त्रिपाठी

50 वर्षों की स्याही अंर्तदृष्टि के अशोक

आत्म-खोज और सामाजिक अवलोकन पर आधारित कलात्मक संवेदना कला के विकास में एक आकर्षक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। विशेष रूप से इसका महत्व तब अधिक होता है जब किसी कलाकार की कला यात्रा विज्ञान की पृष्ठभूमि से गुजरते हुए चित्रकला के प्रति जुनून से शुरू होती हो। और जब कलाकार की 50 वर्षों की यह कलात्मक यात्रा,उसके वैचारिक एवं संवेदनशील भावों के कारण जानी जाए तो कलाकार के साथ-साथ आयोजक तथा संचालित करने वाले लोगों की भी विशेष भूमिका होती है। यह भूमिका लखनऊ स्थित कला स्त्रोत आर्ट गैलरी तथा क्यूरेटर राजन श्रीपद फुलारी की रही। 'अन्वैलिंग पर्स्पेक्टिव : द आर्टिस्टिक ऑडिसी ऑफ अशोक भौमिक 'शीर्षक से प्रदर्शित 50 चित्रों की कला प्रदर्शनी उनके अपने खास वैचारिकी के लिए भी कला जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है।

वरिष्ठ कलाकार भौमिक के पास अपनी एक विशिष्ट कला दृष्टि है, जिसका बुनियादी महत्व भी है। कम से कम सार्थक गंभीर और गहरी कलाकृतियों के लिए तो ऐसी दृष्टि का होना और भी जरूरी होता है, जब कला शिल्पकारिता तक न सीमित हो कर अपने उद्देश्य और वैचारिक दृष्टिकोण से बहुत दूर तक जाने का प्रयास करती है। कानपुर से आरम्भ हुयी यह अनवरत यात्रा कलाकार की रचनात्मकता तथा उनकी संवेदी धारणाओं पर केंद्रित है,जो सचेतन रूप से एक रचनात्मक चेतना की पुनर्कल्पना करती है। इस प्रदर्शनी में कलाकार के कलात्मक विधियों तथा विषयों के माध्यम से एक संबंधपरक कलात्मकता भी देखी जाती है। प्रतिष्ठित कलाकार,लेखक और वक्ता अशोक भौमिक अपनी सोच समझ से वैचारिक दृष्टिकोण को कृतियों में रचनात्मक रूप से समायोजित करते हैं। मानवीय संवेदनाओं को दर्शाते अशोक सामाजिक तथा राजनैतिक रूप से जागृत रहकर एक कला संसार गढ़ते हैं। अपनी चेतना एवं वैचारिक दृष्टि से विकसित समाज को आईना दिखाता यह कलाकार, समकालीन कलाकारों के मध्य मौलिकता के साथ अपनी आंतरिक बेचैनी को समकालीनता से जोड़े रखता है। यहीं इस कलाकार की मौलिक चेतना है।

इनकी कलाकृतियां दर्शाती हैं कि एक कलाकार के रूप में वह भावनात्मक एंव वैचारिक रूप से दृढ़ हैं। चित्रों में उभरती स्याह व स्लेटी आकृतियां रेखीय प्रभाव से कलाकृतियों में विशेष प्रभाव प्रक्षेपित करती हैं। शांत चित व मुखर व्यक्तित्व वाले भौमिक ने सामाजिक चैतन्यता, राजनैतिक उहापोह एवं आमजन के दुख दर्द तथा उनके घावों को कलाकृतियों में दर्शाने का सराहनीय का प्रयास किया है।अपनी क्रॉस-हैचिंग की विशिष्ट तकनीक में स्त्रियों तथा दिहाड़ी मजदूरों को प्रमुखता से चित्रित करते कलाकार ने उनके दुखदर्द को अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। लगातार रचनाशील इस गंभीर कलाकार ने मानव आकृतियों के साथ पशु पक्षी की संवेदनाओं को भी चित्रित किया है। जैसा कि सामाजिक अव्यवस्था के प्रति मुखर इनकी कलाकृतियों में वैचारिक गंभीरता के साथ दिखाई देता है। एक इंसान के रूप में भौमिक के विचार और कलात्मकता एक दूसरे के संपूरक हैं। जिनके अंतर्सबंधों से ही इस कलाकार की मुकम्मल छवि बनती है। कलाकार की चित्र प्रदर्शनी कृतियों के माध्यम से इन अंतर्सबंधों में आए अनेक ऐन्द्रिक भावों की पहचान कराती है।

इंक एडं इनसाइट 'अनवीलिंग पर्सपेक्टिव्स' के माध्यम से वह एक सर्जक के रूप में अपनी रचनात्मक दृष्टि और स्वाभाविक क्षमता को भी दर्शाते हैं। दृश्य कला में भौमिक की यात्रा चित्रकला के प्रति ऐसे जुनून से शुरू हुई जो उनके संवेदनशील चित्त बुद्धि व स्मृति की सृजनात्मकता से रचना का चिन्तन करते हुए, कला मर्मज्ञ के साथ जानी जाती है। वरिष्ठ कलाकार, चिंतक भौमिक इस प्रयास में लगे रहते हैं कि समाज में हो रही असामाजिकता या समाज के दर्द को रचनात्मक सजृना से दर्शाया जा सके, इसके साथ-साथ कलाकारों की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाए। रेखाओं से गढ़ी गई आकृतियां खालीपन को भरने का माध्यम सा भी लगती हैं। उनके पूर्व के चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि एक कलाकार के रूप में जब उनकी संवेदनाएं मूर्त आकार की ओर बढ़ीं, तो चित्र निर्माण में स्वतः यह रचनात्मक प्रक्रिया से आगे बढ़ने लगीं। भौमिक अपनी कला ज्ञान मीमांसा से जिन आकारों का निरूपण करते हैं, वह वस्तुतः वो आकृतियां हैं, जिन्हें इनके चित्र दर्शकों को खुद समझाते हैं, और बताते हैं कि विभिन्न आकारों द्वारा सुन्दर संयोजन में शांत होने की यह प्रक्रिया कितनी स्पष्ट है।

स्याह रंग के कई शेड्स के प्रयोग से इनके भाव चित्रों की श्रंखला दर्शक को उस संसार में ले जाती हैं,जो कलाकार के अंतर्मन के करीब होकर रची गई हैं। जिसमें कलाकार के अंतर्मन की आवाज है। कैनवस एंव कागज की सतह पर उभरती रेखाएं व टैक्चर, रचनाकार के भावों और उसके क्रियात्मक रूप के बीच एक अंतराल भी रखती लगती हैं। कलाकार जब इस अंतराल को अपने भावों के माध्यम से भरने लगता है, तो कुछ यहीं से मूर्तता आकार लेती है जो दर्शक की देखने समझने कि दृष्टि के अनुसार खुलती है। ■

https://t.me/AIINewsPaperPaid

मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि भारतीय लोकतंत्र की रक्षा 'व्हाइट कॉलर' लोगों से कहीं अधिक गंवई और गरीब लोगों ने की है। आप इसे आजाद भारत का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि अधिक पढ़े-लिखे और आर्थिक रूप से बेहतर तबके में राजनीति के प्रति आत्मघाती विराग दिखता है। यह वर्ग मतदान केंद्रों में अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय सैर-सपाटे में अधिक रुचि रखता है।

स्कैन करें
आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

कुछ खुशी, कुछ गम देता चुनाव

शशि शेखर

आजकल

देश में अठारहवीं लोकसभा के आखिरी चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब संसार की सबसे विशाल आबादी को नतीजों का इंतजार है। चुनाव परिणामों को जानने के लिए विदेश के भी वे लोग बेकरार हैं, जिन्हें सही या गलत वजहों से नई दिल्ली की हुकूमत में रुचि है। बरसों से चुनाव-दर-चुनाव मुझे दूसरे महायुद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने विंस्टन चर्चिल याद आते रहे हैं। उन्होंने दंभपूर्वक कहा था कि भारत में लोकतंत्र तीसरी लोकसभा के चुनाव तक नहीं पहुंच पाएगा।

चर्चिल की नजरों में 'जाहिल' हिन्दुस्तानियों ने उस उपनिवेशवादी हुक्मरां को मुंहतोड़ जवाब दिया है।

भारत जैसे देश में चुनावों का वैशिष्ट्य सिर्फ मतदान के दोहराव में निहित नहीं है। हर चुनाव के अपने अलग रंग और तेवर होते हैं। मसलन, इस बार कश्मीर घाटी में औसतन 50 फीसदी से ज्यादा मत पड़े। कभी दहशतगर्दी का दुर्ग माने जाने वाले अनंतनाग में तो आंकड़ा 55.40 पर जा टिका। कश्मीर में पहले चुनाव बदमजगी लेकर आते थे। इस बार उम्मीद और उत्साह साफ दिखते थे।

मौजूदा मतदान को छोड़ दें, तो 1980 के दशक के बाद से ऐसा कोई चुनाव नहीं बीता, जब अलगाववादियों ने आरोप न लगाया हो कि मतदाता जबरदस्ती अपने घरों से उठाकर मतदान केंद्रों पर खड़े किए गए। वे सही थे या गलत? सच जो हो, पर ऐसे बयानों से उनकी खीझ जरूर जगजाहिर होती, क्योंकि वे हर बार चुनाव बहिष्कार की अपील चेतावनी भरे अंदाज में करते थे। मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूं, जिन्होंने ऐसी अपील की अनदेखी कर वोट डालने की हिमाकत की और दुष्परिणाम झेले।

ध्यान रहे। गई 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 की रवानगी के बाद घाटी में यह पहला आम चुनाव था। पुराने अनुभवों का तकाजा था कि चुनाव आयोग पूरी सावधानी बरते। ऐसा किया भी गया। नतीजतन, घाटी में हिंसा की छोटी-मोटी वारदात तक नहीं हुई। कश्मीरियों को समझ में आ गया है कि अब अगर अपनी बात दिल्ली के दरबार में पहुंचानी है, तो उसके लिए चुनाव में हिस्सेदारी से बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसी के जरिये अपने नुमाइंदे देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजे जा सकते हैं, ताकि वे उनके हक-हुकूक की आवाज बुलंद कर सकें। घाटी की जेहनियत जानने वाले इसे शुभ संकेत मानते हैं। यहीं सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तानी प्रवंचनाओं के दिन लद गए? हालात में सुधार के बावजूद अभी एहतियात बरतना होगा।

जम्हूरियत और जनता का रिश्ता इस इलाके में कई बार छुई-मुई साबित हो चुका है।

घाटी में इस उत्साह को देख देश की राजधानी नई दिल्ली में तो लोग उमड़ पड़ने चाहिए थे। ऐसा नहीं हुआ। नई दिल्ली सीट पर सिर्फ 55.43 फीसदी मतदाताओं ने अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का निर्वाह किया। आज से कुछ दशक बाद कोई शोधार्थी इस आंकड़े को देख क्या यह नहीं सोचेगा कि नई दिल्ली और अनंतनाग में एक सी बयार बह रही थी! दिल्ली ही नहीं, मुंबई और देश के अन्य महानगरों ने भी इस मामले में समय की मांग को अनदेखा किया।

मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि भारतीय लोकतंत्र की रक्षा 'व्हाइट कॉलर' लोगों से कहीं अधिक गंवई और गरीब लोगों ने की है।

आप इसे आजाद भारत का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि अधिक पढ़े-लिखे और आर्थिक रूप से बेहतर तबके में राजनीति के प्रति आत्मघाती विराग दिखता है। यह वर्ग मतदान केंद्रों में अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय सैर-सपाटे में अधिक रुचि रखता है। भरोसा न हो, तो एक बार उन खबरों पर नजर डाल देखिए, जो चीख-चीखकर मुनादी करती हैं कि तमाम दर्शनीय स्थलों पर होटलों के सौ फीसदी तक कक्ष पहले से ही आरक्षित करा लिए गए थे। इनमें से अधिकांश महानगरों के समीप हैं।

खुद को संभ्रांत कहने वाले ऐसे लोगों को अब राजनीति और राजनेताओं पर टीका-टिप्पणी बंद कर देनी चाहिए।

यहां एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा। आप जानते हैं कि 1951-52 में पहला आम चनाव हुआ था। 17,32,12,343 वोटर थे। इनमें से 44.87 प्रतिशत लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस वक्त देश में लगभग 97 करोड़ लोग बतौर वोटर पंजीकृत हैं। चुनाव आयोग ने अब जो तथ्य जारी किए हैं, उसके अनुसार इस बार करीब 65 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है, जो पिछली बार, यानी 2019 से कम है।

एक और तथ्य गौरतलब है। पहले आम चुनाव की मतदान-प्रक्रिया पांच महीने से अधिक खिंची थी और इस बार डेढ़ महीना। इस नाते यह देश का दूसरा सबसे लंबा चुनाव रहा। इस दौरान ताप लहरी ने तमाम पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त किए, जिससे प्रचार और मतदान की राह अवरुद्ध हुई। कोई अचरज नहीं कि तमाम राजनेताओं और विचारकों ने चुनाव आयोग से इसकी अवधि घटाने और अत्यधिक गरमी अथवा सर्दी के दिनों में चुनाव न कराने की अपील की है।

इसी दौरान कई लोग 'एक देश एक चुनाव' के पक्ष में भी बात करते दिखाई दिए। भाजपा भी यही संकल्प व्यक्त करती है।

चुनाव प्रचार के दौरान इस बार भी देश की जनता ने दुखी और चकित भाव से अपने नेताओं की गरिमाहीन भाषा को अभिशाप-भाव से झेला। इतनी छिछली भाषा मतदाताओं की आस्थाओं को चोटिल करती है। संवेदनशील हिंदी पट्टी में कम मतदान इस तथ्य का खुलासा करता है। हमारे नेता अभद्र और अनर्गल तर्क गढ़ते समय भूल जाते हैं कि वे भी सोशल मीडिया के उफनते दिनों से गुजर रहे हैं। इन दिनों आनन-फानन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि नेताओं की बेतुकी बातों पर इस बार बेशुमार 'मीम्स' प्रचलित हुए। भारत के राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ इस संबंध में विचार क्यों नहीं करते? अगर यही हाल रहा, तो उनकी सभाओं में भीड़ सिमटती चली जाएगी।

पिछले कुछ वर्षों की तरह इस बार चुनाव आयोग की भी जमकर छीछालेदर हुई। मतदान के आंकड़ों को इकट्ठा करने में देरी पर मामला अदालत पहुंचा। आयोग नेताओं की बदजुबानी पर भी अंकुश लगाने में आम आदमी की आशाओं पर खरा नहीं उतर सका। इससे आयोग का वह भगीरथ प्रयास धूमिल पड़ गया, जिसके चलते इतने बड़े देश में हिंसा रहित चुनाव संपन्न हो सके। यहां एक और तथ्य गौरतलब है कि कश्मीर के मुकाबले बंगाल अधिक हिंसक साबित हुआ। हालांकि, यह भी सच है कि पिछले चुनावों के मुकाबले बंगभूमि काफी शांत रही। चुनाव आयोग के निर्देश पर सरकारी तंत्र ने इस बार लगभग नौ हजार करोड़ रुपये की नकदी, नशीले पदार्थ व उपहार जब्त किए। यह ऐतिहासिक बरामदगी है, पर आयोग इसका अपनी छवि के सुधार में प्रयोग न कर सका। उसे न केवल अदालत की फटकार सुननी पड़ी, बल्कि तमाम संगठनों का अभियान भी झेलना पड़ा। हजारों लोगों ने आयोग को पत्र लिखकर 'ग्रो ए स्पाइन ऑर रिजाइन' अभियान में हिस्सा लिया, जो अभूतपूर्व था।

उम्मीद है कि आयोग समय रहते अपनी सफलताओं की गणना के साथ असफलताओं का भी आकलन करेगा। बेहतर चुनाव प्रक्रिया इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है।

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

जीना इसी का नाम है

संध्या नायर
रंगकर्मी, मोटिवेशनल स्पीकर

उन्होंने मुझे कभी 'संध्या' की तरह नहीं देखा

संध्या के पास आज 'सफेदपोश नौकरी' के अवसरों की कोई कमी नहीं, मगर वह बदलाव की प्रेरणा बनकर न सिर्फ कमाठीपुरा जैसी बदनाम बस्तियों की बेटियों को, बल्कि दुनिया भर की रेडलाइट एरिया की लड़कियों को अपने भीतर यकीन पैदा करना सिखा रही हैं।

अपनी वर्जनाओं के पीछे हमारा समाज कितने सारे पाखंड को जीता है, इसे बेपरदा करती एक बहादुर बेटी की कहानी आज सुनिए। वह एक ऐसे इलाके में पैदा हुईं, जिसकी सीमा पर पहुंचकर तमाम शरीफ लोग अपनी शराफत का लबादा उतार फेंकते हैं। विडंबना देखिए, तमाम पुराने शहरों में ऐसे इलाके तथाकथित भद्र लोगों की बदौलत ही आबाद हुए। मगर शहराती दुनिया ने सबसे अधिक नफरत इन्हीं इलाकों के बाशिंदों से पाली। बंगाल की परंपरा में तो देवी प्रतिमा के लिए मिट्टी भी इन्हीं बस्तियों की आंगन की चाहिए, मगर स्नेह और सम्मान पर उनका कोई हक नहीं! मुंबई का कमाठीपुरा एक ऐसा ही इलाका है, जहां संध्या नायर पैदा हुईं।

जी हां! संध्या एक यौनकर्मी मां की बेटी हैं और उन्हें इस पहचान से अब कोई गिला नहीं है, शिकायत बस समाज से है, जो इन इलाकों में पैदा हुए बच्चों को नफरत व हिकारत की निगाहों से देखता है और उनसे उनका बुनियादी हक छीनने वालों को पारसा समझता है। बहरहाल, दुनिया की हरेक समझदार मां की तरह संध्या की माता भी उन्हें एक तालीमयाफ्ता, काबिल, खुदमुख्तार लड़की के रूप में देखना चाहती थीं। मगर मां की यह हसरत नन्ही संध्या को कितनी भारी पड़ेगी, उन्होंने कभी सोचा न होगा। छह-सात साल तक बाहरी दुनिया से संध्या का कोई साबका नहीं पड़ा था, इसलिए उसके तेवर से वह पूरी तरह अनजान थीं। अपनी पहचान छिपाकर मां ने एक निजी स्कूल में उनका दाखिला करा दिया।

संध्या बेहद खुश थीं। एक बिल्कुल नया फलक उनके आगे खुला था। नए-नए दोस्त मिले थे, स्कूल यूनिफॉर्म में होने का एहसास ही कुछ अलग था। मगर यह खुशी बहुत दिनों तक नहीं टिक सकी। पहले तो उनकी त्वचा के रंग को सहपाठियों ने निशाना बनाया। कभी 'काली', तो कभी 'कौआ' कहकर संध्या को पुकारा जाता। इसे वह फिर भी झेल लेती थीं, मगर जब उनकी मां के पेशे के बारे में साथियों को पता चला, तो रातोंरात सबका नजरिया ही बदल गया। सबने उनसे बात करना बंद कर दिया। यहां तक कि दोपहर का खाना भी संध्या अकेली ही खातीं।

कई बार बेमतलब ही सहपाठी थप्पड़ जड़ दिया करते और शिकायत करने पर शिक्षकों का रवैया उपेक्षा भरा होता। क्लास के एक कोने में उन्हें टूटी बेंच पर बैठना पड़ता। चूंकि स्कूल प्रशासन उन्हें निकालकर मीडिया में नहीं आना चाहता था, लिहाजा उसने हर मुमकिन कोशिश की कि संध्या खुद ही स्कूल छोड़कर चली जाएं। आखिरकार उन्होंने अपने साथ दुर्व्यवहार की शिकायत करनी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। संध्या को कमाठीपुरा अपने लिए सबसे सुरक्षित जगह लगता, जहां किसी की नजर में उनके लिए दया या नफरत नहीं होती थी। स्कूल

का माहौल बर्दाश्त करना बहुत कठिन था, पर काफी मुश्किल से मिले स्कूल में दाखिले को वह गंवा नहीं सकती थीं।

संध्या की मां को घरेलू सहायक का काम मिला, तो उन्होंने मजबूरी का पुराना पेशा छोड़ दिया, मगर यह समाज उनकी बेटी को कहां बख्शने जा रहा था! दस से सोलह साल तक स्कूल में संध्या का यौन उत्पीड़न और बलात्कार होता रहा। जिस शख्स ने पहली बार उनके साथ ज्यादती की, उसने उनकी गरदन पर पांव रखकर कहा- 'तुम पढ़-लिखकर क्या करेगी? ...की बेटी हो, ...ही बनोगी!' मगर संध्या ने इस मान-मर्दन को सहते हुए भी स्कूल न छोड़ने का फैसला किया। साल 2013 में दसवीं करने के बाद संध्या अपनी मां के साथ केरल चली आईं, क्योंकि उनके पिता बहुत बीमार थे। यहां पहली बार उन्हें आजादी का एहसास हुआ, क्योंकि इस शहर में उनकी मां की पृष्ठभूमि को कोई नहीं जानता था।

मां ने सिलाई का काम शुरू कर दिया था, मगर उससे घर की सारी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं, लिहाजा संध्या ने भी घरेलू सहायिका का काम पकड़ लिया, ताकि अपने कॉलेज व ट्यूशन की फीस वह चुका सकें। साल 2015 की बात है, संध्या को एक अखबार की कतरन मिली, जिसमें श्वेता कट्टी की कहानी छपी थी। श्वेता 'रेडलाइट एरिया' से स्कॉलरशिप पर विदेश जाकर पढ़ने वाली पहली भारतीय लड़की हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क के बार्ड कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। संध्या को भी आगे पढ़ने का बहुत शौक था। साइबर कैफे के जरिये उन्होंने श्वेता से संपर्क साधा, तो श्वेता ने उन्हें 'क्रांति' (गैर-सरकारी संस्था) की मुखिया रॉबिन चौरसिया से बात करने को कहा। यह संस्था यौनकर्मियों की बेटियों को रिहाइश, शिक्षा व अन्य अवसर मुहैया कराने में सहयोग करती है।

रॉबिन ने संध्या की आपबीती सुन उन्हें फौरन मुंबई बुलाया और अपने 'शेल्टर होम' में रहने की जगह दी। इस होम में 24 और लड़कियां रह रही थीं। सबका अतीत बेहद दर्दनाक था। रॉबिन ने उन सबकी जिंदगी को मानीखेज बना दिया। 'लालबत्ती एक्सप्रेस' नामक थियेटर ग्रुप के जरिये ये पूरी दुनिया में घूम-घूमकर अपनी दास्तान सुनाने लगीं। इसी संस्था की मदद से संध्या को प्रतिष्ठित अशोका विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में ग्रेजुएशन करने का अवसर मिला और आगे की उच्च शिक्षा के लिए वह कोस्टारिका की यूनिवर्सिटी फॉर पीस जा सकीं। उन्होंने अपने सफरनामे को एक किताब की भी शक्ल दी है- *बियोंड द ओसन्स व्यू।*

पहले उनकी त्वचा के रंग को निशाना बनाया गया। कभी 'काली', तो कभी 'कौआ' कहकर संध्या को पुकारा जाता। इसे वह फिर भी झेल लेती थीं, मगर जब उनकी मां के पेशे के बारे में साथियों को पता चला, तो रातोंरात सबका नजरिया बदल गया। सबने उनसे बात करना बंद कर दिया।

संध्या के पास आज 'सफेदपोश नौकरी' के अवसरों की कोई कमी नहीं, मगर वह बदलाव की प्रेरणा बनकर न सिर्फ कमाठीपुरा जैसी बदनाम बस्तियों की बेटियों को, बल्कि दुनिया भर की रेडलाइट एरिया की लड़कियों को अपने भीतर यकीन पैदा करना सिखा रही हैं। बकौल संध्या, इसी की बदौलत वे नैतिकता के ठेकेदारों की आंखों में आंखें डालकर एक इंसान की हैसियत से बात कर सकेंगी, बल्कि अपनी पहचान की शर्मिंदगी से भी मुक्ति पा सकेंगी।

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

वो लम्हा

जॉर्ज फर्नांडिस
पूर्व रक्षा मंत्री व राजनेता

समानता की तलाश में निकली जिंदगी

धर्म को समर्पित संस्थान से ज्यादा समानता तो आम लोगों के घरों में है। हर घर की रसोई में समान भोजन पकता है और सब समान भाव से मिल-बांटकर खाते हैं। यह कैसा धार्मिक कायदा कि गुरु छप्पन भोग उड़ाए और चेला सूखी रोटी चबाए? कथनी और करनी में इतना फर्क?

वह छह लड़कों से भरा-पूरा कैथोलिक परिवार था। जॉर्ज, लॉरेंस, माइकल, पॉल अलॉयसियस और रिचर्ड, सब एक से बढ़कर एक। तब दौर ऐसा था कि दक्षिण भारत में ईसाई परिवारों का बड़ा बेटा धर्म के नाम पर भेंट कर दिया जाता था, वह प्रीस्ट या फादर बनता था। साथ ही, हरेक परिवार से एक बेटी नन बनने के लिए भेज दी जाती थी। बहरहाल, इस परिवार में तय था कि बड़ा लड़का, जिसे सब गैरी पुकारते थे, धर्म की राह पर भेजा जाएगा। गैरी ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, तो पिता में तमन्ना जागी कि उसे आगे पढ़ाया जाए। किशोर गैरी भी जान गए थे कि पिता उन्हें वकील बनाना चाहते हैं। पेशे से बीमा अधिकारी पिता को एक वकील पुत्र की जरूरत थी, जो उनके लिए मुकदमे लड़ सके। पिता के पास शहर से बाहर एक जमीन थी, जिससे वह किरायेदारों को अक्सर बेदखल करते थे, आए-दिन विवाद होते थे और वकील की जरूरत पड़ती थी। पुत्र ने साफ मना कर दिया कि वह वकील नहीं बनेगा, वह किसी का भी दिल नहीं दुखाएगा। पिता थोड़े नाराज हुए, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि वह जानते थे कि कुछ और नहीं, तो बेटा फादर तो बनेगा ही, धर्म की सेवा में जाएगा, तो उससे क्या नाराज होना।

एक दिन आया, जब बड़ा बेटा मंगलुरु से बेंगलुरु रवाना हो गया। बेंगलुरु में प्रीस्ट और फादर बनने की शिक्षा दी जाती थी। बड़े बेटे की उम्र 16 वर्ष थी, उसके मन में धर्म को लेकर बड़े ऊंचे विचार, स्वप्न और आदर्श थे। बेंगलुरु के सेंट पीटर सेमिनरी में एक से बढ़कर एक ईसाई गुरु थे। शुरू में सब अच्छा लगा। समय से जागना-सोना, खाना-पीना, पढ़ना, अभ्यास। प्रशिक्षक मुस्तैदी से बताते थे कि धर्म की निगाह में सब समान है, ईश्वर भेद नहीं करते, पर एक दिन अनायास उस किशोर का इस बात पर ध्यान गया कि जब सब समान हैं, तो यह श्रीमान प्रशिक्षक हम सभी से ऊपर स्थान पर क्यों बैठे हैं, उन्हें भी हमारे समान बैठना चाहिए। क्या वह श्रेष्ठ हैं और हम तुच्छ? थोड़ा अंतर होना चाहिए, पर वह अर्श पर हैं और हम फर्श पर, आखिर क्यों?

सोच की एक ऐसी शुरुआत हुई कि किशोर ने प्रशिक्षकों की कथनी को उनकी करनी से परखना शुरू कर दिया। सब समान हैं, तो प्रशिक्षकों के लिए अलग भोजन क्यों बनता है? धर्म को समर्पित संस्थान से ज्यादा समानता तो आम लोगों के घरों में है। हर घर की रसोई में समान भोजन पकता है और सब समान भाव से मिल-बांटकर खाते हैं। यह कैसा धार्मिक कायदा कि गुरु छप्पन भोग उड़ाए और चेला सूखी रोटी चबाए? कथनी और करनी; सिद्धांत और अभ्यास में इतना फर्क?

बाकी भी विद्यार्थी थे, भेड़चाल में पढ़े चले जा रहे थे कि एक दिन उनका समय भी आएगा, वे भी अच्छा पहनेंगे-खाएंगे। किशोर का मन उचटने लगा। उम्र के 18 साल पार करते ही वह युवा ईसाई पुरोहित बनाने वाले संस्थान से भाग निकला। घर लौटना आसान नहीं था, तो मंगलुरु में ही मजदूर बनकर आजाद जिंदगी की शुरुआत हुई। धर्म का पवित्र आदेश स्वीकारने और फिर पाखंडी करार दिए जाने के डर से घुटन महसूस करने के बजाय उन्होंने दुनिया का डटकर सामना करने का फैसला किया। पास में न बिस्तर था, न सिर पर छत, सड़कों पर जिंदगी बसर होने लगी। यही वह समय था, जब उनकी समाजवादी नेताओं से मुलाकात शुरू हुई, जो समता से भरे समाज का सपना देख रहे थे। यह मन ही मन शुरू में ही स्पष्ट हो गया कि शोषितों के हित में उद्योग मालिकों से लड़ना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए।

वह मंगलुरु से मुंबई आ गए। वहां भी मजदूरों के लिए झंडा उठाया। कुछ ही समय में मुंबई में उन्हें लोग श्रमिक नेता के रूप में जानने लगे। एक समय नारे लगते थे, टैक्सी चालकों का नेता कौन- जॉर्ज फर्नांडिस...जॉर्ज फर्नांडिस। दक्षिण मुंबई जैसी लोकसभा सीट पर उन्होंने कांग्रेस के एक दिग्गज नेता को ऐसी पटकनी दी कि वह फिर उबर न पाए। भारत में रेलवे की पहली और अंतिम हड़ताल का नेतृत्व उन्होंने किया। कई बार जेल गए। आपातकाल के समय भी जेल गए और जेल में ही उन्हें सूचना मिली कि वह मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव जीत गए हैं। पूरे देश को अपना क्षेत्र समझने वाले जॉर्ज फर्नांडिस (1930-2019) ताउम्र कुरता-पायजामा और चप्पल में रहे। वह देश के रक्षा मंत्री हुए, पर कपड़ों पर सिलवटें हों, तो कोई बात नहीं, इस देश के आम लोगों और मजदूरों के कपड़ों पर भी सिलवटें हैं। लोगों का नेता लोगों जैसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भूखी जनता के बीच खुद ऊंची कुरसी पर बैठ जाए और मालपुआ भोग लगाए। बेंगलुरु से मुंबई और बिहार तक बार-बार याद किए जाने वाले, 3 जून को जन्मे जॉर्ज फर्नांडिस कहते थे, 'इतिहास में रहने के बजाय हमें इतिहास से सीखना चाहिए।'

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

कोई तुझे भले न पूछे, तू अपने को पूछ

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

फिल्मों में अक्सर 'खलनायक' बनने वाला उस दिन समझा रहा था कि वोट देने जरूर जाना। एक हीरो समझा रहा था कि अरी जनता, वोट देना तेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है, वोट देने जाना। एक नेता जी कहे जा रहे थे कि वोट देने जरूर जाना जी! वोट देना आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है! मैं भी कहता रहा हूं कि वोट देने जरूर जाना, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। जब-जब चुनाव आए हैं, मैंने भी सबको कहा कि वोट देना जरूरी है, लेकिन एक भी मीडिया ने मुझे यह कहते कभी न दिखाया। जब दिखाया, तो 'सेलिब्रिटीज' को दिखाया, लेकिन मेरे जैसे देशभक्त, जनतंत्रभक्त लेखक को किसी ने यह कहते नहीं दिखाया कि कि वोट देने जरूर जाना जी!

इस बार जब मैं वोट डालने गया, तो ऐसे टाइम पर गया, जब चैनल वाले लाइव कवर करते हैं, लेकिन वहां न कोई रिपोर्टर मिला, न कोई कैमरा दिखा, जो मुझसे पूछता कि लेखक जी! आपको वोट देना कैसा लगा? देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? और मैं उंगली पर लगे स्याही के निशान दिखाते हुए कहता- वोट डालकर बड़ा बढ़िया लग रहा है, आप भी वोट डालने अवश्य जाएं।

आह! वह पंद्रह सेकंड का टीवी का अमरत्व मुझे आज तक नसीब न हुआ, जो हर नेता-अभिनेता को होता है। शायद इसीलिए मैं पाता हूं कि लेखक की किसी को जरूरत नहीं। हम जैसे लेखक, कवि, कहानीकार, आलोचक अपने आपको भले कहीं का तिम्मन खां समझते रहें, लेकिन सच यही है कि पूछने वाला कोई नहीं! आप ही बताइए, आज लेखक की हैसियत ही क्या है? आज न उसके लिखे को कोई भाव देता है, न उसके कहे को कोई मानता है और न उसकी हैसियत कोई पहचानता है।

ऐसे में, मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू कैसे बनूं? कैसे बताऊं कि लेखक होने के नाते जनतंत्र का पहला पहरेदार मैं हूं। उसी को बचाने के लिए मेरी कलम चलती है। यह जनतंत्र हमारी कलम से जिंदा है। जब तक कलम है, तब तक जनतंत्र है। मगर हम जैसों को पूछता कौन है? हम जो शब्द जगत के प्रजापति हैं, सृजनकर्ता हैं, आत्मा के शिल्पी हैं, युग निर्माता हैं, मशाल' हैं... सब मारे-मारे फिरते हैं। नेता की वोट के निशान वाली उंगली की पूछ है। अभिनेता की उंगली की पूछ है। आंटा-आंटी, नानी-दादी, सबकी उंगली की पूछ है, पर हमारी उंगली की नहीं। वे सब अपनी उंगली के निशान को दिखा-दिखाकर हमारे जैसे लेखक को जलाते हैं और हम जलते हैं।

यूं तो दिल्ली लेखकों की नगरी है। ईंट उठाओ, तो दस लेखक, बीस बुद्धिजीवी निकलते हैं, लेकिन जब-जब चुनाव आते हैं, सबकी पूछ होती है, लेखक की नहीं। और हो भी क्यों? न वह वोट बैंक है, न सेलिब्रिटी है और न ही किसी का सगा है, तब कोई क्यों लिफ्ट दे? फिर भी एक लेखक के रूप में हम न जाने किस नशे में रहते हैं और अपने को न जाने किस अलौकिक लोक का वासी समझते हैं।

हम में से हर कोई अपने को तुलसी, सूर, कबीर समझता है, कोई अपने को गालिब, मीर समझता है, तो कोई अपने को देश की तकदीर समझता है, लेकिन जब-जब चुनाव आता है, उसे उसकी औकात बता दिया जाता है। भजते रहिए टैगोर, निराला; अकड़ते रहिए प्रेमचंद, प्रसाद, पंत, अज्ञेय, मुक्तिबोध पर और बचाते रहिए जनतंत्र-लोकतंत्र! लेकिन जब जनतंत्र का पर्व आएगा, कोई नहीं पूछेगा।

आप भी कहेंगे कि मैं क्या रोना लेकर बैठ गया! अरे भई, लेखक का काम है लिखना, कोई नहीं पूछता तो शिकायत काहे की? लोग नेकी कर दरिया में डालते हैं, तू लिख-लिखकर में लोक में डालता चल! अगर, इतनी उपेक्षा पर भी आज हर व्यक्ति एक लेखक, कवि, कथाकार बनना चाहता है, तो इसीलिए कि लेखक का जनतंत्र ही असली जनतंत्र है। कोई तुझे पूछे न पूछे, तू अपने को पूछ! यही लेखक का जनतंत्र है। यही लेखक की कीमत है!

कटाक्ष

राजेंद्र धोड़पकर

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

परिणाम सदैव प्रयास के अनुपात में प्राप्त होता है

चुनाव प्रक्रिया के सबक

अंतिम चरण की 57 सीटों पर मतदान के साथ ही 18वीं लोकसभा के लिए सात चरणों वाली लंबी चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई। इसी के साथ एक्जिट पोल के नतीजे भी आ गए, लेकिन यह स्पष्ट ही है कि सभी को वास्तविक नतीजों की प्रतीक्षा है, जो 4 जून को आएंगे। इसी दिन पता चलेगा कि किसने बाजी मारी। एक्जिट पोल कुछ भी कह रहे हों, पक्ष और विपक्ष अभी भी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरह से यह अच्छा ही है। इस दावे का मतलब है कि दोनों ही पक्षों को यह भरोसा है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए। और भी अच्छा यह होगा कि हारने वाला पक्ष अपनी पराजय का दोष चुनाव आयोग अथवा अन्य किसी पर मढ़ने के बजाय आत्ममंथन करे। दुर्भाग्य से अब ऐसा कम ही होता है। हारने वाले राजनीतिक दल कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं, कभी मीडिया को कोसने लगते हैं और कभी-कभी तो जनता को ही नासमझ बताने लगते हैं। इससे राजनीतिक दलों की अपरिपक्वता का ही परिचय मिलता है। हमारे देश के राजनीतिक दलों को अभी काफी कुछ सीखने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति इसलिए की जानी चाहिए, क्योंकि करीब दो माह के लंबे चुनाव प्रचार के दौरान अनेक दलों ने नकारात्मकता का परिचय दिया और ऐसे विषयों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, जो जनहित के विषय ही नहीं थे। चुनाव में जब जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता नहीं मिलती, तब उससे जनता के साथ-साथ दलों को भी नुकसान उठाना पड़ता है।

इस बार के आम चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपने-अपने घोषणा पत्रों के बजाय दूसरे दलों के घोषणा पत्रों का उल्लेख अधिक किया और वह भी आधे-अधूरे ढंग से। इस बार अपेक्षा से कम मतदान भी चर्चा का विषय रहा। यह चर्चा का विषय बनना भी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक हद तक राजनीतिक दल भी जिम्मेदार हैं। वे जनता को बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक जाने के लिए प्रेरित नहीं कर सके। अपेक्षा से कम मतदान पर चुनाव आयोग को भी गंभीरता से विचार-विमर्श करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे इस पर तो अनिवार्य रूप से विचार करना चाहिए कि मई-जून की भीषण गर्मी में चुनावों से कैसे बचा जाए? हैरानी नहीं कि कम मतदान का एक कारण प्रतिकूल मौसम भी रहा हो। जो भी हो, चुनाव आयोग को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि अंतिम चरणों के मतदान के दौरान मतदाताओं के साथ-साथ चुनाव कराने वाले कर्मचारियों के साथ सुरक्षा कर्मियों को भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी। कई चुनाव एवं सुरक्षा कर्मियों की तो लू लगने से मौत भी हो गई। निःसंदेह यह भी अच्छा नहीं हुआ कि देश के कुछ हिस्सों और विशेष रूप से बंगाल में चुनावी हिंसा देखने को मिली। बंगाल को चुनावी हिंसा से मुक्ति न मिलना एक गंभीर चिंता की बात है।

अब विकास की बात

समूचे देश में लोकसभा चुनाव के महापर्व का सातवें चरण की वोटिंग के साथ ही समापन हो गया है। आखिरी चरण के मतदान में झारखंड की तीन सीटों पर भी वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई। लगभग दो महीने लंबी इस चुनाव प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से विकास और सामान्य प्रशासन के कार्य बाधित हुए। अब चार जून को मतगणना के साथ ही आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद झारखंड में बंद पड़ी विकास प्रक्रिया पर तीव्र गति से काम करना होगा। राज्य में सड़क, आवास निर्माण समेत कई आधारभूत संरचना पर काम होना है। इससे एक ओर जहां लोगों को सहूलियत मिलती है, वहीं दूसरी ओर यह रोजगार सृजन का भी एक माध्यम है। खास बात यह है कि इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अक्टूबर के बाद राज्य विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अगले दो महीने तक फिर से आचार संहिता लागू रहेगी। जून से सितंबर के बीच राज्य में मानसून की बारिश भी होती है। नई योजनाओं में किसानों के लिए भी राहत की उम्मीद है। खेती किसानी के इस मौसम में निर्णय लेने में तेजी और डिलीवरी सिस्टम को अपडेट करना होगा। चुनाव के बाद केंद्र की नई सरकार भी अपने घोषणापत्र के हिसाब से सभी वर्गों के लिए योजनाओं को लागू करेगी। इसके लिए भी राज्य सरकार की मशीनरी को तैयार रहना होगा। लोकतंत्र के महापर्व का समापन विकास गाथा की शुरुआत का अवसर बने, इसके लिए सरकार समेत सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उम्मीद की जा सकती है कि आचार संहिता हटने के बाद राज्य में विकास की गति तेज होगी।

चार जून की मतगणना के बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी, जिसके बाद विकास की गति होगी तेज

लापरवाही की भेंट चढ़ती जिंदगियां

संजय गुप्त

वैसे तो प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षा के नियम-कानून हैं, लेकिन वे कागजों पर ही अधिक रहते हैं और इसी कारण उनकी अवहेलना होती दिखती है

अवधेश राजपूत

पिछले दिनों गुजरात के राजकोट शहर में एक गेमिंग सेंटर में आग लगने से 28 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके कुछ दिनों बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक बेबी केयर सेंटर में भी आग लगने से सात नवजात मौत के मुंह में समा गए। एक के बाद एक घटी इन दोनों घटनाओं से देश दहल सा उठा। इस तरह की घटनाएं कोई नई नहीं हैं। इस जैसी न जाने कितनी घटनाएं अपने देश में होती ही रहती हैं, जिनमें लोग जान भी गंवाते हैं। आम तौर पर ये घटनाएं नगर निकायों की कामचलाऊ प्रवृत्ति और उनके अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही एवं घूसखोरी का नतीजा होती हैं। राजकोट के गेमिंग सेंटर में न तो आग से बचाव के कोई उपाय थे और न ही उसके संचालन की कोई स्वीकृति नगर निकाय से हासिल की गई थी। वहां दर्शकों का प्रवेश जारी था और वेल्डिंग का काम भी हो रहा था। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में भी आग से बचाव का कोई उपाय नहीं था। वहां अग्निशमन यंत्र तक नहीं थे। इस बेबी केयर सेंटर को चलाने के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वह चल रहा था। वहां सुरक्षा के अन्य उपाय भी नहीं थे। इस बेबी केयर सेंटर में क्षमता से अधिक बच्चों का उपचार हो रहा था।

अपने देश में नगर निकाय अथवा अग्निशमन विभाग एवं ऐसी ही अन्य नगरीय संस्थाओं की अनदेखी के कारण लगातार घटनाएं होती चली आ रही हैं। ऐसी हर घटना में नगरीय निकायों की नाकामी तो उजागर होती ही है, उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार का भी पता चलता है। चूंकि इन घटनाओं में बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, इसलिए देश की छवि पर बुरा असर पड़ता है और उसे शर्मसार भी होना पड़ता है। जैसा कि हमेशा होता है, हर बड़ी घटना के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं और नेता-नौकरशाह यह आश्वासन देते हैं कि स्थितियां सुधारी जाएंगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होने दी जाएंगी। आग लगने की घटनाओं के मामले में यह भी देखने में आता है कि शहर विशेष के अस्पतालों, होटलों, मनोरंजन स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों की छानबीन शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वैसी ही घटना घट जाती है। इन घटनाओं में जब लोग मारे जाते हैं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत अन्य नेतागण पीड़ितों को सांत्वना देते हैं, लेकिन घटना के कारणों का निवारण सही तरह से नहीं किया जाता। इसी कारण स्थितियां जस की तस बनी रहती हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के उपाय मजबूत बनाने पर ध्यान नहीं दिया जाता।

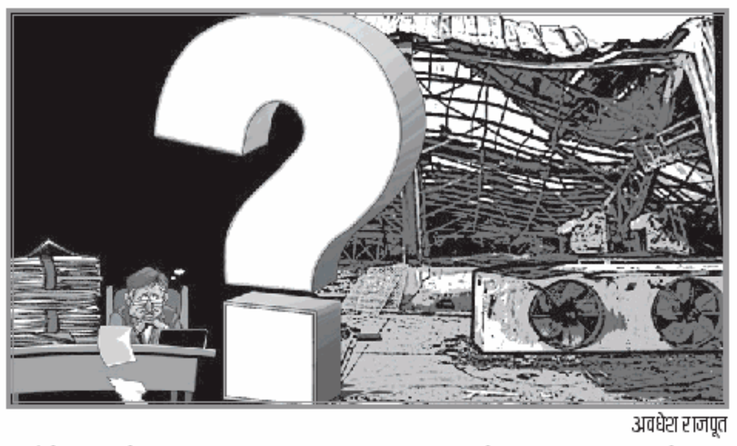

वैसे तो प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षा के नियम-कानून हैं, लेकिन वे कागजों पर ही अधिक रहते हैं और इसी कारण हर जगह उनकी अवहेलना होती दिखती है। बात चाहे मनोरंजन स्थलों की हो या व्यावसायिक स्थलों, होटलों, अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे एवं बस स्टेशनों की-हर जगह अव्यवस्था और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ही अधिक दिखती है। एक समस्या यह भी है कि औसत भारतीय नागरिक सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाही का परिचय देता है। वह भीड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासन का भी परिचय नहीं देता। अपने देश में प्रत्येक सार्वजनिक अथवा व्यावसायिक स्थल के लिए नगरीय निकायों से सुरक्षा मानकों के प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। वह उन्हें आसानी से मिल भी जाता है, लेकिन जब कोई घटना घट जाती है तो यही सामने आता है कि सुरक्षा उपायों की या तो अनदेखी हो रही थी या वे केवल कागजों पर ही थे। राजकोट की घटना के बाद यह सामने आया कि गुजरात में चलने वाले अधिकांश गेमिंग सेंटरों में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं थे। दिल्ली की घटना के बाद भी यह सामने आया कि कई अस्पतालों में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध नहीं हैं। प्रश्न यह है कि ऐसे स्थान सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर कैसे चलते रहते हैं? कोई भी समझ सकता है कि इसका कारण नगरीय निकायों के भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं, जो पैसे लेकर दिखावटी जांच करते हैं और पर्याप्त सुरक्षा उपाय न होने पर भी आवश्यक प्रमाण पत्र भी दे देते हैं।

भ्रष्टाचार के चलते सुरक्षा मानकों की जो अनदेखी हो रही है, वह तब तक नहीं रुकने वाली, जब तक जिम्मेदार नेताओं और नौकरशाहों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। हर घटना के बाद नेतागण नौकरशाहों पर दोष मढ़ देते हैं और नौकरशाह निचले स्तर के कर्मचारियों पर। कभी-कभी किसी अधिकारी-कर्मचारी का निलंबन भी हो जाता है, लेकिन उन्हें अपने किए की कोई ऐसी सजा नहीं मिलती, जो नजीर बन सके। वे कुछ समय बाद फिर नौकरी पर बहाल हो जाते हैं। उनकी नौकरी शायद ही कभी जाती हो। हमारे अधिकांश नेतागण जमीनी स्तर पर राजनीति शुरू करके मंत्री पदों तक भी पहुंचते हैं, लेकिन वे नगरीय निकायों के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कभी सक्रिय नहीं होते। इसका कारण यह है कि भ्रष्टाचार में अक्सर उनकी भी मिलीभगत होती है। यह समय की मांग है कि नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों और इसी तरह विधायकों, सांसदों एवं मंत्रियों आदि के कामकाज का आकलन इस आधार पर हो कि वे व्यवस्था को सुधारने और विशेष रूप से सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के उपाय लागू करने में कितने सफल हैं? अक्षम एवं भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों को उनके खराब कामकाज के लिए पदों से हटाने की कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

यह सही समय है कि जनप्रतिनिधियों के मामले में राइट टू रिकाल की व्यवस्था लागू की जाए, ताकि उनके अंदर यह भय व्याप्त हो कि यदि वे अपना काम सही तरह से नहीं करेंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। भ्रष्ट एवं अक्षम नौकरशाहों के मामले में भी ऐसा कुछ करना होगा। उन्हें उनकी दायित्वहीनता के लिए जवाबदेह बनाना होगा और दंडित करना होगा। वे जवाबदेह तब बनेंगे, जब उनकी गलतियों के लिए उन्हें वास्तव में जिम्मेदार ठहराने के नियम बनेंगे और जनता अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगी। ऐसे लोकतंत्र का कोई लाभ नहीं, जिसमें निर्वाचित संस्थाओं के पदाधिकारी अपना काम सही तरह से न करें। वास्तव में ग्राम पंचायतों से लेकर नगर निकायों के कामकाज की नए सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए और उनके कामकाज को सुधारने के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए, ताकि रह-रहकर होने वाली दुर्घटनाओं से मुक्ति मिल सके।

response@jagran.com

अबकी बार पारा पचास के पार

हास्य-व्यंग्य

कमल किशोर सक्सेना

नौतपा की तपिश में पत्थर जैसे दिमाग भी पिघल गए हैं। सूर्यदेव के तेज के समक्ष जीवन की लौ मद्धम हो चली है

मकई के दाने के पापकार्न बनने की प्रक्रिया समझनी हो तो आजकल धूप में खड़ी बाइक की गद्दी पर बैठकर देखिए। खुद को बड़ा 'स्नानवीर' समझते हों तो छत पर रखी टंकी के पानी से नहा लीजिए। 'आग का दरिया' तैर कर जाने की बात करने वालों, जरा सड़कों पर पिघलते तारकोल की 'काली वैतरणी' पार करके देखिए। यही जवाब मिलेगा 'बारंबार-अबकी बार हाहाकार, पारा पचास के पार।'

आजकल संपूर्ण उत्तर भारत की हालत चूल्हे पर चढ़े तवे जैसी हो गई है। बर्फ तक से धुआं निकल रहा है। लगता है कि उसे भी पसीना आ रहा है। गर्मी से लोगों के चेहरे झुलस गए हैं। समझना मुश्किल है कि ओरिजिनली किसका रंग दबा हुआ है और किसने चेहरे पर मौसम से फेशियल करवाया है। सूर्यदेव का तेज इतना विकराल है कि जीवन की लौ मद्धम हो चली है। कपड़ों में दांत उग आए हैं। पहनते ही काटने को दौड़ते हैं। मौसम कुछ ऐसा हो चला है कि धुले हुए कपड़े तुरंत सूख जा रहे हैं और सूखे कपड़े पसीने की जुगलबंदी से प्रीमियम तत्काल में गीले हो जा रहे हैं। पशु-पक्षी से लेकर चल-अचल सभी जीव-जंतु त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जमीन पर रेंगती चींटियों को कुत्ते के मुंह से टपकती लार की आस है। कुत्तों को हड्डी से अधिक चिकन सूप की प्यास है। घोर कलयुग आ गया है। किसने सोचा था कि बिजली के दो खंभों, कार, बाइक और स्कूटी के सगे पहियों में, आपस में ही ठन जाएगी और वह भी महज एक कुत्ते के लिए। हमारे यहां जेठ के महीने को महत्वपूर्ण माना गया है। संयुक्त परिवार में अब इसका भले उतना महत्व न रह गया हो, मगर हिंदू पंचांग में इसके नाम से आज भी पतलून भीग जाती है और कैलेंडर गीला हो जाता है। ऊपर से नौतपा। गरीबी में गीले आटे के गुलगुले बनाने की हिम्मत की जा सकती है, लेकिन जेठ का नौतपा। भाड़ भी इसके आगे दंडवत है। आजकल वही चल रहा है। इस पीढ़ी के कई लोग 'नौतपा' का नाम भी नहीं जानते थे, मगर अबकी बार उनके सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि हुई है। नौतपा की तपिश में पत्थर जैसे ठोस दिमाग भी पिघल गए हैं। दूध के दही बनने में फिर भी समय लगता है, किंतु भीषण गर्मी ने अच्छे-अच्छे दिमागों का रायता बनाकर रख दिया है।

सुबह मैं अपने घर की बगिया में टहलने गया तो एक नन्हा पौधा आंखों में आंसू लिए उदास दिखा। मैंने उससे कारण पूछा तो उसने कहा-तुम्हारी बेचैनी देखकर ही मैं दुखी हूं, लेकिन इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। विकास की दौड़ में अपने पालनकर्ता की गोद सूनी कर दी। प्रकृति के जंगल कम हो गए। कंक्रीट के बढ़ गए। शहरों में गगनचुंबी इमारतें तो बेशुमार हैं, लेकिन राहगीरों को छांव देने वाले मेरे पूर्वज पेड़ लगातार कम हो रहे हैं। घरों में लगे एसी गरम हवा छोड़ रहे हैं, किंतु आक्सीजन देने वाले मेरे पितामह को यह जहां छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पहाड़ भी नंगे हो गए हैं। उन पर से हरियाली गायब है। उसकी जगह प्लास्टिक तथा अन्य कचरे ने ले ली है। इन हालात में बताओ, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं। लाखों करोड़ों वृक्षों की हत्या का दंड है ये, जो आज तुम लोग भोग रहे हो। सूरज की तपिश को रोकने वाली ढाल पर तो खुद तुमने कुल्हाड़ी चला दी। मेरे बड़े होकर पेड़ बनने और ठंडी छांव देने में समय है। तब तक क्या करोगे।

उसकी बातों से अब मेरी आंखें नम हो गई हैं। फिर तो घर में रखी मेज-कुर्सी-पलंग आदि हर फर्नीचर मुझे अखरने लगा, क्योंकि सबके भीतर किसी न किसी पेड़ का आत्मा बसा था।

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रेरणा पुंज

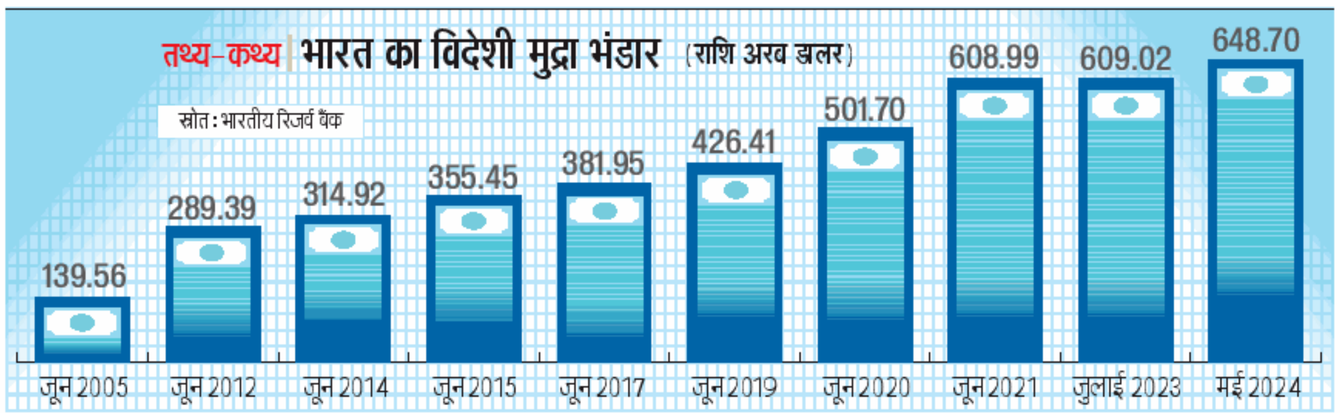

महानता एक दिन में प्राप्त नहीं होती। महान व्यक्तियों के जीवन का समग्र देखा जाता है कि उन्होंने अपनी सीमाओं से परे जाकर कितनी उपलब्धियां हासिल कीं। इसका अर्थ यह नहीं होता कि उनका जीवन सर्वदा त्रुटिरहित है। उन्होंने संघर्षों में स्वयं को घिस-घिस कर चमक पाई होती है। उनसे त्रुटियां हुई होंगी, जिनको उन्होंने सुधारा होगा। तभी वे नायक-महानायक के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार मानव मन ने जिसे नायक स्वीकार कर लिया उसे आदर्शों के इतने उच्च प्रतिमानों पर बैठा देता है कि वहां से उसके तनिक भी दोष हमारी श्रद्धा को हिला देते हैं। इतिहास में कोई भी अवतार, महापुरुष, नायक या सुधारक ऐसा नहीं देखा गया जो आलोचनाओं का शिकार न बना हो। कारण सिर्फ वही कि यदि वे महापुरुष हैं तो उनसे एक भी त्रुटि कैसे हुई? प्रकृति के नियमों के अधीन रहकर क्या ऐसा कोई आदर्श व्यक्तित्व संभव है जो त्रुटिरहित हो?

भगवान श्रीकृष्ण का एक नाम रणछोड़ है, जिसका अर्थ है रणभूमि छोड़कर भागने वाला। राजा कालयवन को अजेय रहने का वरदान था। श्रीकृष्ण जब उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सके तो उन्होंने रणछोड़ दिया और वहां से भाग निकले। रण से भागना उनकी युद्धनीति थी। अपने पीछे आते कालयवन को उन्होंने युक्तिपूर्वक एक गुफा में भेजा। गुफा में सोए राजा मुचकुंद के क्रोध का पात्र बनकर भस्म होकर कालयवन काल की भेंट चढ़ गए। इस उद्धरण का उद्देश्य यह संदेश देना था कि यदि ऐसी परिस्थिति आए तो युद्ध छोड़कर युक्ति का प्रयोग कर लेना उचित है, भले ही युद्ध छोड़ना आदर्श के प्रतिमानों पर खरा न उतरता हो।

किसी भी महान पुरुष के चरित्र में भिन्न-भिन्न अतिमानवीय एवं अतिआदर्शवादी अपेक्षाएं जोड़ देना सही नहीं है। महापुरुषों या अवतारों का पूरा ही जीवन अध्ययन का विषय और एक प्रेरणा पुंज जैसा होता है। हमें उनके जीवन से समग्रता में सीख लेनी चाहिए। ट्विंकल तोमर सिंह

हृदय की धमनियों में माइक्रोप्लास्टिक

मुकुल व्यास

धमनियों और नसों के लिए माइक्रोप्लास्टिक नुकसानदेह है, लिहाजा इससे बचाव का उपाय किया जाना चाहिए

पृथ्वी पर हर जगह माइक्रोप्लास्टिक (प्लास्टिक के अत्यंत सूक्ष्म कण) पहुंच चुके हैं। मानव अंगों में भी उनकी उपस्थिति बढ़ रही है। इस साल की शुरुआत में एक बड़े अध्ययन में अवरुद्ध धमनियों में जमा वसा के 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सों में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए थे। यह मानव स्वास्थ्य पर उसके प्रभावों के बीच संबंध स्थापित करने वाला अपनी तरह का पहला डाटा था। अब चीन के शोधकर्ताओं के एक नए अध्ययन में हृदय और मस्तिष्क की धमनियों तथा निचले पैरों की नसों से शल्य चिकित्सा द्वारा निकाले गए रक्त के थक्कों में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की जानकारी मिली है। ताजा चीनी अध्ययन में 30 रोगियों को शामिल किया गया, जबकि मार्च में प्रकाशित इतालवी अध्ययन में 34 महीनों तक 257 रोगियों का अनुसरण किया गया था। इतालवी विज्ञानियों की नेतृत्व वाली टीम ने पता लगाया था कि धमनियों की जमावट अथवा प्लेक में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी लोगों में दिल के दौरे या स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाती है। अब चीनी टीम ने भी रक्त के थक्कों में माइक्रोप्लास्टिक के स्तर और बीमारी की गंभीरता के बीच संभावित संबंध को रेखांकित किया है।

इस अध्ययन में शामिल 30 रोगियों को स्ट्रोक, दिल का दौरा या डीप वेन थ्रोंबोसिस का अनुभव होने के बाद रक्त के थक्कों को हटाने के लिए सर्जरी करानी पड़ी थी। डीप वेन थ्रोंबोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैरों की गहरी नसों में रक्त के थक्के बनते हैं। लिहाजा इनमें रक्त के 30 थक्कों का अध्ययन किया गया। इनमें से 24 में रासायनिक विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न आकारों के माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाया गया। परीक्षण में उसी प्रकार के प्लास्टिक की पहचान की गई जो इतालवी अध्ययन में पाए गए थे। ये प्लास्टिक हैं पालीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) और पालीइथिलीन (पीई)।

पहचाने गए 15 प्रकारों में से, पीई सबसे आम प्लास्टिक था। विश्लेषित कणों में इसका हिस्सा 54 प्रतिशत था। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि जिन लोगों के रक्त के थक्कों में माइक्रोप्लास्टिक का स्तर अधिक था, उनमें डी-डिमर का स्तर भी उन रोगियों की तुलना में अधिक था, जिनके रक्त थक्कों में माइक्रोप्लास्टिक नहीं पाया गया था। डी-डिमर प्रोटीन का एक टुकड़ा है जो रक्त के थक्कों के टूटने पर निकलता है। यह सामान्य रूप से रक्त प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है। इसलिए रक्त परीक्षण में डी-डिमर का उच्च स्तर रक्त के थक्कों की उपस्थिति का संकेत दे सकता है। शोधकर्ताओं को संदेह है कि माइक्रोप्लास्टिक रक्त में जमा होकर थक्के को बदतर बना सकता है। लेकिन इसकी जांच के लिए अधिक शोध की जरूरत है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

कूटनीतिक गलियारों की दुविधा

आम चुनाव के परिणाम को लेकर राजनीतिक दल और उनके कार्यकर्ताओं के बीत पसरा तनाव तो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन राजधानी दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में भी इस मामले में टेंशन कम नहीं है। उच्च आयोगों-दूतावासों से पत्रकारों को एक नहीं, बल्कि कई स्तरों पर फोन करके पूछा जा रहा है कि माहौल क्या है और किसकी कितनी संभावनाएं हैं। दूतावासों एवं मिशनों में चुनाव पर नजर रखने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। उनसे हर चरण के चुनाव के बाद का स्टेटस मांगा जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे रणनीतिक साझेदार देशों के स्तर पर चुनाव परिणाम समझने की चिंता को तो समझा जा सकता है, लेकिन यूरोप के कई छोटे-छोटे देश भी भावी परिणामों को लेकर बेचैन हैं। पिछले दिनों कुछ मिशनों के सदस्य संयुक्त तौर पर एक कूटनीतिक सम्मेलन में बहस के लिए जुटे, लेकिन पूरी बातचीत चुनाव परिणामों पर होती रही। बैठक में शामिल एक भारतीय अधिकारी को कहना पड़ा कि, 'अच्छा हो कि हम अब राजनयिक संबंधों पर भी कुछ चर्चा कर लें।'

भाग्य के सहारे चमत्कार

अंतिम चरण की वोटिंग के बाद लोकसभा चुनाव के नतीजों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है तो संभावित नतीजों को लेकर भी राजनीतिक दल अपनी भावी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। विपक्षी गठबंधन में इसे लेकर सक्रियता कुछ ज्यादा है और इसलिए वैकल्पिक राजनीतिक योजना के साथ-साथ गठबंधन के नेता पद को लेकर भी कानाफूसी चल रही है। बेशक औपचारिक तौर पर गठबंधन के नेतृत्व को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, मगर संकेत हैं कि अगर आइएनडीआइए के लिए चुनावी संभावनाएं बनीं तो विपक्षी गठबंधन देश को पहला दलित प्रधानमंत्री देने के विकल्प पर चिंतन-मनन करेगा। विपक्षी खेमे की इन अंदरूनी चर्चाओं से साफ है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आइएनडीआइए के नेतृत्व की पहली पसंद बन सकते हैं। घटक दलों की ऐसी राय मुखर हुई तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे यह भी कम रोचक नहीं कि एक समय खरगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते-बनते रह गए, मगर राजनीतिक स्थिति ऐसी बनी कि वह आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शायद तभी नतीजों से पहले आइएनडीआइए की बैठक में हिस्सा लेने आए सहयोगी दल के नेता ने सियासत में किस्मत फैक्टर की बात करते हुए कहा कि कौन जाने कहीं खरगे का भाग्य ही विपक्ष के लिए चमत्कार ले आए।

राजरंग

'रीयल' नहीं तो 'रील' सही

चुनावों के दौरान जनता दल-सेक्युलर के नेता प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल मामला सामने आया तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री बलकार सिंह का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ। इंटरनेट मीडिया पर दोनों की खूब बखिया उधेड़ी जा रही हैं। उन्हें लेकर विरोधी राजनीतिक दल भी खुलकर मैदान में हैं, क्योंकि हमले का मौका जो मिल गया। विरोध का यह मोर्चा केवल रीयल ही नहीं, बल्कि रील यानी रुपहले पर्दे को लेकर भी खुला रहा। दिल्ली से भाजपा सांसद और फिर से लोकसभा पहुंचने के प्रयास में लगे मनोज तिवारी को उनके गानों की क्लिप निकालकर घेरने की कोशिश हुई तो गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के खिलाफ भी यही दांव आजमाया गया। यह जानते हुए भी कि यह वास्तविक नहीं, बल्कि महज अभिनय का मामला है, फिर भी इससे परहेज नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि जब मुद्दों का संकट हो और वाकई घेरने को कुछ न मिले तो विरोधियों को रील की क्लिप में ही सियासी दम दिखने लगता है। चुनाव में रील की क्लिप कितनी हिट रही या फ्लाप इसका पता परिणाम से ही सामने आएगा।

हौसले की उड़ान

लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या रहेंगे यह तो चार जून को ही पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक दल अलग-अलग किस्म के आंकड़ों के जरिये अपनी जीत को लेकर उड़ान भरते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने हाल ही में एक ऐसा आंकड़ा जारी करके बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान उसके वीडियो एवं दूसरी प्रचार सामग्रियों को इंटरनेट मीडिया पर भाजपा के मुकाबले कहीं ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। कार्यकर्ताओं का हौसला कायम रखने के लिहाज से यह नए किस्म की युक्ति बन गई।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

https://t.me/AllNewsPaperPaid

शिकंजे में प्रज्वल

कर्नाटक के हाई प्रोफाइल सैक्स स्कैंडल में अंतत: जद(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी से लौटते ही बैंगुलरु हवाई अड्डे पर विशेष जांच दल ने गिरफ्तार कर लिया। प्रज्वल की गिरफ्तारी के लिए महिला आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मियों ने प्रज्वल को आते ही घेर लिया जिससे एक सकारात्मक संदेश गया कि महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि वह किसी भी आरोपी को पकड़ सकती हैं। खासतौर पर जब मामला महिलाओं के यौन उत्पीड़न का हो। वर्तमान राजनीति में जब नैतिकता और मर्यादाएं कहीं नजर नहीं आ रही हों तो ऐसे मामले सामने आने पर कोई आश्चर्य नहीं होता। जेहन में यही सवाल उठता है कि वह इंसान है या भेड़िया अथवा कोई हवसी जानवर है। हालांकि कानून की भाषा में प्रज्वल पर अभी यह आरोप है लेकिन क्या वीडियो सम्पादित हो सकते हैं। प्रज्वल के वीडियो की पैन ड्राइव कर्नाटक में आसानी से उपलब्ध है। राजनीति में प्रतिष्ठित परिवार के बंगले के भीतर दुराचार और जघन्य अपराध की घटना ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के सम्मान पर कालिख पोत दी है। उनके पौत्र प्रज्वल पर ही नहीं बल्कि उसके पिता और विधायक एच.डी. रेवन्ना पर भी आरोप लगे। अगर उस पर आरोप लगे थे तो उसे भारत में रहकर कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी लेकिन प्रज्वल के जर्मन भाग जाने से शक और पुख्ता हो गया।

जब प्रज्वल के वीडियो सामने आ गए तो यौन उत्पीड़न का शिकार कुछ महिलाएं भी साहस बटोर कर सामने आई और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बाप-बेटे की दबंगई के सामने यौन उत्पीड़न का शिकार अनेक महिलाएं अब भी खामोश हैं। समाज और परिवारों के डर से वे खामोश ही रहेंगी। विडम्बना तो यह है कि बड़े नेता महिला सशक्तिकरण का ढिंढोरा तो पीटते हैं लेकिन वे व्यावहारिक जीवन में दुराचार की प्राकाष्ठा देख कर भी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। कई नेता इस शर्मनाक कांड की व्याख्या अपनी सुविधा की राजनीति के अनुसार कर रहे हैं। सवाल तो उठ रहे हैं कि जब इस स्कैंडल की जानकारी एक वर्ष पहले ही मिल गई थी तो राज्य सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। महिलाओं की अस्मिता से जुड़े इस मामले की जानकारी होने पर भी सभी दलों के नेता खामोश क्यों रहे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह भी है कि देवेगौड़ा परिवार की एक समुदाय विशेष पर काफी पकड़ है और वोट बैंक के चलते सब चुप रहे। आम लोग तो यही कहते हैं कि राजनीतिक दल एक-दूसरे के नेताओं को बचाने के लिए तब तक सुरक्षा कवच बने रहते हैं जब तक पानी हद से नहीं गुजर जाता।

विडम्बना तो यह है कि बड़े नेता महिला सशक्तिकरण का ढिंढोरा तो पीटते हैं लेकिन वे व्यावहारिक जीवन में दुराचार की प्राकाष्ठा देख कर भी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। कई नेता इस शर्मनाक कांड की व्याख्या अपनी सुविधा की राजनीति के अनुसार कर रहे हैं। सवाल तो उठ रहे हैं कि जब इस स्कैंडल की जानकारी एक वर्ष पहले ही मिल गई थी तो राज्य सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। महिलाओं की अस्मिता से जुड़े इस मामले की जानकारी होने पर भी सभी दलों के नेता खामोश क्यों रहे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह भी है कि देवेगौड़ा परिवार की एक समुदाय विशेष पर काफी पकड़ है और वोट बैंक के चलते सब चुप रहे।

अब जबकि प्रज्वल पुलिस के शिकंजे में है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जांच निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ेगी। यौन उत्पीड़न के मामलों में दोष सिद्धि और सजा की दर बहुत कम होती है। खासतौर पर उन मामलों में जिन में प्रभावशाली लोग शामिल हैं। सबूतों को तोड़ने-मरोड़ने और कानूनी बारीकियों की मनचाही व्याख्याएं करने और कानूनी दांव-पेंचों से मामले को लटकाने की हर कोशिश अब भी की जाएगी। केन्द्र सरकार ने तीन महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन कर एक नई न्याय प्रणाली बनाई है। उसी के तहत अपराध के मुताबिक दंडात्मक कार्रवाई भी की जानी चाहिए। मामले की निष्पक्ष और गंभीरता से जांच हो तो अदालत को सही नतीजे पर पहुंचाने में मदद मिल सकती है। प्रज्वल ने इस बार भी लोकसभा का चुनाव लड़ा है। मतदान से ही पता चलेगा कि वह चुनाव जीतता है या नहीं। निस्संदेह ऐसे दागी जनप्रतिनिधि का चुना जाना लोकतंत्र के दामन पर एक दाग सरीखा होगा। अब जिम्मेदारी एसआईटी की है कि वह इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता दिखाती है।

देवेगौड़ा परिवार प्रज्वल के बचाव में देश के नामी-गिरामी वकीलों की फौज अदालत में खड़ी कर सकता है। हो सकता है कि मामला अदालतों तक पहुंचते-पहुंचते कुछ खुलासे भी हो। ऐसे मामलों में देखा जाता है कि महिलाएं लंबी कानूनी प्रक्रिया के चलते अपना बयान बदल लें लेकिन इसका अर्थ यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि उनके साथ अत्याचार हुआ ही नहीं। यह अपने आप में एक वीभत्व प्रकरण है। यौन उत्पीड़न की शिकार घर की नौकरानी से लेकर दफ्तर में काम करने वाली पार्टी की महिला कार्यकर्ताएं और नेता जी की सिफारिश पर नौकरी पाने वाली लड़कियां भी शामिल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीड़ित महिलाओं को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। इस मामले पर लीपा-पोती और टालमटोल कर रवैया अपनाने से जन आक्रोश फैल सकता है। संस्कृति और धर्म शास्त्रों की दुहाई देने वाले लोग क्या अब भी खामोश बैठे रहेंगे या महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जांच पर पैनी नजर रखकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ने को तैयार होंगे। समाज को भी यह सबक लेना चाहिए कि यौन शोषण करने वाले लोगों को जनसेवक के तौर पर निर्वाचित करना कितना घातक सिद्ध हो सकता है।

आदित्य नारायण चोपड़ा

Adityachopra@punjabkesari.com

अवसर रुठे रहते हैं हम उन...

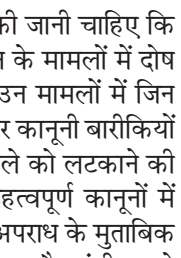

गीता पाढा

जिंदगी सबसे हसीन झूठ है ये हम जान ही नहीं पाते,
और मौत एक कटु सत्य है ये बात जानकर भी हम मान नहीं पाते,
अक्सर रुठे रहते हैं हम उन रिश्तों से,
जिनके बिना हम जिंदगी के मायने पहचान नहीं पाते...!!

न्यूयॉर्क में 'आजाद फलस्तीन' के बैनर लहराए

न्यूयॉर्क, (एपी): अमेरिका में सैकड़ों फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार दोपहर को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन संग्रहालय तक मार्च किया और उसके परिसर में तंबू लगाने के अलावा इमारत की छत से 'आजाद फलस्तीन' के बैनर लहराए। इसके बाद पुलिस ने संग्रहालय में पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क शहर के पुलिस अधिकारियों की संग्रहालय के बाहर भीड़ में शामिल लोगों से मारपीट हुई और कुछ प्रदर्शनकारियों ने भी अधिकारियों पर प्लास्टिक की बोतलें फेंकीं एवं

ब्रुकलिन संग्रहालय तक मार्च किया

अपमानजनक नारे लगाए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने भव्य 'बीक्स आर्ट्स संग्रहालय' की सीढ़ियों पर हाथ में बैनर लेकर फलस्तीनी ध्वज लहराने के साथ जोरदार नारे लगाए। यह शहर का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है।

रैली की शुरुआत शुक्रवार दोपहर में 'बार्कलेज सेंटर' की सड़क पर हुई। रैली में शामिल लोग ढोल बजाते और नारे लगाते हुए लगभग एक मील दूर संग्रहालय की ओर बढ़े।

चंडीगढ़-पंजाब में आप-कांग्रेस की धाक

'बेवफा तेरे आने का हर तरफ
इतना शोर क्यों है
तूने एक चेहरे पर लगा रखे हैं
हजार चेहरे, पर तू मेरी ओर क्यों है'

जम्हूरियत के सबसे बड़े महापर्व का समापन हो गया। इस 1 जून को पंजाब की 13 और चंडीगढ़ केंद्र शासित सीट पर मतदान संपन्न हुआ। मजे की बात तो यह कि पंजाब में भाजपा ने 13 सीटों पर जो अपने प्रत्याशी उतारे इनमें से 11 अन्य पार्टियों से आयातित थे। अकाली पूरी तरह इन चुनावों में दरकिनार होते दिखे सो, उन्होंने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' की बरसी के चलते पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। सो, इस मौके को भुनाने के लिए अकालियों ने पंजाब के गुरुद्वारों के बाहर पोस्टर लगा दिए, कांग्रेसी दिग्गज मनीष तिवारी कमजोर पिच पर खेलते नज़र आए, पर 20 मई के बाद धीरे-धीरे उन्होंने अपने पक्ष में माहौल बना लिया। उन्होंने चंडीगढ़ के 'गवर्नेंस मॉडल' को परिभाषित करने के लिए अपना एक विजन डॉक्यूमेंट 'सिटी स्टेट मॉडल' भी रिलीज किया जो खासा चर्चा में रहा।

आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी उनके पक्ष में चुनावी अलख जगाने के लिए चंडीगढ़ पधारे। प्रियंका गांधी जब राजीव शुक्ला के साथ हेलिकॉप्टर से चंडीगढ़ उतरीं तो हेलीपैड पर प्रियंका को जैसे ही मनीष ने रिसीव करते हुए फूलों का गुलदस्ता भेंट किया तो प्रियंका ने एक झटके में मनीष से पूछ लिया, 'पवन बंसल जी नहीं आए?' तो मनीष ने किंचित भावुक होते हुए कहा -मैंने

उनसे रिक्वेस्ट की थी, उनसे फोन पर भी रोजाना बात हो जाती है, पर चुनाव में वे मेरे साथ नहीं आए। इस पर प्रियंका ने अपने सचिव से बंसल को फोन लगाने को कहा, जैसे ही बंसल लाइन पर आए प्रियंका ने छूटते ही उनसे कहा-मैं एक जनसभा को संबोधित करने जा रही हूं, आप भी मंच पर उपस्थित रहिएगा। यह सुनने भर कि देर थी कि बंसल भागे-भागे सभा स्थल पर जा पहुंचे और मंच पर अवतरित हो गए। इस घटना के बाद ही बंसल चंडीगढ़ के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी सक्रिय दिखे।

जयंत की असली चिंता

राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी नए-नए भगवा ताने-बाने में ढले हैं, पर वे भी इन दिनों खुद को ठगा-ठगा महसूस कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में जब तक चुनाव चल रहे थे तो जयंत को भाजपा वाले पहचान भी रहे थे, कुछ भाव भी दे रहे थे, खास कर जाट बहुल इलाकों में लेकिन लगता है कि भाजपा में जयंत का अब कोई सुधलेवा बचा नहीं है। मिसाल के तौर पर इसी 29 मई को चौधरी चरण सिंह की पुण्य तिथि थी। इस बड़े किसान नेता को पीएम मोदी ने

ताजा-ताजा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से नवाज़ा है। सो, जयंत को पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली के किसान घाट पर उनके दादा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भाजपाइयों की भारी भीड़ जुटेगी, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी क्योंकि किसी छुटभैय्ये भाजपा नेता ने भी वहां पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जरूर आए, पर वो भी सिर्फ इस वजह से कि उन्हें एक बड़े जाट नेता के पक्ष में कदमताल करनी थी।

राहुल का दो टूक फैसला

इस बार बदले-बदले सरकार नजर आते हैं। राहुल गांधी अपने एक नए अवतार में हैं, वे न सिर्फ राजनीतिक रूप से परिपक्व हुए हैं बल्कि त्वरित निर्णय लेने में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। राहुल ने अपनी कोर टीम को ऐसे पार्टी नेताओं की शिनाख्त का काम सौंपा था जो नेतागण पार्टी के अंदर रह कर पार्टी के खिलाफ काम कर रहे है, जो काम नहीं कर रहे थे उनके लिए राहुल का मंत्र था उन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। दिल्ली कांग्रेस के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, जब राहुल को खबर मिली कि अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में शीला दीक्षित गुट पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है तो उन्होंने अपने बड़े नेताओं से कहा कि 'फौरन प्रेस कांफ्रेंस कर इन्हें बाहर का दरवाजा दिखाएं।' लवली तो भाजपा में रम गए? पर कन्हैया कुमार को टिकट मिलने से नाराज संदीप दीक्षित ने भंगिमाएं बदल लीं और वे फौरन बेमन से ही सही पार्टी के काम में जुट गए।

मंडी और करनाल का भगवा ऐलान

हिमाचल की मंडी और हरियाणा की करनाल दो हाई प्रोफाइल सीटों को इस

दफे भाजपा ने अपनी नाक का सवाल बना लिया था। मंडी लोकसभा सीट से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और करनाल से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इन दोनों सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बात कंगना की करें तो उनके लिए स्वयं पीएम मोदी ने रैली की। पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज मसलन योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने उनके पक्ष में चुनावी सभाएं कीं। कमोबेश यही हाल करनाल सीट का रहा, जहां मोदी दुलारे मनोहर लाल खट्टर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी कांग्रेस के युवा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा से टक्कर है। करनाल सीट भाजपा के नजरिए से इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहीं से उनके नए नवेले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए खट्टर ने सीट छोड़ी थी ताकि सैनी उपचुनाव के मार्फत विधानसभा में पहुंच सकें।

क्या यूपी बदल रहा है?

भाजपा के लिए इस दफे यूपी का चुनावी मैदान किंचित इतना आसान नहीं रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने यहां की 80 में से 62 सीटें जीत ली थीं और इस दफे भाजपा न सिर्फ अपना रिकार्ड बरकरार रखना चाहती थी बल्कि उसे और बेहतर भी बनाना चाहती थी। राजनैतिक पर्यवेक्षक बताते हैं कि इस दफे यूपी की चुनावी फिज़ा किंचित बदली-बदली सी थीं। अगर भाजपा का 2019 का आंकड़ा देखें तो इस चरण की महाराजगंज, गोरखपुर, कशीनगर, बांसगांव, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, चंदौली और वाराणसी में भाजपा ने अपना भगवा झंडा लहराया था वहीं मिर्जापुर और राबर्टसगंज की सीटें भाजपा के सहयोगी अपना दल के हिस्से आई थी। साफ तौर पर दिख रहा है कि देवरिया, बलिया और चंदौली जैसी सीटें फंसी हुई हैं और भाजपा ने इन चुनावों

में जो 'नेरेटिव' तैयार किया था यहां की जनता उसे हाथों-हाथ नहीं ले पायी। जनता के लिए फ्री राशन और राम मंदिर यहां कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया बल्कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महंगी बिजली, महंगा गैस सिलेंडर, पुलिस, सेना, रेलवे और शिक्षकों की भर्ती न होना यहां एक बड़ा मुद्दा रहा है। यूपी के अन्य चरणों के मतदान में भी कानपुर, कन्नौज, धौरहरा, शाहजहांपुर, अमेठी और रायबरेली जैसी सीटों पर जनता द्वारा परिभाषित यही मुद्दे मुखर नजर आ रहे थे जो इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी ख़बर हो सकती है।

...और अंत में

2024 का आम चुनाव देश का अब तक का सबसे महंगा चुनाव साबित हुआ है। 'सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज' के आंकड़ों के मुताबिक इस दफे के चुनाव के आखिरी चरण के मतदान तक 1.35 लाख करोड़ खर्च हो चुके हैं। एक वोट की कीमत तकरीबन 1400 रुपए आंकी गई है। वहीं 2019 में 55-60 हजार करोड़ चुनावी खर्च का अनुमान किया गया था। देखा जाए तो चुनावी खर्च के मामले में भारत ने अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है। सनद रहे कि 2020 के अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में 1.20 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे।

सारा चुनाव मोदी के नाम रहा

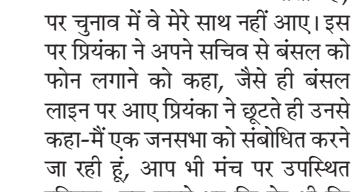

भीषण गर्मी के बीच 42 दिनों से चल रहा सबसे लंबा लोकसभा चुनाव अभियान आखिरकार शनिवार शाम को सातवें चरण के मतदान के साथ ही समाप्त हो गया है। अब 4 जून को मतगणना होने तक लोग चुनावी नतीजों को लेकर तरह-तरह के अनुमान लगा सकते हैं, जिसके लिए उनके पास चर्चाओं को गर्म करने के लिए अलग-अलग तरह के एग्जिट पोल भी होंगे। वैसे, पिछले दो लोकसभा चुनावों में एग्जिट पोल ने सावधानी बरतने में गलती की थी, जिसमें भाजपा और एनडीए को वास्तव में जीती गई सीटों की तुलना में कम सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। बेशक, अगर सट्टा बाजार की बात करें तो मोदी का लगातार तीसरा कार्यकाल तय है। बीजेपी के जीतने के भी आसार हैं। यानी अगर आप बीजेपी की जीत पर एक रुपया दांव पर लगाते हैं तो बदले में आपको बीजेपी जीतने पर केवल एक रुपया मिलेगा। हालांकि, कांग्रेस नेतृत्व वाले 'इंडिया' गठबंधन के जीतने पर आपको दांव पर लगाए गए प्रत्येक एक रुपये के बदले नौ रुपये मिलेंगे।

वहीं पूरे चुनावी अभियान के अंत में विवाद का मुख्य कारण जो बना वह कन्याकुमारी में विवेकानन्द रॉक मैमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'मौन व्रत' था जो कि भारत के सबसे दक्षिणी छोर है जहां हिंद महासागर और अरब सागर मिलते हैं और जहां महान भिक्षु स्वामी विवेकानन्द ने दिसंबर 1892 में तीन दिनों तक मेडिटेशन किया था। यह आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी एकनाथ रानाडे थे जिन्होंने कन्याकुमारी में प्रसिद्ध संन्यासी के मेडिटेशन की स्मृति में विवेकानन्द स्मारक की कल्पना की थी। उधर 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने तब विरोध नहीं किया जब मोदी ने अंतिम चरण के मतदान से पहले एक व्यस्त अभियान के अंत में केदारनाथ गुफा में मेडिटेशन किया था लेकिन इस बार यह शिकायत तुरंत की गई कि कन्याकुमारी मौन व्रत को टेलीविजन पर प्रसारित करना मतदान से 48 घंटे पहले बिना प्रचार के प्रचार का एक सूक्ष्म तरीका था।

मोदी के मौन व्रत पर सबसे ज्यादा आपत्ति ममता बनर्जी ने जताई है। यह देखते हुए कि स्वामी विवेकानन्द बंगालियों के आदर हैं, उन्हें डर था कि अंतिम चरण में नौ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान मोदी के मौन व्रत से प्रभावित हो

सकता है लेकिन मोदी ने बिना ब्रेक लिए कितनी मेहनत से प्रचार किया, परिणाम घोषित होने के बाद सरकार बनाने के कार्य में उतरने से पहले ऊर्जा को पुन: प्राप्त करने के लिए वह शायद एक ब्रेक के हकदार थे। क्योंकि सभी दलों के नेता आमतौर पर चुनाव प्रचार समाप्त होने और नतीजों की घोषणा के बीच थोड़े अंतराल के दौरान आराम करते हैं और स्वास्थ्य लाभ करते हैं।

इस बीच यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक-दूसरे पर दुर्व्यवहार और अपशब्दों का सहारा लेकर अभियान की गुणवत्ता को कम करने का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं ने मोदी पर प्रधानमंत्री पद के लिए अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। चुनाव अभियान में राजनेताओं को कुछ हद तक छूट हो सकती है लेकिन सीधे तौर पर दुर्व्यवहार और नाम पुकारना स्पष्ट रूप से अनुचित है। आलम यह है कि मतदाताओं को मंच से तू-तू, मैं-मैं करके आपस में उनका टकराव करवा दिया जाता है।

जहां मोदी और कुछ हद तक शाह ने पूरे देश में भाजपा के अभियान को अपने कंधों पर उठाया, वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 'इंडिया' गठबंधन का नेतृत्व किया। पूरे चुनाव अभियान में शुरू से लेकर अंत तक सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच चुनावी गारंटी की लड़ाई देखने को मिली। इस अभियान में मोदी की गारंटी भाजपा के अभियान का मूलमंत्र बन गई जिसमें पार्टी ने लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया, जिसमें 'श्रमिक' महिलाएं विशेष रूप से भाजपा का समर्थन करती नजर आई।

दूसरी ओर राहुल ने महिला वोटर को लुभाने के लिए प्रत्येक महिला को प्रति वर्ष एक लाख रुपये या प्रति माह आठ हजार से थोड़ा अधिक देने का वायदा किया। उधर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह घोषणा करने में कोई समय नहीं गंवाया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे। हालांकि इससे पहले कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा था कि बहुमत हासिल करने पर विपक्ष उस पार्टी से प्रधानमंत्री चुनेगा जिसके पास सबसे ज्यादा संख्या होगी यानी कांग्रेस पार्टी लेकिन इस मनमाने दावे से ममता बनर्जी खुश नहीं हो सकती हैं। इस चुनाव में मतदाताओं को लुभाने में सोशल मीडिया, विशेषकर व्हाट्सएप की अहम भूमिका रही है।

इन चुनावों में घर-घर जाकर प्रचार करने के बजाय पार्टियों ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को बेहतर बनाया और अपना संदेश फैलाने व प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए विभिन्न अनुकूल व्हाट्सएप समूहों को बढ़ावा दिया। संक्षेप में कहे तो स्मार्ट फोन पार्टी प्रचार के उपकरण में बदल गए। अंत में, यह चुनाव विपक्ष के सभी दलों के मुकाबले मोदी बनाम बन गया। मोदी सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में एनडीए के उम्मीदवार थे जबकि भाजपा और उसके सहयोगियों के अन्य लोग अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में सहायक भूमिका निभा रहे थे।

गर्मी में 'राजनीति' और राजनीति में 'गर्मी'

आजकल दो ही चीजों की सबसे ज्यादा चर्चा है। चुनावों के चलते हर तरफ राजनीति की चर्चा है और इसी सियासत को लेकर कौन जीतेगा, कौन हारेगा? को लेकर आपसी तलखियां भी बढ़ रही हैं लेकिन चुनावों के इस बेहद लंबे सात चरणों के दौर में भीषण गर्मी की भी चर्चा चल रही है और हमने अपने जीवन में पहली बार यह देखा कि तापमान 50 डिग्री पार कर गया। वहीं राजनीतिक दलों के अनेक नेताओं ने एक-दूसरे के बारे में क्या कुछ नहीं कहा? यानि कि राजनीति में गर्मी बनी रही और उधर चुनाव के मौसम में प्रकृति की तरफ से सूर्य देव ने अपने तेवर बढ़ाकर पूरे भारत को ही गर्मी में झुलसाए रखा। इसलिए इन चुनावों से किसी भी आम और खास के साथ-साथ राजनेताओं को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। फिर भी चुनाव आयोग से अर्जी तो लगाई जा ही सकती है कि भले ही चुनाव कराना संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है और पांच साल के बाद ऐसा करना जरूरी है तो भी कम से कम अप्रैल-मई के महीने से बचा जाए तो ज्यादा अच्छा है।

एक सकारात्मकता जरूर होनी चाहिए। प्रकृति के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन सरकार के मामले में बहुत कुछ अनुरोध कर सकते हैं। वहीं नेताओं को भी पब्लिक तो कुछ नहीं समझा सकती क्योंकि पब्लिक तो एक ही दिन जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन समझाती है और बाकी पांच साल तो फिर नेताजी के ही होते हैं। इसे ही लेकर राजनीतिक पार्टियों में पूरे चुनाव में आरोप-प्रत्यारोप चले हैं। एक-दूसरे पर काम न करने के आरोप और वहीं खुद सरकार में आने के तरह-तरह के दावे किए गए। व्यक्तिगत रूप से हर पार्टी की ओर से बड़े ही नेता सामने आए जिन्होंने भाषा की गरिमा की परवाह न करते हुए असभ्य शब्दों का प्रयोग किया। कुल मिलाकर ऐसा कहकर गर्मी के मौसम में इन लोगों ने चुनावी गर्मी को और झुलसा दिया। सकारात्मकता यह कहती है कि राजनीति में भी हम आदर्श स्थापित कर सकते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। लोग आज भी आदर्शवान नेताओं को याद रखते हैं। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की

बातचीत की जाए तो सुशासन की नींव श्रीराम ने ही रखी थी। आज भी भारत में सुशासन की बात भगवान श्रीराम के आदर्शों को सामने रखकर ही की जाती है हमने देखा कि कितने ही स्थानों पर, कितनी ही जाति-पाति के लोग, कितने ही मामलों में नेताओं को कोसते नजर आए। हम ऐसे उदाहरण स्थापित कर सकते हैं कि लोग हमारे नाम पर नहीं हमारे काम पर मोहर लगाएं। आज की तारीख में तरह-तरह के घोषणापत्र जनता के सामने लाए गए। एक तरफ तो मुफ्तखोरी की बातें करके जनता को सुविधाएं देने के वायदे किए जाते हैं और दूसरी तरफ मुफ्तखोरी का विरोध भी किया जाता है। सबकी अपनी-अपनी नजर और अपना-अपना नजरिया है।

मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगी कि अगर चुनावों का बारीकी से अध्ययन किया जाए, चुनावों के बारे में देश के मतदाताओं में वृद्धों, पुरुषों, महिलाओं और यूथ के बारे में चर्चा की जाए तो मैं यही कहूंगी कि वोट का अधिकार हर कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। यद्यपि चुनाव आयोग ने वोटिंग अर्थात मतदान को एक पर्व कहा और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया परंतु फिर भी यह आंकड़ा 60 से 65 प्रतिशत ही पहुंच पाया। दूसरे शब्दों में मैं यह स्पष्ट कह सकती हूं कि 35 प्रतिशत से अधिक लोगों ने अपने आपको मतदान से दूर रखा। यह प्रश्न भी चिंतनीय है। अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत हैं, हम सचमुच नेताओं का भाग्य संवारने वाले जनार्दन हैं तो फिर हमें मतदान करने के लिए जरूर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि राजनीतिक पार्टियों को यूथ और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़ना चाहिए। जो देश में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की बात राजनीति से जोड़कर की जा रही हो तो सब कुछ टिकट के मामले में दिखाई भी दिया जाना चाहिए। फिर भी चुनावों में गर्मी और गर्मी में राजनीति चलती रही। एक मामले में नेता शामिल हैं तो प्रकृति के मामले में हमारा कोई वश नहीं लेकिन सब कुछ मर्यादा में रहना चाहिए। राजनीति और राजनीतिज्ञों की नीयत और नीति के चलते भारत का भविष्य अच्छा होगा, हमें इसका एक आदर्श स्थापित करना होगा। यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होगी।

अभी तक जितने चुनाव देखे हैं ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा खूब जोश एक्साइटिंग चौंकाने वाला सबसे अधिक हर देश के नागरिक के चेहरे पर कांफिडेंस कि उनकी एक-एक वोट कीमती है और वो ही डिसाइड करेंगे कौन बनेगा? वाह क्या लोकतंत्र है जिसमें देश का हर व्यक्ति हिस्सा ले रहा। वोट लेने वाला वोट देने वाला, इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू देने वाला प्रिंट, डिजीटल, सोशल मीडिया, व्हाट्सप अलर्ट सब नेता उठते-बैठते सोते-जागते हाथ जोड़ते नजर आते हैं। बड़े-बड़े वायदे करते हैं। हर एक के दरवाजे पर दस्तक देते हैं फिर पांच साल तक जनता को उन्हें ढूंढना पड़ता है। इस बार तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कड़ा मुकाबला है किसकी हार होगी किसकी जीत परंतु यह तो तय है कि विपक्ष खड़ा हो चुका है, यह लोकतंत्र की मजबूत निशानी है।

आज वोट डालने का समापन हो चुका, सभी प्रत्याशी पूजा-पाठ कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री कन्याकुमारी ऐतिहासिक स्थान पर ध्यान लगा रहे हैं। अमित शाह जी अपनी पत्नी के साथ तिरुपति बाला जी मंदिर में पूजा-अर्चना कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने हिमाचल के शिमला में जाखू मंदिर में दर्शन कर पूजन किया। चिराग पासवान हनुमान गढ़ी, मोहन यादव ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। अब 4 जून का सबको इंतजार है किसकी जीत होगी किसकी हार यह लोकतंत्र की आवाज होगी।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

पंजाब केसरी

दिल्ली कार्यालय :

फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

परिणाम सदैव प्रयास के अनुपात में प्राप्त होता है

चुनाव प्रक्रिया के सबक

अंतिम चरण की 57 सीटों पर मतदान के साथ ही 18वीं लोकसभा के लिए सात चरणों वाली लंबी चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई। इसी के साथ एक्जिट पोल के नतीजे भी आ गए, लेकिन यह स्पष्ट ही है कि सभी को वास्तविक नतीजों की प्रतीक्षा है, जो 4 जून को आएंगे। इसी दिन पता चलेगा कि किसने बाजी मारी। एक्जिट पोल कुछ भी कह रहे हों, पक्ष और विपक्ष अभी भी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरह से यह अच्छा ही है। इस दावे का मतलब है कि दोनों ही पक्षों को यह भरोसा है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए। और भी अच्छा यह होगा कि हारने वाला पक्ष अपनी पराजय का दोष चुनाव आयोग अथवा अन्य किसी पर मढ़ने के बजाय आत्ममंथन करे। दुर्भाग्य से अब ऐसा कम ही होता है। हारने वाले राजनीतिक दल कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं, कभी मीडिया को कोसने लगते हैं और कभी-कभी तो जनता को ही नासमझ बताने लगते हैं। इससे राजनीतिक दलों की अपरिपक्वता का ही परिचय मिलता है। हमारे देश के राजनीतिक दलों को अभी काफी कुछ सीखने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति इसलिए की जानी चाहिए, क्योंकि करीब दो माह के लंबे चुनाव प्रचार के दौरान अनेक दलों ने नकारात्मकता का परिचय दिया और ऐसे विषयों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, जो जनहित के विषय ही नहीं थे। चुनाव में जब जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता नहीं मिलती, तब उससे जनता के साथ-साथ दलों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। इस बार के आम चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपने-अपने घोषणा पत्रों के बजाय दूसरे दलों के घोषणा पत्रों का उल्लेख अधिक किया और वह भी आधे-अधूरे ढंग से। इस बार अपेक्षा से कम मतदान भी चर्चा का विषय रहा। यह चर्चा का विषय बनना भी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक हद तक राजनीतिक दल भी जिम्मेदार हैं। वे जनता को बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक जाने के लिए प्रेरित नहीं कर सके। अपेक्षा से कम मतदान पर चुनाव आयोग को भी गंभीरता से विचार-विमर्श करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे इस पर तो अनिवार्य रूप से विचार करना चाहिए कि मई-जून की भीषण गर्मी में चुनावों से कैसे बचा जाए? हैरानी नहीं कि कम मतदान का एक कारण प्रतिकूल मौसम भी रहा हो। जो भी हो, चुनाव आयोग को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि अंतिम चरणों के मतदान के दौरान मतदाताओं के साथ-साथ चुनाव कराने वाले कर्मचारियों के साथ सुरक्षा कर्मियों को भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी। कई चुनाव एवं सुरक्षा कर्मियों की तो लू लगने से मौत भी हो गई। निःसंदेह यह भी अच्छा नहीं हुआ कि देश के कुछ हिस्सों और विशेष रूप से बंगाल में चुनावी हिंसा देखने को मिली। बंगाल को चुनावी हिंसा से मुक्ति न मिलना एक गंभीर चिंता की बात है।

चुनावी विवाद निंदनीय

लोकसभा चुनाव का सातवां चरण मिला-जुलाकर शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, हालांकि आरा में मतदान के विवाद में एक जगह फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें चार लोग घायल हो गए हैं। पांचवें चरण के चुनाव में छपरा में भी चुनाव से जुड़े विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई थी। लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं बहुत ही निंदनीय हैं। यह गलत है। यह अच्छी बात है कि इक्का-दुक्का घटना को छोड़ चुनाव लगभग शांतिपूर्ण रहा है। प्रशासनिक तंत्र भी कड़ी निगरानी करता रहा। मतदाताओं ने निर्भीक होकर मतदान किया। सासाराम, कैमूर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मतदाता वोट डालने को 30-40 किलोमीटर पैदल भी चले। यह लोकतंत्र के प्रति मजबूत आस्था का प्रमाण है। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की यही सुंदरता है कि हर किसी को अपनी इच्छा से प्रतिनिधि चुनने का समान अधिकार है। जनता सभी को सुनने-समझने के बाद अपना निर्णय सुनाती है, लेकिन समाज में इन सबको लेकर आपस में विवाद और अप्रिय घटना हो तो वह गलत है। ऐसा करना लोकतंत्र की परिभाषा के प्रतिकूल है। संविधान ने सभी को समान अधिकार दिया है। किसी का किसी के प्रति झुकाव हो सकता है, वह उसके विचारों से प्रभावित हो सकता है, लेकिन यही सब सामाजिक विद्वेष का कारण बनने लगे तो उसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। समाज के प्रबुद्धों को ऐसे तत्वों पर दृष्टि रखनी चाहिए। चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, मतदान होता है, परिणाम आता है और सरकार बनती है। पक्ष हो या विपक्ष, विचारों को लेकर मत भिन्नता स्वाभाविक है और यह होना भी चाहिए। कोई भी इक्का-दुक्का घटनाओं का कारण बनता हो तो इसकी आलोचना की जानी चाहिए। प्रशासन को ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

लोकतंत्र में चुनाव के समय आरोप-प्रत्यारोप सामान्य बात है। यह सामाजिक विद्वेष का कारण नहीं बनना चाहिए।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या टी-20 विश्व कप के सह-आयोजन से अमेरिका में क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ेगी?

आज का सवाल

क्या एक्जिट पोल्स के नतीजे वास्तविक जनादेश की झलक पेश कर रहे हैं?

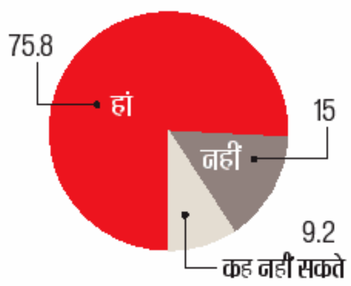

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

लापरवाही की भेंट चढ़तीं जिंदगियां

संजय गुप्त

वैसे तो प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षा के नियम-कानून हैं, लेकिन वे कागजों पर ही अधिक रहते हैं और इसी कारण उनकी अवहेलना होती दिखती है

पिछले दिनों गुजरात के राजकोट शहर में एक गेमिंग सेंटर में आग लगने से 28 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके कुछ दिनों बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक बेबी केयर सेंटर में भी आग लगने से सात नवजात मौत के मुंह में समा गए। एक के बाद एक घटी इन दोनों घटनाओं से देश दहल सा उठा। इस तरह की घटनाएं कोई नई नहीं हैं। इस जैसी न जाने कितनी घटनाएं अपने देश में होती ही रहती हैं, जिनमें लोग जान भी गंवाते हैं। आम तौर पर ये घटनाएं नगर निकायों की कामचलाऊ प्रवृत्ति और उनके अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही एवं घूसखोरी का नतीजा होती हैं। राजकोट के गेमिंग सेंटर में न तो आग से बचाव के कोई उपाय थे और न ही उसके संचालन की कोई स्वीकृति नगर निकाय से हासिल की गई थी। वहां दर्शकों का प्रवेश जारी था और वेल्डिंग का काम भी हो रहा था। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में भी आग से बचाव का कोई उपाय नहीं था। वहां अग्निशमन यंत्र तक नहीं थे। इस बेबी केयर सेंटर को चलाने के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वह चल रहा था। वहां सुरक्षा के अन्य उपाय भी नहीं थे। इस बेबी केयर सेंटर में क्षमता से अधिक बच्चों का उपचार हो रहा था।

अपने देश में नगर निकाय अथवा अग्निशमन विभाग एवं ऐसी ही अन्य नगरीय संस्थाओं की अनदेखी के कारण लगातार घटनाएं होती चली आ रही हैं। ऐसी हर घटना में नगरीय निकायों की नाकामी तो उजागर होती ही है, उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार का भी पता चलता है। चूंकि इन घटनाओं में बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, इसलिए देश की छवि पर बुरा असर पड़ता है और उसे शर्मसार भी होना पड़ता है। जैसा कि हमेशा होता है, हर बड़ी घटना के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं और नेता-नौकरशाह यह आश्वासन देते हैं कि स्थितियां सुधारी जाएंगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होने दी जाएंगी। आग लगने की घटनाओं के मामले में यह भी देखने में आता है कि शहर विशेष के अस्पतालों, होटलों, मनोरंजन स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों की छानबीन शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वैसी ही घटना घट जाती है। इन घटनाओं में जब लोग मारे जाते हैं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत अन्य नेतागण पीड़ितों को सांत्वना देते हैं, लेकिन घटना के कारणों का निवारण सही तरह से नहीं किया जाता। इसी कारण स्थितियां जस की तस बनी रहती हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के उपाय मजबूत बनाने पर ध्यान नहीं दिया जाता।

वैसे तो प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षा के नियम-कानून हैं, लेकिन वे कागजों पर ही अधिक रहते हैं और इसी कारण हर जगह उनकी अवहेलना होती दिखती है। बात चाहे मनोरंजन स्थलों की हो या व्यावसायिक स्थलों, होटलों, अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे एवं बस स्टेशनों की-हर जगह अव्यवस्था और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ही अधिक दिखती है। एक समस्या यह भी है कि औसत भारतीय नागरिक सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाही का परिचय देता है। वह भीड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासन का भी परिचय नहीं देता। अपने देश में प्रत्येक सार्वजनिक अथवा व्यावसायिक स्थल के लिए नगरीय निकायों से सुरक्षा मानकों के प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। वह उन्हें आसानी से मिल भी जाता है, लेकिन जब कोई घटना घट जाती है तो यही सामने आता है कि सुरक्षा उपायों की या तो अनदेखी हो रही थी या वे केवल कागजों पर ही थे। राजकोट की घटना के बाद यह सामने आया कि गुजरात में चलने वाले अधिकांश गेमिंग सेंटरों में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं थे। दिल्ली की घटना के बाद भी यह सामने आया कि

अवधेश राजपूत

कई अस्पतालों में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध नहीं हैं। प्रश्न यह है कि ऐसे स्थान सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर कैसे चलते रहते हैं? कोई भी समझ सकता है कि इसका कारण नगरीय निकायों के भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं, जो पैसे लेकर दिखावटी जांच करते हैं और पर्याप्त सुरक्षा उपाय न होने पर भी आवश्यक प्रमाण पत्र भी दे देते हैं।

भ्रष्टाचार के चलते सुरक्षा मानकों की जो अनदेखी हो रही है, वह तब तक नहीं रुकने वाली, जब तक जिम्मेदार नेताओं और नौकरशाहों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। हर घटना के बाद नेतागण नौकरशाहों पर दोष मढ़ देते हैं और नौकरशाह निचले स्तर के कर्मचारियों पर। कभी-कभी किसी अधिकारी-कर्मचारी का निलंबन भी हो जाता है, लेकिन उन्हें अपने किए की कोई ऐसी सजा नहीं मिलती, जो नजीर बन सके। वे कुछ समय बाद फिर नौकरी पर बहाल हो जाते हैं। उनकी नौकरी शायद ही कभी जाती हो। हमारे अधिकांश नेतागण जमीनी स्तर पर राजनीति शुरू करके मंत्री पदों तक भी पहुंचते हैं, लेकिन वे नगरीय निकायों के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कभी सक्रिय नहीं होते। इसका कारण यह है कि भ्रष्टाचार में अक्सर उनकी भी मिलीभगत होती है। यह समय की मांग है कि नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों और इसी तरह विधायकों, सांसदों एवं मंत्रियों आदि के कामकाज का आकलन इस आधार पर हो कि वे व्यवस्था को सुधारने और विशेष रूप से सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के उपाय लागू करने में कितने सफल हैं? अक्षम एवं भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों को उनके खराब कामकाज के लिए पदों से हटाने की कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

यह सही समय है कि जनप्रतिनिधियों के मामले में राइट टू रिकाल की व्यवस्था लागू की जाए, ताकि उनके अंदर यह भय व्याप्त हो कि यदि वे अपना काम सही तरह से नहीं करेंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। भ्रष्ट एवं अक्षम नौकरशाहों के मामले में भी ऐसा कुछ करना होगा। उन्हें उनकी दायित्वहीनता के लिए जवाबदेह बनाना होगा और दंडित करना होगा। वे जवाबदेह तब बनेंगे, जब उनकी गलतियों के लिए उन्हें वास्तव में जिम्मेदार ठहराने के नियम बनेंगे और जनता अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगी। ऐसे लोकतंत्र का कोई लाभ नहीं, जिसमें निर्वाचित संस्थाओं के पदाधिकारी अपना काम सही तरह से न करें। वास्तव में ग्राम पंचायतों से लेकर नगर निकायों के कामकाज की नए सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए और उनके कामकाज को सुधारने के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए, ताकि रह-रहकर होने वाली दुर्घटनाओं से मुक्ति मिल सके।

response@jagran.com

अबकी बार पारा पचास के पार

हास्य-व्यंग्य

मकई के दाने के पापकार्न बनने की प्रक्रिया समझनी हो तो आजकल धूप में खड़ी बाइक की गद्दी पर बैठकर देखिए। खुद को बड़ा 'स्नानवीर' समझते हों तो छत पर रखी टंकी के पानी से नहा लीजिए। 'आग का दरिया' तैर कर जाने की बात करने वालों, जरा सड़कों पर पिघलते तारकोल की 'काली वैतरणी' पार करके देखिए। यही जवाब मिलेगा 'बारंबार-अबकी बार हाहाकार, पारा पचास के पार।'

आजकल संपूर्ण उत्तर भारत की हालत चूल्हे पर चढ़े तवे जैसी हो गई है। बर्फ तक से धुआं निकल रहा है। लगता है कि उसे भी पसीना आ रहा है। गर्मी से लोगों के चेहरे झुलस गए हैं। समझना मुश्किल है कि ओरिजिनली किसका रंग दबा हुआ है और किसने चेहरे पर मौसम से फेशियल करवाया है। सूर्यदेव का तेज इतना विकराल है कि जीवन की लौ मद्धम हो चली है। कपड़ों में दांत उग आए हैं। पहनते ही काटने को दौड़ते हैं। मौसम कुछ ऐसा हो चला है कि धुले हुए कपड़े तुरंत सूख जा रहे हैं और सूखे कपड़े पसीने की जुगलबंदी से प्रीमियम तत्काल में गीले हो जा रहे हैं। पशु-पक्षी से लेकर चल-अचल सभी जीव-जंतु त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जमीन पर रेंगती चींटियों को कुत्ते के मुंह से टपकती लार की आस है। कुत्तों को हड्डी से अधिक चिकन सूप की प्यास है। घोर कलयुग आ गया है। किसने सोचा था कि बिजली के दो खंभों, कार, बाइक और स्कूटी के सगे पहियों में, आपस में ही ठन जाएगी और वह भी महज एक कुत्ते के लिए। हमारे यहां

कमल किशोर सक्सेना

नौतपा की तपिश में पत्थर जैसे ठोस दिमाग भी पिघल गए हैं। सूर्यदेव के तेज के समक्ष जीवन की लौ मद्धम हो चली है

जेठ के महीने को महत्वपूर्ण माना गया है। संयुक्त परिवार में अब इसका भले उतना महत्व न रह गया हो, मगर हिंदू पंचांग में इसके नाम से आज भी पतलून भीग जाती है और कैलेंडर गीला हो जाता है। ऊपर से नौतपा। गरीबी में गीले आटे के गुलगुले बनाने की हिम्मत की जा सकती है, लेकिन जेठ का नौतपा। भाड़ भी इसके आगे दंडवत है। आजकल वही चल रहा है। इस पीढ़ी के कई लोग 'नौतपा' का नाम भी नहीं जानते थे, मगर अबकी बार उनके सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि हुई है। नौतपा की तपिश में पत्थर जैसे ठोस दिमाग भी पिघल गए हैं। दूध के दही बनने में फिर भी समय लगता है, किंतु भीषण गर्मी ने अच्छे-अच्छे दिमागों का रायता बनाकर रख दिया है। हर बात में अपने जमाने की दुहाई देने वाले बुजुर्ग भी कहना भूल गए हैं कि गर्मी तो हमारे समय में पड़ती थी।

सुबह मैं अपने घर की बगिया में टहलने गया तो एक नन्हा पौधा आंखों में आंसू लिए उदास दिखा। मैंने उससे कारण पूछा तो उसने कहा-तुम्हारी बेचैनी देखकर ही मैं दुखी हूं, लेकिन इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। विकास की दौड़ में अपने पालनकर्ता की गोद सूनी कर दी। प्रकृति के जंगल कम हो गए। कंक्रीट के बढ़ गए। शहरों में गगनचुंबी इमारतें तो बेशुमार हैं, लेकिन राहगीरों को छांव देने वाले मेरे पूर्वज पेड़ लगातार कम हो रहे हैं। घरों में लगे एसी गरम हवा छोड़ रहे हैं, किंतु आक्सीजन देने वाले मेरे पितामह को यह जहां छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पहाड़ भी नंगे हो गए हैं। उन पर से हरियाली गायब है। उसकी जगह प्लास्टिक तथा अन्य कचरे ने ले ली है। इन हालात में बताओ, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं। लाखों करोड़ों वृक्षों की हत्या का दंड है ये, जो आज तुम लोग भोग रहे हो। सूरज की तपिश को रोकने वाली ढाल पर तो खुद तुमने कुल्हाड़ी चला दी। मेरे बड़े होकर पेड़ बनने और ठंडी छांव देने में समय है। तब तक क्या करोगे।

उसकी बातों से अब मेरी आंखें नम हो गई हैं। फिर तो घर में रखी मेज-कुर्सी-पलंग आदि हर फर्नीचर मुझे अखरने लगा, क्योंकि सबके भीतर किसी न किसी पेड़ का आत्मा बसा था।

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रेरणा पुंज

महानता एक दिन में प्राप्त नहीं होती। महान व्यक्तियों के जीवन का समग्र देखा जाता है कि उन्होंने अपनी सीमाओं से परे जाकर कितनी उपलब्धियां हासिल कीं। इसका अर्थ यह नहीं होता कि उनका जीवन सर्वदा त्रुटिरहित है। उन्होंने संघर्षों में स्वयं को घिस-घिस कर चमक पाई होती है। उनसे त्रुटियां हुई होंगी, जिनको उन्होंने सुधारा होगा। तभी वे नायक-महानायक के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार मानव मन ने जिसे नायक स्वीकार कर लिया उसे आदर्शों के इतने उच्च प्रतिमानों पर बैठा देता है कि वहां से उसके तनिक भी दोष हमारी श्रद्धा को हिला देते हैं। इतिहास में कोई भी अवतार, महापुरुष, नायक या सुधारक ऐसा नहीं देखा गया जो आलोचनाओं का शिकार न बना हो। कारण सिर्फ वही कि यदि वे महापुरुष हैं तो उनसे एक भी त्रुटि कैसे हुई? प्रकृति के नियमों के अधीन रहकर क्या ऐसा कोई आदर्श व्यक्तित्व संभव है जो सर्वदा त्रुटिरहित हो?

भगवान श्रीकृष्ण का एक नाम रणछोड़ है, जिसका अर्थ है रणभूमि छोड़कर भागने वाला। राजा कालयवन को अजेय रहने का वरदान था। श्रीकृष्ण जब उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सके तो उन्होंने रणछोड़ दिया और वहां से भाग निकले। रण से भागना उनकी युद्धनीति थी। अपने पीछे आते कालयवन को उन्होंने युक्तिपूर्वक एक गुफा में भेजा। गुफा में सोए राजा मुचकुंद के क्रोध का पात्र बनकर भस्म होकर कालयवन काल की भेंट चढ़ गए। इस उद्धरण का उद्देश्य यह संदेश देना था कि यदि जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो युद्ध छोड़कर युक्ति का प्रयोग कर लेना उचित है, भले ही युद्ध छोड़ना आदर्श के प्रतिमानों पर खरा न उतरता हो।

किसी भी महान पुरुष के चरित्र में भिन्न-भिन्न अतिमानवीय एवं अतिआदर्शवादी अपेक्षाएं जोड़ देना सही नहीं है। महापुरुषों या अवतारों का पूरा ही जीवन अध्ययन का विषय और एक प्रेरणा पुंज जैसा होता है। हमें उनके जीवन से समग्रता में सीख लेनी चाहिए।

द्विवंकल तोमर सिंह

कूटनीतिक गलियारों की दुविधा

आम चुनाव के परिणाम को लेकर राजनीतिक दल और उनके कार्यकर्ताओं के बीत पसरा तनाव तो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन राजधानी दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में भी इस मामले में टेंशन कम नहीं है। उच्च आयोगों-दूतावासों से पत्रकारों को एक नहीं, बल्कि कई स्तरों पर फोन करके पूछा जा रहा है कि माहौल क्या है और किसकी कितनी संभावनाएं हैं। दूतावासों एवं मिशनों में चुनाव पर नजर रखने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। उनसे हर चरण के चुनाव के बाद का स्टेटस मांगा जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे रणनीतिक साझेदार देशों के स्तर पर चुनाव परिणाम समझने की चिंता को तो समझा जा सकता है, लेकिन यूरोप के कई छोटे-छोटे देश भी भावी परिणामों को लेकर बेचैन हैं। पिछले दिनों कुछ मिशनों के सदस्य संयुक्त तौर पर एक कूटनीतिक सम्मेलन में बहस के लिए जुटे, लेकिन पूरी बातचीत चुनाव परिणामों पर होती रही। बैठक में शामिल एक भारतीय अधिकारी को कहना पड़ा कि, 'अच्छा हो कि हम अब राजनयिक संबंधों पर भी कुछ चर्चा कर लें।'

भाग्य के सहारे चमत्कार

अंतिम चरण की वोटिंग के बाद लोकसभा चुनाव के नतीजों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है तो संभावित नतीजों को लेकर भी राजनीतिक दल अपनी भावी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। विपक्षी गठबंधन में इसे लेकर सक्रियता कुछ ज्यादा है और इसलिए

राजरंग

वैकल्पिक राजनीतिक योजना के साथ-साथ गठबंधन के नेता पद को लेकर भी कानाफूसी चल रही है। बेशक औपचारिक तौर पर गठबंधन के नेतृत्व को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, मगर संकेत हैं कि अगर आइएनडीआइए के लिए चुनावी संभावनाएं बनीं तो विपक्षी गठबंधन देश को पहला दलित प्रधानमंत्री देने के विकल्प पर चिंतन-मनन करेगा। विपक्षी खेमे की इन अंदरूनी चर्चाओं से साफ है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आइएनडीआइए के नेतृत्व की पहली पसंद बन सकते हैं। घटक दलों की ऐसी राय मुखर हुई तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगी। वैसे यह भी कम दिलचस्प नहीं कि एक समय खरगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते-बनते रह गए, मगर राजनीतिक स्थिति ऐसी बनी कि वह आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शायद तभी नतीजों से पहले आइएनडीआइए की बैठक में हिस्सा लेने आए एक सहयोगी दल के नेता ने सियासत में किस्मत फैक्टर की बात करते हुए कहा कि कौन जाने कहीं खरगे का भाग्य ही विपक्ष के लिए चमत्कार ले आए।

'रीयल' नहीं तो 'रील' सही

चुनावों के दौरान जनता दल-सेक्युलर के नेता प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल मामला सामने आया तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री बलकार सिंह का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ। इंटरनेट मीडिया पर दोनों की खूब बखिया उधेड़ी जा रही हैं। उन्हें लेकर विरोधी राजनीतिक दल भी खुलकर मैदान में हैं, क्योंकि हमले का मौका जो मिल गया। विरोध का यह मोर्चा केवल रीयल ही नहीं, बल्कि रील यानी रुपहले पर्दे को लेकर भी खुला रहा। दिल्ली से भाजपा सांसद और फिर से लोकसभा पहुंचने के प्रयास में लगे मनोज तिवारी को उनके गानों की क्लिप निकालकर घेरने की कोशिश हुई तो गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के खिलाफ भी यही दांव आजमाया गया। यह जानते हुए भी कि यह वास्तविक नहीं, बल्कि महज अभिनय का मामला है, फिर भी इससे परहेज नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि जब मुद्दों का संकट हो और वाकई घेरने को कुछ न मिले तो विरोधियों को रील की क्लिप में ही सियासी दम दिखने लगता है। चुनाव में रील की क्लिप कितनी हिट रही या फ्लाप इसका पता तो चुनाव परिणाम से ही सामने आएगा।

हौसले की उड़ान

लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या रहेंगे यह तो चार जून को ही पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक दल अलग-अलग किस्म के आकंड़ों के जरिये अपनी जीत को लेकर उड़ान जरूर भरते दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में एक ऐसा आंकड़ा जारी करके बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान उसके वीडियो एवं दूसरी प्रचार सामग्रियों को इंटरनेट मीडिया पर भाजपा के मुकाबले कहीं ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। ऐसे कई आंकड़ों में अंतर दो से तीन गुना तक का था। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के आंकड़ों की यह उड़ान वास्तविक नतीजों के कितनी नजदीक रहती है, यह तो मतगणना के दिन पता चल जाएगा, लेकिन अंतिम समय तक अपने कार्यकर्ताओं का हौसला कायम रखने के लिहाज से यह नए किस्म की युक्ति जरूर बन गई।

पोस्ट

भारतीय चुनाव आइपीएल की तरह ही होते हैं। परिणाम चाहे जो हो, लेकिन इसमें भी अंतत: कोई भारतीय टीम ही जीतती है। चेतन भगत@chetan_bhagat

जनतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है हारने वाले का हार को शिष्टता से स्वीकार न करना। ट्रंप उसका उदाहरण हैं। घटिया बयानबाजी में हुए चुनाव के बाद भारत में अब हार से सीखने की जगह हर बात को दोष देने का दौर शुरू होगा। बेतुके अनुमान लगाना और पूरे न होने पर धांधली बताना एक परिपाटी बन गई है। शिव कांत@shivkant

वन नेशन-वन इलेक्शन हो या न हो, लेकिन सबसे पहले गर्मी में चुनाव कराने की परंपरा तब तक बंद होनी चाहिए, जब तक कि बढ़ते तापमान की चिंता राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र का एक मुख्य मुद्दा नहीं बन जाता। अतुल कुमार राय@AuthorAtul

अब से देश में मुखिया से लेकर लोकसभा तक कोई भी चुनाव मई के पहले हफ्ते से आगे नहीं जाना चाहिए। सात मई तक समूची चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। इस बार प्रचंड गर्मी में चुनाव ने तमाम जानें ली हैं। यह अपराध अब कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

जनपथ

देखो-देखो आ गया सबका एक्जिट पोल,
लेकिन यही सलाह है तोल-तोल कर बोल।
तोल-तोल का बोल न समझो इसे नतीजा,
क्यों विपक्ष है आज दिख रहा खीझा-खीझा।
मत हो अभी निराश कि धीरज रखना सीखो,
चार जून की राह धैर्य के संग अब देखो।

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्र, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 51

****

सैनिक नफरत के कारण नहीं लड़ता, बल्कि अपने मुल्क और परिवार से प्यार की वजह से लड़ता है। -जीके चेस्टर्टन

वहां शोक मनाने का वक्त नहीं मिलता

यह एक देश के सैनिकों की कथा नहीं है। हर सैनिक के लिए युद्ध में जिंदगी की यही लय है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी में जितनी मौतें, चोटें और नुकसान का अनुभव नहीं करते हैं, उससे ज्यादा दुखद घटनाओं का अनुभव सैनिकों को थोड़े समय में ही करना पड़ता है। जब किसी सैनिक का अपने परिवार के साथ संपर्क टूट जाता है, तो घर के लोगों को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। आखिर सैनिक भी इन्सान हैं। बटुए में रखी परिवार की तस्वीरें देखकर उनकी आंखों से भी आंसू निकलते हैं।

डेविड फ्रेंच
वरिष्ठ लेखक-पत्रकार

कॉन्टैक्ट आईईडी', जब मैं इराक में तैनात था, तो रेडियो पर ये शब्द सुनता था और मेरा दिल बैठ जाता था। इसका मतलब था कि हमारा कोई वाहन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस (आईईडी) या सड़क के किनारे रखे गए बम की चपेट में आ गया है। इसका मतलब था नुकसान। इसका मतलब था चोटें। इसका मतलब था मौत। और जब आपके भाइयों की मौत होती है, तो यह आपके दिल पर एक गहरा घाव छोड़ जाती है, जो पूरी तरह से कभी नहीं भरता। एक सैनिक के रूप में देश की सेवा करने की एक अनोखी मांग यह भी है कि सैनिकों के लिए जिंदगी अलग ढंग से होती है, और मौत भी। सामान्य नागरिकों की दुनिया में, मौत हमारे जीवन में बाधा डालती है। हम किसी मरणासन्न रिश्तेदार या मित्र की मदद के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। समय ठहरा हुआ सा प्रतीत हो सकता है। हम सारा काम रोक देते हैं। पारिवारिक यात्राएं स्थगित कर देते हैं। शोक एवं राहत की रस्मों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि हम सारा काम-धाम छोड़कर परिवार के साथ बैठते हैं और शोक मनाते हैं। लेकिन युद्ध में ऐसा नहीं होता।

■ मौतों से युद्ध नहीं ठहरते

युद्ध में मौत से कुछ भी नहीं ठहरता। वक्त रुकता नहीं, बल्कि तेजी से भागता हुआ प्रतीत होता है। और यह बेहद अप्राकृतिक है। जिस क्षण दुश्मनों के साथ हिंसक मुठभेड़ के बारे में बताने के लिए वह कॉन्टैक्ट कॉल मुख्यालय में आती है, आप दो हिस्सों में बंट जाते हैं। आपके भीतर का मानवीय पक्ष यह जानना चाहता है कि क्या किसी को नुकसान हुआ है। और जब आप रेडियो पर वीएसआई (बहुत गंभीर रूप से घायल) या केआईए (कार्रवाई में शहीद) सुनते हैं, तो आप घबराते नहीं, बल्कि आंशिक रूप से भय और चिंता से उबर जाते हैं। लेकिन केवल आंशिक रूप से ही। उस क्षण और उस जगह पर दुख शत्रु है। आप उदास हो ही नहीं सकते। यह आपके दिमाग को धुंधला कर सकता है और आपके निर्णय को प्रभावित कर सकता है। चूंकि आपकी जिंदगी दांव पर लगी होती है, इसलिए आप इसे किनारे रख देते हैं और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

■ सिर्फ खुद को जिंदा रखना होता है

युद्ध के मैदान में आपको सिर्फ खुद को जिंदा रखना होता है। आप लड़ते हैं, अपने घायल साथी का उपचार करते हैं और मदद के लिए कॉल करते हैं। जब आप युद्ध में होते हैं, तो बस एक अलग तरह का उन्माद होता है। लड़ने और नुकसान का मुंहतोड़ जवाब देने, दोनों की तत्काल जरूरत होती है। सैनिकों का एक समूह लड़ाई का निर्देशन करता है, हवाई संसाधनों को हमले की जगह पर भेजता है, गोलीबारी में घिरे सैनिकों के समर्थन के लिए त्वरित प्रतिक्रिया बल यानी क्यूआरएफ को भेजता है और तात्कालिक खतरे का जवाब देने के लिए तोपखाने को गोले बरसाने का आदेश देता है। अन्य सैनिक मारे गए जवानों की निजी वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं और फिर कुछ अन्य लोग इंटरनेट का प्लग खींच देते हैं, जिससे बेस का उसके दोस्तों और परिजनों से संपर्क खत्म हो जाता है।

■ बटुए में रखी परिवार की तस्वीर

हम नहीं चाहते कि शहीद सैनिक के परिजनों को टैक्स्ट मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट से नुकसान का पता चले। इससे भी बुरी बात यह होती है कि ऑनलाइन अफवाह से हताहत व्यक्ति की गलत पहचान हो सकती है, जिससे अनावश्यक ही परेशानी बढ़ सकती है। सैनिकों के परिवार जानते हैं कि हताहत होने की सूचना व्यक्तिगत रूप से दी जाती है और जब किसी सैनिक का अपने परिवार के साथ संपर्क टूट जाता है, तो घर के लोगों को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। हम जानते हैं कि हमारे परिवार के लोग डरे हुए हैं, लेकिन हम उनसे संपर्क नहीं कर सकते। हम उन्हें नहीं बता सकते कि हम ठीक हैं। दरअसल, जब इंटरनेट बंद हो जाता है, तो यह बेस पर मौजूद सैनिकों के लिए भी पहला संकेत होता है कि किसी की मौत हो गई है। हम लगातार अपने कर्तव्यों को पूरा करने में डटे रहते हैं, लेकिन हम हैं तो आखिर इन्सान ही। आदेशों पर जान देने के लिए तैयार बैठे हम सैनिकों की भी सभी की तरह निजी भावनाएं होती हैं। बटुए में रखी परिवार की तस्वीरें देखकर हमारी आंखों से भी आंसू निकलते हैं।

मुझे अपनी तैनाती से नफरत थी, लेकिन मुझे यह तो पता था कि मैं वहां क्यों हूं और मुझे वहां क्या करना है। जिंदगी की लड़ाई ज्यादा खतरनाक है, जहां पता ही नहीं होता कि हम यहां क्यों हैं।

■ टोरे एक दोस्त, पति और पिता भी था

'क्यूआरएफ छोटे हथियारों से गोलीबारी का सामना कर रही है।' 'इसकी पुष्टि हो चुकी है। हमने फॉक्स सिक्स को खो दिया। हमने टोरे को खो दिया।' अगले ही पल मुझे ऐसा लगा, मानो किसी ने पेट में मुक्का मार दिया हो। मैं उल्टी करना चाहता था। मेरी आंखों में आंसू तैर रहे थे। फॉक्स ट्रूप, सेकेंड स्क्वाड्रन, थर्ड आर्मर्ड कैवेलरी रेजिमेंट का कमांडर टोरे मल्लार्ड मेरा दोस्त था। वह एक पति और पिता भी था। हमने उसकी मौत से एक दिन पहले ही सेना से बाहर निकलने के बाद की योजनाओं पर बात की थी। वह बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अब वह चला गया। अब हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना था।

■ युद्ध में जिंदगी

कमांड-डिटोनेटेड आईईडी का मतलब था कि विस्फोट मैन्युअल तरीके से किया गया था। इसका यह मतलब भी था कि वे अभी पास में ही हो सकते हैं। संभवतः हम उन्हें खोज सकते थे। या हो सकता है कि दूसरे विद्रोही भी पास में हों और यह बड़े हमले की शुरुआत भर हो। युद्ध में जीवन और मृत्यु की यही लय है। वहां शोक मनाने का समय नहीं होता। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी में जितनी मौतें, चोटें और नुकसान का अनुभव नहीं करते हैं, उससे ज्यादा दुखद घटनाओं का अनुभव सैनिकों को थोड़े समय में करना पड़ता है। उनके छोटे-छोटे स्मारक हैं, लेकिन सच्ची अंत्येष्टि नहीं। यहां दुख की कोई रस्म नहीं होती। इसलिए आप दुख को दूर धकेलते रहते हैं। लेकिन आप इससे पूरी तरह भाग नहीं सकते। और जिन दोस्तों को आपने खोया, उनकी यादें आपको परेशान करती हैं। टोरे की मृत्यु के बाद कई दिनों तक मैं परेशान रहा। वह मुझे दिखता था। उसकी हंसी मुझे सुनाई देती थी। जब लगता था कि युद्ध थोड़ा धीमा हुआ है, अब कुछ ठहरा जा सकता है, तभी अचानक दूसरी कॉल आती है- कॉन्टैक्ट आईईडी। और, आपका दिल फिर से बैठ जाता है, आप फिर से काम पर ध्यान लगाते हैं और ऐसा आप बार-बार तब तक करते हैं, जब तक कि आप लौटकर घर नहीं आ जाते।

{ धूप आने दो

■ जिंदगी का युद्ध ज्यादा मुश्किल

मैं जब उन पुराने सैनिकों से बात करता हूं, तो दो बातें सामने आती हैं। एक तो यह कि हम उद्देश्य के खोने से जूझते हैं। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, मुझे अपनी तैनाती से नफरत थी, लेकिन मुझे यह तो पता होता था कि मैं वहां क्यों हूं और मुझे वहां क्या करना है। जिंदगी की लड़ाई ज्यादा खतरनाक है, जहां पता ही नहीं होता कि हम यहां क्यों हैं। दूसरी बात यह कि घर लौटने पर हम उन दुखों का सामना करते हैं, जिनसे हम किनारा कर चुके थे। अपने शहीद साथियों की यादें उमड़ने लगती हैं। आज बेशक हम अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन जब हम अपने परिवार से दूर थे, तब बेहद मुश्किल हालातों में वही सैनिक तो हमारा परिवार थे।

■ वह यादगार रात

आज हम भले ही पूरे देश में बिखरे हुए हैं, लेकिन हमें अब भी एक-दूसरे की जरूरत थी। उन गर्मियों में हम अपने साथी एवन के घर गए, जो हमारी टुकड़ी का अंतिम शहीद था। हम उसके दोस्तों से मिले, उसके माता-पिता और बहन से भी मिले। उनकी आंखें हममें एवन को देख रही थीं। हमने खूब बातें कीं। वे सभी बड़े खुश थे। वह रात यादगार थी।

https://t.me/AllNewsPaid

जानना जरूरी है
संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग
लेखक एवं अनुवादक

उत्तरी छोर पर आध्यात्मिक भार अधिक होने पर भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य से कहा कि आप दक्षिणी छोर पर चले जाएं, ताकि हमारा विवाह निर्विघ्न संपन्न हो सके। अन्यथा प्रलय आ जाएगी।

ऋषि के सहयोग से हुआ शिव-पार्वती का विवाह

हिमवान और मैना की पुत्री पार्वती बड़ी हुईं, तो उन्होंने भगवान शिव से विवाह करने का प्रण कर लिया। माता-पिता ने बहुत समझाया कि शिव योगी हैं, लेकिन पार्वती ने हठ नहीं छोड़ा। आखिर पुत्री की खुशी के लिए हिमवान ने विवाह के लिए सहमति प्रदान कर दी। परंतु शिव को पाना सरल नहीं था। इसलिए पार्वती ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप आरंभ कर दिया। आखिर, शिव ने प्रसन्न होकर पार्वती को दर्शन दिए और उनसे विवाह करना भी स्वीकार कर लिया। उस दिव्य विवाह-समारोह में सम्मिलित होने के लिए हिमालय के उच्च शिखर पर स्थित स्वर्ग और पृथ्वी पर रहने वाले अनेक ऋषि-मुनि, देवी-देवता, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, आदि एकत्र होने लगे।

विवाह पर्वत-शिखर के उत्तरी छोर पर होना था। नियत समय पर विवाह-स्थल पर इतने लोग जमा हो गए कि उनके संयुक्त आध्यात्मिक भार से पर्वत हिलने लगा। फिर भी अतिथियों का आगमन नहीं थमा। एक समय आया, जब पर्वत एक ओर से झुकने लगा। ऋषि-मुनि एवं देवता घबराकर महादेव शिव की शरण में पहुंचे और उनसे सहायता मांगने लगे। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, 'महादेव! अतिथियों के आध्यात्मिक भार से हिमालय का उत्तरी छोर नीचे की ओर झुक रहा है। अब आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा यह पर्वत पलट जाएगा और धरती पर प्रलय आ जाएगी।' शिव बोले, 'हिमालय के दक्षिणी छोर पर उत्तरी छोर के बराबर आध्यात्मिक भार हो जाए, तो पर्वत फिर से स्थिर हो जाएगा।' 'परंतु हम सबके बराबर का आध्यात्मिक भार आएगा कहां से?' देवताओं ने पूछा। 'चिंता न करें,' शिव ने मुस्कराते हुए कहा। 'इस समस्या का निवारण करने महर्षि अगस्त्य आने ही वाले हैं।'

देवता और ऋषि-गण सोचने लगे कि अकेले अगस्त्य के आने से पर्वत कैसे संतुलित होगा। इसी बीच, उन्होंने देखा कि सामने से छोटे कद के गोल-मटोल महर्षि अगस्त्य धीमी गति से चले आ रहे थे। अगस्त्य के निकट पहुंचते ही शिव बोले, 'महर्षि, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। हमें आपसे सहायता चाहिए।' 'आदेश कीजिए, प्रभु!' अगस्त्य ने हाथ जोड़कर कहा। 'असंख्य ऋषि-मुनि, देवतागण हिमालय के उत्तरी छोर पर एकत्र हो गए हैं। इन सबके आध्यात्मिक भार के कारण हिमालय का उत्तरी छोर नीचे झुक रहा है। अब आप ही पर्वत को संतुलित कर सकते हैं।' 'वह कैसे?' अगस्त्य को आश्चर्य हुआ। शिव मुस्कराए और बोले, 'महर्षि आपका आध्यात्मिक ज्ञान, यहां उपस्थित सबके संयुक्त आध्यात्मिक ज्ञान के बराबर है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप हिमालय के दक्षिणी छोर पर चले जाएं, ताकि पर्वत स्थिर हो जाए और विवाह निर्विघ्न संपन्न हो सके।'

अगस्त्य दुविधा में पड़ गए। वह बोले, 'प्रभु, मैं तो विवाह में भाग लेने आया हूं। दक्षिणी छोर पर चला गया, तो इस दिव्य समारोह से वंचित रह जाऊंगा।' शिव ने फिर कहा, 'महर्षि, यदि आप भी उत्तरी छोर पर ही उपस्थित रहेंगे, तो आज पर्वत निश्चित रूप से पलट जाएगा। यदि ऐसा हो गया, तो विवाह होना तो दूर की बात है, प्रलय आ जाएगी! इसलिए आपका दक्षिणी छोर पर जाना बहुत आवश्यक है।' महादेव ने स्वयं अगस्त्य से जाने को कह दिया, तो बेचारे महर्षि क्या करते! उन्होंने निराश होकर शिव के सामने हाथ जोड़े और 'जैसी प्रभु की आज्ञा' कहकर हिमालय के दक्षिणी छोर की ओर चल पड़े।

भगवान शिव अगस्त्य मुनि का दुख समझ रहे थे। उन्होंने अगस्त्य को रोककर कहा, 'महर्षि! आप कष्ट उठाकर विवाह में सम्मिलित होने आए हैं। इसलिए मैं आपको वचन देता हूं कि आप पर्वत के दक्षिणी छोर से भी विवाह का पूरा अनुष्ठान देख पाएंगे। इतना ही नहीं, भविष्य में जब कभी आप मेरा और देवी पार्वती का स्मरण करेंगे, तो हम आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे।'

यह सुनकर महर्षि अगस्त्य का उदास मुखमंडल फिर से खिल उठा। वह प्रसन्न मुद्रा में हिमालय पर्वत के दक्षिणी छोर पर चले गए। उनके दक्षिणी छोर पर जाते ही पर्वत, दक्षिण की ओर झुकते-झुकते आखिरकार फिर से संतुलित हो गया। विवाह संपन्न हो जाने तक अगस्त्य ने अपने स्थान पर ही रहकर शिव के वरदानस्वरूप मिली दिव्य-दृष्टि से विवाह-समारोह का आनंद लिया। इस तरह, अगस्त्य मुनि के आध्यात्मिक सहयोग के बाद ही भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हो पाया।

सक्ता: कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत।
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकी र्षुर्लोकसंग्रहम्।।

अर्थात जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें।

- भीष्म पर्व, गीता 3/25
(अर्जुन के प्रति साक्षात भगवान श्रीकृष्ण का गीतोपदेश)

प्रस्तुति : **विवेक चौरसिया**

डायनासोर फिर पैदा हो सकते हैं?

विलियम औसिच
ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में जीवाश्म विज्ञान के एमेरिटस प्रोफेसर

क्या डायनासोर के जीवाश्म के डीएनए से उन्हें फिर से पैदा करना संभव है? जीवाश्म वैज्ञानिक होने के नाते मुझसे हमेशा यह सवाल पूछा जाता है। आखिरकार *जुरासिक पार्क* (बाद में *जुरासिक वर्ल्ड*) के वैज्ञानिकों ने दर्जनों डायनासोर का फिर से निर्माण करने के लिए डीएनए का इस्तेमाल तो किया ही था। उन फिल्मों में से किसी भी फिल्म को अगर आप देखते हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या वास्तव में वैज्ञानिक आज ऐसा कर सकते हैं?

डीएनए डायनासोर सहित इस पृथ्वी पर रहने वाले हरेक जीव की कोशिकाओं में रहता है। हर किसी का डीएनए दूसरे से अलग होता है, जो उसकी कई विशेषताओं को निर्धारित करता है। ध्यान रहे, जीवों के नरम हिस्सों, जैसे अंगों, रक्त वाहिकाओं, तंत्रिकाओं, मांसपेशियों एवं वसा में डीएनए को ढूंढना आसान है। लेकिन डायनासोर के नरम हिस्से बहुत पहले खत्म हो गए। वे या तो विघटित हो गए या दूसरे डायनासोर द्वारा खा लिए गए। डायनासोर के जीवाश्म उन प्रागैतिहासिक जानवरों के अवशेष हैं। ये जीवाश्म डायनासोर के कथित कठोर हिस्सों-हड्डियों, दांत एवं खोपड़ी से प्राप्त हुए हैं। पर्याप्त जीवाश्म से वैज्ञानिक डायनासोर का कंकाल तैयार कर सकते हैं, जिन्हें आप संग्रहालय में देख सकते हैं। लेकिन डायनासोर के जीवाश्म से जब वैज्ञानिक डीएनए प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें समस्या होती है। डीएनए के अणु अंततः नष्ट हो जाते हैं। हाल के अध्ययनों में पाया गया कि सत्तर लाख वर्ष के बाद डीएनए खराब होकर अंततः विघटित हो जाते हैं। आखिरी डायनासोर क्रेटेशियस काल के अंत में मरा था। यह 6.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। यानी आज अगर जीवाश्म से डायनासोर का डीएनए प्राप्त करने की कोशिश की जाए, तो वह बेकार होगा, क्योंकि वह काफी पहले नष्ट हो चुका होगा। यानी आज सर्वोत्तम तकनीक का उपयोग करके भी डीएनए से डायनासोर बनाना संभव नहीं है।

डायनासोर का डीएनए खोजने में काफी देर हो चुकी है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ प्राप्त किया है, जो उतना ही दिलचस्प है।

डायनासोर का डीएनए खोजने में काफी देर हो चुकी है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ प्राप्त किया है, जो उतना ही दिलचस्प है। उन्होंने निएंडरथल और अन्य प्राचीन स्तनधारियों, जैसे कि वूली मैमथ (मध्य प्लेइस्टोसिन युग के दौरान साइबेरिया में पाए जाने वाले रोएंदार हाथी) के जीवाश्मों में डीएनए के टुकड़े खोजे। कल्पना कीजिए कि भविष्य में कभी यदि शोधकर्ता किसी तरह डायनासोर के डीएनए के टुकड़े लेकर आ भी गए, तो क्या होगा? केवल डीएनए के टुकड़ों से वैज्ञानिक डायनासोर नहीं बना सकते हैं। उन्हें जीवित जीव का निर्माण करने के लिए उन टुकड़ों को आधुनिक पशु के डीएनए के साथ संयोजित करना होगा। *(कन्वर्सेशन से)*

अध्ययन कक्ष

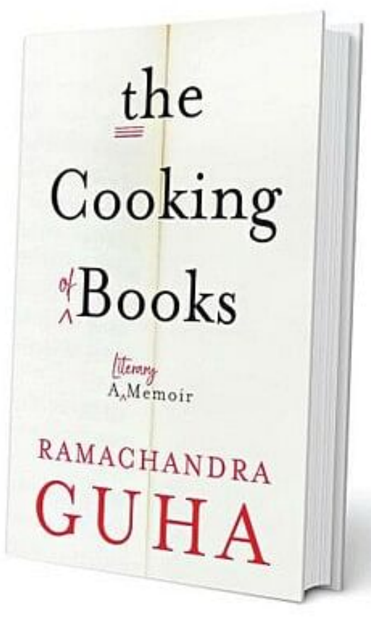

द कुकिंग ऑफ बुक्स
ए लिटरेरी मेमायर
लेखक : रामचंद्र गुहा
प्रकाशक : जगरनॉट्स
मूल्य : 498 रुपये

संपादक को याद करते हुए

लेखक-इतिहासकार रामचंद्र गुहा की पुस्तक 'द कुकिंग ऑफ बुक्स : ए लिटरेरी मेमायर' उनके शुरुआती संपादक रुकुन आडवाणी के चालीस साल पुराने रिश्तों और उनसे जुड़ीं तमाम खूबसूरत यादों को ताजा करती है।

लेखक-इतिहासकार रामचंद्र गुहा की यह पुस्तक *द कुकिंग ऑफ बुक्स : ए लिटरेरी मेमायर* उनके और उनके शुरुआती संपादक रुकुन आडवाणी के चालीस साल पुराने रिश्ते पर एक विशिष्ट और अलग तरह की किताब है। 1980 के दशक में यह दोस्ती शुरू हुई, जब रामचंद्र गुहा पीएच.डी. कर रहे थे, और रुकुन आडवाणी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के संपादक थे। 1990 के दशक में यह दोस्ती मजबूत हुई, जब गुहा पर्यावरण और क्रिकेट के क्षेत्र में एक विद्वान के रूप में उभर रहे थे, और वैरियर एल्विन की शानदार जीवनी पर काम कर रहे थे। बाद के दिनों में आडवाणी गुहा के सर्वाधिक विश्वस्त और भरोसेमंद पाठक के रूप में सामने आए, जिन्होंने गुहा से उनकी लेखन शैली पर ध्यान देने के प्रति प्रोत्साहित किया।

गुहा उदाहरण देते हैं कि वैरियर एल्विन की जीवनी की पहली प्रति जब उन्होंने एक अमेरिकी विद्वान को दी, तब उन्होंने व्यक्तित्व वाले हिस्से को छोटा करने की सलाह दी थी। लेकिन रुकुन आडवाणी ने ऐसा न करने की सलाह दी। उनका कहना था कि वैरियर एल्विन को समझने के लिए उनके व्यक्तित्व के विस्तार में जाना जरूरी है। ऐसे ही, वर्ष 1993 में महान इतिहासकार एडवर्ड थॉमसन की मृत्यु पर एक श्रद्धांजलि लिखकर गुहा ने रुकुन आडवाणी को भेजी, तो उन्होंने दिवंगत इतिहासकार के लिए एडवर्ड शब्द का इस्तेमाल न करने की सलाह दी। शुरुआती अध्याय में गुहा बताते हैं कि 1970 के दशक में वह और रुकुन आडवाणी, दोनों दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ते थे, हालांकि आडवाणी उनसे सीनियर थे। अमिताभ घोष और शशि थरूर भी तब सेंट स्टीफन के छात्र थे। गुहा कहते हैं कि बहुत पढ़ने वाले, एकांतप्रिय और संगीत में रुचि रखने वाले आडवाणी बाद में सेंट स्टीफेंस से अंग्रेजी में फर्स्ट क्लास पानेवाले विरल छात्रों में से थे। उस दौर में गुहा खुद को उधमी, लेकिन खराब तरह से कपड़े पहनने वाले युवा के रूप में याद करते हैं। गुहा ने क्रिकेट खेलने के साथ अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल करने के लिए सेंट स्टीफेंस में दाखिला लिया था। लेकिन इन फर्क के बावजूद जो चीज दोनों को एक साथ लाती थी, वह थी नेहरूवादी सोच, और यह भरोसा कि विज्ञान और तकनीक के जरिये भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। चार दशक बाद रुकुन आडवाणी भले ही गुहा के प्रकाशक नहीं रहे, लेकिन तब भी वह उनके सबसे विश्वस्त सलाहकार बने हुए हैं। अनेक मुद्दों पर दोनों एकमत नहीं हैं। फिर भी अपने इस संपादक को गुहा आज भी अपने मेंटोर के रूप में देखते हैं। इस किताब से पहले भी लेखक ने अपने विविध लेखों में रुकुन आडवाणी को याद किया है। एक जुझारू विद्वान और लोगों से संवाद करने वाले इतिहासकार तथा एक एकांतप्रिय और मृदुभाषी संपादक के बीच की दोस्ती पर यह अद्भुत किताब है। गुहा की शोधपरक पुस्तकों की तुलना में यह किताब बेशक पतली है, लेकिन एक इतिहासकार के रूप में गुहा के उत्तरोत्तर विकास के बारे में जानने के लिए यह अनिवार्य पुस्तक है। संपादक और लेखक के आपसी रिश्तों पर केंद्रित यह उल्लेखनीय किताब है, जिसका साहित्यिक मूल्य तो है ही, निश्चित तौर पर ऐतिहासिक मूल्य भी है।

अभियान

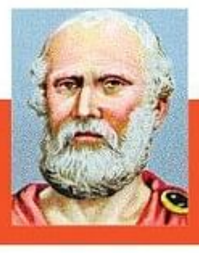

अच्छी तरह किया गया थोड़ा-सा कार्य भी बेहतर है, बजाय इसके कि ढेर सारा कार्य अपूर्णता से किया जाए।
- प्लेटो, महान दार्शनिक

amarujala.com
अमर उजाला

गोल चबूतरा

Hindi@mithelesh

■ मिथिलेश बारिया

बस पन्ने ही फड़फड़ाते हैं
उस किताब के, हवा से,
कहानियां जो अंदर हैं, खामोश-सी हैं...

उस महंगे गद्दों की दुकान के बाहर देखा
उसी का चौकीदार,
रात में जमीन पर सोए हुए...

बना रहे थे टेलीग्राफ बन गया टेलीफोन

आज के ही दिन सन 1875 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ध्वनि का पहली बार प्रसारण किया था। एक हार्मोनिक टेलीग्राफ पर काम करते समय ग्राहम बेल और थॉमस वॉटसन ने यह महत्वपूर्ण खोज की थी। बेल ने 1872 में बधिर छात्रों के लिए 'स्कूल ऑफ वोकल फिजियोलॉजी एंड मैकेनिक्स ऑफ स्पीच' खोला था। छात्रों को पढ़ाने के साथ-साथ उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय में ध्वनि से संबंधित अपनी खोज को भी जारी रखा। यहीं पर बेल और उनके सहायक वॉटसन ने तार के माध्यम से ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के प्रयास किए। इस खोज ने बेल को अपना ध्यान टेलीग्राफ में सुधार करने से हटाकर ध्वनि प्रसारण की क्षमता को बेहतर बनाने की ओर प्रेरित किया। उन्होंने और वॉटसन ने अगले कई महीने एक कार्यशील ट्रांसमीटर और रिसीवर बनाने में बिताए। ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉनिक धाराओं को अलग-अलग करने और रिसीवर बातचीत सुनने में सक्षम था। 10 मार्च, 1876 को इस नवीन उपकरण के माध्यम से बोलते हुए ग्राहम बेल ने अपने सहायक को फोन किया। उनके पहले शब्द थे, "मिस्टर वॉटसन, यहां आओ। मैं आपको देखना चाहता हूं।" इस तरह टेलीफोन दुनिया के सामने आया।

झरोखा
2 जून

■ मनाली से किरण घोष

पंजाब-हरियाणा में गेहूं के खेतों में आग लगाई जा रही है। अग्नि की चपेट में आकर आसपास के जीव-जंतु भी झुलस रहे हैं। इस आग ने पंछी, कीट-पतंगे और सरीसृप का जीवन संकट में डाल दिया है। सवाल यह है कि इन जीव-जंतुओं की कौन सुनेगा?

झुलसते जीवन की कौन सुने?

ये मुसीबत हमने खुद खड़ी की है

उत्तर भारत में बैसाख के महीने में गेहूं की कटाई हो जाती है और आषाढ़ में धान की बिजाई की जाती है। ज्येष्ठ के महीने में किसान गेहूं की फसल से फारिग हो नई बिजाई की तैयारी में लग जाते हैं।

जब हाथ से कटाई होती थी तो गेहूं के अवशेष (नाड़) को चारे के रूप में पशुओं के लिए संरक्षित कर लिया जाता था, लेकिन खेती के मशीनीकरण के चलते फसल के बचे हुए हिस्से को जलाया जाने लगा है। हालांकि समझदार किसान परामर्श देते हैं कि अगर बचे हुए डंठलों को खेत में ही जोत दिया जाए तो जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और अगली फसल अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोगों की दबंगई के कारण आज नाड़ जलाने का प्रचलन खतरनाक स्तर पर बढ़ रहा है। इसी वर्ष पंजाब में 11 हजार से अधिक खेतों में नाड़ को आग लगाने की घटनाएं सामने आई हैं और अभी इसका पूरा निष्पादन भी नहीं हो पाया है। खेतों की यही आग अनियंत्रित हो पर्यावरण को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही है, साथ ही मौसम की तपिश में भी वृद्धि कर रही है। हैरानी की बात है कि न तो सामाजिक संगठन और न ही धार्मिक संस्थाएं इस मुद्दे पर अपनी जुबां खोलने को तैयार हैं। भारत के इस उत्तरी हिस्से में आषाढ़ और सावन महीने को पावस का मौसम माना जाता है। इस दौरान जीव जगत प्रसव काल से गुजरता है। बारिश की प्राणदायक बूंदें तपती धरती पर राहत बरसाती हैं, जो प्राणी जगत में प्रेम और प्रजनन की कामना पैदा करती हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पंजाब-हरियाणा के लोग इन्हीं किसानों के रहमो-करम पर जीने को विवश हैं। जब शासन, प्रशासन और आम नागरिक इतना बेबस है तो जलते हुए इन असहाय पेड़-पौधों और मूक जीव-जंतुओं की कौन सुनेगा?

चिट्ठी 1

■ राकेश सैन, जालंधर

बैंक फ्रॉड से बचना होगा

देश में एक साल में बैंक फ्रॉड 166 प्रतिशत बढ़े हैं। 2023-24 में कुल 36,075 लोग बैंक फ्रॉड के शिकार हुए हैं। 2022-23 में इनकी संख्या 13,564 थी।

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा 80 प्रतिशत फ्रॉड क्रेडिट या डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े हैं। 11 प्रतिशत कार्ड डिजिटल लैंडिंग से जुड़े हैं। साढ़े पांच प्रतिशत लोग बैंकों में पैसा जमा करने के दौरान ठगी का शिकार हुए। 2022-23 में ग्राहकों ने 26.12 हजार करोड़ रुपये गंवाए, जो 2023-24 में घटकर 13.93 हजार करोड़ रुपये रह गए। रिजर्व बैंक की यह रिपोर्ट निश्चित ही चौंकाने वाली है। साथ ही सचेत होने की भी जरूरत है। भले ही फ्रॉड की राशि 2023-24 में कम हुई है, फिर भी खून-पसीने की गाढ़ी कमाई को इस तरह गंवाना खून के आंसू पीने के समान है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक हाथ पर हाथ धरकर न बैठें। बैंक में हो रहे इन फ्रॉड को रोकने के लिए ऐसा मजबूत तकनीकी जाल तैयार करें, जिससे फ्रॉड करने वाले ग्राहकों को अपना शिकार बना न सकें।

चिट्ठी 2

एक नागरिक होने के नाते यह हमारा भी कर्तव्य है कि अगर हम बैंक में किसी कार्य से जाएं तो पहले उस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। अक्सर देखा गया है कि जानकारी के अभाव में आकर हम ठगी का शिकार हो जाते हैं। अगर बैंक से संबंधित कोई कार्य ऑनलाइन करना है तो भी आप इस संबंध में अधिकारियों से पहले बात कर लें।

■ हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन

ड्राइविंग के वक्त फोन नहीं

आज के समय में स्मार्टफोन हर किसी के लिए जरूरी बन गया है। आवश्यकता अनुसार मोबाइल का इस्तेमाल करके अपनों का हाल-चाल जानते रहना चाहिए, परंतु यही मोबाइल सड़क पर पैदल चलते समय या फिर वाहन चलाते समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कब, किधर से कोई खतरा सिर पर आ जाए, कह नहीं सकते। हमें उन सब वाहन चालकों से सख्त नाराजगी है, जो दुपहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातचीत करते हैं। बातचीत करते समय उन्हें आगे-पीछे से आने वाले किसी भी खतरे का भान नहीं रहता। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना सड़क सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा करता है। अक्सर सड़कों पर लोगों के ऐसे व्यवहार को रोकने के लिए और जिम्मेदार ड्राइविंग आदतों को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाती है, मगर स्थिति नहीं सुधरती। जो लोग वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातचीत करते हैं, उन्हें न केवल रोकने का प्रयास किया जाए, बल्कि इस अपराध के लिए दंडित भी किया जाए, उनका चालान हो और उन्हें ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाए। देशभर में पुलिस अपनी ओर से समझाने का भरपूर प्रयास करती है कि चालक अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल न करें। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि वाहन चलाते समय हमें मोबाइल का उपयोग करने से बचना चाहिए।

चिट्ठी 3

■ एमएम राजावतराज, शाजापुर

इनकी चिट्ठियां भी सराहनीय रहीं

मेरठ से डॉ. सुधाकर आशावादी, नैनीताल से अमृता पांडे, नैनीताल से डॉ. प्रमोद अग्रवाल गोल्डी, मोहाली से अभिलाषा गुप्ता, फिरोजाबाद से नितिन रावत, भिवानी से डॉ. सत्यवान सौरभ, जालंधर से राजेश कुमार चौहान, बाड़मेर से मुकेश बोहरा अमन, शाजापुर से कुमार गौतम, नैनीताल से अशोक वार्ष्णेय, अंबाला से मनीषा पांडे, मथुरा से अटल राम चतुर्वेदी।

हमें लिखें
abhiyan@amarujala.com

कुछ अलग

एक ही प्रजाति के पेड़ों का जंगल

क्या आपने दुनिया के सबसे बड़े और भारी पेड़ के बारे में सुना है? इस पेड़ का अपना पूरा जंगल है।

अमेरिका के यूटा राज्य में 'फिशलेक राष्ट्रीय वन' है। यह एक ऐसा वन क्षेत्र है, जो एक ही प्रजाति के पेड़ों से आच्छादित है। ये पेड़ 'पांडो' नाम से जाने जाते हैं, जिनको दुनिया के सबसे बड़े और भारी पेड़ों में गिना जाता है। इस जंगल में 40,000 से अधिक पेड़ हैं। माना जाता है कि ये पेड़ 106 एकड़ क्षेत्रफल में फैले हैं। इस जंगल के पेड़ आनुवंशिक रूप से समान हैं। वे सभी एक विशाल भूमिगत जड़ प्रणाली से जुड़े हुए हैं, जिसको 'ट्रेम्बलिंग जॉइंट' के रूप में जाना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, पांडो में प्रत्येक नया पेड़ मूल वृक्ष का आनुवंशिक क्लोन है। पांडो का लैटिन में अर्थ होता है 'मैं फैलता हूं' और इसकी जड़ों के फैलते रहने के कारण ही इसे पांडो नाम दिया गया। इसका दूसरा नाम 'क्वेकिंग ऐस्पन' भी है, जो इसकी पत्तियों के चपटे डंठलों के हवा में हिलने या कांपने के कारण पड़ा है। कुछ वैज्ञानिकों ने पांडो की आवाज रिकॉर्ड की है। जब इस अविश्वसनीय पेड़ की लाखों पत्तियां कंपन करती हैं तो इससे उत्पन्न ध्वनि केवल हवा में नहीं फैलती, बल्कि वह शाखाओं और तने तक पहुंचती है और वहां से अपनी जड़ प्रणाली के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है। हजारों वर्षों से यह जंगल अनेक चुनौतियों का सामना करता रहा है, जिनमें जंगल की आग, शाकाहारी भोजन, जलवायु परिवर्तन और विशेष रूप से सूखा शामिल हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं में हुई क्षति के बावजूद तेजी से नए अंकुर फूटने और जड़ों के जरिये फिर से उगने की अपनी क्षमता के कारण ये पेड़ सदियों से यहां खड़े हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि पांडो का संरक्षण करना अत्यावश्यक है। न केवल इसलिए कि यह दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह अकेले ही एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। यह जगह वन्यजीवों के लिए जरूरी आवास है। यह झरनों और नदियों में पानी के प्रवाह और कटाव को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।

■ नेहा गुप्ता, हरिद्वार

खेल, सिनेमा और सितारे...

यह तस्वीर पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव की है। इसमें वह सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्राण और मनोज कुमार के साथ नजर आ रहे हैं।

■ दिल्ली से ओम रावत

छायानट

गायक, कलाकार या डबिंग आर्टिस्ट !

एसपी बालासुब्रमण्यम का नाम संगीत जगत के दिग्गजों में शुमार है। कम ही लोगों को पता है कि वह कमाल के डबिंग आर्टिस्ट भी थे। कमल हासन की ज्यादातर तेलुगु फिल्मों में उन्होंने ही डबिंग की थी। फिल्म 'दशावतारम' के तेलुगु वर्जन में कमल हासन के 10 किरदारों में से अधिकतर की डबिंग उन्होंने ही की थी। डबिंग के लिए उन्हें दो बार नंदी पुरस्कार भी मिला था। नंदी पुरस्कार तेलुगु सिनेमा, थिएटर और टीवी के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। अनिल कपूर, गिरीश कारनाड, मोहनलाल और रजनीकांत के लिए भी वह तमिल या तेलुगु में डबिंग करते रहे। कॅरिअर की शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया। 1946 में जन्मे एसपी बालासुब्रमण्यम की संगीत में रुचि जरूर थी, मगर सपना इंजीनियर बनने का था। 1966 में तमिल फिल्म 'श्रीश्री मर्यादा रामन्ना' में उन्होंने पहला गाना गाया। वहीं से तमिल और कन्नड़ में मौके मिलने लगे थे।

■ राम सिन्हा, जम्मू

कब सुधरेंगी हमारी गलतियां !

भारत के सामने आज गलतियों की एक लंबी लिस्ट है, जिसे अगर अच्छी तरह से सुधारा नहीं गया तो एक गणतंत्र के रूप में हमारा भविष्य कमजोर हो सकता है।

रामचंद्र गुहा
जाने-माने इतिहासकार

इस बार का चुनाव बहुत ही कठिन रहा और पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी। इसके परिणाम कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। जो भी पार्टी या गठबंधन अगली सरकार बनाएगा, उसे उन गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें चुनाव अभियान ने पीछे धकेल दिया है। भारत के सामने आज गलतियों की एक लंबी लिस्ट है, जिसे अच्छी तरह सुधारा नहीं गया तो एक गणतंत्र के रूप में हमारा भविष्य कमजोर हो सकता है।

पहली गलती पार्टी प्रणाली का भ्रष्टाचार है। ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र होता है, जिसमें नेता स्वतंत्र रूप से चुने जाते हैं और वे अपनी पार्टी के सहयोगियों के प्रति जवाबदेह होते हैं। भारतीय राजनीति आज इस मॉडल से बिल्कुल अलग है। यहां राजनीतिक पार्टियां या तो व्यक्तित्व के साये तले हैं या एक पारिवारिक फर्म बन गई हैं। व्यक्तित्व के साये तले वाली बात का ज्वलंत उदाहरण भारतीय जनता पार्टी है। पिछले एक दशक में पूरी पार्टी और सरकारी तंत्र का बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी को दिव्य व्यक्तित्व वाला बनाने में जुटा रहा है। हालांकि भौगोलिक तौर पर अपने सीमित क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, केरल में पिनाराई विजयन, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और ओडिशा में नवीन पटनायक जैसे मुख्यमंत्री भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। कुछ इस तरह कि मानो वे ही शासन करते रहेंगे। लोकतांत्रिक संस्थाओं का दिखावा करने वाली पारिवारिक पार्टियां भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस इसके लिए मुख्य रूप से दोषी है। उसने पार्टी के लिए दशकों तक काम करने वालों को नजरअंदाज कर प्रियंका गांधी को रातों-रात महासचिव बना दिया।

गांधी परिवार से पीछे न रह जाएं, इस वजह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुलबर्गा की अपनी पुरानी सीट अपने दामाद को दे दी, जबकि उनका एक बेटा पहले से ही कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री है। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, सपा उत्तर प्रदेश में और डीएमके तमिलनाडु में ऐसी पार्टियां हैं, जो एक ही परिवार के नियंत्रण में रही हैं। यह सोचने पर मजबूर करता है कि जिस ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली को हमने अपनाया, उससे हम कितने अलग हैं।

प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने कोई धर्म-पंथ नहीं है। मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के नेता केर स्टार्मर किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं। वे दोनों आज जिस मुकाम पर हैं, वहां अपनी मेहनत और पार्टी के सहयोगियों के समर्थन से हैं। जब भी वे समर्थकों का विश्वास खो देंगे, बिना किसी हंगामे के अपना पद छोड़ देंगे और उनकी जगह पर ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा, जो किसी राजनीतिक वंशावली से नहीं होगा।

भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता इस बात से भी और कम हुई है कि नागरिकों को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता है और वर्षों तक जेल में रखा जा सकता है। कानूनों का उपयोग राजनीतिक विरोधियों ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह की असहमति जताने वालों को डराने और चुप कराने के लिए किया जाता है। इस तरह के दुरुपयोग में अदालतें भी शामिल हैं।

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि हमारी राजनीतिक कमियां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के दावों के आडंबरों के पीछे छिपी हैं। दूसरा दावा विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का है। हालांकि आर्थिक उदारीकरण की वजह से गरीबी में तो कमी आई है, लेकिन इससे असमानता भी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हुई। शिक्षित वर्गों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है।

भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है और इसके पर्यावरणीय रिकॉर्ड विनाशकारी रहे हैं। आर्थिक तौर पर भारत के सबसे 'समृद्ध शहर' बेंगलुरु में जल संकट और भारत के 'वैश्विक उत्थान' वाले शहर नई दिल्ली में वायु प्रदूषण की उच्च दर इस बात का प्रतीक है कि हमने संसाधनों का कितना दुरुपयोग किया है। जैसा कि मैंने पहले लिखा है, हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा पर्यावरण संकट है। जहरीली हवा, गिरता जल स्तर, दूषित मिट्टी और विलुप्त होती जैव विविधता की वजह से करोड़ों भारतीयों की आजीविका और सेहत खतरे में पड़ गई है और ये भविष्य के बारे में गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारे औद्योगिक और आर्थिक संसाधन टिकाऊ हैं?

कई दशकों तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी इसमें सबसे अधिक बनती है। उसका कहना है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, उसके बाद से स्थिति और खराब होती गई। हम जिसे सांप्रदायिक समस्या कहते हैं, वह भी कोई नई नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद जो मुसलमान भारत में रह गए, उन्हें पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह कहते हुए आश्वस्त किया था कि पाकिस्तान में जो भी अधिकार दिए गए हैं, वही समान नागरिक अधिकार यहां भी दिए जाएंगे। लेकिन उन्हें अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा गया। धर्मों के बीच की यह खाई राजीव गांधी के शासनकाल में बढ़ती गई, क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम, दोनों के बीच कट्टरता को बढ़ावा दिया।

2014 के बाद से भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना कई गुना बढ़ गई, क्योंकि स्वतंत्र राष्ट्र के इतिहास में पहली बार केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अपनी हिंदू बहुसंख्यकवादी महत्वाकांक्षा को स्पष्ट कर दिया था। राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में धर्म का बोलबाला बढ़ गया, जब प्रधानमंत्री ने खुद को ईश्वर द्वारा धरती पर भेजे गए उस हिंदू राजा की तरह दिखाया, जो हिंदुओं की सभी परेशानियों को दूर कर देगा। इसके परिणामस्वरूप भारतीय मुसलमानों ने खुद को इतना डरा हुआ कभी महसूस नहीं किया, जितना अब कर रहे हैं। ये भविष्य के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, कहना मुश्किल है।

एक अंतिम समस्या, जो मैं उठाना चाहता हूं, वह है राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध। भाजपा समर्थक 1959 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा केरल की वामपंथी सरकार को बर्खास्त करने और इंदिरा गांधी के बार-बार अनुच्छेद 356 का उपयोग करने पर चर्चा तो करना पसंद करते हैं, लेकिन दूसरे दलों के शासन वाले राज्यों के प्रति उनका रवैया अच्छा नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शासनकाल में उन राज्यों की ओर कम ध्यान दिया गया, जहां भाजपा का शासन नहीं है। चुने हुए मुख्यमंत्रियों का मजाक उड़ाया गया। जान-बूझकर ऐसे राज्यपालों को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर हर मोड़ पर राज्य सरकार के काम में बाधा पहुंचाई है। यहां तक कि गणतंत्र दिवस परेड जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों से अन्य दलों द्वारा शासित राज्यों की झांकियों को हटाकर यह स्पष्ट कर दिया कि वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि भारत के प्रत्येक राज्य में भाजपा का शासन नहीं हो जाता। उनके इस व्यवहार से अधिनायकवाद और निरंकुशता की बू आती है।

हमने अभी देखा है कि आम चुनाव में करोड़ों भारतीयों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। हालांकि यह कहना सही है कि ये वोट गैर प्रतिनिधित्व वाली पार्टी, समझौता किए गए संस्थानों, अलोकतांत्रिक कानून, गिरती अर्थव्यवस्था, असुरक्षित अल्पसंख्यक और संघीय ढांचे के बढ़ते तनाव के संदर्भ में दिए गए थे। आने वाले समय में जो भी सरकार सत्ता में आएगी, उसके लिए सबसे पहला काम इन सभी गलतियों को सुधारना होगा।

तलत हुसैन दिल्ली को कभी नहीं भूले

प्रसिद्ध अदाकार तलत हुसैन इस दुनिया से विदा हो गए। वह भारत और पाकिस्तान सिनेमा के एक ऐसे अदाकार रहे, जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप में अपनी अदाकारी और आवाज से सिनेमा का एक नया अध्याय लिखा। भारतीय सिनेमा संसार की हिंदी फिल्म 'सौतन की बेटी' जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के जमकर जौहर दिखाए।

डॉ. कृष्ण कुमार रत्तू

स्मृति शेष

तलत हुसैन

उनके दिल में दिल्ली थी, पांवों में कराची थी, जबरदस्त अदाकारी और आवाज का जादू पूरी दुनिया में समाया हुआ था।

पाकिस्तानी सिनेमा स्क्रीन की एक लंबी फेहरिस्त उनके खाते में है। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में भी काम किया। जहां-जहां भी हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू को जानने वाले लोग हैं, वहां-वहां वह एक दिलफरेब आर्टिस्ट की तरह छा गए थे। अपनी जीवनी पर पुस्तक जब उन्होंने जुबानी रिकॉर्ड कराई तो लोग वाह-वाह कर उठे थे। वह भारत और पाकिस्तान के बीच में राजनीतिक बातों को प्यार, मोहब्बत, सिनेमा, संस्कृति और विरासत के इतिहास से जोड़ना चाहते थे। उनका पूरा नाम तलत हुसैन वारसी था।

18 सितंबर, 1940 को दिल्ली में उनका जन्म हुआ और यही एक अहसास था, जिसको तलत भारत में अपने जन्म की जड़ों में ढूंढते थे। वह सारी उम्र कराची, लाहौर में रहकर लंदन तक काम करते रहे, मगर उनके दिल में दिल्ली की मोहब्बत सदैव जिंदा रही।

अपनी मुलाकातों में तलत हुसैन एक पढ़े-लिखे, विनम्र और साधारण इन्सान थे। पाकिस्तान सरकार ने उनको देश के सबसे बड़े सम्मान 'सितारा ए इम्तियाज' से नवाजा था। भारतीय सिनेमा संसार के भी कई पुरस्कार उनको मिले थे। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कराची के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।

पाकिस्तानी टेलीविजन, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए उनकी सेवाओं को याद किया जाएगा। वह नई पीढ़ी के लिए भारत-पाकिस्तान में एक ऐसे गुरु एक्टर की तरह थे, जिनकी एक अलग पहचान थी और जिनकी आवाज के मुरीद उन्हें नम आंखों से याद कर रहे हैं। उन्होंने सदैव भारत को जी भरकर याद किया और नम आंखों से अपनी जन्मभूमि दिल्ली जैसे शहर को कभी नहीं भूले, इसीलिए उनको भारत-पाकिस्तान की दोस्ती का ऐसा अदाकार कहा जाता है, जिसको आज याद किया जा रहा है।

https://t.me/InNewsPaperPdf

एक सफल सम्राट को उसके देशवासियों का विश्वासपात्र होना चाहिए। इससे राजा और राज्य, दोनों की भलाई होती है।

– जूलियस सीजर

परिवर्तनकारियों की चुनौती

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

भारत में बदलाव की जरूरत है और वह इसका हकदार भी है। दस वर्ष पहले, बदलाव की मांग उठी थी और सरकार यूपीए से एनडीए में बदल गई थी। मुझे लगता है कि भारत फिर से ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। पिछले दस वर्षों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, जिसे बदला जाना चाहिए या सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

पिछले सप्ताह के स्तंभ का समापन मैंने इन शब्दों के साथ किया था, 'जैसे-जैसे चुनाव सात चरणों में पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है, लड़ाई यथास्थिति बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों और यथास्थिति को भंग करने के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों के बीच बढ़ती गई है।' वोटों की गिनती में अभी दो दिन बाकी हैं, फिर हम जान जाएंगे कि बहुसंख्य लोग (या बहुमत) परिवर्तन चाहते हैं या यथास्थिति को बनाए रखने में खुश हैं।

यथास्थिति में सुख

निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों में बदलाव की ख्वाहिश है, मगर मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बदलाव नहीं चाहते। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि बदलाव न चाहने वालों को डर है कि बदलाव उनके जीवन को बदतर बना सकता है; या फिर अज्ञात, ज्ञात से अधिक भयावह लगता है; या उन्हें डर है कि एक पक्ष का परिवर्तन जीवन के अन्य पक्षों को प्रभावित करेगा। जैसे, रीति-रिवाजों को तोड़ना, समुदाय की नाराजगी मोल लेना हो सकता है। यथास्थिति में एक निश्चित सुख है।

भारत के पिछले तीस वर्षों में कुछ ऐसे दौर रहे हैं, जब प्रेरक शक्ति परिवर्तन थी। कुछ विशेष कालखंडों में यथास्थिति की रक्षा का प्रयास किया गया। अन्य समयों में इसे अतीतवाद के रूप में देखा गया, जिसे शब्दकोश में 'पश्चगामी प्रवृत्ति' के रूप में परिभाषित किया गया है। (अतीतवादी लोग अपने खोए हुए और गौरवशाली अतीत में ही सब कुछ देखते हैं।)

मेरा मानना है कि भारत में बदलाव की जरूरत है और वह इसका हकदार भी है। दस वर्ष पहले, बदलाव की मांग उठी थी और सरकार यूपीए से एनडीए में बदल गई थी। मुझे लगता है कि भारत फिर से ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। पिछले दस वर्षों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, जिसे बदला जाना चाहिए या सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके कुछ उदाहरण हैं :

भुक्तभोगी

2016 में किया गया विमुद्रीकरण एक बहुत बड़ी गलती थी। नकदी में भारी कमी ने लोगों के जीवन के साथ-साथ सैकड़ों-हजारों सूक्ष्म और लघु इकाइयों के कामकाज में उथल-पुथल मचा दी। कई इकाइयां उससे उबर नहीं पाईं और बंद हो गईं।

महामारी के वर्षों (2020 और 2021) में की गई अनियोजित पूर्णबंदी ने स्थिति को और खराब कर दिया। वित्तीय पैकेज और ऋण की अनुपलब्धता के चलते सूक्ष्म और लघु इकाइयों की दशा और खराब हो गई। बहुत सारी इकाइयां बंद हो गईं और दोहरे झटके के परिणामस्वरूप, सैकड़ों-हजारों नौकरियां चली गईं। इस विकट स्थिति को बदलने के लिए एक साहसिक योजना की आवश्यकता है, जिसमें कर्ज माफी, बड़े पैमाने पर ऋण, सरकारी खरीद, निर्यात प्रोत्साहन और कर रियायतें शामिल हों। मुझे इनमें से किसी से भी जुड़ी कोई योजना नजर नहीं आती। आरक्षण पर मौन प्रहारों ने एससी, एसटी और ओबीसी से किए गए संवैधानिक वादों को खत्म कर दिया है। सरकार और सरकारी क्षेत्र में तीस लाख पदों को खाली छोड़ना आपराधिक उपेक्षा और आरक्षण विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। आरक्षण पर पचास फीसद की सीमा की कसम खाते हुए, यथास्थितिवादियों ने चुपचाप आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए पचास फीसद के अलावा दस फीसद कोटा जोड़ दिया, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी के बीच ईडब्ल्यूएस को बाहर रखा, क्यों? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नौकरियों में शुद्ध कमी, आरक्षण पर शर्तों के बिना निजीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सरकारी की तुलना में निजी क्षेत्र को वरीयता, प्रश्नपत्रों के लीक का हवाला देकर सार्वजनिक परीक्षाओं को रद्द करना, पदोन्नति न करना और नौकरियों में ठेकेदारी और अस्थायीकरण से आरक्षण की नीति गंभीर रूप से कमजोर हो गई है। बदलाव केवल उन लोगों के कहने पर आएगा, जो यथास्थिति को चुनौती देते हैं।

नुकसान की भरपाई

कानूनों के शस्त्रीकरण को पलटा जाना चाहिए। पिछले दस वर्षों में पारित किए गए नए विधेयकों या संशोधन विधेयकों को पलटने वाले लोगों के वर्चस्व वाली संसद कैसे पलटेगी? जांच एजंसियों पर लगाम कौन लगाएगा और उन्हें संसद/विधानसभा समितियों की निगरानी में कौन लाएगा? संविधान के अनुच्छेद 19, 21 और 22 के अर्थ और विषय-वस्तु को कौन बहाल करेगा और कानून का शासन फिर से स्थापित करेगा? 'बुलडोजर न्याय' और 'परीक्षण-पूर्व कारावास' को कौन समाप्त करेगा? लोगों में कानून के प्रति भय को कौन दूर करेगा और उसकी जगह कानून के प्रति सम्मान को कौन स्थापित करेगा? 'उचित प्रक्रिया' को आपराधिक कानून का अपरिवर्तनीय सिद्धांत कौन बनाएगा और कानून में यह सिद्धांत शामिल करेगा कि 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है'? ये बदलाव केवल निडर सांसदों के एक समूह द्वारा ही किए जा सकते हैं, जो बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के मौलिक मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

उदारीकरण, खुली अर्थव्यवस्था, प्रतिस्पर्धा और विश्व व्यापार के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आया है, लेकिन ये तभी प्रासंगिक रहेंगे जब आर्थिक नीतियों को पुनर्निर्धारित किया जाएगा। धीरे-धीरे बढ़ते नियंत्रण, प्रच्छन्न लाइसेंसिंग, बढ़ते एकाधिकार, संरक्षणवाद और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के डर के कारण विकास दर में गिरावट आई है, जैसा कि होना ही था। श्रम की कीमत पर पूंजी के प्रति पूर्वाग्रह (हमारे पास पीएलआइ है, लेकिन ईएलआइ नहीं है) ने रोजगार और मजदूरी को दबा दिया है- जो बढ़ती असमानता के कारणों में से एक है। विश्व असमानता प्रयोगशाला के अनुसार, भारत की असमानता 1922 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है।

कई लोग औसत आय में वृद्धि से धोखा खा जाते हैं। याद रखें, औसत से नीचे पचास फीसद भारतीय (71 करोड़) हैं और एक अन्य डेटा पर गौर करें: भारत की वयस्क आबादी (15-64 वर्ष) 92 करोड़ है, लेकिन केवल 60 करोड़ श्रमबल में हैं। श्रमबल भागीदारी दर (एलएफपीआर) का सबसे उदार अनुमान 74 फीसद (पुरुष) और 49 फीसद (महिलाएं) हैं। असंतोषजनक एलएफपीआर, उच्च बेरोजगारी दर और उम्रदराज आबादी को मिलाएं, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि हम तेजी से जनसांख्यिकी के फायदे गवां रहे हैं। मौजूदा आर्थिक नीतियों को चुनौती देने और उन्हें फिर से स्थापित करने की हिम्मत कौन करेगा? यथास्थितिवादी तो कतई नहीं।

केवल व्यवधान ही बदलाव लाएगा। व्यवधान और बदलाव, कई लाभ और कुछ नुकसान लाएंगे, जिन्हें ठीक किया जा सकता है। 1991 का प्रमुख सबक यह है कि जो हिम्मत करता है, वह जीतता है। यथास्थितिवादियों ने- जो कोई बदलाव नहीं चाहते- वह सबक नहीं सीखा है और न ही सीखेंगे।

विकसित बनने का सपना

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने का। लेकिन क्या इसके बारे में हम सोच भी सकते हैं, जब हर दूसरे दिन कोई ऐसी घटना घट जाती है, जिसमें लोग बेमौत मारे जाते हैं सिर्फ इसलिए कि अपने देश में कानून का डर किसी को नहीं है। यही कारण है कि हत्यारों, बलात्कारियों और आतंकवादियों को भी दंडित करने में कई दशक लग सकते हैं।

सच पूछिए तो, चुनावों के बारे में लिखने का इस सप्ताह मन ही नहीं हो रहा। कहने को अब है भी क्या, जब तक नतीजे नहीं आ जाते। ऊपर से, पिछले दिनों इतने दर्दनाक हादसे हुए हैं, जिन्होंने अपने तथाकथित प्रगतिशील, 'विश्वगुरु' भारत के चेहरे के सामने आईना दिखा कर साबित किया है कि 'विकसित' देश होने से हम कितनी दूर हैं।

इन दर्दनाक, शर्मनाक घटनाओं में सबसे शर्मिंदा करने वाली घटना हुई थी पुणे में कुछ दिन पहले, जिस पर लिखने में भी तकलीफ होती है। एक रईस के बिगड़ैल बेटे ने शराब पीकर पिता की दी हुई पोर्श गाड़ी तेज रफ्तार में चलाते हुए दो जवान लोगों को रौंद डाला। भीड़ जब इकट्ठा हुई और इस बिगड़े रईसजादे को गाड़ी में से घसीट कर उसकी पिटाई शुरू की तो उसने बेशर्मी से कहा कि 'जितना पैसा चाहिए दे दूंगा, हमको मारो मत'। कहानी यहां खत्म हो गई होती, तो शायद कुछ कहने को न होता, इसलिए कि ऐसा तो विकसित देशों में भी हो सकता है। मगर जो आगे हुआ वह नहीं हो सकता है। बच्चे को जेल में बंद होने से बचाने के लिए उसके बाप और दादा ने अपने ही ड्राइवर को अगवा किया और उस पर दबाव डाला यह कहने के लिए कि गाड़ी वह चला रहा था। इतने में अस्पताल में डाक्टरों को रिश्वत दी गई हत्यारे बच्चे के खून की जांच कूड़े में फेंक कर दूसरे का खून रखने के लिए, ताकि सबूत न रहे कि उसने शराब पीकर गाड़ी चालाई थी। कहते हैं कि इस अपराध में साथ दिया कुछ नेताओं और पुलिसवालों ने भी।

ऐसी चीजें विकसित देशों में नहीं हो सकती हैं। विकसित देशों में कानून-व्यवस्था इतनी मजबूत होती है कि उसके साथ इस तरह की छेड़खानी कोई नहीं कर सकता है, न पैसों के बल से, न राजनीतिक दबाव से। ऐसी चीजें होती हैं उन देशों में जहां कानून-व्यवस्था इतनी कमजोर होती है कि देश की राजधानी में तीस फीसद अस्पताल चलाए जा रहे हैं नाजायज तरीके से। यह मालूम हुआ तब जब बच्चों के एक अवैध अस्पताल में आग लगी और उसमें कई नवजात बच्चों की मौत हो गई। ऐसी दर्दनाक घटना अगर किसी विकसित देश में होती तो कई दिनों तक खबर को मीडियावाले सुर्खियों में रखते, ताकि न्याय मिल सके उन बेचारों को, जिनके नवजात बच्चे उस अवैध अस्पताल के आइसीयू के अंदर जन्म लेते ही जिंदा जलकर मर गए थे। अपने भारत महान में बहुत कठिन है रास्ता न्याय का आम नागरिकों के लिए। न्याय मिलना आसान होता है सिर्फ धनवानों, राजनेताओं और आला सरकारी अफसरों के लिए।

हम जानते हैं कि अवैध निर्माण होता है अस्पतालों, स्कूलों और मनोरंजन स्थलों में भी, जहां बच्चे जाते हैं। इन जगहों में आग अक्सर लगती है, लोग अक्सर मरते हैं, जैसे पिछले दिनों राजकोट के एक मनोरंजन पार्क में तीस से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें कई बच्चे थे। गुजरात हमारे विकसित राज्यों में है, लेकिन यहां कोई दो साल पहले मोरबी शहर में पुल के गिरने से 141 लोगों की मौत हुई थी और कोई 200 लोगों को चोटें आईं। बाद में मालूम हुआ कि पुल की मरम्मत का काम दिया गया था ऐसी कंपनी को जो घड़ियां बनाती थी, पुल नहीं।

उस हादसे के बाद कंपनी के मालिक कई दिनों तक फरार रहे। अब सजा हुई है कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, याद दिलाते हैं हमको कि भारत को विकसित देश बनने में अभी कई दशक लगेंगे। प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने का। लेकिन क्या इसके बारे में हम सोच भी सकते हैं, जब हर दूसरे दिन कोई ऐसी घटना घट जाती है, जिसमें लोग बेमौत मारे जाते हैं सिर्फ इसलिए कि अपने देश में कानून का डर किसी को नहीं है। यही कारण है कि हत्यारों, बलात्कारियों और आतंकवादियों को भी दंडित करने में कई दशक लग सकते हैं।

विकसित देशों में राष्ट्रपति भी दंडित किए जा सकते हैं, जैसे पिछले सप्ताह डोनल्ड ट्रंप को दंडित किया गया था न्यूयार्क की एक अदालत में। लाख बार कह चुके हैं ट्रंप कि उन पर चल रहे मुकदमे सब झूठे हैं, राजनीतिक बदला लिया जा रहा है उनसे, लेकिन मुकदमे फिर भी चल रहे हैं और वह भी इतनी पारदर्शिता से कि मीडिया मुकदमों के हर पहलू पर खुल कर टिप्पणी कर रहा है। इन पर चर्चाएं होती हैं टीवी पर, जिनमें लोग निडर होकर कहते हैं कि ट्रंप को याद रखना चाहिए कि कानून के सामने सब बराबर होते हैं, चाहे वह राष्ट्रपति क्यों न हो।

ऐसी कानून-व्यवस्था जब बनेगी भारत में तब हम वास्तव में देख सकेंगे विकसित होने का सपना। अभी हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी बनते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री वे कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। अदालतों पर आम भारतीय नागरिकों का भरोसा इतना कमजोर है कि इस देश के कई ऐसे लोग हैं, जो अदालतों तक जाते ही नहीं हैं। एक तो न्याय मिलने में दशकों लग सकते हैं और दूसरा इसलिए कि बहुत कम लोग हैं इस देश में, जो इतने अमीर हैं कि वकीलों के पैसे दे सकें। पिछली बार जब मैंने किसी वकील से सलाह ली थी तो एक घंटे के लिए मुझे तीस हजार रुपए देने पड़े और वह भी एक ऐसे वकील को जो नामी नहीं थे। न्याय-व्यवस्था अपने देश में सिर्फ धनवानों के लिए है। विकसित देशों में ऐसा नहीं है। इसलिए फिलहाल हमको विकसित बनने का सपना भूल जाना चाहिए।

अभिव्यक्ति की आजादी

हाल के कुछ वर्षों से भारत की ज्ञान परंपरा विषय के रूप में लोकप्रिय हो रही है। इसकी महत्ता और उपयोगिता स्वीकार की जा रही है। यह स्वाभाविक प्रश्न है कि ज्ञान को भूगोल विशेष से जोड़ना कितना उचित है। यह समझना जरूरी है कि भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने और जीवन दर्शन का प्रवाह अर्जित करने, दोनों में बुनियादी अंतर है। पहली श्रेणी मानव जीवन के स्वार्थ का पक्ष है। भौतिक विज्ञान इसमें काम आता है। दूसरा पक्ष मानव जीवन के निस्वार्थ पक्ष को सबल करता है, जिसमें वह मनुष्य होने के औचित्य को ढूंढ़ता है। भारत में ज्ञान को मुक्ति का साधन माना गया है, जबकि भारत के बाहर की दुनिया में यह मनुष्य को ताकतवर बनाता है। वह इससे भौतिक संपन्नता प्राप्त करता है। भारत की रचनाएं वेद, उपनिषद, महाभारत, बौद्ध-जैन ग्रंथ, गुरुग्रंथ साहिब आदि मनुष्य को व्यापकता, विविधता, आलोचनात्मकता और विवेकवाद की ओर ले जाती है। इसीलिए भारत की ज्ञान परंपरा कहना उचित है।

ज्ञान परंपरा पर चर्चा और इसकी उन्नति तो स्वतंत्रता के बाद ही हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं। दरअसल, तब शासक भारतीय थे, पर यूरोप के दर्शन को ही वे मानसिक-सांस्कृतिक प्रगति का आधार मानते थे। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा को समझने और उसे बढ़ाने वाले लोग नहीं थे। पुरुषोत्तम दास टंडन, संपूर्णानंद, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी आदि प्रमुख नाम थे। पर वे सत्ता के केंद्र नहीं थे। राजसत्ता ने जिस बौद्धिक धारा को आगे बढ़ाया, उसमें भारत की विरासत, इतिहास, सांस्कृतिक योगदान की बात करना दक्षिणपंथ, पुराणपंथ और यहां तक कि सांप्रदायिक और संकीर्ण माना जाने लगा। बुद्धिजीवियों की फौज ने अध्ययन, चिंतन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पहरेदारी शुरू कर दी। कठोरता के बावजूद शत्रुता की ताकत और प्रकृति प्रतिरोध के सामने देर-सबेर घुटने टेक देती है, पर अपने बीच में ही ज्ञान को परिभाषित कर उसकी धारा निर्धारित कर देना अभिव्यक्ति की आजादी पर सबसे घातक चोट होती है।

संस्कृति और राजनीति के बीच आंख-मिचौली चलती रहती है। संस्कृति राजनीति को रेगिस्तान बनने नहीं देती है। आजादी से पूर्व साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन जब अधिकार और अर्थ तक सीमित था, तब राजनीतिक प्रतिभाओं ने संस्कृति का सहारा लिया। महर्षि अरविंद, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक जैसे सैकड़ों लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन की जड़ में संस्कृति और विरासत का खाद-पानी दिया। सांस्कृतिक चेतना से राष्ट्रवाद को समृद्ध किया गया। भारत की ज्ञान परंपरा ने कुछ साम्राज्यवादी शासकों को भी प्रभावित किया और उन्होंने भी इसे प्रोत्साहित करना अपनी नैतिक जिम्मेदारी माना था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं।

अब भारत की ज्ञान परंपरा पर काम राष्ट्रवादी उपक्रम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए कि इस पर रुकावट के विरुद्ध राजनीतिक अभियान चला, लेकिन वर्तमान परिवेश में कथित दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी छपी-छपाई बातों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इसमें खतरा सतही लेखन का है, जो भारत की ज्ञान परंपरा को पहले हुए दमन से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। विरासत और वर्तमान के बीच पुल बनाने के लिए करिअरवादी मानसिकता से मुक्त विद्वानों की आवश्यकता होती है। यह आसान काम नहीं है। बदली परिस्थिति में अपने अकादमिक व्यवसाय को लोग बढ़ाने के लिए छद्म विद्वानों की फौज विकसित हो जाती है। वे स्वभाव से सतही होते हैं। परिणाम उसी के अनुकूल होता है।

भारत में समृद्ध लोकतंत्र था। इसे बीसवीं शताब्दी के आरंभ में कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। तब केपी जायसवाल, जो व्यवसाय से वकील थे, ने यह बीड़ा उठाया। गहन शोध का। पहला लेख कोलकाता से प्रकाशित 'माडर्न रिव्यू' में 1913 में प्रकाशित हुआ। इसमे हिंदू राजनीति के विकसित स्वरूप को तथ्यात्मक रूप से दर्शाया गया। उस वक्त रामानंद चटर्जी इस स्तरीय पत्रिका को प्रकाशित करते थे। उन्हें इसके व्यावसायिक लाभ या प्रसार की चिंता नहीं थी। अद्भुत योगदान था। यूरोपीय विद्वान विंसेट स्मिथ ने जायसवाल से इस विषय पर पुस्तक लिखने की सलाह दी। 1924 में पुस्तक प्रकाशित हुई। जायसवाल को क्या मिला? इसका उत्तर वे स्वयं

संदर्भ

राकेश सिन्हा

अब भारत की ज्ञान परंपरा पर काम राष्ट्रवादी उपक्रम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए कि इस पर रुकावट के विरुद्ध राजनीतिक अभियान चला, लेकिन वर्तमान परिवेश में कथित दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी छपी-छपाई बातों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इसमें खतरा सतही लेखन का है, जो भारत की ज्ञान परंपरा को पहले हुए दमन से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है।

उसकी प्रस्तावना में देते हैं, 'विषय लोकप्रिय हो गया। इसे स्वीकृति प्राप्त हुई और अपनाया गया।' उन्हें संतुष्टि मिली कि उनका कार्य 'उनके नाम को संदर्भ बनाकर या बिना उल्लेख किए उद्धृत किया जा रहा है।'

आठवीं शताब्दी में बौद्ध के महायान परंपरा से जुड़े शांतिदेव की रचना लोकप्रिय हुई। उन्होंने प्राक्कथन में लिखा था, 'मैं कुछ नया नहीं लिख रहा हूं। जो कुछ भी लिख रहा हूं, वह अपनी संतुष्टि के लिए लिख रहा हूं।' शांतिदेव और जायसवाल, भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसे हम फिर लोकप्रिय करने, स्वीकृति प्राप्त करने और अपनाने के लिए अभी सपने देख रहे हैं, उसके प्रतिनिधि स्वरूप में हैं।

स्वतंत्रता ही रचनात्मकता और विविधता को जीवित रखती है। इसमें तर्क की ताकत उपजती है जो शैक्षणिक परिसर की आत्मा होती है। इसकी उपेक्षा से ताकत का तर्क अपनी जगह बनाना शुरू कर देता है। भारत की ज्ञान परंपरा साध्य न होकर भविष्य के लिए साधन है। इसकी सार्थकता विरासत के महिमामंडन में न होकर उसे संदर्भित करने और नव-रचना को नए संदर्भ में प्रोत्साहित करने में है, जो भौतिकता के कारण बदलती परिस्थितियों में मानव मन को अशांति और उपद्रवी मानसिकता से बचा सके।

आराधन और दृढ़ आराधन

बाखबर

सुधीश पचौरी

एक चैनल पर एक आस्थावादी कहिन कि ये सब 'पतित धर्मनिरेपक्षता' है। एक एंकर भी कहिन कि ये विपक्ष का 'हड़बड़ी का शोर' है। एक आचार्य कहिन कि जो लोग ध्यान का, साधना का, अध्यान आदि का महत्त्व नहीं जानते, वही ऐसा कहते हैं।

'मुझे परमात्मा ने भेजा है... परमात्मा का आशीर्वाद है... परमात्मा की कृपा है!'

– 'ये 'परमात्मा-कांप्लेक्स' है!'

– 'वे परमात्मा हैं तो हमें उसके लिए एक मंदिर बना देना चाहिए!'

– 'वे कहते हैं कि वे 'जैविक प्राणी' नहीं हैं!'

– 'प्रधानमंत्री तो 2047 की बात कर रहे हैं!'

– 'नौकरी खटाखट-खटाखट, माहौल टनाटन टनाटन!'

– 'ये हारेंगे खटाखट, फटाफट सटासट सनासन टनाटन दनादन!'

– '4 जून को टनाटन बांड स्कीम सफाचट जनता कहेगी फटाफट!'

– 'आजकल मोदी ज्यादा नहीं बोल रहे कि 400 पार... एक दिन वे कहीं रोने न लगें!'

– 'चुनाव आयोग में आत्मविश्वास की कमी है... अगर कुछ इधर-उधर न हुआ तो हम तीन सौ पार!'

– 'मछली मटन मंगलसूत्र मुजरा... ये कौन-सी भाषा है?'

– 'वे 'जहर' हैं!'

एक पूछता है कि आपका 'प्रधानमंत्री का चेहरा' कौन, तो जवाब आता है: यह तो 'कौन बनेगा करोड़पति' जैसा है! एक खबर कि एक जून को विपक्षी गठबंधन की बैठक दिल्ली में कि एक बड़े नेता का आने से इनकार। एक कटाक्ष आया कि विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है! एक रैली में प्रधानमंत्री बोले कि मैं ओबीसी, एससी, एसटी कोटे को कम नहीं होने दूंगा... मैं इनके पक्ष में खड़ा रहूंगा... मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है! एक चर्चक बताता रहा कि ईसाइयत या इस्लाम में जब जाति ही नहीं तो इनको आरक्षण कैसे दे दिया गया? एक कहिन कि यह घपला तो भाजपा के राज्यों में भी हुआ है! तो जवाब आया कि ऐसी बात है तो हम इसकी समीक्षा करेंगे, धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधनिक है।

फिर आया वही पुराना रोना कि ईवीएम में गड़बड़... मैनपुरी में एक व्यक्ति ने आठ वोट कैसे डाले? फिर एक दिन एक चैनल पर चार ज्ञानी एक दूसरे से पूछते भए कि चार जून को क्या होने जा रहा है? एक कहिनः बहुत हुआ तो भाजपा की तीन सौ.. बाकी एक जून को बताएंगे! दूसरे कहिन कि युवा मुखर हो रहा है, औरतें भी मुखर हो रही हैं! ऐसे में किसको कितनी मिलेंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता! तीसरे कहिन कि महंगाई बेरोजगारी कब नहीं रहीं... अरे जो जरूरतमंद को देता है, उसका वोट उसे ही मिलता है। चौथे कहिन कि माना कि महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर भी लोग सोचते हैं कि इसका इलाज भी मोदी ही कर सकता है। अंत में सभी सहमत रहे कि मुद्दे हैं, लेकिन बहुत व्यापक नाराजी नहीं है। इस तरह सभी सुरक्षित खेले और पूरा 'प्राइम टाइम' निकाला।

एक 'चुनाव विशेषज्ञ' कहिन कि 2019 में बंगाल में जो 'फाल्ट लाइन' भाजपा ने उभारी थी 2024 में, वह और गहरी होती दिखती है। इधर कन्याकुमारी जाकर विवेकानंद मेमोरियल राक पर मोदी जी का पैंतालीस घंटे के ध्यान का एलान और विपक्ष परेशान। एक कहिन, ये 'ढोंग' है, दूजे कहिन कि यह 'पाखंड' है। तीजे कहिन कि ये 'प्रचार-भूख' है, चौथे कहिन कि 'राक' के आगे तो पानी ही पानी है। पाचवें कहिन कि ये विदा होने वाले प्रधानमंत्री की अंतिम यात्रा है, छठे फरमाए कि इसका कवरेज मतदान को प्रभावित कर सकता है, इसलिए टीवी कैमरों को इसे नहीं दिखाना चाहिए। सातवें ने काले झंडे दिखाए और नारे लिखे कि 'गो बैक मोदी गो बैक मोदी' और जब इतने से भी दिल न भरा तो सीधे चुनाव आयोग से शिकायत कर दी गई।

एक चैनल पर एक आस्थावादी कहिन कि ये सब 'पतित धर्मनिरेपक्षता' है। एक एंकर भी कहिन कि ये विपक्ष का 'हड़बड़ी का शोर' है। एक आचार्य कहिन कि जो लोग ध्यान साधना का, अध्यान आदि का महत्त्व नहीं जानते, वही ऐसा कहते हैं। हम तो कवि निराला की एक पंक्ति के जरिए, विपक्ष से कहेंगे कि हर वक्त 'प्रतिक्रिया' करने की जगह 'आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर!'

बहरहाल, शुक्रवार की सुबह से ही कुछ चैनल दिखाते बताते रहे कि किस तरह प्रधानमंत्री कन्याकुमारी आए, किस तरह उन्होंने तीन हजार साल पुराने भगवती अम्मन देवी के मंदिर में पूजा की। अगली सुबह से फिर कई चैनल दिखाते बताते रहे कि किस तरह प्रधानमंत्री एकदम 'ध्यानमग्न हैं... उनके माथे पर त्रिपुंड है... नेत्र बंद हैं... हाथ जुड़े हैं... गैरिक वसना हैं... सामने विवेकानंद की मूर्ति है..! कई विपक्षी कई चैनलों में कलहरत रहे और कहते रहे कि इसे मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन कई चैनल मोदी जी को पद्मासन मारे ध्यानमग्न मुद्रा में दिखाते रहे।

एक चैनल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कुल एक सौ अस्सी रैली की है जो अब तक की सबसे अधिक है और किसी भी विपक्षी नेता की रैलियों से अधिक हैं। विपक्ष के एक नेता यह भी कटाक्ष किए कि यह सब उनकी निराशा है। एक विपक्षी नेता एक चैनल पर कहिन कि प्रधानमंत्री के पास सात दिन बचे हैं तो अगले पल उसी चैनल पर लिखा दिखाः प्रधानमंत्री ने भूचाल की चेतावनी दी।

www.readwhere.com

18वीं लोकसभा के लिए सभी सात चरण के मतदान पूरे हो गए हैं। अंतिम चरण के मतदान के बाद अलग अलग एजेंसियों द्वारा किए गए एग्जिट पोल के अनुमानों में केंद्र में तीसरी बार मोदी की सरकार बनने जा रही है। अंतिम परिणाम चार जून को आएगा, इससे पहले अगर इस बार के आम चुनाव के प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों का अवलोकन करें तो, बेरोज़गारी, महंगाई, हिन्दू-मुस्लिम, राम मंदिर, मुस्लिम आरक्षण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातीय जनगणना, पाकिस्तान, तुष्टिकरण आदि मुद्दे हावी रहे, लेकिन सामाजिक-आर्थिक सुधार और विकास की भावी रूपरेखा को लेकर सन्नाटा-सा छाया रहा। किसान कर्जमाफी और एमएसपी के आश्वासन भी 'सियासी' ही दिखे, क्योंकि ऐसी घोषणा वालों को भीतरी एहसास था कि उन्हें सत्ता में नहीं आना है। राजनीतिक दलों और नेताओं ने खूब आश्वासन बांटे, वादे भी परोसे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियां चर्चा में रहीं। विपक्ष के प्रवक्ता नेता आखिर तक देश को पूरी तरह आश्वस्त नहीं कर सके कि वे चुनाव जीत रहे हैं। सारांश में रोटी, कपड़ा, मकान और बुनियादी न्याय पर यह चुनाव लड़ा गया, लेकिन मुद्दों का मज़ाक भी बनता रहा। पूरे चुनाव के दौरान दलों की ओर से कोई ठोस, निश्चित 'राष्ट्रीय विज़न' पेश नहीं किया गया। आखिर नई संसद और सरकार किन मुद्दों के आधार पर देश को संचालित करेंगे। इस बार के आम चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान पक्ष व विपक्ष के दलों के वादों, मुद्दों, कटाक्षों और व्यक्तिगत हमलों का विश्लेषण करता आजकल का यह अंक...

मोदी के इर्द-गिर्द ही रहा चुनाव अभियान

विश्लेषण

सुशील राजेश
वरिष्ठ पत्रकार

दरअसल यह आम चुनाव प्रधानमंत्री मोदी का ही रहा। चुनाव या तो उनके पक्ष अथवा विरोध का रहा। प्रधानमंत्री मोदी के इर्द-गिर्द ही चुनाव केंद्रित रहा। 'मोदी है तो मुमकिन है' और 'अब की बार, 400 के पार' मानने और हुंकार भरने वालों की बड़ी संख्या रही, तो मोदी से नफरत करने वाले समूह भी अपने दुराग्रहों पर जमे रहे। चुनावी मुद्दा यह था कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या उन्हें सत्ता के बाहर कर दिया जाएगा। यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी बनाम मुद्दों का रहा। विपक्ष ने मुद्दे जरूर उठाए, लेकिन उन्हें जनता तक पहुंचाने में वे नाकाम रहे। 'इंडिया' गठबंधन तो न्यूनतम कार्यक्रम तक नहीं बना पाया। गांवों तक एक भ्रामक प्रचार फैलाने में विपक्ष सफल रहा कि संविधान बदल दिया जाएगा।

अठारहवीं लोकसभा के लिए आम चुनाव सम्पन्न हो गया। करीब 60 करोड़ भारतीयों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया और नई संसद के लिए जनादेश दिया। इस बार 1.80 करोड़ नए, युवा मतदाता भी जोड़े गए। हैरानी है कि अधिकांश चुनाव के प्रति उदासीन रहे। राजनीतिक दलों और नेताओं ने खूब आश्वासन बांटे, वादे भी परोसे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियां चर्चा में रहीं। उन्हें कसौटी पर परखा जा चुका है, लेकिन जनादेश घोषित होने के बाद उनकी नई अग्निपरीक्षा होगी। चुनाव के दौरान बेरोज़गारी, महंगाई, हिन्दू-मुस्लिम, राम मंदिर, मुस्लिम आरक्षण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातीय जनगणना, पाकिस्तान, तुष्टिकरण आदि ढेरों मुद्दे उठाए गए, लेकिन सामाजिक-आर्थिक सुधार और भावी रूपरेखा को लेकर सन्नाटा-सा छाया रहा। किसान कर्जमाफी और एमएसपी के आश्वासन भी 'सियासी' रहे, क्योंकि ऐसी घोषणा वालों को भीतरी एहसास था कि उन्हें सत्ता में नहीं आना है। अलबत्ता प्रधानमंत्री किसानों के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा जरूर करते रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'खटाखट' गरीबी हटाने और 'टकाटक' संसदीय सीटें जीतने की हास्यास्पद पैरोडी जरूर पेश की। इसी तर्ज पर 'फटाफट' और 'गटागट' के जरिये विपक्ष ने खुद पर ही तंज कसे, लेकिन विपक्ष के प्रवक्ता नेता आखिर तक देश को पूरी तरह आश्वस्त नहीं कर सके कि वे चुनाव जीत रहे हैं। सारांश में रोटी, कपड़ा, मकान और बुनियादी न्याय पर यह चुनाव लड़ा गया, लेकिन मुद्दों का मज़ाक बनता रहा। विपक्ष ने मतदान के तीसरे चरण से यह राग अलापना शुरू किया कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा देश का संविधान बदल देंगे और लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान कोई ठोस, निश्चित 'राष्ट्रीय विज़न' पेश नहीं किया गया। आखिर नई संसद और सरकार किन मुद्दों के आधार पर देश को संचालित करेंगे।

पक्ष अथवा विरोध

दरअसल यह आम चुनाव प्रधानमंत्री मोदी का ही रहा। चुनाव या तो उनके पक्ष अथवा विरोध का रहा। प्रधानमंत्री मोदी के इर्द-गिर्द ही चुनाव केंद्रित रहा। 'मोदी है तो मुमकिन है' और 'अब की बार, 400 के पार' मानने और हुंकार भरने वालों की बड़ी संख्या रही, तो मोदी से नफरत करने वाले समूह भी अपने दुराग्रहों पर जमे रहे। चुनावी मुद्दा यह था कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या उन्हें सत्ता के बाहर कर दिया जाएगा। यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी बनाम मुद्दों का रहा। विपक्ष ने मुद्दे जरूर उठाए, लेकिन उन्हें गंभीरता से जनता तक पहुंचाने में वे नाकाम, असहाय रहे। 'इंडिया' गठबंधन तो न्यूनतम कार्यक्रम तक नहीं बना पाया। हालांकि गांवों तक एक भ्रामक प्रचार फैलाने में विपक्ष सफल रहा कि संविधान बदल दिया जाएगा। संविधान बदला गया, तो आरक्षण की व्यवस्था भी समाप्त हो

जाएगी। संभवतः 2024 अंतिम चुनाव साबित होगा, क्योंकि उसके बाद संसदीय चुनाव 'एकाधिकारवाद' के तहत होंगे। ग्रामीण जनता ने इस दुष्प्रचार पर कुछ यकीन भी किया, नतीजतन प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पलटजवाब देते हुए देश को भरोसा बांटते रहे कि अब बाबा आंबेडकर भी संविधान को बदल नहीं सकते। संविधान और लोकतंत्र पर विपक्षी दुष्प्रचार हास्यास्पद और बेमानी था, क्योंकि भारत कोई 'केला गणतंत्र' नहीं है। यह चुनाव मोदी आधारित इसलिए भी रहा, क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत की हद तक प्रचार करते रहे, लिहाजा भाषा की मर्यादाएं भी टूटीं।

मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा

दरअसल चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा घोर प्रबल रहा। दूसरी ओर युवा चेहरे बेरोज़गारी को लेकर चिन्ता और आक्रोश जताते रहे, लेकिन बेरोजगारी देश का जनादेश तय नहीं कर पाई। चुनाव के शुरुआत में एक डाटा सार्वजनिक किया गया कि मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान 51.40 करोड़ रोज़गार सृजित किए। इनमें नौकरियां, स्वरोज़गार और निजी क्षेत्र में दिहाड़ीदार रोज़गार भी शामिल हैं। यह भी दावा किया गया कि 43 करोड़ से अधिक लोगों को 'मुद्रा लोन' दिए गए। जाहिर है कि वह भी रोज़गार का एक हिस्सा है। सरकार की 12 प्रमुख परियोजनाओं के तहत 19.79 करोड़ को रोज़गार दिया गया। दलील दी गई कि यदि यूपीए सरकार मनरेगा दिहाड़ी को रोज़गार मानती थी, तो मोदी सरकार के दौरान ऐसे अवसरों को रोज़गार क्यों नहीं माना जाना चाहिए? इन दावों के विपरीत देश में बेरोज़गारी का संकट बदतर होता जा रहा है। सरकार कुछ भी दावा करे, लेकिन आम चुनाव के 6 चरणों तक केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र सरीखे सम्पन्न राज्यों से लेकर बिहार, ओडिशा, राजस्थान जैसे अपेक्षाकृत गरीब राज्यों तक बेरोज़गारी सबसे बड़ी चीख रही है। 7वें चरण के प्रचार में भी ये मसले रहे। सीएसडीएस-लोकनीति के सर्वे में यह निष्कर्ष भी सामने आया कि 29 फीसदी से अधिक लोग बेरोज़गारी को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। 'आवधिक श्रम बल सर्वे' के ताज़ा डाटा के मुताबिक, जनवरी-मार्च तिमाही में बेरोज़गारी, 15-29 साल के आयु-वर्ग में 17 फीसदी से अधिक रही है। बेशक जीडीपी दर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 8.2 फीसदी बताई जा रही है, जो दुनिया के देशों में सर्वाधिक है, लेकिन वर्तमान कॉरपोरेटी आर्थिक मॉडल में अमीर ज्यादा अमीर हो रहे हैं और मजदूर, किसान और कामगार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है।

अल्पसंख्यक दर्जा कांग्रेस का पुराना खेल

मुस्लिम आरक्षण 2024 के चुनाव का ही मुद्दा नहीं था, बल्कि इसकी शुरुआत देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के कालखंड से हुई, जब नेहरू मुस्लिम आरक्षण का कोई प्रस्ताव पारित कराना चाहते थे। सरदार पटेल की आपत्ति और उनके आग्रह के कारण वह पारित नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस सरकारों के दौरान 13,000 से अधिक स्कूलों को 'अल्पसंख्यक दर्जा' दिया गया और उनमें दलित, आदिवासी, ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था नहीं रखी गई। बाद में ऐसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी आदि में लागू किया गया। कांग्रेस ने केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण दिया। इसका उल्लेख 2009 के कांग्रेस घोषणा-पत्र में है। अब 2024 के चुनाव कांग्रेस इसी धार्मिक विभाजन पर लड़ना चाहती थी और देशभर में मुस्लिम आरक्षण लागू करना चाहती थी। यह दीगर है कि जीत की उसे उम्मीद नहीं थी। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी चुनाव भर मुस्लिम आरक्षण का विरोध करते रहे। उन्होंने बार-बार कहा कि जब तक मोदी जिंदा है, तब तक दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण छीनने नहीं देगा।' कमोबेश चुनाव में हिन्दू-मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण और लामबंदी इसी मुद्दे के कारण हुई। इसमें राम मंदिर का भी योगदान अहम है, क्योंकि भाजपा काडर की टीमें कई बार घर-घर गई हैं और राम के नाम पर वोट मांगे हैं।

एक चुनाव रणनीति पर काम

भाजपा ने एक चुनाव-रणनीति पर काम किया था। वह चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी के विशेष कार्यक्रमों से जोड़ कर लाभ लेना चाहती थी। उसके लिए अलग-अलग लाभार्थी समूह तैयार किए गए। 'मुफ्त आवास' से ही 1.18 करोड़ परिवार लाभार्थी माने गए हैं। रणनीति थी कि ऐसे प्रत्येक घर से औसतन 2 वोट जरूर हासिल किए जाएं। मोदी सरकार 80 करोड़ से अधिक गरीबों को 'मुफ्त राशन' बांटती रही है। रणनीति थी कि यदि 50 फीसदी लाभार्थी भी भाजपा को वोट देते हैं, तो 40 करोड़ वोट मिल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य तय किया गया था कि कमोबेश 25 फीसदी ऐसे लाभार्थी जरूर वोट करें। इसी रणनीति के आधार पर प्रधानमंत्री और भाजपा नेता चुनाव के अंत तक 400 पार के लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। दूसरी ओर कांग्रेस ने एक अंदरूनी सर्वे कराया था, जिसकी रपट 1 जून के अंतिम चरण के मतदान से पहले सामने आई है। उसमें खुद कांग्रेस 100-115 सीट जीतने की मान रही है। स्पष्ट बहुमत के आंकड़े 273 तक पहुंचने के लिए शेष संख्या कहां से आएगी? अलबत्ता राहुल गांधी अंत तक दावा करते रहे कि जीत निश्चित है। क्लीन स्वीप होगा। जीतने वाली सीटों की ऐसी लाइन लगेगी कि टकाटक, टकाटक....! और फिर मोदी जी तथा भाजपा को बाय, बाय। टाटा...! बहरहाल किस पक्ष की कितनी सीटें आएंगी, कौन बहुमत आसानी से पा कर लेगा, इसकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती। चुनाव का 'एग्जिट पोल' देश के सामने है। यह कुछ विशेषज्ञों का अनुमान भर है, जो पूरी तरह गलत भी साबित होता रहा है। फिर भी चुनावी लहर और हवा की दिशाओं का कुछ खुलासा तो हुआ है। गंभीर सवाल है कि यदि कांग्रेस और 'इंडिया' अपनी बहुमती जीत के प्रति आश्वस्त थे, तो खासकर कांग्रेस ने एग्जिट पोल का बहिष्कार क्यों किया? बहस से क्यों भाग गई?

सवाल या संदेह नहीं

चुनाव आयोग की निष्पक्षता, ईमानदारी, तटस्थता और व्यापकता पर कोई सवाल या संदेह नहीं है। सर्वोच्च अदालत के सामने भी मामला गया था, जिसने हस्तक्षेप या आयोग का आधार बड़ा करने का कोई फैसला सुनाने से इंकार कर दिया। चुनाव आयोग लंबे मतदान कार्यक्रम पर पुनर्विचार जरूर करे। लोकसभा का कार्यकाल मई-जून तक है, तो चुनाव अप्रैल तक सम्पन्न कराए जा सकते हैं। आयोग के पास बजट और मानव-बल की कोई कमी नहीं। प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन आ जाता है। हम इतने तकनीक सम्पन्न भी हो चुके हैं कि कम अवधि में ज्यादा बड़ा चुनाव सम्पन्न करा सकते हैं। अगले संसदीय चुनाव तक ईवीएम का भी पर्याप्त बंदोबस्त किया जा सकता है। चूंकि जलवायु-परिवर्तन के कारण मौसम भी बदल रहा है। हमने पहली बार देखा है कि तापमान 50-52 डिग्री सेल्सियस तक उछल गया है। गर्मी-लू से देशभर में करीब 60 मौतें हो चुकी हैं। मतदान भी प्रभावित हुआ है। क्या मतदान 4-5 चरण में नहीं हो सकते? क्या पहले ऐसा नहीं किया गया है? कमोबेश उन स्थितियों से आज हम ज्यादा प्रगति पर हैं। आयोग जरूर सोचे।

दिलचस्प है एग्जिट पोल का इतिहास

हकीकत

योगेश कुमार गोयल
वरिष्ठ पत्रकार

देश में कोई भी आम चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद लगभग सभी टीवी चैनल एग्जिट पोल का प्रसारण करते हैं, जिनमें अनुमान लगाया जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है और किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन कई बार एग्जिट पोल जमीनी हकीकत से कोसों दूर भी नजर आते रहे हैं। पिछले कई चुनावों में एग्जिट पोल के अनुमान के विपरीत नतीजे रहे हैं। भारत में एग्जिट पोल का इतिहास ज्यादा सटीक नहीं रहा है।

एग्जिट पोल का वैज्ञानिक आधार

एग्जिट पोल वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि वोटर का केवल रुझान ही होता है, जिसके जरिये अनुमान लगाया जाता है कि नतीजों का झुकाव किस ओर हो सकता है। एग्जिट पोल के दावों का ज्यादा वैज्ञानिक आधार नहीं माना जाता है। एग्जिट पोल में प्रायः मीडिया से आ रही खबरों, चुनाव का इतिहास और हवा के रुख का घालमेल भी शामिल रहता है। दुनियाभर में अधिकांश लोग एग्जिट पोल को विश्वसनीय नहीं मानते।

एग्जिट पोल से सटीक होते हैं पोस्ट पोल

मतदाताओं की राय जानने के लिए 'ओपिनियन पोल' और 'पोस्ट पोल' भी किए जाते हैं। एग्जिट पोल हालांकि ओपिनियन पोल का ही हिस्सा होते हैं, किन्तु ये मूल रूप से ओपिनियन पोल से अलग होते हैं। ओपिनियन पोल में मतदान करने और न करने वाले सभी प्रकार के लोग शामिल हो सकते हैं। ओपिनियन पोल के परिणामों के लिए चुनावी दृष्टि से क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास किया जाता है और क्षेत्रवार यह जानने की कोशिश की जाती है कि जनता किस बात से नाराज और किस बात से संतुष्ट है। इसी आधार पर ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया जाता है कि जनता किस पार्टी या किस प्रत्याशी का चुनाव करने जा रही है। ओपिनियन पोल को ही 'प्री-पोल' भी कहा जाता है।

कब शुरू हुआ सर्वे का सिलसिला

जहां तक चुनावी सर्वेक्षणों के इतिहास की बात है तो सबसे पहले अमेरिका में चुनावी सर्वे कराया गया था, जब अमेरिकी सरकार के कामकाज पर लोगों की राय जानने के लिए जॉर्ज गैलप और क्लॉड रोबिंसन ने इस विधा को अपनाया था, जिन्हें ओपिनियन पोल सर्वे का जनक माना जाता है। चुनाव उपरांत उन्होंने पाया कि उनके द्वारा एकत्रित किए गए सैंपल तथा चुनाव परिणामों में ज्यादा अंतर नहीं था। उनका यह तरीका काफी विख्यात हुआ। इससे प्रभावित होकर ब्रिटेन तथा फ्रांस ने भी इसे अपनाया और बहुत बड़े स्तर पर ब्रिटेन में 1937 जबकि फ्रांस में 1938 में ओपिनियन पोल सर्वे कराए गए। इन देशों में भी ओपिनियन पोल के नतीजे बिल्कुल सटीक साबित हुए थे। जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम तथा आयरलैंड में जहां चुनाव पूर्व सर्वे करने की पूरी छूट है, वहीं चीन, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको इत्यादि कुछ देशों में इसकी छूट तो है किन्तु कुछ शर्तों के साथ। एग्जिट पोल को लेकर माना जाता है कि इनकी शुरूआत नीदरलैंड के समाजशास्त्री तथा पूर्व राजनेता मार्सेल वॉन डैम द्वारा की गई थी, जिन्होंने पहली बार 15 फरवरी 1967 को इसका इस्तेमाल किया था और उस समय नीदरलैंड में हुए चुनाव में उनका आकलन बिल्कुल सटीक रहा था। जहां तक भारत की बात है तो हमारे यहां 1960 में ही एग्जिट पोल का खाका खींच दिया गया था। तब 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) द्वारा इसे तैयार किया गया

था। भारत में एग्जिट पोल की शुरूआत का श्रेय इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रमुख एरिक डी कोस्टा को दिया जाता है। शुरूआत में देश में सबसे पहले इन्हें पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित किया गया जबकि बड़े परदे पर चुनावी सर्वेक्षणों ने 1996 में उस समय दस्तक दी, जब दूरदर्शन ने सीएसडीएस को देशभर में एग्जिट पोल कराने के लिए अनुमति प्रदान की। 1998 में चुनाव पूर्व सर्वे अधिकांश टीवी चैनलों पर प्रसारित किए गए और तब ये बहुत लोकप्रिय हुए थे लेकिन कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग पर 1999 में चुनाव आयोग द्वारा ओपिनियन पोल तथा एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद एक अखबार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया।

मतदान के बाद ही क्यों?

एग्जिट पोल सदैव मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दिखाए जाते हैं। मतदान खत्म होने के कम से कम आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल का प्रसारण नहीं किया जा सकता। इनका प्रसारण तभी हो सकता है, जब चुनावों की अंतिम दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी हो। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि आखिर एग्जिट पोल के प्रसारण-प्रकाशन की अनुमति मतदान प्रक्रिया के समापन के पश्चात ही क्यों दी जाती है? जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126ए के तहत मतदान के दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए, जो मतदाताओं के मनोविज्ञान पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डाले अथवा मत देने के उनके फैसले को प्रभावित करे। यही कारण है कि मतदान से पहले या मतदान प्रक्रिया के दौरान एग्जिट पोल सार्वजनिक नहीं किए जा सकते बल्कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने के आधे घंटे बाद ही इनका प्रकाशन या प्रसारण किया जा सकता है। अधिकांश मीडिया संस्थान कुछ प्रोफेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर एग्जिट पोल करते हैं। ये एजेंसियां मतदान के तुरंत बाद मतदाताओं से यह जानने का प्रयास करती हैं कि उन्होंने अपने मत का प्रयोग किसके लिए किया है और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर यह जानने का प्रयास किया जाता है कि कहां से कौन जीत रहा है। इस आधार पर किए गए सर्वेक्षण से जो व्यापक नतीजे निकाले जाते हैं, उसे ही 'एग्जिट पोल' कहा जाता है। चूंकि इस प्रकार के सर्वे मतदाताओं की एक निश्चित संख्या तक ही सीमित रहते हैं, इसलिए एग्जिट पोल के अनुमान हमेशा सही साबित नहीं होते, उत्सुकता जरूर पैदा करता है।

हमले व कटाक्ष के लिए याद रखा जाएगा

लोकसभा चुनाव प्रचार के 76 दिनों के दौरान नेताओं ने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर हमला व कटाक्ष करने के लिए जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया उसके लिए इस आम चुनाव को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस चुनाव में 'विष गुरु', 'अनुभवी चोर', 'दो शहजादे' के अलावा 'मंगलसूत्र, मुजरा, मटन, मछली' सहित कई ऐसे शब्दों के जरिए आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चला, जिसने खूब सुर्खियां बटोरीं। साथ ही इन पर मीडिया के विभिन्न मंचों पर चर्चा हुई तथा इनके पक्ष व विपक्ष में तर्क भी गढ़े गए। इन वजहों से लोकसभा चुनाव की सरगर्मी पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक बनी रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 'अडाणी और अंबानी से टेम्पो में नकदी' मिलने पर उनकी टिप्पणी के मद्देनजर कटाक्ष करते हुए उन्हें "टेम्पो वाले अरबपतियों" का एक "कठपुतली राजा" बताया था। मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली में कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए 'दो शहजादे' एक साथ आए हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक स्पष्ट हमला था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनावी रैलियों में मोदी के भाषणों को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उससे लगता है कि वह 'विश्व गुरु' नहीं बल्कि 'विष गुरु' हैं। रमेश ने अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री को 'स्व-घोषित भगवान' करार दिया। एक टीवी साक्षात्कार के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए मोदी ने कहा कि 'अनुभवी चोर' जानता है कि कैसे सफाई की जाती है। मोदी ने 'इंडिया' गठबंधन पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए 'मुजरा' करने का आरोप लगाया और विपक्षी समूह द्वारा दलितों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लूटने के प्रयासों को विफल करने का संकल्प लिया।

दंगल में किसका होगा मंगल

आंकलन

राज कुमार सिंह
राजनीतिक विश्लेषक

अठारहवीं लोकसभा के चुनाव में मतदान के बीच ही सत्तापक्ष और विपक्ष ने जिस तरह बहुमत मिल जाने के दावे किए, वह आत्मविश्वास से ज्यादा अनिश्चितता का संकेतक लगता है। पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव बजरंग बली के नाम पर लड़े गए थे। लोकसभा चुनावों में बजरंग बली का नाम ज्यादा सुनाई नहीं पड़ा। शायद इसलिए कि उनके आराध्य श्रीराम को ही चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। अयोध्या में निर्माण और उसमें राम लला की प्राण प्रतिष्ठा ने लोकसभा चुनावों में क्या भूमिका निभाई, उसका पता भी चार जून को चल पाएगा। सात चरणों में मतदान के बीच ही चुनावों में जिस तरह मुद्दे बदले गए, उनसे भी राजनीतिक दलों की रणनीति के बजाय दिग्भ्रम का ही संकेत गया। यह दिग्भ्रम दोनों पक्षों में दिखा। दस साल के शासन को विकास का ट्रेलर मात्र बताने वाली भाजपा ने भी चुनाव में राम से लेकर पाकिस्तान तक और मटन-मछली से ले कर मंगलसूत्र तक तमाम मुद्दे आजमाये, शायद इसलिए कि आश्वस्त नहीं थी कि कौन-सा मुद्दा मतदाताओं के मन पर प्रभाव छोड़ पाएगा।

इन मुद्दों से शुरूआत

इंडिया गठबंधन के बैनर तले एकजुट कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों ने चुनाव प्रचार की शुरूआत नरेंद्र मोदी सरकार के अच्छे दिन आने, हर साल दो करोड़ नौकरियां देने और विदेशों में जमा काला धन वापस लाकर हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख देने जैसे अधूरे वादों तथा महंगाई और बेरोजगारी जैसे जनता से सीधे जुड़े मुद्दों से की थी, लेकिन वह भी बीच मतदान अरबपति मित्र, आरक्षण और संविधान जैसे मुद्दों को आजमाता नजर आया। सत्तापक्ष की तरह विपक्ष भी असमंजस का शिकार था कि पता नहीं कौन से मुद्दे मतदाता का मन मोह पाएंगे। मतदाता द्वारा अपने मन की थाह न देना उसकी और लोकतंत्र की परिपक्वता की निशानी है, लेकिन उसकी मुश्किलें और जरूरतें भी न समझ पाना राजनीति के जनता से कट जाने का प्रमाण है। जन संपर्क से रोड शो में सिमट गई राजनीति की यही सीमाएं हैं कि वह मतदाता का मन पढ़ने के बजाय मोहने का प्रयास करती है। कार्यकर्ताओं और प्रतिबद्ध समर्थकों से इतर आम मतदाता इन चुनावों में जोर-शोर से उठाए गए मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया देता नहीं दिखा। इसी से राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ी, जिसे वह चुनाव के बीच ही बहुमत मिल जाने का दावा कर छिपाने की कोशिश करते दिखे।

लहर नहीं दिखी

साफ कहें तो मतदान के बीच भी मुद्दों के बदलाव के बावजूद इन लोकसभा चुनावों में किसी दल या पक्ष की लहर नहीं दिखी। शायद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इन चुनावों में यही बड़ा बदलाव है। ये चुनाव मतदाता के अपने मुद्दों तथा स्थानीय समीकरणों पर ज्यादा केंद्रित दिखे। जाहिर है, हवा बना कर राजनीति करने वाले दलों-नेताओं को यह अच्छा नहीं लगा होगा, पर पांच साल में चुनाव ही तो वह अवसर है, जब मतदाता वह करते हैं, जो उन्हें अच्छा और सही लगता है। अगर मतदाताओं के मुद्दों और स्थानीय समीकरण पर इन चुनावों का आकलन करें तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि इस चुनावी दंगल में मंगलवार को किसका मंगल होने जा रहा है। इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा सबसे बड़ा और मजबूत राजनीतिक दल है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय राजनेता। फिर भी भाजपा के लिए 370 और उसकी अगुवाई वाले राजग के लिए 400 सीटों का लक्ष्य बहुत दूर की कौड़ी लगती है। इसके बावजूद यह तय है कि भाजपा ही सबसे बड़ा दल होगी।

कारण भी बहुत स्पष्ट

अपने प्रभाव क्षेत्रों में भाजपा 2014 और 2019 में अपना लगभग सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है। फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और सुखबीर सिंह बादल के शिरोमणि अकाली दल के अलगाव के बाद राजग भी पहले जितना मजबूत नहीं रह गया है। गिनती के लिहाज से राजग का कुनबा भले ही बढ़ा हो, पर ताकत घटी है। कभी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड की राजग में वापसी विपक्ष के लिए बड़ा झटका था, लेकिन उसके बावजूद वहां से 40 में से 39 लोकसभी सीटें जीत लेने की खुशफहमी खुद भाजपा को भी नहीं है। कर्नाटक में सत्ता में रहते हुए 2019 में भाजपा ने समर्थित निर्दलीय समेत 28 में से 26 लोकसभा सीटें जीत ली थीं। अब वहां कांग्रेस सरकार है। राजस्थान में सरकार बना लेने के बावजूद पहले की तरह सभी 25 लोकसभा सीटें जीतने का दावा भाजपा नेता निजी बातचीत में नहीं करते। हरियाणा में सभी 10 सीटें जीत पाना इस बार संभव नहीं दिखता। सात सीटों वाली दिल्ली में भी झटका लग सकता है। जनवरी में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा और फिर अचानक जयंत चौधरी के रालोद के पाला बदल कर राजग में चले जाने से ऐसा लगा था कि भाजपा अन्य राज्यों में होने वाले नुकसान की भरपाई उत्तर प्रदेश से कर लेगी। ध्यान रहे कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 2014 में 71 और 2019 में 62 जीती थीं, लेकिन बाद में जिस तरह मुद्दे बदलने पड़े और सपा-कांग्रेस गठबंधन ने समीकरणों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया, उससे वह भरपाई मुश्किल दिख रही है। ऐसे में सीटों के संभावित नुकसान की भरपाई की भाजपाई उम्मीदें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम जैसे राज्यों पर टिक गई हैं, पर वहां भी संभावनाएं सीमित हैं। बंगाल में भाजपा की चुनौती 18 सीटें बरकरार रखना या एक-दो सीट की वृद्धि ही लगती है। अगर विपक्ष का यह दावा सही हुआ कि चुनाव उसने नहीं, जनता ने लड़ा है, तब तमाम आकलन बेमानी साबित हो सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

Want to get these Newspapers Daily at earliest

1. AllNewsPaperPaid
2. आकाशवाणी (AUDIO)
3. Contact I'd:- https://t.me/Sikendra_925bot

Type in Search box of Telegram
@AllNewsPaperPaid And you will find a Channel
Name All News Paper Paid Paper join it and receive
daily editions of these epapers at the earliest

Or you can tap on this link:

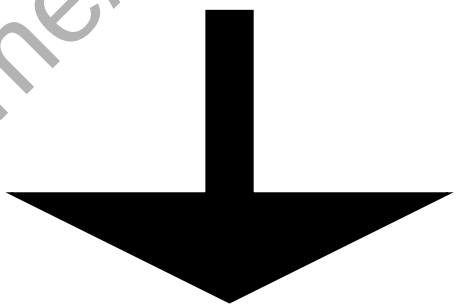

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid